



1947-उपरात भारत

का

सामाजिक यथार्थ

एक ऐतिहासिक विश्लेषण

इतिहास मानव ज्ञान के दो मूल स्रोतों में से एक है,  
दूसरा प्राकृतिक विज्ञान है

सहयोग राशी 60 रु०

पता सी 5, बीपीसीआई बिल्डिंग, इण्डिया, दिल्ली 110009

इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए और उसकी ओर से  
आर०पी० सराफ द्वारा प्रकाशित  
तथा मानस प्रिंटिंग प्रेस, गाँधी नगर, दिल्ली में मुद्रित



## प्रस्तावना

(1) इस लेख में अपनी मनागत और वस्तुगत सीमाओं के भीतर रहत हुए 1947 उपरांत भारत के सामाजिक यथाथ को समझने की कोशिश की गई है। इस मूल्यांकन में जहां कहीं त्रुटि रह गई हो, उस बारे में सभी उचित सुझावों का हम तहे-दिल से स्वागत करेंगे और उस पर अमल करेंगे तथा अपनी गलतियों, कमियों व खामियों को सुधारेंगे। दुनिया में कोई भी चीज तकदोप से परे नहीं होती, हालांकि जहां तक संभव हो पूर्णता या विशिष्टता तक पहुँचने की वाशिशों की जा सकती है और की भी जानी चाहिए।

(2) इस लेख में अभिव्यक्त समझ के समीक्षकों से उम्मीद है कि वे इसे निम्न-लिखित कसौटी पर परखेंगे। एक तो यह कि इसमें जो कुछ कहा गया है वह सही है या गलत, उचित है या अनुचित और यथाथ के अनुरूप है या नहीं। दूसरे, यह कि इसमें की गई टिप्पणियाँ मनुष्य के नैतिक मानदंडों के अनुरूप है या नहीं। मूल्यांकन इसके किसी एक भाग तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसके सभी भागों सहित समूचे लेख में अभिव्यक्त समझ पर होना चाहिए। चहुँमुखी जायजा लेना ही चीजों को परखने का ऐतिहासिक वैज्ञानिक ढंग है।

(3) इस लेख में भूमिका के अतिरिक्त आठ अध्याय हैं। भूमिका में इस दस्तावेज के दृष्टिकोण और विषयवस्तु की व्याख्या की गई है। अध्याय एक में 1947 के बाद के भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, शुरू से लेकर 1947 तक, बयान की गई है। अध्याय दो में 1947 के बाद की भारतीय सामाजिक व्यवस्था के सामान्य लक्षणों का वर्णन है। अध्याय तीन में 1947 के बाद के भारतीय राज्यतंत्र का जायजा लिया गया है। अध्याय चार में 1947 के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्लेषण है। अध्याय पाँच में 1947 के बाद की भारतीय संस्कृति का अवलोकन प्रस्तुत है। अध्याय छह में 1947 के बाद भारत की कूटनीति-सह-रक्षा नीति का मूल्यांकन दज है। अध्याय सात में 1945 के बाद की दुनिया का विवरण दिया गया है। अध्याय आठ में दुनिया की सामाजिक इकाई के एक भाग के तौर पर भारत के आधुनिकीकरण की दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजनाएँ प्रस्तुत की गई हैं।

(4) इस लेख को पूरा करने में जिन आदरणीय मित्रों ने दुरुस्तियाँ, आलोचनाएँ, सुझाव, टाइपिंग, पांडुलिपि का मूल व सशोधित अध्ययन, कर्पोरिंग, प्रूफ रीडिंग, छपाई, भोजन व आवास मुहैया कराने अलग अलग तरह से योगदान दिया है, मैं उन सभी का तहेदिल से आभारी हूँ।

(5) यह लेख मूलतः तीन ऐतिहासिक सवालों का जवाब प्रस्तुत करता है। एक यह कि भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को चलाते चले ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दफा होने तथा मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तुत और राष्ट्रीय एकता की जड़ छोड़ने वाले 'भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवाद' के सिद्धांत की रवानगी के 40 साल बाद भी सांप्रदायिकता और जातिवाद भारत में क्यों तबही मचाए हुए हैं? दूसरे, क्या बजह है कि भारतीय राष्ट्र राज्य की स्थापना के चार दशक बाद, एक परिवार की अगुआई में एक ही पार्टी के लंबे और निरंतर शासन के 38 साल बाद तथा समाजवाद लाने और गरीबी हटाने का लक्ष्य रखने वाली नियोजित आर्थिक प्रक्रिया के 37 साल बाद भी 40 फीसदी से अधिक भारतीय लोग आधा पेट ही भर पाते हैं, एक तिहाई बिना घर बार के हैं जिनमें शहरी बेघर पटरियों पर सोते और झुग्गियों में रहते हैं जबकि देहाती बेघर जानवरों सहित घासफूस के झोपड़ों में बसर करते हैं, दो तिहाई लोग अनपढ़ हैं तथा करीब 20 लाख हर साल कुपोषण की यज्ञ से मर जाते हैं? तीसरा सवाल यह है कि आठ आम चुनावों सहित एक लंबी संसदीय प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी भारत का राष्ट्रीय चरित्र ऐसे राजनैतिक नेतृत्व के प्रति क्यों सहनशील है जो धन शक्ति व बाहुबल, जातिवाद और सांप्रदायिकता के आधार पर खड़ा है तथा चुनाव प्रक्रिया का भ्रष्ट करने के लिए काले धन का इस्तेमाल करता है और फिर चुनाव खर्चों के बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त के पास झूठा विवरण दाखिल करता है? (राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सरीखे ऊंचे पदों के लोग भी इस आचरण से परे नहीं)

(6) उपरोक्त तीन चीजों के बने रहने यानी सांप्रदायिकता और जातिवाद का बालबाला होने, दो तिहाई आबादी के लिए बेहद गरीबी जारी रहने तथा भ्रष्ट राजनैतिक नेतृत्व के चलते रहने से क्या अभिप्राय है? इसका सीधा सादा मतलब है कि मानवीय विचारों, व्यवहार और संगठन के मामले में भारत के औद्योगिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जिस हद तक जरूरी और संभव है उस स्तर तक विकसित नहीं है।

(7) 1947 से पहले इन तीनों चीजों के बारे में भारतीय लोगों की क्या समझ थी? यह कि उपनिवेशी शासन की देन इन तीनों चीजों का 'खात्मा इस शासन के खत्म होने से ही होगा। इस तरह, गांधी ने पूरे घोषणा की थी कि ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार के खात्मे के बाद ही भारत में 'समराज्य कायम होगा। नेहरू का पूर्वानुमान था कि उनका समाजवादी नियोजन भारत को एक अत्याधुनिक देश में बदल डालेगा। पटेल का अनुमान था कि देश से 'भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवाद' की रवानगी के बाद सांप्रदायिकता और जातिवाद खत्म हो जाएंगे।

(8) सत्ता सभालने के बाद (1971 में) इंदिरा गांधी ने 10 साल के भीतर भारत से गरीबी खत्म करने का वादा किया। 1985 में राजीव ने सावजनिक जीवन को पाक साफ बनाने का हलफ लिया।

(9) उपरोक्त घोषणाओं के विपरीत भारत आज भूटान और बांग्लादेश सहित दुनिया के 10 सबसे गरीब देशों की श्रेणी में है और इस दर्जे में पाकिस्तान से

भी मोचे है। यह दुनिया में सबसे कम उम्रवाले दर वाले देशों में एक है। चीन 1950 के दशक के बाद 1970 के और दक्षिण अफ्रीका 1980 के दशक में इस नीचे छोट टिया था। अब 1990 के दशक के शुरू में साइप्रस, विमीनीय और सायप्र पाकिस्तान भी इसे पछाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बहुत से देशों में तो भारत दुनिया भर का अगुआ है। आर्थिक तौर पर यह कराची, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, बढ़ती पूंजी/उत्पादन अनुपात, उत्पादन की उच्च लागत, गामा की घटिया क्वालिटी, गैर-उत्पादक खप, अपव्यय, अकृषकता और समय बर्बाद का मतलब है सामान्य गरीबी इनो से आगे है। दरभंगस, गरीबी और असमानता में भारत का दुनिया का अग्रणीतम अर्थोपे राष्ट्र राज्य बना दिया है। सामूहिक तौर पर यह प्रत्याहार, धायाधरी बापसुभी जो हूनुरी बाटुकारिता अपराध हत्या, टीबी, प्रहोता, पुष्ट-राग आदि का मामले में दुनिया का अधिकांश देशों से आगे है। राजनितिक तौर पर यहाँ करीब 38 साल से एक एगो पार्टी और परिवार का गामा की अनुठी परंपरा रही है जिसका एकमात्र मंगल किसी भी तरह से सत्ता हथियाता और उत्तम पिपये रहता है। इसका मरिछाण सभी किस्म की सरकारी गतिविधियों में लोगों का शामिल किए जात की आदर्श करता है जबकि बायपासिता और अपगणनाही का (पुताय के समय को छोड़कर) लोग का प्रति जवाबदही से छूट देता है।

(10) क्या कोई राष्ट्र इस लक्षणों का चलत विकास कर सकता है? किसी भी जरिए में देखें, भारत की तरफ से आज घुघली गही तो उजली भी नहीं है। इस किसी भी मूरत में राष्ट्र निर्माण की गाथा नहीं ब्रहा जा सकता।

(11) इस बठोर मयाप की सीपापाती की कोशिश करत बाएन कृष्ट निर्दिष्ट स्वार्थी अपगण बाए-बाए एत आंकडे पण करते है जिनमें भारत क कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों की वृद्धि को चुन चुनकर दिखामा जाता है। इस अमूर्त प्र सिद्ध करत की भी कोशिश की जाती है कि देश में जातीय, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता तथा बाहरी तौर पर सैनिक और अर्थ धनिक गणनाओं में सिद्ध करत बायसुद भारत का चार दशक लया सतदीय रिवाज कायम किया है। यह प्रत्यक्ष रूप से ता उम समय आये मुह गिरता है जब हम देखते है कि गणना, अर्थिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में हुआ हर विवाह पोषित लक्ष्य में हुए है। प्रत्यक्ष रूप से बायीं दिशा में भारी कीमत चुकाने के बाद ही हासिल किया जा सकता है। दूसरी, बायींका प्रत्यक्ष भी बेहतर आर्थिक उपलब्धि पान का प्रयास किया जा रहा है। अतः प्रत्यक्ष बाये की बरकरार रहे हुए है।

अपनी गलतियों के प्रति आलोचनात्मक रख अपनाते से हमेशा इनकार किया है। पार्टी ने 1916 की कांग्रेस लीग लखनऊ संधि (जिसमें मुसलमानों के लिए अलग मत दाता प्रणाली का समर्थन किया गया) और 1935 के सांप्रदायिक पंचनिर्णय (जिसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात दुहराई गई) को स्वीकार कर लेने को कभी खुलेआम अपनी गंभीर गलतियां नहीं माना है। वह 1947 के सांप्रदायिक विभाजन को अपनी हार मानने से अभी भी इनकार करती है। इसने नेहरू मार्का समाजवाद (जिसे लगभग 1964 में धन सर्वेक्षण के बारे में महालनोबिस समिति की रिपोर्ट ने पगु बना दिया), और नेहरू मार्का निर्गुणता (जिसे 1962 के चीन भारत युद्ध ने अपनी औकात बता दी), इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ कार्यक्रम (जिसका छह 1970 और 1980 के दशक में हुए विभिन्न सरकारी सर्वेक्षणों में पाई गई उसी स्तर की गरीबी और आर्थिक असमानताओं तथा बढ़ती बेरोजगारी से होता है) और राजीव की मि० वलीन की ट्वि (जो बोफोर्स, फेयरफक्स आदि से खटित हुई है) की नाकामी को कभी स्वीकार नहीं किया है। इन सबसे पता चलता है कि इस पार्टी ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए मयाथ को सोड मरोडकर अपनी कथनी और करनी में फक डाला है।

(14) इस स्थिति से हम कैसे पार पाएँ? दरअसल, भारत के औद्योगिक आधुनिकीकरण की समस्या का यही केंद्रबिंदु है। यह समस्या निबटाने के लिए एक ता भारत के विज्ञान व तकनीकी को विकसित करने और दूसरे, उसके मानवीय विचारा सस्थानों और सागठनिक स्वरूपों को आधुनिक बनाने की जरूरत है। ये दोनों पहलू अंतरनिभर हैं और एक के बिना दूसरे की पूर्ति नहीं हो सकती। कांग्रेस ने एक पहलू का पूरा करने (यानी भौतिक पक्ष का विकास करने) की कोशिश की है। पर उसे नाकामी ही हाथ लगी है। क्योंकि साथ साथ मानवीय पूजा के विकास के बिना समाज में भौतिक पूजा उत्थति नहीं कर सकती। दरअसल, अनुभव बताता है कि नेहरू मार्का व्यक्तिवादी एवं परिणामवादी राजनीति मानवीय पूजा का विकास नहीं कर सकती क्योंकि सैद्धांतिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया की तुलना में यह जातिवाद और सांप्रदायिकता के ज्यादा करीब है। पिछले 40 साल में यदि नेहरू मार्का व्यक्तिवादी एवं परिणामवादी राजनीति नाकाम रही तो उस जैसी कोई और विस्म में काम याव नहीं हो पाएगी। कोई दूसरा शाटकट भी काम नहीं आने वाला। वदिकवालीन हो या पौराणिक काल का अथवा जातिवादी, सांप्रदायिक या राजतंत्रीय किसी भी विस्म का पुनरुत्थानवाद आज साधक नहीं है भले ही अपने अपने युग में उनमें हरेक न भारी भूमिका जदा की है। एक वक्त वह भी था जब उदारवादी अथवा मार्क्सवादी राष्ट्रीय विचार, सस्थान और सागठनिक स्वरूप औद्योगिक आधुनिकीकरण के अग्रदूत हुआ करते थे। पर आज वे भी अपना बहुत सी वधता खो चुके हैं। ऐसा इसलिए है कि वतमान वैज्ञानिक और तकनीकाजिकल प्रक्रिया ने राष्ट्रीय सीमाएं तोडकर विभिन्न राष्ट्रीय इकाइयों का अंतरनिभर बना दिया है। राष्ट्रीय इकाइयों के विघटन और

१८८ इकाई व उदय से राष्ट्रीय मॉडल बहुत हद तक निप्रभावी हो गए हैं।

यह बात विवक्षित पश्चिमी और समाजवादी दोनों देशों में हुई हाल ही की घटनाओं से सिद्ध होती है। ये सभी देश नमो, बाल अपराध, मजदूरों की विमुपता आदि जैसी सामान्य समस्याओं से दो चार हैं। आज अंतरनिभर राष्ट्रीय इकाइयों का औद्योगिक आधुनिकीकरण न तो मार्क्सवादी राष्ट्रीय राज्य नियंत्रण वाले माडल और न ही उदारवादी व्यक्तिपरक राष्ट्रीय मंडी वाले माडल के जरिए हो सकता है। बल्कि यह काम गाँव से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियों में लोकतांत्रिक नियंत्रण के सिद्धांतों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय लोकतांत्रिक माडल के जरिए ही संभव है।

जितना अधिक लोकतंत्रीकरण होगा, उतनी ही अधिक आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति होगी। जब लोगों को किसी भी धारणा के बारे में शका का समाधान करने की आजादी हो, तभी प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान तेजी से उन्नत होते हैं। इस सामाज्य निष्वय की पुष्टि मनुष्यजाति के समूचे इतिहास और खासकर 18 वीं से 20 वीं सदी के बीच के इस इतिहास से होती है जब जनता की सामाजिक सृजनात्मकता ने पिछले सारे रिवाज मातकर अथाह सामाजिक और प्राकृतिक ज्ञान अर्जित किया।

आर० पी सराफ

31 दिसंबर 1988





## विषय-सूची

### भूमिका

1	हमारे कुछ प्राक्ल्प	1
2	हमारी प्रेरण विधि	2
3	विश्लेषण की हमारी सामान्य विधि	3
4	सामाजिक अध्ययन की हमारी विधि	4
5	आधुनिकीकरण या पूंजीकरण की हमारी धारणा	6

### अध्याय एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1	भू भौतिक इकाई के रूप में भारत	8
2	मनुष्य की रिहायशगाह के रूप में भारत	8
3	भारत का 1947 का सांप्रदायिक बंटवारा क्या अपरिहाय था ?	9
4	भारत में सांप्रदायिकता की धारणा और इतिहास	9
5	भारत में आधुनिक सांप्रदायिकता	12
6	हिंदू पुनरुत्थानवाद और कांग्रेस	12
7	मुस्लिम कट्टरवाद और मुस्लिम लीग	15
8	विभाजन के विकल्प	16
	(क) भारत विभाजन के लिए दोषी कौन ?	16
	(ख) क्या विभाजन अनिवार्य था ?	19
	(ग) क्या विभाजन सर्वोत्तम समाधान था या कमतर बुराई ?	20
	(घ) अगर विभाजन कबूल न किया जाता तो क्या हालात और विगड़ते ?	21
	(ङ) क्या कैबिनेट मिशन योजना अव्यवहाय नहीं थी ?	21

### अध्याय दो भारत की सामाजिक व्यवस्था

1	व्यवस्था, राज्य, राष्ट्र और जनता के बीच संबंध	23
2	राज्य और सरकार के बीच अंतर	23

3 पार्टी तंत्र पर आधारित सरकार व्यवस्था	23
4 भारतीय राष्ट्र राज्य—एक पंचमुखी प्रक्रिया	24
5 भारत की सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता	24
6 इस व्यवस्था के बारे में प्रमुख सवाल	24

### अध्याय तीन भारतीय राज्यतंत्र

1 सविधान	26
2 संरचना	27
3 प्रशासकीय प्रक्रिया	28
4 पूर्व 1947 के राज्यतंत्र से तुलना	28
5 भारतीय राज्यतंत्र के मूल्यांकन की कसौटी	29
6 सविधान के मूल उद्देश्यों की पूर्ति—भारतीय राज्यतंत्र की असल परीक्षा	29
7 कायपालिका	30
8 विधायिका	37
9 न्यायपालिका	39
10 प्रेस	41
11 राजनैतिक दल	43
12 भारत की विविधता, मे एकता का आधार	44
13 भारतीय जनता द्वारा चुकाई गई भारी कीमत	44

### अध्याय चार भारतीय अर्थव्यवस्था

1 संरचना	48
2 समस्याएँ	48
3 आर्थिक विकास के मूल सिद्धांत के रूप में राज्य नियोजन	48
4 पीछे की स्थिति और मौजूदा कामकाज की कसौटी	49
5 कुल आर्थिक विकास	49
(i) कृषि	51
(ii) उद्योग	52
सांख्यिक क्षेत्र	52
निजी क्षेत्र	53
(iii) संरचनात्मक उद्योग	55
(iv) शिक्षा और स्वास्थ्य	55

6	आधुनिकीकरण	56
	(i) राष्ट्रीय आय का ढांचा	56
	(ii) अथर्ववस्था में विविधता किस हद तक	57
	(iii) टेक्नोलॉजी	58
7	आत्मनिर्भरता	58
	(i) विदेशी ऋज	58
	(ii) आयात प्रतिस्थापन	60
	(iii) निर्यात प्रोत्साहन	61
8	सामाजिक न्याय	61
	(i) गरीबी	61
	(ii) बेरोजगारी	64
	(iii) परिसंपत्ति और आय वितरण में असमानताएँ	66
9	काला घन	67
10	भारतीय जनता पर लादी गई भारी हानि	68
	(i) नियोजित लक्ष्यों के अछूरा रहने से हुई हानि	69
	(ii) पूँजी/उत्पाद के अनुपात में वृद्धि से हुई हानि	70
	(iii) गैर उत्पादक खर्च में वृद्धि से हुई हानि	70
11	आर्थिक परिणाम	72
अध्याय पाँच भारतीय संस्कृति		
1	प्रचलित जीवन पद्धति	76
2	भारतीय राज्य के सांस्कृतिक, सिद्धांत और इसकी सरकार की सांस्कृतिक शैली की अभिव्यक्ति	76
3	दैनिक जीवन में शासक संस्कृति	78
4	आचरण के शासकीय मानदंड	78
5	दमघोटू माहौल	79
6	शासक संस्कृति के लिए प्रचार माध्यम या इस्तेमाल	81
7	संस्कृति की दूसरी किस्में	82
8	संस्कृति का रचयिता कौन	82
9	भारतीय संस्कृति का योगदान	83
अध्याय छह भारतीय कूटनीति-सह रक्षा नीति		
1	विदेश नीति बनाने वाले तत्व	
2	भारतीय विदेश नीति का सिद्धांत	

3	भारतीय विदेश नीति का व्यवहार	86
	(क) भारत और दो महाशक्तिया व उनके पश्चिमी सहयोगी	87
	(ख) भारत और नव स्वतंत्र देश	89
	(ग) पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंध	91
4	हथियारों, विदेशी सहायता और देशों के बीच विवादों के प्रति भारत का रुख	93
5	भारतीय विदेश नीति की उपलब्धि	94
6	रक्षा नीति	94
7	भारतीय कूटनीति-सह-रक्षा नीति द्वारा बटारी गई भारी कीमत	95
अध्याय सात 1945 के बाद की दुनिया		(11)
1	देशों के बीच बढ़ती अंतरनिभरता	98
	(क) नए विश्व संगठनों का उदय	98
	(ख) राष्ट्रीय समस्याओं का सावर्भौमिकरण	99
	(ग) राष्ट्रीय आर्थिक मॉडलों की बढ़ती अप्रासंगिकता	99
	(घ) सत्ता के नए मापबंद का उदय-	100
	(ङ) राष्ट्र-राज्य का घटता प्राधिकार	100
2	नए घटनाक्रम को समझने में मुश्किल	100
3	सावर्भौमिकता के प्रति मनुष्य की पिछड़ी अनुक्रिया	101
4	सावर्भौमिकता के देर बोध से मानवीय उद्देश्य को पहुंचती हानि	102
5	विश्व लोकतान्त्रिक राज्य ही उचित अनुक्रिया	103
अध्याय आठ भारत के आधुनिकीकरण की व्यापक योजना और राष्ट्रीय विकल्प बनाने की नीति ।।		
भारत के आधुनिकीकरण की व्यापक योजना		104
1	इसका मूल उद्देश्य, निदेशक सिद्धांत और कायशीली	104
2	अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में	105
3	भारतीय राज्यतंत्र के क्षेत्र में	106
4	भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में	111
5	भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में	113
6	विभिन्न वर्गों की जीवन स्थितियों के क्षेत्र में	117
7	राष्ट्रीय विकल्प का तबाल	120

## भूमिका

यह 1947 उपरांत भारत के सामाजिक यथाथ के मूल्यांकन का एक और प्रयास है। समकालीन भारत के बारे में अनेक सामाजिक विश्लेषण पहले ही मौजूद हैं तो नए मूल्यांकन की क्या जरूरत है ? इसकी एकमात्र वजह यह है कि भारत के सामाजिक यथाथ के बारे में हमारा मूल्यांकन विद्यमान सामाजिक विश्लेषणों से भिन्न है। यह बात हमारे सामाजिक विश्लेषण के निम्न प्राकल्पों से स्पष्ट है।

### 1 हमारे कुछ प्राकल्प

(क) यह कि 1947 में भारत का सांप्रदायिक विभाजन ऐतिहासिक दृष्टि से अनिवाय नहीं था, राजनैतिक तौर पर इसे टाला जा सकता था और भारतीय लोगो को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसमें 10 लाख लोग मारे गए, 40 लाख घायल हुए और 250 लाख को अपनी जायदाद से महारूम होना पड़ा। दुनिया के किसी भी पैमाने से यह बेमिसाल कीमत थी।

(ख) यह कि 1947-उपरांत भारत की सामाजिक व्यवस्था पश्चिमी उदारवाद, रूसी अथवा और धर्मो-मुख धमनिरपेक्षता का घालमेल रही है।

(ग) यह कि 1947-उपरांत भारतीय राज्यतंत्र ब्रिटिश उपनिवेशी राज्यतंत्र की तुलना में विकसित होने के बावजूद अति केंद्रीयकृत संविधान वाला राज्यतंत्र और दमनकारी नीतियों वाला निरंकुश शासन रहा है जिसने किसी भी राजनैतिक मानदंड के विपरीत भारतीय जनता से बहुत भारी कीमत बटोरी है। (मसलन इसके तहत सेना और पुलिस की फायरिंग में मरे करीब 40 000 और घायल हुए लगभग 1,20,000, पंजाब और दूसरी जगहों पर अदरूनी सशस्त्र संघर्षों में मरे करीब 50,000 और घायल हुए लगभग 1,00,000 तथा सांप्रदायिक दंगा में मरे करीब 20,000 और घायल हुए लगभग 40 000 लोगो समेत कुल मिलाकर करीब 1,10 000 लोग मारे गए और लगभग 2,60,000 घायल हुए हैं—देखें अध्याय तीन, उपशीपक 13)।

(घ) यह कि 1947-उपरांत भारतीय अर्थव्यवस्था एक तरफ अपने नियोजित आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने में दूर पीछे रही है और दूसरी तरफ अपने नियोजित आर्थिक उद्देश्यों को पाने में नाकाम रही है। इस तरह वह विश्व स्तर या तीसरी दुनिया के किसी भी आर्थिक मापदंड की बसोटी पर खरी नहीं उतरी और उसने माली व जानी लिहाज से भारतीय लोगो को अनावश्यक नुकसान पहुंचाया है (मसलन इसके तहत एक साल में गरीबी या भुपोषण से करीब 20 लाख मौतें होती हैं, नियोजित लक्ष्यों की पूर्ति न होने से करीब 3,33,334 करोड़ रुपये और पूंजी/उत्पादन के

अनुपात में बढ़ि से करीब 5,43,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है—देखें अध्याय चार, उपशीपक 10 क, 10 ख और 11) ।

(ड) यह कि 1947-उपरात भारतीय संस्कृति ने एक तरफ सभी विस्म की कट्टरता घासकर बहुसंख्यक समुदाय की कट्टरता को चिरस्थायी बनाया है और दूसरी तरफ आधुनिक व पारंपरिक संस्कृति के निवृष्ट रूपों (जैसे जी हुजूरी, चाटुकारिता, झूठ, तिक्डम, चुगलखोरी, पक्षपात, भ्रष्टाचार, चोरबाजारी, तस्कारी, कर चोरी, चोरी, गुंडागर्दी आदि) को बढ़ावा दिया है। इस तरह उसने भारतीय जनता से भारी कीमत बटोरी है (मसलन इसके तहत करीब 5,00,000 गिरफ्तारियां और करीब 4,00,000 लोगो की हत्याएं हो चुकी हैं—देखें अध्याय पांच, उपशीपक 5) ।

(च) यह कि 1947 उपरात भारतीय कूटनीति सह रक्षा नीति की दिशा दक्षिण एशिया में भारत का क्षेत्रीय प्रभुत्व जमाने की रही है जिसकी कीमत भारतीय जनता को अनावश्यक युद्धों में जान व माल की कुरबानियां देकर चुकानी पड़ी है (मसलन भारत द्वारा लड़े गए चार युद्धों में करीब 13,000 लोग मारे गए और लगभग 30,000 घायल हुए हथियारों की होड़ और चार युद्धों में खरबों रु० का माली नुकसान हुआ है—देखें अध्याय छह, उपशीपक 7) ।

(छ) यह कि 1945 उपरात विश्व, जिसमें भारत भी शामिल है, जगतातर अंतरनिभर राष्ट्र राज्यों के एक अंतरराष्ट्रीय तंत्र के रूप में विकास पा रहा है। इस तरह अंतरनिभर दुनिया की समस्याओं का हल करने में सभी प्रकार के पारंपरिक राष्ट्रीय माडल (यानी पश्चिमी उदारवादी, रूसी समाजवादी और मिश्रित अल्प-विकसित) अप्रासंगिक हाते जा रहे हैं ।

(ज) यह कि भारत के आधुनिकीकरण के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन पणों समेत कोई भी योजना इन्हीं प्राकृत्यों पर आधारित होनी चाहिए। आधुनिकीकरण से अभिप्राय टेक्नोलॉजिकल विकास, लोकतंत्रोकरण और सामाजिक न्याय है ।

## 2 हमारी प्रेक्षण विधि

(क) उपरोक्त सभी सामाजिक प्राकृत्य प्रेक्षणीय प्रमाण पर आधारित हैं (उन्हें आंकड़ों, तथ्य यथाथ अथवा विज्ञान की कसौटी पर परखा जा सकता है) ।

(ख) प्रमाण जुटाने के प्रेक्षण काय में हमारा रुख यह रहा है कि यहाँ तक व्यवहाय हो सके शोध प्रक्रिया का यह हिस्सा निष्पक्ष रहे और उसे पूर्व निर्धारित धारणाओं से मुक्त रखा जाए ।

(ग) जुटाए गए प्रमाण की व्याख्या करन में हमारा रुख यह रहा है कि शोध प्रक्रिया के इस हिस्से के प्रति हम निष्पक्ष या तटस्थ नहीं हो सकते। क्योंकि हर मनुष्य किसी घटनाक्रम की व्याख्या अपने सिंद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान के भंडार (यानी यथाथ की अपनी आम धारणा के साथ साथ यथाथ की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में अपनी विशिष्ट धारणाओं) के आधार पर कर सकता है। मानवीय मनोविज्ञानी

कायशैली से जुड़े इस मानदंड से हम भी नहीं बच सकते ।

(घ) इस तरह समूची शोध प्रक्रिया से हमने प्रमाण (जो तटस्थ और मूल्यों से मुक्त हो सकता है) और प्राक्ल्प अथवा कथन (जो किसी हद तक मूल्यों पर आधारित ही हो सकता है) के बीच अंतर किया है ।

### 3 विश्लेषण की हमारी सामान्य विधि

(क) विश्लेषण विधि और कम के मागदशक के रूप में हम इन मायताओं को स्वीकार नहीं करते कि सामाजिक विकास एक निश्चित ढर्रे पर चलते हुए अपरिहाय लक्ष्य की ओर ले जाता है (निश्चयवाद), अथवा सामाजिक विकास अज्ञात शक्तियों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है (भाग्यवाद), अथवा मानव व्यवहार पूरी तरह स्वतंत्र इच्छा द्वारा निर्धारित होने के कारण सामाजिक विकास के बारे में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता (स्वेच्छावाद), अथवा संपूर्ण एकतरफा तौर पर अपने भागों के गुण निर्धारित करता है (सामायवाद), अथवा व्यवहार हमेशा अगुआ और सिद्धांतगोण भूमिका अदा करता है (इंद्रियानुभववाद), अथवा दशन की कोई उपयोगिता नहीं होती (वस्तुनिष्ठावाद), अथवा विज्ञान को राजनीति के अधीन होना चाहिए (अपचयनवाद), अथवा उपयोगिता एकमात्र मागदशक सिद्धांत है (उपयोगितावाद) ।

(ख) हम यथाथ को अनेक प्रक्रियाओं से गठित एक सामाय प्रक्रिया के रूप में देखते और समझते हैं । इन प्रक्रियाओं के विभिन्न रूप और आचरण हैं । लेकिन वे आपस में कभी एकता और कभी सघष के जरिए अंतरक्रिया की सामाय पद्धति पर चलती हैं । यह दोतरफा अंतरक्रिया हरेक प्रक्रिया के परिणाम और गुण में लगातार आशिक परिवर्तनों को जन्म देती है और एक नाजुक मोड़ पर पहुँचकर हर प्रक्रिया को दूसरी में बदल देती है ।<sup>1</sup>

(ग) यह सामाय धारणा नीचे दिए बज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है ।

(1) क्वाटम यांत्रिकी विज्ञान (सूक्ष्म जगत से संबंधित विज्ञान) हमें बताता है कि (यूरेनियम 235 अथवा प्लूटोनियम-239 जैसे मध्यम भार वाले तत्वों के) रेडियोधर्मी नाभिक में प्रोटोन और न्यूट्रॉन के बीच एकता भंग होने से परमाणु ऊर्जा निकलती है । परमाणु विखंडन नामक इस प्रक्रिया को किसी परमाणु रिएक्टर अथवा परमाणु बम में देखा जा सकता है । इसके विपरीत (एक ही परमाणु से गठित हल्के भार वाले तत्व) हाइड्रोजन के दो परमाणु जब मिलकर हीलियम (दो परमाणुओं से गठित) बनाते हैं तो उससे भारी मात्रा में परमाणु ऊर्जा निकलती है । इस प्रक्रिया को परमाणु संयोजन कहा जाता है । हमारे सूर्य समेत सभी तारों में ऊर्जा उत्पादन की यह सामाय विधि है ।

(ii) भौतिक विज्ञान (बृहत् जगत से संबंधित विज्ञान) हमें बताता है कि निश्चित हालात में पानी के अणुओं के बीच करीबी एकता उसे बर्फ में बदल देती जबकि उसके अणुओं को अलग करने से वह भाप में तब्दील हो जाता है ।



ठोस चीजों के मुकाबले हवा में अणुओं के बीच की औसत दूरी करीब 10 गुना ज्यादा है। हमारी पृथ्वी खुद गैसों, धूल और पत्थर व लोहे के कणों का मिश्रण है जो गुरुत्वाकर्षण, गैस दाब और विद्युत चुंबकीय शक्ति के जरिए आपस में मिल गए थे।

(iii) रसायन विज्ञान हमें बताता है कि निश्चित मात्रा में दो तत्वों के मिश्रण से एक नया यौगिक बनता है (मसलन सोडियम + क्लोराइड = साधारण नमक)। किसी यौगिक को निश्चित मात्राओं वाले दो तत्वों में विघटित किया जा सकता है (मसलन पानी = आक्सीजन का एक परमाणु + हाइड्रोजन के दो परमाणु)। गैसों के मिश्रण से हवा बनी है। हवा को गैसों में विघटित किया जा सकता है।

(iv) जीव विज्ञान हमें बताता है कि जैविक प्रक्रियाएं (यानी पौधों, पशुओं और मनुष्यों) में पाचन प्रक्रिया और विकास प्रक्रिया की मेटाबोलिक प्रक्रियाएँ कैसे उनमें आंशिक और मूलभूत परिवर्तन लाती हैं।

(घ) हम अपनी इस सामान्य धारणा को सोच व अमल के लिए उपयोगी एक मॉडल के रूप में ही मानते हैं। हम इसे सिद्धांत के तौर पर पेश नहीं करते जो किसी चीज का आधिकारिक और प्रामाणिक विवरण देने का दावा करता है।

#### 4 सामाजिक अध्ययन की हमारी विधि

(क) सामाजिक विज्ञानों के गहरे अध्ययन से भी पता चलता है कि मानव समाज (प्रकृति की ब्रह्मांड-यापी प्रक्रिया का एक भाग) एक दोतरफा अंतरक्रिया के कारण बज्रूद रखता है। उसमें गति और परिवर्तन भी इसी वजह से होते हैं। यह दोतरफा अंतरक्रिया एक तो प्रकृति की संरचना (जिसमें विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बीच अंतरक्रिया शामिल है) और मनुष्यजाति व सगठन के बीच है तथा दूसरे, मानवीय सामाजिक सगठन के भीतर उसकी विभिन्न सामाजिक इकाइयों (जिसमें व्यक्ति की सामाजिक इकाई शामिल है) के बीच है।

(ख) प्रकृति अनेक अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रक्रियाओं (मसलन हवा, पानी, भोजन, विषाणु, भूकंप आदि) के जरिए मनुष्य के साथ प्रक्रिया-प्रतिक्रिया करती है। मनुष्य भी विभिन्न एवतामूलक अथवा सघनमूलक तरीकों (मसलन सास लेने, पीने, घाने, औद्योगिक, कृषि और खनिज उत्पादन करने आदि) के जरिए प्रकृति के साथ प्रक्रिया-प्रतिक्रिया करता है। इसी प्रकार मनुष्य या तो अपने विचारों और व्यवहार को जोड़कर (कभी व्यक्तिगत और कभी सामाजिक तौर पर) अथवा अपने विचारों और व्यवहार को मिटाकर (कभी व्यक्तिगत और कभी सामाजिक तौर पर) आपस में अंतरक्रिया करता है।

(ग) प्रकृति मनुष्य को अपने सामाजिक धर्म विभाजन पर चलने के लिए मजबूर करती है (मसलन मनुष्य मशीन की गति के साथ अपनी गति का तात्कालिक बिठाकर ही उस चला सकता है)। नतीजतन, मनुष्य निश्चित सामाजिक धर्म विभाजन के मुताबिक अपनी सामाजिक इकाईया (मसलन पहल कुल, पिर ब्रह्मीमा, वर्ग,

क्षेत्रीय समुदाय और अब राष्ट्र) और सामाजिक संबन्ध बनाता है। इससे विपरीत, प्रकृति की विभिन्न प्रक्रियाओं की संरचना और आचरण के बारे में अधिकाधिक ज्ञान हासिल करने मनुष्य प्रकृति को विकसित और नियंत्रित करता है।

(घ) मानव ज्ञान, प्राकृतिक हो या सामाजिक और सैद्धांतिक हो या व्यावहारिक, उपरोक्त दो अंतरक्रियाओं से आता है। प्राकृतिक ज्ञान के मामले में जानबारी का आधार प्राकृतिक वस्तुओं में निहित होता है जबकि उनका प्रेक्षण, व्याख्या और धारणाओं का निर्धारण मानवीय सोच द्वारा होता है। इसी प्रकार, सामाजिक ज्ञान के मामले में जानबारी का आधार जहाँ सामाजिक श्रम विभाजन (जिसमें सामाजिक संगठन और सामाजिक इकाइयाँ शामिल हैं) में निहित होता है, वहीं उनका प्रेक्षण, व्याख्या और धारणाओं का निर्धारण मानवीय सोच द्वारा होता है। ज्ञान की मनोगत रचना में असाधारण व्यक्ति की सामाजिक इकाई वैचारिक परिशोधन सत्र की भूमिका निभाती है जबकि उससे जुड़ा समूह, वग, संगठन आदि वैचारिक तौर पर अच्छा माल मुहैया करता है।

(ङ) अभी तक मनुष्य को मोटे तौर पर चार प्रकार के टेक्नोलाजिकल रचनात्मक (उनके उपर रचनात्मक सहित) और उनसे जुड़े चार प्रकार के सामाजिक श्रम विभाजन को विकसित करने और चलाने का ही ज्ञान है। इन्हीं के आधार पर इतिहास में मोटे तौर पर चार प्रकार के समाज अथवा सामाजिक व्यवस्थाएँ (अनेक उपव्यवस्थाओं सहित) रही हैं। य है (i) भोजन संग्रहण और शिकार करने की टेक्नालॉजी और उससे जुड़े सामाजिक श्रम विभाजन वाली कुल व्यवस्था जो लाखों साल चली, (ii) पशुपालन टेक्नालॉजी और उससे जुड़े सामाजिक श्रम विभाजन वाली कबीलाई व्यवस्था जो हजारों साल चली (iii) कृषिकारी टेक्नालॉजी और उससे जुड़े सामाजिक श्रम विभाजन वाली सैन्य सह धार्मिक राजवाड्याही व्यवस्था जो करीब दो हजार साल चली, तथा (iv) औद्योगिक टेक्नालॉजी और उससे जुड़े सामाजिक श्रम विभाजन वाली राष्ट्र राज्य व्यवस्था जो अभी जारी है।

(च) सामाजिक विकास के जरिए व्यवस्था में परिवर्तन एक बहुपक्षीय (यानी राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि) और बहुआयामी प्रक्रिया है। जाहिर है, कोई भी अकेली सामाजिक इकाई (चाहे पश्चिमी उदारवादी मॉडल का प्रतिभासपन व्यक्ति हो या समाजवादी मॉडल का कोई सामाजिक वर्ग) समूची सामाजिक उन्नति की बहुदेशीय इकाई या एकमात्र वाहक नहीं होती और न हो सकती है। कभी किसी असाधारण वैज्ञानिक ने अपने समकालीन वैज्ञानिकों के साथ ता कभी किसी असाधारण अर्थशास्त्री ने अपने समकालीन अर्थशास्त्रियों, कभी असाधारण कलाकार ने अपने समकालीन कलाकारों आदि आदि के साथ मिलकर सामाजिक विकास में प्रमुख योगदान दिया है। राज्य की सवशक्तिमान इकाई में कोई निश्चित राजनैतिक इकाई उसका नतत्व मूल भूमिका निभाते हैं और निभाते आए हैं (मसलन हमारे राजनैतिक पाटियाँ)।

## 5 आधुनिकीकरण या पूँजीकरण की हमारी धारणा

(क) इतिहास में रही चार व्यवस्थाएँ आधुनिकीकरण की एक लम्बी प्रक्रिया की प्रतीक हैं। यह एक ओर टेक्नोलॉजी और उससे जुड़े सामाजिक श्रम विभाजन तथा दूसरी ओर मनुष्य के सिद्धांत, व्यवहार और संगठन में परिवर्तन की दोतरफा प्रक्रिया है। इस तरह, भोजन संग्रहण और शिकार करने की टेक्नोलॉजी और उसके सामूहिक श्रम विभाजन के दौरान भोजन संग्रह करने वाले शिकारी के साथ उसका कुटुंबीय सिद्धांत और कुल व्यवस्था मौजूद थी जबकि औद्योगिक टेक्नोलॉजी और उसके माल के श्रम विभाजन के दौरान औद्योगिक मनुष्य के साथ उसका धमनिरपेक्ष जावादी सिद्धांत और राष्ट्रीय ससदीय व्यवस्था मौजूद है। दरअसल, आधुनिकीकरण की यह प्रक्रिया (टेक्नोलॉजी और मनुष्य दोनों के) पूँजीकरण की प्रक्रिया है, जो मानव समाज के बनने से ही शुरू हुई (यानी उस समय जब मनुष्य ने टेक्नोलॉजी की रचना की और बदले में वह उसके श्रम विभाजन से बंध गया)।

(ख) मानव समाज की प्रक्रिया के अनुरूप ही सामाजिक पूँजी की प्रक्रिया भी विभिन्न चरणों से गुजरी है। भोजन संग्रहण और शिकार करने की व्यवस्था के तहत सामाजिक पूँजी में छड्डियों, पत्थरों, हड्डियों, तीर कमानों, जंगली उपज, पशुओं के मांस आदि की टेक्नोलॉजी के साथ साथ मनुष्य के सिद्धांत और व्यवहार तथा इन चीजों को पाने व चलाने के लिए कुल का संगठन शामिल था। माल के विनिमय ने पहले चीजों की अदला बदली और बाद में सवत्र माध्यम का रूप अद्वितीय किया। यह माध्यम कभी अनाज तो कभी पर, घोड़ा, मछलियों आदि के विभिन्न रूपों में मौजूद रहा लगता है। पशुपालन व्यवस्था के तहत सामाजिक विनिमय और सामाजिक निवेश के लिए पशु सवत्र माध्यम का मुख्य रूप बन गए। कृषिकारी व्यवस्था के तहत भूमि और पशुओं के अलावा धातु मुद्रा भी विनिमय और सामाजिक निवेश का माध्यम बन गई जबकि औद्योगिक व्यवस्था के तहत मुद्रा ने विनिमय और निवेश दोनों क्षेत्रों में प्रमुख स्थान हासिल कर लिया। हरेक सामाजिक व्यवस्था के तहत पूँजी का नियंत्रण मुख्य रूप से उसकी अगुआ सामाजिक इकाई के हाथों में रहा है।

(ग) जाहिर है पूँजी की उपरोक्त धारणा मौजूदा दो विचारशाखाओं द्वारा प्रस्तुत पूँजी के दो आम सिद्धांतों से भिन्न है। पश्चिमी उदारवादी अर्थशास्त्र पूँजी को उत्पादन के साधनों का समग्र रूप मानता है जबकि मार्क्सवादी अर्थशास्त्र उसे उत्पादन संबंधों अथवा मजदूरों के अतिरिक्त मूल्य अथवा संचित श्रम के रूप में देखता है। पहली किस्म मानवीय पक्ष (यानी श्रम) की गौण हैसियत देती है जबकि दूसरी टेक्नोलॉजी का।

(घ) बहरहाल, इतिहास और विज्ञान बताते हैं कि टेक्नोलॉजी (प्रकृति के उस भाग की प्रतीक जिसे मनुष्य चलाता है) और मनुष्य हमेशा से अंतरसंबंधित, अंतरनिभर और अभिन्न रहे हैं। दोनों ही अपने अपने ढंग से सज्जमान हैं। मनुष्य का नय परिवर्तन उसकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा में निहित है जबकि टेक्नो

साजी की उत्पादकता विद्युतीय, रसायनिक, गतिज, तापीय, स्थितिज, विकिरित, आणविक आदि ऊर्जा के विभिन्न रूपा में पाई जाती है। दरअसल, मानवीय धम के मुकाबले टेक्नोलॉजी अधिक मूल्य पैदा करती है (मसलन स्वचालित मशीन जहाँ मनुष्य कोई शारीरिक ताकत नहीं लगाता)। इसकी वजह यह है कि एक औसत मजदूर रोजाना शारीरिक काम के दौरान 120 घाट ऊर्जा (जो हाल की वैज्ञानिक खोज के मुताबिक 2400 कैलॉरी के बराबर है) खर्च कर सकता है जबकि उसके मुकाबले मशीन एक दिन में बसियों हजार घाट ऊर्जा मुहैया करती और इस्तेमाल करती है। लेकिन मनुष्य यदि भौतिक उत्पादन में टेक्नोलॉजी से पीछे है तो अपने मानसिक अनोखेपन के कारण वह भौतिक और धारिक नव परियोजना में टेक्नोलॉजी का अगुआ भी है। इसलिए मानव समाज में टेक्नोलॉजी और मनुष्य पूंजीकरण या आधुनिकीकरण के दो मूल कारक हैं।

(6) हमारी विषयवस्तु और दृष्टिकोण के बारे में यही सक्षिप्त विवरण है।

---

सदभ

1 अधिक विवरण के लिए देखें 'इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का कार्यक्रम'

## अध्याय एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

### 1 भू भौतिक इकाई के रूप में भारत

(क) भू भौतिक तौर पर भारत पृथ्वी का 41वा हिस्सा है (पृथ्वी के कुल 13 39 करोड़ वर्ग किमी क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल 33 लाख वर्ग किमी है)। आज यह दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला दूसरा देश है और इसकी आबादी (1988 में) 80 करोड़ है। यह उस बड़े भूखंड का एक भाग है जिसे हम एशिया महाद्वीप कहते हैं।

(ख) वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि करोड़ों साल पहले भारत उस रूप में, जैसा आज हम जानते हैं, विद्यमान नहीं था। अरावली पर्वत के दक्षिण में यह क्षेत्र उस भूखंड का भाग हुआ करता था जिसे भूगर्भ शास्त्रियों ने गोडवाना प्रदेश नाम दिया है। यह प्रदेश पश्चिम में मारीशियस और पूव में दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप समूह से जुड़ा हुआ था (इस द्वीप समूह को भूगर्भशास्त्री लेमूरियन महाद्वीप का नाम देते हैं जो बाद में आज के अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी अमेरिका में बंट गया)। हिमालय पर्वत और समूचा उत्तरी व मध्य भारत टेथिस सागर नामक एक विशाल समुद्र के नीचे डूबा था। वक़्त बीतने के साथ साथ सागर की तह में जमा तलछट चूना पत्थर में बदल गया, जो पृथ्वी की बाहरी परत में होती हलचल की वजह से भूक्षेत्र बनता गया। एशियाई और यूरोपीय भूभागों के जुड़ने से हिमालय पर्वत तल से एक एक इंच कर ऊपर सरकता गया। आज वह करीब 6 मील ऊंचा है और अभी भी बढ़ता जा रहा है। टेथिस सागर का पानी मौजूदा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समा गया जिससे पश्चिम में अफ्रीका और पूव में दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप समूह दक्षिण भारत से अलग हो गया। यह बात 10 लाख साल से अधिक पहले की है। हिमालय से निकली नदियाँ अपने साथ रेत मिट्टी लाई जिनकी तहें जमने से भारत के उत्तरी मदान बजुद में आए। धीरे धीरे एक भू भौतिक इकाई अस्तित्व में आई जिसे आज हम भारत कहते हैं। भूगर्भशास्त्रियों के मुताबिक उत्तरी भारत के बहुत बड़े भाग में करीब 8,000 12,000 ई० पू० तक भी कोई आबादी नहीं हुआ करती थी क्योंकि दलदलों के रूप में समुद्र के अवशेष अब भी वहाँ मौजूद थे। 5,000 7,000 ई० पू० के बीच ही यह इलाका रहने लायक बना।

### 2 मनुष्य की रिहायशगाह के रूप में भारत

मनुष्य की रिहायशगाह के तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में एक उन्नत स्तर की सभ्यता भी मिले हैं। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। यह करीब

3,000 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम भारत में फली फूली। लगभग 1700 ई० पू० में बाहर से आए इंडो-आर्य परिवारों ने सिंधु घाटी में वाग्निदा की शायद दक्षिण की ओर धकेलकर धीरे-धीरे उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत में फैल गए। इंडो-आर्य लोगों ने अपनी वैदिक सभ्यता का विकास किया जिससे भारतीय लोगों ने ज्ञान, तृप्ति, निष्कपटता व धर्मनिष्ठा के सूत्र और पारिवारिक व सामाजिक आचार संहिता ग्रहण की। 500 ई० पू० से लेकर 700 ई० तक बौद्धमत और जैनमत उपमहाद्वीप में बहुत बड़े भाग पर छाए रहे। बौद्धमत और जैनमत में भारतीय लोगों को दया, सहनशीलता व सादगी के गुणों और शांतमय संसार की प्रवृत्ति का पाठ पढ़ाया। 700 से 1200 ई० तक के काल में अनेक मझोल और छोटे राजवाड़े पैदा हुए और मिट गए। इनमें ज्यादातर वैदिक धर्म के अनुयायी थे। 1200 से 1800 ई० तक भारत में बहुत बड़े भाग पर मुख्यतः पर अफगान, तुर्क और मुगल बादशाहों का राज रहा। उन्होंने इस्लाम को सरकारी धर्म बनाए रखा। इस्लाम में भारतीय लोगों को समानता, एकता और अनुशासन के गुणों से लैस किया। मध्य 18वीं सदी में अंग्रेजों का बंगाल पर प्रभुत्व कायम हुआ और अगले सौ साल में वे समूचे भारत को अपने नियंत्रण में तहत ले आए। अंग्रेजी राज करीब 190 साल (1757 से 1947) तक चला। इतिहास में पहली बार एक शासक के अधीन इकट्ठा हो जाने से भारत एक ही इकाई के रूप में विकसित हुआ और समूचे देश में राष्ट्रीय भावनाएं बलवती हो उठी। अंग्रेजी राज के तहत भारत का स्वतंत्रता आंदोलन शांतिपूर्ण और गैर-शांतिपूर्ण रूपों में विकसित होता गया। लेकिन मुख्यतः सांप्रदायिक मनमुटाव के कारण कोई भी तरीका अंग्रेजी शासन का हटाने में नाकाम रहा। दूसरा विश्वयुद्ध खत्म होने के बाद वर्तमानवी उपनिवेशवाद सैनिक और आर्थिक तौर पर कमजोर हो गया तो उसने भारत में जोर पकड़ती विरोधी जन भावनाओं को भांपते हुए अगस्त 1947 में भारत को आजादी दे दी। लेकिन ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा तैयार की गई आजादी की योजना से भारत सांप्रदायिक आधार पर दो टुकड़ों—भारत और पाकिस्तान—में बांट दिया गया।

### 3 भारत का 1947 का सांप्रदायिक बंटवारा क्या अपरिहार्य था ?

इस बारे में अनेक मत हैं। लेकिन यह सवाल आज भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर विचार करने से हमें 1947 की आजादी का चरित्र और सांप्रदायिक बंटवारा कराने वाले राजनितिक नेताओं की भूमिका का पता चलता है। और इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें भारत में सांप्रदायिकता की धारणा और उसके संक्षिप्त इतिहास पर नजर डालनी होगी।

### 4 भारत में सांप्रदायिकता की धारणा और इतिहास

(क) शाब्दिक अर्थों में, सांप्रदायिकता एक समुदाय यानी साक्षे आधार वाले

एक जनसमूह की भलाई के नजरिए की द्योतक है। और समुदाय हमेशा अपने सन्स्यों की पहचान का आधार रहा है। इतिहास में कुटुंबीय, वकीलाई, क्षेत्रीय, धार्मिक आदि अनेक सांप्रदायिक प्रणालियां रही हैं। आज ऐसी राष्ट्रीय प्रणाली का वचस्व है। लेकिन कई क्षेत्रों में ठोस हालात के मुताबिक वहां अभी भी धार्मिक और क्षेत्रीय प्रणालियां हावी हैं।

(ख) आधुनिक सदन में सांप्रदायिकता का मतलब वह विचारधारा है जो राजनैतिक व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी धर्म को इस्तेमाल करती है।

(ग) सांठनिक तौर पर, सांप्रदायिकतावादियों की कई किस्में हैं। हर किस्म धर्म की अनेक प्रणालियां में किसी एक का प्रतिनिधि होने का दावा करती है। कई भी धर्म हालांकि सिद्धांत रूप में धृणा का सबक नहीं सिखाता और मनुष्य के सबन भाईचारे की शिक्षा देता है, फिर भी हर सांप्रदायिक किस्म अपने ही धर्म को सर्वोत्तम बताती है। विडवना यह है कि कई धार्मिक लोग (मसलन गांधी, आजाद, गणपार खान, शेख अब्दुल्ला) भी राष्ट्रवादी हुए हैं और हो सकते हैं जबकि कुछ गर-धार्मिक व्यक्ति (मसलन जिन्ना) धर्म को अपने राजनैतिक हित साधने के लिए इस्तेमाल करने वाले कट्टर सांप्रदायिकतावादी थे और हो सकते हैं।

(घ) ऐतिहासिक तौर पर धर्म कोई ज्यादा पुराना नहीं है। बौद्धमत, जैनमत, ईसाईमत, इस्लाम और सिखमत क्रमशः लगभग 2500, 2000, 1400 और 500 साल पुराने हैं। धर्म ने शुरू से ही मानव समाज में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से भारी भूमिका निभाई है। इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि पूर्व औद्योगिक काल में इसने अपने अनुयायियों का बुराई का त्याग करके शिष्ट जीवन जीने का उपदेश देकर सामाजिक गतिविधि को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया। इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि इसने हमेशा और हर वही प्राकृतिक व सामाजिक घटनाओं की भगवान के नाम पर गलत व्याख्या करके तथा श्रद्धा और पूजा के सिद्धांत पकड़कर मनुष्य की जिन्नामु और खोजी प्रवृत्ति को गलत दिशा दी और उसका गला घोटा है।

(ङ) सोलहवीं सदी तक धर्म दुनिया भर में सामाजिक जीवन के आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में हावी रहा। उसके बाद इसका प्रभाव घटता आया है। वजह यह है कि तब औद्योगिक टेक्नोलॉजी और उसके सामाजिक श्रम विभाजन ने जन्म ले लिया था और उन्हें चलाने के लिए धर्मनिरपेक्ष सशक्ति यानी धर्म का राजनीति से अलग करने की जरूरत थी। औद्योगिक प्रणाली और धर्मनिरपेक्षता पहले यूरोप में वजूद में आई और फिर धीरे धीरे अलग अलग पमाने तक दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में फैल गई।

(च) भारत में धार्मिक असहिष्णुता और धर्म का जन्म से ही चोली-दामन का साथ रहा है। जूनूनी कारवाइया तो मुख्यतया सभी धार्मिक संप्रदायों के शासकों की है। धार्मिक असहिष्णुता की शुरुआती घटनाएं ब्राह्मणवाद, बौद्धमत और जैनमत में हुई लगती हैं (मसलन 1193-1210 के दौरान परमार राजा मुभताचमन का

गुजरात के जैन मंदिरों को लूटना और उन्हें अपवित्र करना), हालांकि उस काल (400 ई० पू० से 1000 ई०) के ऐतिहासिक प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। यहाँ तक अफगान-नुव मुगल काल के दौरान धार्मिक अमहिष्णुता का ताल्लुक है, यह सही है कि उस समय के शासकों ने अपने पूर्ववर्तियों की तरह धर्म को विभिन्न तरीकों से अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। उनमें से एक तरीका मंदिरों का लूटकर धन घटोरना भी था। लेकिन उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच स्थायी दरार पैदा करने की कभी कोशिश नहीं की। इससे उनकी व्यवस्था की जड़ें घुटने का अदशा था। दरअसल, मुस्लिम धर्मोपस्थापना की ज्यादातर पहलियाँ अति-धार्मिकतापूर्ण हैं। यह बात उन शासकों के व्यवहार से जाहिर होती है जिन्हें कुछ इतिहासकार बहद बट्टर सांप्रदायिक मानते हैं। मसलन, अगर महमूद गजनवी महज ब्रूतशिवन (मूर्तिभजन) था तो उसकी सेना की एक डिवीजन में सभी हिंदू ही क्यों थे? लाहौर का उसका गवर्नर हिंदू कैसे था? उसके दरबारियों में क्या इतना ज्यादा ब्राह्मण थे? दरअसल वह सबसे ज्यादा दौलत का पुजारी था। शाहनामा के रचयिता न लिखा है कि महमूद गजनवी को "एक ही मंदिर से 230 मन सोना और 40 मटके स्वर्ण धूल मिली थी। तोलन पर मटकों में 1320 मन साना पाया गया।" और गजेब ने जहाँ कुछ मंदिरों को गिरवाया, वही उसने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर समेत संकड़ा दूसरे मंदिरों का अनुदान और सहायता दी। टीपू सुलतान ने 18वीं सदी के आखिरी चतुर्थांश में शृंगरी मठ को बचाने के लिए अपनी फौज भेजी। हिंदू पेशवा रघुनाथ राव पटवर्धन इस हिंदू तीर्थ को लूटना चाहता था। टीपू का बजीरेआजम (पुरनया), बजीरे पजाना (वृष्ण राव) और बजीरे दाखिला (शामा आयगर) हिंदू थे। 712 ई० में सिंध पर हमले के दौरान जब कुछ मंदिर क्षतिग्रस्त हो गए तो खलीफा न कासिम को नुबसा का हरजाना देने का हुकुम दिया। बड़े पैमाने पर मुसलमान बनाए जाने की घटनाएँ दरअसल ऐसे क्षेत्रों (मसलन कश्मीर, केरल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब आदि) में हुई जहाँ कभी दिल्ली दरबार का ज्यादा सिक्का नहीं चला। जाहिर है कि ये धर्म परिवर्तन सरकारी दबाव के बिना हुए। मुसलमान सूफियों के प्रचार का इसमें ज्यादा योगदान रहा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में हिंदू हमेशा बहुसंख्यक रहे। हिंदू और मुसलमानों के बीच वैवाहिक सम्बन्ध भी आम थे। 18वीं सदी के शुरू में मुगल राज के खिलाफ लड़ते सिख किसानों के साथ साथ हजारों मुसलमान किसानों ने भी अपने प्राण चोखाकर किए। उस समय हिंदू राजा तो और गजेब के पक्ष में लड़े। हिंदू मुसलमान और मराठा किसानों ने मुगल राज के खिलाफ मिलकर गुरिल्ला लड़ाई लड़ी। राणा प्रताप की सेना में अनेक मुसलमान थे, जिनमें उनके तोपखाने का सिपहसालार भी शामिल था (तोपखाना उस समय सेना का वेहद महत्वपूर्ण अंग था)। विजयनगर के हिंदू राजा की सेना में करीब 80,000 मुसलमान थे। इन दोनों तथ्यों से उस समय के सामाजिक संबंधों और परंपराओं का पता चलता है।



## 5 भारत में आधुनिक सांप्रदायिकता

ब्रिटिश राज के दौरान आकर ही धर्म को संगठित तरीके से राजनीतिक हितों में बरता जाने लगा। 1857 से पहले तक ब्रिटिश राज ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने और मजबूत करने की खातिर हिंदू मुसलमान राजाओं के अंतरविरोध को ही इस्तेमाल किया था। लेकिन 1857 में भारत के स्वतंत्रता युद्ध के बाद उसने फूट डालो और राज करो की नीति हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ही नहीं बल्कि सवण हिंदुओं और हरिजनों व आदिवासियों के अलावा 'द्रविड दक्षिण और 'आर्य' उत्तर को लड़ाने के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दी। इस नीति के तहत पहले सनातन, फिर अभिजात्य वर्ग में और बाद में लोगों में सांप्रदायिक भावना पैदा करने के लिए सुनियोजित पग उठाए गए। भारतीय राजनीति को सांप्रदायिक बनाने में ब्रिटिश राज को हिंदू पुनरुत्थानवाद और मुस्लिम कट्टरपथ की मदद मिली।

## 6 हिंदू पुनरुत्थानवाद और कांग्रेस

(क) हिंदू पुनरुत्थानवाद का शुरुआती इजहार राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती बंकिमचंद्र चटर्जी, विवेकानंद, तिलक, अरविंदो, मदनमोहन मालवीय, सावरकर सरीखे अनेक आधुनिक सुधारक नेताओं की धारणाओं में हुआ। राजा राममोहनराय ने ब्रह्म समाज स्थापित किया जो यूरोपी ज्ञान के सिद्धांतों और उपनिषदों के दार्शनिक विचारों का संयोजन था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की नींव रखी जिसमें सवत्र वैदिक आर्य सर्वोच्चता को स्वीकार किया। बंकिमचंद्र चटर्जी ने हिंदू पौराणिकी का प्रचार किया। विवेकानंद ने सवत्र पौराणिक हिंदू सर्वोच्चता का उपदेश दिया। तिलक तो शिवाजी की विरासत को फिर से जिलाना चाहते थे। वे गणपति उत्सव भी मनाया करते। अरविंदो ने काली को युगचेतना बनाने के साथ साथ सनातन धर्म को भारत की आत्मा बताया। मदनमोहन मालवीय सनातन हिंदूमत के समर्थक थे। सावरकर हिंदू आदर्शों की सर्वोच्चता के प्रचारक रहे। संक्षेप में, इन सभी सुधारकों का मत था कि प्राचीन (अथवा वैदिक) भारत ही दुनिया की सारी सभ्यता का स्रोत और देवी नतिकता का ध्वजवाहक रहा है। उनका दावा था कि भारतीय ऐतिहासिक प्रक्रिया अलौकिक किस्म की रही जो ऋषियों द्वारा रचे गए दशन पर आधारित थी और उसका अंतरराष्ट्रीय ऐतिहासिक प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने यह मिथ्या धारणा भी पैदा की कि वैदिक भारत सर्वोत्तम था। उनमें कइयों का तो यहाँ तक था कि प्राचीन भारत की उज्ज्वल छवि दुष्ट मुसलमान शासकों ने खराब की जिन्होंने भारत के समृद्ध धर्म का नाश करके उसकी खुशहाल जिंदगी को नष्ट कर डाला।

(घ) सन् 1920 के लगभग कांग्रेस का नेतृत्व गांधी के हाथ में आ जाने के बाद भी इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने भी प्रायः हिंदू धर्म पुस्तकालयों में बंधकों से मुहावरे, ताक्षणिक अर्थ और उदाहरण इस्तेमाल किए।

ए रामराज्य एक आदर्श राज्य था। उन्होंने लगातार उसे भारत की नई व्यवस्था का लक्ष्य करार दिया। गीता न उह मनुष्य के बम का एक उतके हितव आधार मुहैया किया। उनका राष्ट्रीय गीत बदे मातरम' प्रथमचद्र सामाजिक एवं उपास से लिया गया था। उस उपास म एक हिंदू मठ के सदस्य आदर्श 'रम' को मुसलमान हमलावरो के खिलाफ युद्धनाद के तौर पर इस्तेमाल करते चटर्जी के जा और वण व्यवस्था के बारे मे उन्होंने 'यग इडिया' मे लिखा 'इसम 'वदे मा' म मे) गौ पूजा मेरी राय मे मानवतावाक के प्रथम विकास के प्रति एक है। गौ योगदान है। अतत वर्णाश्रम धम की खोज सत्य की अथक खोज का ही (हिंदू ध परिणाम है।' इन धारणाओ (यानी रामराज्य, गीता, बदे मातरम, गौ अभूतपूर्व आश्रम धम) पर जोर देने का मतलब राजनीति म धम को घुसेडना है।

शानदार (ग) जाहिर है, सुधारवादी नेताओ द्वारा भारत के वैदिक युग के स्तुतिगान पूजा, की द्वारा हिंदू अलवारो के इस्तेमाल से लोगो मे सांप्रदायिक चेतना मजबूत से एक तरफ हिंदू समुदाय प्राचीन सभ्यता का पुनर्जीवित करने की ओर और गांधी और दूसरी तरफ मुसलमान समुदाय मे भी मुस्लिम पुनरुत्थान के विचार हुई। इस गण। इससे मुस्लिम लीग गांधी को हिंदुओ के नेता और कांग्रेस का हिंदुआ प्रेरित हुई के तौर पर प्रस्तुत करने मे कामयाब हुई।

पैदा हो (घ) गांधी और दूसरे सुधारवादी नेताओ के इस हाव भाव से जहाँ उनकी के सगठान प्रकट होती थी, वही उनके वेजसूले समझौते और दभी व्यवहार ने कट्टरपथियो को पनपने मे मदद दी। वेजसूले समझौते न मुसलमानों की चान की भावना को मजबूत किया जबकि दभी व्यवहार ने मुसलमानों को हिंदू पहलू लोग की तरफ धकेल दिया। इस सदी के पहले अर्द्धाश म हुई अनेक घटनाएँ मुस्लिम की पुष्टि करती है। 19वीं सदी के अंत मे जब ब्रिटिश सरकार ने मुसल- अलग पर अलग नुमायदगी देने का विचार रखा तो किसी भी पुनरुत्थानवादी नेता मुस्लिम स ने इसका कारगर विरोध नहीं किया। उ होने 1909 के मॉले मिंटो इस तथ्य को चुपचाप कबूल कर लिया जिनके तहत अलग मतदाताओ और सांप्रदायिक मानो कत्व की व्यवस्था बज्द मे आई। 1916 म मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ या कांग्रेस र स्तखत करके कांग्रेस न मुसलमानों की अलग पहचान कबूल कर ली सुधारो लम लीग को भारत के मुसलमान समुदाय का प्रवक्ता मान लिया। इससे प्रतिनिधि लोग मुसलमान और हिंदुओ के दो मुख्य सांप्रदायिक गुटो मे बट गए। सच्चि प साल मे मुस्लिम लीग से बह योजना मनवाने की अनेक कोशिशों की गई और मुस्लिम लीग के अडियल रख, कांग्रेस के अधमने खय (यह पार्टी मुस्लिम भारतीय मुस्लिम लीग के अडियल रख, कांग्रेस के अधमने खय (यह पार्टी मुस्लिम अगले 2) साथ एवता फामूले के बारे म हिंदू महासभा से मजूरी लिया करती थी, जैसे जिसम र राजेंद्र प्रसाद और जिना के बीच हुए समझौते के वकन) तथा ब्रिटिश राज थी। पर एक भूमिका के कारण ये सभी कोशिशें नाकाम हो गई। इस सबध मे लीग के 1935 की विध

एक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि गांधी जहाँ 1935 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक पंच निणय के तहत अनुसूचित जातियाँ व जनजातियाँ को अलग मतदान अधिकार दिए जाने के विरोध में मरणत्रत पर बैठ गए, वहीं मुस्लिम समुदाय को ऐसा अधिकार मिलने पर उन्होंने कुछ नहीं किया। शायद वे मुस्लिम समुदाय को अलग राष्ट्रीयता मानते थे।

(ड) 1937 में ऐसा माकूल मौका आया भी। प्रांतीय विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की शानदार जीत और मुस्लिम लीग व कमजोर प्रदर्शन के बाद लीग ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिली-जुली सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। नेहरू ने यह कहकर इस पेशकश को ठुकरा दिया कि भारत में दा ही पार्टियाँ हैं—एक कांग्रेस और दूसरी ब्रिटिश—तथा कांग्रेस के सिवा कोई भी भारतीय लोगों की नुमायंदगी नहीं करता। यह बेहद नासमझी भरा वयान था जिससे न सिर्फ मुस्लिम लीग के साथ बल्कि विभिन्न क्षेत्रीय मुस्लिम गुटों के साथ भी समुक्त मार्च बनाने का विकल्प खत्म हो गया। इससे एक तो बंगाल की कृषक प्रजा पार्टी ने नता फजल उल हक मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाने पर मजबूर हुए। दूसरे, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी के सिक्कर हयात खाँ को जिना के साथ एक संधि पर दस्तखत करके मुस्लिम लीग से समझौता करना पड़ा। तीसरे, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के एक अहम नेता खलीकुज्जमा सख्त नाराज हो गए और बाद में पाकिस्तान के भारी समर्थक बन गए।

(च) अनेक महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं इतिहासकारों और लेखकों का मत है कि मिली जुली सरकारें बनाने में कांग्रेस की हिचकिचाहट देखते हुए मुसलमान उससे अलग हटकर देश विभाजन की मांग का समर्थन करने लगे। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और दीवान चमनलाल<sup>2</sup> सरीखे जाने माने कांग्रेसी नेता लिखते हैं कि 1937 में जिना समुक्त मतदाता प्रणाली कबूल करने को तैयार थे। प्रसिद्ध इतिहासकार जार० सी० मजूमदार<sup>3</sup> ने लिखा है कि कांग्रेस के स्वमतवादा<sup>4</sup> भावी राजनीति में बेहद विनाशकारी परिणामों को जन्म दिया। जाने माने लेखक माइकल ब्रेंडर<sup>5</sup> कहते हैं कि (चुनावों) जीत व नशे में चूर कांग्रेस ने बाकी सभी राजनैतिक पार्टियों के प्रति अभिमान की रवैया अप्रतिपाद्य करके एक भारी गलती की जिसकी आने वाले वर्षों में उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक मशहूर पत्रकार फ्रेंक मोरेस<sup>6</sup> ने टिप्पणी की है कि चुनावों के बाद अगर कांग्रेस ने लीग के साथ उचित व्यवहार किया होता तो पाकिस्तान कभी वजूद में न आता। एक जाने माने लेखक के० के० अजीज<sup>7</sup> ने लिखा है कि कांग्रेस ने 1937 में मुसलमानों की सत्ता में हिस्सा देने से इनकार करके पाकिस्तान को अवश्यभावो बना दिया। मोताना आज़ाद का भी मानना था कि अगर कांग्रेस ने 1937 में लीग के प्रस्ताव पर उचित प्रतिक्रिया दिखाई होती तो प्रांत में मुस्लिम लीग छिन भिन हो जाती और पाकिस्तान की मांग न उठती।<sup>7</sup>

(छ) जहाँ कांग्रेस ने 1937 में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि स्वरूप को मानने

से इनकार कर दिया था, वही 1944 में गांधी ने राजगोपालाचाय फामूले के आधार पर जिना से समझौता वार्ता शुरू की। इस फामूले में मुसलमानों की बहुसंख्य वाले इलाकों में उनका आत्मनिर्णय का अधिकार स्वीकार किया गया था। यह भारवार्द पाकिस्तान की मांग के विरुद्ध गांधी द्वारा पहले दिए गए अनन्य बयानों के विपरीत थी और 1944 के स्टेफोर्ड रिप्स सुझावों के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा अपनाए गए रुख के भी उलट थी। रिप्स मिशन ने उन प्रांतों और राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने का सुझाव दिया था जो सभ में शामिल नहीं होना चाहते थे। पर कांग्रेस ने इन सुझावों को रद्द कर दिया था। इससे पाकिस्तान के विचारों को और मजबूती मिली। मौलाना आजाद<sup>8</sup> ने राजगोपालाचाय फामूले पर असफल वार्ताओं के दौरान गांधी द्वारा बर्बई में रोजाना जिना के घर जाने और उन्हें बायदे-आज़म के नाम से पुकारने की बड़ी आलोचना की थी। मौलाना के मुताबिक इससे लीग का अडिगलपन ही बढ़ा।

(ज) भारत विभाजन को टालने का आखिरी मौका भी जुलाई 1946 में हाथ से निकल गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मई 1946 की ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना मान ली थी (इसमें कुछ शर्तों के तहत संयुक्त भारत बने रहने का प्रावधान था)। पर उसी साल जुलाई में नेहरू ने अपनी पार्टी से सलाह किए बिना अखबारों को एक बयान जारी कर दिया कि कांग्रेस समझौते के बंधन से मुक्त होकर संविधान सभा में जाएगी और हालात के मुताबिक काम करने को स्वतंत्र होगी। इस बयान या मतलब वस्तुतः कैबिनेट मिशन योजना को ठुकराना था। इसके तत्काल बाद मुस्लिम लीग ने इस योजना पर हुए समझौते से हाथ खींच लिया। मौलाना आजाद<sup>9</sup> ने लिखा है कि जवाहरलाल का बयान गलत था क्योंकि कांग्रेस इस योजना को पहले ही मान चुकी थी।

(झ) ज्यादा तफसील में न जाते हुए यहाँ इतना ही कहना काफी है कि हिंदू पुनरुत्थानवाद ने समझौतापरस्त और दभी तरीके अपनाकर भारत विभाजन में बड़ी भूमिका निभाई। जब एक समुदाय के मूर्यों को दूसरों से श्रेष्ठ बताया जाए और अल्पसंख्यक अपनी पहचान को छतरा महसूस करें तो अलगाववाद को बल मिलेगा ही।

## 7 मुस्लिम कटटरवाद और मुस्लिम लीग

मुस्लिम कटटरवाद के दो स्वरूप हुए। एक तो शाह बलीउल्लाह का सब इस्लामपय था जिसके तहत ऐसे परंपरावादी कटटरपथी आते थे जो ब्रिटिश राज द्वारा मुसलमान शासकों से राजनैतिक सत्ता हथियाए जाने की वजह से उससे खफा थे। दूसरा संयद अहमद खान का मुस्लिम अलगाववाद था जिसके अनुयायी हिंदुओं द्वारा ब्रिटिश प्रशासन में निचले स्तर की नौकरियाँ पर एकाधिकार जमाने की वजह से उनसे ईर्ष्या करते थे। पहला खतान 19वीं सदी के शुरू में पदा हुआ। उसे मानने वाला ने इस पूरी सदी के दौरान, खासकर उत्तर पश्चिम में सशस्त्र संघर्ष छेड़े रखा

लेकिन जन समर्थन न मिल पाने से यह नाकाम हो गया। दूसरे रस्मान ने 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में जन्म लिया। उसने ब्रिटिश राज के साथ समझौता करने और कांग्रेस (1885 में स्थापित) को सहयोग न देने की लाइन अख्तियार की। यही रस्मान धीरे धीरे विवक्षित होकर 1906 में मुस्लिम लीग में बदल गया। वजूद में आने के बाद लीग ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाता प्रणाली अपनाए की मांग की। मॉर्ले मिंटो सुधारों (1909) में अलग मतदाता प्रणाली के शुद्ध रूप से जहाँ उसे सरकारी प्रोत्साहन मिला वही कांग्रेस द्वारा अलग मतदाता प्रणाली की अभिप्रेक्षा किए जाने (1916 में कांग्रेस लीग की लयनऊ संधि) से उसे नैतिक और तार्किक आधार भी मिल गया। पाकिस्तान के लक्ष्य की ओर इसका अगला सफर जिन्ना की अगुआई में तय हुआ। जिन्ना को एक तरफ ब्रिटिश सरकार का पूरा संरक्षण मिला और दूसरी तरफ अलग चेतन के पक्ष में मुसलमानों को लाकर उठाने वाली चतुराई से कांग्रेस को मात भी दे दी। नतीजा यह हुआ कि 1947 में भारत का दुर्भाग्यपूर्ण बंटवारा हो गया।

## 8 विभाजन के विकल्प

ऊपर दिए तथ्यों के मद्देनजर कुछ सवाल उठने स्वाभाविक ही हैं।

(क) (1) भारत विभाजन के लिए बोयी कौन? कुछ हलकों (नेहरू-समर्थक कांग्रेसियों कम्युनिस्टों मार्क्सवादी कम्युनिस्टों आदि) के अनुसार मुख्य बसूतवार ब्रिटिश उपनिवेशवाद है जिसने मुस्लिम लीग को दासी की तरह इस्तेमाल किया। कुछ दूसरों (पटेल समर्थक कांग्रेसियों भाजपाइयां और दूसरे बटटर हिन्दू समर्थक तत्वों) का मानना है कि इसकी मुख्य जिम्मेदारी मुस्लिम अलगाववाद पर है जिसे ब्रिटिश उपनिवेशवादियों का समर्थन हासिल था। मौलाना आजाद<sup>10</sup> ने लिखा है याद रखें भारत में लाड माउटबेटन के विचार को सबसे प्रथम मानने वाले व्यक्ति सरदार पटेल थे उन्हें यकीन था कि वे मुस्लिम लीग के साथ काम नहीं कर सकते। उन्होंने संसद में कहा था कि वे लीग को भारत का एक हिस्सा देने को तयार हैं बशर्ते वे उससे छूटकारा पा सकें। पटेल के इस कथन पर कि हम पसंद करें या न करें, भारत में दो राष्ट्र हैं—मुझे ताज्जुब हुआ और दुख भी। उन्हें अब यकीन हो गया था कि मुसलमान और हिंदू एक राष्ट्र में नहीं रह सकते। मौलाना के अनुसार नेहरू तो एक समय विभाजन के सख्त खिलाफ थे पर बाद में वे सरदार पटेल का साथ देने लगे। इसका एक कारण उन पर लाड माउटबेटन और उनकी पत्नी का प्रभाव होना था। मौलाना को उस समय और गहरा आघात लगा जब उन्होंने गांधी को पटेल के दबाव में आत देखा। मौलाना के मुताबिक विभाजन के पक्ष में जोर लगाने के बावजूद पटेल को भरासा था कि नया पाकिस्तानी राज्य ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान की मांग मान लेने से मुस्लिम लीग को बड़वा सबक मिल जाएगा। पाकिस्तान तो थोड़े ही अरसे में बह जाएगा और भारत से अलग होने वाले प्रांतों को

भारी मुसीबतों और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एलन कैपबेल-जॉनसन<sup>11</sup> ने लिखा है पूरी समस्या के प्रति वे (पटेल) स्पष्ट और दृढ़निश्चयी मत रखते थे कि भारत को मुस्लिम लीग से छुटकारा पा लेना चाहिए। जाने माने अमेरिकी पत्रकार लूई फिशर<sup>12</sup> ने लिखा है कि नेहरू ने पटेल की इस दलील के आगे घुटने टेक दिए कि एकीकरण चार, पाच या दस साल में हो ही जाएगा।

(ii) हमारी राय में, ब्रिटेन और मुस्लिम लीग इसके लिए अपनी अपनी तरह से जिम्मेदार जरूर हैं पर मुख्य दोषी कांग्रेस ही है। वजह यह कि उसके पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद ने मुसलमानों को विमुख कर दिया, अलग मतदाता प्रणाली की मांग से उसके बेअमूले समझौते और मुस्लिम लीग के प्रति उसके दभी व्यवहार से लीग को मुसलमानों में अपना असर बढ़ाने में अप्रत्यक्ष मदद मिली, तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रति अपने घुटनाटेक रवैए से वह ब्रिटिश प्रशासन की 'फूट डालो और राज करो' की नीति को विफल बनाने में अक्षम हो गई। राष्ट्रीय पहचान बनाने का काम तभी सिरें चढ़ सकता है जब संघित पार्टी दबता से सांप्रदायिकता की सभी किस्मों के खिलाफ लड़े और धमनिरपेक्षता (धर्म को राजनीति से अलग रखने की नीति) का झंडा बुलंद रखे। अगर वह पुनरुत्थानवादी नीति पर चले तो विभिन्न प्रकार के कट्टरवाद के बीच होड़ चल पड़ती है जिससे समूची राज्य व्यवस्था सांप्रदायिक रंग में रंग जाती है। यही 1947 से पहले के भारत में हुआ और 1947 के बाद भी होता आया है। यही वजह है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद और मुस्लिम अलगाववाद की रवानगी के 40 साल बाद भी सांप्रदायिकता आज भारतीय राज्य व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या बनी चली आ रही है तथा 1947 के बाद के सांप्रदायिक दंगों ने 1947 से पहले का रिकार्ड भी तोड़ दिया है। अगर कांग्रेस का राष्ट्रवादी सचमुच धमनिरपेक्ष है तो 40 साल तक इसके अमल में रहने के बाद भी क्यों सिख अलगाववाद ने भारत में जन्म लिया है हालांकि सिख और हिंदू समुदाय सदियों से चोली-दामन की तरह साथ रहते आए हैं? अगर कांग्रेस का राष्ट्रवाद पुनरुत्थानवादी नहीं तो धमनिरपेक्ष भारत में जातिवाद ने क्यों पहले से भी ज्यादा तेजी से देहातो को अपनी गिरफ्त में ले लिया है तथा अनुसूचित जातियाँ व जनजातियाँ क्यों अधिकाधिक विमुख होकर जातिवादी हिंदुओं से नाता तोड़कर बौद्धमत अरितीयार कर रही है और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपने राजनैतिक संगठन (जैसे बहुजन समाज पार्टी) बना रही हैं? अगर कांग्रेस की धमनिरपेक्षता में हिंदुवाद का पुट नहीं है तो इसके 40 वर्षीय शासन में हिंदू कट्टरवाद की नई नई किस्में (शिवसेना विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सुरक्षा समिति, बजरंग दल, हिंदू जागरण समिति, राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति आदि) क्यों पैदा हुई है? अगर कांग्रेस की धमनिरपेक्षता सचमुच राष्ट्रवादी है तो 40 साल के औद्योगीकरण के बावजूद वह जोर क्यों नहीं पकड़ पाई तथा नई नई सांप्रदायिक, जातिवादी, क्षेत्रीय और सकीणतावादी ताकतें क्यों उस पर आघात करती आ रही हैं। फिर, अगर भारतीय राज्य की धमनिरपेक्षता

धर्मों के प्रति समान जादर के अमूल (सब धर्म समभाव) पर आधारित है ता भारतीय सविधान (यानी भारतीय राज्य का मूल सिद्धांत) बहुसंख्यक समुदाय की भाषा सहिता को संरक्षण क्यों देता है ? मसला—\*संस्कृत भाषा (जो भारत में किसी भी जन समूह की बोली नहीं होकर महज कुछ शैक्षणिक संस्थाओं तक ही सीमित है लेकिन हिंदू परंपरा में इसे देवी भाषा माना जाता है) को राष्ट्रीय भाषा के बतौर सर्वोच्च निकाय दर्जा देना।<sup>13</sup> \*\*सविधान में इंडिया का नाम भारत रत्न करना (यह शब्द भारत माता अथवा महाभारत की हिंदू धारणा से पदा हुआ है)। \*\*\* राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते (हिंदू उपनिषद 'मुष्टका' से ली गई एक सूक्ति) लिखना अनिवार्य बनाकर उसे सर्वोच्च निकाय हैसियत देना।\*\*\*\* हिंदी को भारत की एकमात्र सरकारी भाषा के तौर पर सर्वोच्च निकाय दर्जा देना—हालांकि यह भाषा हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई है और हिंदू पौराणिकी के मुताबिक इसकी लिपि देवों की लिपि है पर इसे बोलने वाले महज 33 फीसदी लोग हैं।\*\*\*\*\* वंदे मातरम् (हिंदू रस के एक गीत) को राष्ट्रीय गीत के तौर पर सर्वोच्च निकाय दर्जा देना।\*\*\*\*\* मार (जा कि हिंदू परंपरा के मुताबिक पवित्र पत्थर है) को राष्ट्रीय पत्थर के तौर पर सर्वोच्च निकाय दर्जा देना।\*\*\*\*\* सविधान में सिद्ध धर्म बौद्धमत और जैनमत को हिंदूमत की शाखाएं बताना (अनुच्छेद 25 2वीं)।\*\*\*\*\* राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में गोवर्धन पर पावनी का शामिल करके उसे सर्वोच्च निकाय दर्जा देना (अनुच्छेद 48)। अगर भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्षता बहुसंख्यक समुदाय के कट्टरवाद की तरफ दारी नहीं करती तो क्या वजह है कि राज्य और सरकार का हर अहम काम पूजा और आरती से शुरू होता है और लगभग हर हिंदू मंदिर और तीर्थस्थल को एक या दूसरे रूप में केंद्रीय राज्य या स्थानीय सरकार से आर्थिक मदद और सांस्कृतिक रियायतें मिलती हैं क्या वजह है कि सभी सरकारी बयान और इतिहास ग्रंथों के वैदिक काल को भारतीय इतिहास का सुनहरा युग बताते हैं और इस तरह बाकी ऐतिहासिक कालों (यानी वैदिक युग से पहले और बाद के कालों) का गौण महत्त्व देते हैं।

(iii) दरअसल भारत और पाकिस्तान की राज्य संस्कृतियाँ धर्म पर आधारित हैं—पाकिस्तान में इस्लामी और भारत में बहुधार्मिक धर्मनिरपेक्षता के लंबाई में हिंदू पुनरुत्थानवादी। यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही एकतामूलक राष्ट्र बनाने में नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान तो दो टुकड़ा में बँट ही गया है। बांग्लादेश एक नया राष्ट्र राज्य बन गया है। बाकी बचे पाकिस्तान में पंजाबी सिंधी, बलूच और पठानों का चार राष्ट्रियताओं के बीच जबरदस्त रसाक्षी चल रही है। पाकिस्तानी राष्ट्रवाद का तो पूरी तरह दिवाला निकल गया है पर भारतीय राष्ट्रवाद में कुछ दरारें ही दिखती हैं। बढ़ते साम्प्रदायिक और जातिवादी तनावों के अलावा ये दरारें पंजाब, कश्मीर असम मणिपुर नगालड तमिलनाडु झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और कालहनिस्तान (बिहार) में झलकती हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रवाद जहाँ पूरी तरह नाकाम रहा वहीं भारतीय राष्ट्रवाद को थोड़ी नाकामी मिली है। निष्पक्ष साफ है।

बिसी भी राष्ट्र का निर्माण धार्मिक आधार पर नहीं किया जा सकता। यह बात मध्य-पूर्व के अनुभव से जाहिर होती है। भारत के मामले में एक ही बात उसके पक्ष में है और यह उसकी बहुदलीय समद्रीय प्रणाली है जो तनावों को बर्दाश्त कर पाती है। इस पर हम उपयुक्त जगह पर विचार करेंगे।

(घ) (i) क्या विभाजन अनिवार्य था? दीर्घकालिक अथवा अल्पकालिक बिसी भी कोण से देखें, यह जरूरी नहीं था।

(ii) दीर्घकालिक नजरिए से देखें तो अगर गांधी ने हिंदू अलखारा का प्रयोग न किया होता और कांग्रेस ने एक तरफ मुसलमानों के लिए अलग मतदाता प्रणाली के संवोध पर बलपूर्वक समझौते की नीति पर और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के प्रति धोसबाजों की नीति पर अमल न किया होता तो लीग मुसलमानों में बेहद लोकप्रिय न हो पाती। ऐतिहासिक तथ्य इसकी गवाही देते हैं। सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत जैसे इलाकों में जहाँ मुसलमान भारी संख्या में थे, आम पिछड़ापन होने के बावजूद ज्यादा लोग पाकिस्तान की मांग के समर्थन में नहीं थे। यहाँ तक कि इनमें से कुछ इलाकों (मसलन सीमा प्रांत) में तो लोकप्रिय मुसलमान नेताओं ने 1947 तक भी पाकिस्तान बनाने के विचार का समर्थन नहीं किया। उन इलाकों में जहाँ मुसलमानों की थोड़ी बहुसंख्या थी (जैसे बंगाल और पंजाब), वहाँ भी लोकप्रिय नेतृत्व उन क्षेत्रीय पार्टियों के हाथ में था जो जिनके पाकिस्तान बनाने के विचार से सहमत नहीं थी (बंगाल में फजल उल हक की अगुआई में वृषक प्रजा पार्टी थी तो पंजाब में पहले सिक्ख दर ह्यात था और फिर उनकी मृत्यु के बाद खिख ह्यात था की अगुआई में यूनियनिस्ट पार्टी के अलावा खाकसार और अहंरार पार्टियाँ)। मुस्लिम लीग के विभाजन सिद्धांत को सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में समर्थन प्राप्त था जहाँ मुसलमान बहुत ही कम संख्या में थे। 1947 के आसपास आकर ही वृषक प्रजा पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी मुस्लिम लीग में शामिल हुई। अगर कांग्रेस ने कुछ अक्लमंदी से काम लिया होता (भले ही रुख उसका पुनरुत्थानवादी रहता) तो वह क्षेत्रीय मुसलमान ताकतों को मुस्लिम अलगाववाद के खिलाफ एकजुट कर सकती थी, जैसे कि उसने कश्मीर में शेख अब्दुल्ला का समर्थन करके किया। इसके अलावा, कांग्रेस ने '20 और '30 के दशक के दौरान (मसलन 1921, 22, 1935, 1937 आदि में) उन मौकों का सही इस्तेमाल नहीं किया जब मुस्लिम लीग समझौते के मूड में थी और कांग्रेस के साथ उसके दोस्ताना संबंध थे। यहाँ तक 1947 से पहले की दूसरी राजनैतिक ताकत का संबंध है, कम्युनिस्ट पार्टी ने पाकिस्तान के नारे को आत्मनिर्णय के राष्ट्रीय अधिकार के समकक्ष रखकर गलती की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा ने हिंदू कट्टरवाद पर जार देकर माहिल को अधिक सांप्रदायिक रगत दी और परोक्ष रूप से मुस्लिम अलगाववाद को मजबूत बनाया। कांग्रेस के अवसरवादी रुख का बिना शर्त समर्थन करके अकाली दल ने भी भूल की।



(iii) अल्पकालिक नजरिए से देखें तो 1947 में जब विभाजन की मांग मुसलमानों में लोकप्रिय हो गई तो उसने तीन विकल्प थे। ये थे \*ब्रिटिश क्विंट मिशन योजना जिसे दोनों पक्षों ने मंजूर कर लिया था, \*\*दोनों देशों का एक महासंघ जिसमें उनकी संयुक्त रक्षा व्यवस्था रहती, और\*\*\* सभी समझौते रद्द करके संयुक्त आजाद भारत की एक ही भाग उठाई जाती जिसकी भले ही कितनी ही कीमत चुकानी पड़ती, चाहे ब्रिटिश हुकूमत कुछ और वक़्त के लिए जारी रहती या देश के कुछ भागों में गड़बड़ी के हालात रहते। पहला विकल्प मुख्यतया 14 जुलाई 1946 को नेहरू के बयान से धराशायी हो गया। तीसरे विकल्प का गांधी ने भी सुझाव दिया था पर नेहरू और पटेल ने उसे रद्द कर दिया था। हाल ही में हुए रहस्योद्घाटन के अनुसार वे सत्ता पाने के लिए बेनाब थे और मूल बातों पर आपसी मतभेदों के बावजूद 1946 में भारत का सांप्रदायिक बंटवारा मानने के लिए एक हो गए थे। इसे ही वे भारत की राष्ट्रीय समस्या का अमली समाधान मानने लग गए थे। विभाजन के बाद की घटनाओं से अब लगता है कि तीनों में से कोई भी विकल्प कामयाब हो सकता था। अब उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार जिना को भी अपने अंतिम दिनों (1948) में विभाजन का अफसोस हुआ था और उन्होंने यह कहा बताते हैं "पाकिस्तान बनाकर मैंने सबसे बड़ी भूल की है। मैं दिल्ली जाकर नेहरू से कहना चाहूंगा कि बीते वक़्त की मूर्खताओं को भूल जाएँ और दोबारा दोस्त बन जाएँ।"<sup>14</sup> माइकल एडवर्ड्स ने लिखा है, 'जिना सचमुच पाकिस्तान चाहते थे, यह बात सदिग्ध है। उनके सार्वभौमिक नकारात्मक थे जिनका मकसद कांग्रेस के नेतृत्व में अविभाजित भारत को उभरने से रोकना था। पाकिस्तान बनने के कुछ ही समय बाद मुस्लिम लीग में विखराव से लगता है कि अगर कांग्रेस ने भारत को एकीकृत रखने के लिए कोई संवैधानिक स्वरूप मान लिया होता तो लीग के भीतर ही ताकतों का नया जोड़ तोड़ हो जाता जिससे कट्टरवादी सांप्रदायिक ताकतों की गिरफ्त कमजोर हो जाती।"<sup>15</sup>

(ग) क्या विभाजन सर्वोत्तम समाधान था या कमतर बुराई, जैसा कि कांग्रेसी नेता दावा करते हैं? इस समाधान के लिए वेमिसाल कीमत अदा की गई। सांप्रदायिक विनाशालीला भयावह थी। बच्चों के टुकड़े कर दिए गए। बलात्कार के बाद महिलाओं की हत्या कर दी गई। पुरुष मौत के घाट उतार दिए गए। बेहिसाब संपत्ति बर्बाद कर दी गई। कुल मिलाकर 10 लाख लोग मौत के घाट उतार दिए गए 40 लाख घायल हुए और 250 लाख पूरी तरह लूट लिए गए।<sup>16</sup> इतिहास में शायद यह सबसे बड़ा हत्याकांड था जिसमें किसी मुक्ति युद्ध से भी ज्यादा जानें गईं। यह था ब्रिटेन का शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण और कांग्रेस की अहिंसापूर्ण शक्ति। दरअसल कुछ चीजों के लिए भारी कीमत अदा की गई थी। और इतनी भारी कीमत अदा करने के बाद हमने क्या पाया? राजनैतिक तौर पर हम एक केंद्रीकृत राज्य और तानाशाही शासन के तहत सबंध मताधिकार मिला। आर्थिक तौर पर हमें घीमे

आर्थिक विकास के साथ ही बढ़ती गरीबी, वरोजगारी, महंगाई, आमदनी में असमानता, भ्रुपोपण, बीमारी आदि मिली। सांस्कृतिक तौर पर हमने सभी धार्मिक आस्थाओं खासकर बहुसंख्यक समुदाय की ओर अभिमुख धमनिरपेक्षता पाई जिसमें नित नए सांप्रदायिक और जातिवादी दंगे, आतंकवादी हत्याएँ, गुंडा गतिविधियाँ, भ्रष्टाचार, पक्षपात, पडयंत्र, चापलूसी आम घटनाएँ हैं। हमें हुए राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लाभों पर अगले अध्याय में विचार किया गया है।

(घ) जगर विभाजन कबूल न किया जाता तो क्या हालात और बिगड़ते ? नहीं, इसके बजाय फौरी तौर पर और दीर्घकालिक लिहाज से हालात बेहतर हो जाते। फौरी तौर पर तो विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक हत्याकांड न हुए होते और लोगों को बेघरबार होकर दर दर न भटकना पड़ता। इस लिहाज से सामाजिक जिदगी में खलल न पैदा होता। इसके साथ ही गांधी की हत्या भी न होती। सांप्रदायिक दंगे होते जरूर पर वे अनिश्चितकाल तक न चलत रहते। आधिर सामाजिक जिदगी अपने ढर्रे पर लौट ही आती है। जिना की मृत्यु (1948) के साथ ही मुस्लिम लीग के भीतर स्थिति निश्चित रूप से बदल जाती। ज्यादा सभावना यही लगती है कि मुस्लिम बहुसंख्या वाले सभी प्रांतों में स्थानीय मुसलमान नेता खुदमुत्तार बनने की होड़ में लियावत अली खा (जिना के बाद नेता) के प्रभाव को चुनौती देते क्योंकि खा का इन प्रांतों में कोई जनाधार नहीं था। पटेल की मृत्यु (1950) के बाद कांग्रेस के भीतर और मुस्लिम लीग के साथ उसके संबंधों में नए शक्ति सतुलन पैदा हो सकते थे। दीर्घकालीन स्थिति के लिहाज से भारत एक संपूर्ण संघीय राज्य बन गया होता जहाँ मौजूदा राजनैतिक माडला (यानी भारत में एकदलीय शासन और पाकिस्तान में सैनिक शासन) के बजाय बहुदलीय व्यवस्था चल रही होती। इस समय दोनों देशों द्वारा रक्षा पर खर्च की जाने वाली भारी रकम आर्थिक विकास में लगती। भारत चीन के बीच एक तथा भारत और पाकिस्तान के बीच तीन युद्ध न हुए होते। इन युद्धों में मरे लोग आज जिंदा हाते और इन पर खर्च अरबों रुपए आम आदमी की जिदगी बेहतर बनाने में इस्तेमाल हाते। अल्पसंख्यकों से भेदभाव नहीं होता। सांप्रदायिक दंगे कम हो गए होते। जातिवादी हिंसा न रहती। पंजाब की मौजूदा समस्या जन्म न लेती। इंदिरा गांधी की हत्या न होती। न वे और न ही राजीव के भी दिल्ली की गद्दी पर काबिज होते।

(ङ) क्या कबिनेट मिशन योजना अव्यवहाय नहीं थी ? यह नेहरू के मजबूत केंद्रीयकृत राज्य के फलसफे अथवा पटेल की ब्राह्मणी पुनर्रूपानवादी धारणा के लिहाज से पूरी तरह अव्यवहाय थी। यह लोकतांत्रिक, संघीय और धमनिरपेक्ष दृष्टिकोण के आधार पर ही फलदायक होती। इसकी खामियाँ अमल की प्रक्रिया में दुस्त की जा सकती थीं।

(९) यही वे हालात थे जिनके गभ से 1947 के बाद के भारत न लिया। इन्हें समझे बिना हम भारत को ठीक से नहीं समझ सकते।

## सदभ

- 1 'महात्मा गांधी', स्टनले जास, अविगटन पॉवसबरो प्रेस, 'यूवाक, प० 5
  - 2 मुशी, मौयिक इतिहास प्रतिलेख सख्या 15, एन एम एम एल, 1ई दिन्ती, दीवान चमनलाल, मौयिक इतिहास प्रतिलेख सख्या 220, वही
  - 3 'हिस्टरी आफ फ्रीडम मूवमेट इन इंडिया', छट 3, प० 563
  - 4 'नेहरू—ए पालिटिकल बायाग्राफी', लदन, ओयूपी, 1959, पृ० 231
  - 5 जवाहरलाल नेहरू—ए बायोग्राफी', बबई, 1956, प० 268
  - 6 'ब्रिटन ऐंड मुस्लिम इंडिया', लदन, हीनमैन लि०, 1963, पृ० 143
  - 7 एस० आर० मेहरोत्रा, टुवडस फ्रीडम ऐंड पाटिशन', विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1977, पृ० 228 29
  - 8,9 और 10 'इंडिया वि'स फ्रीडम', दिल्ली, 1959
  - 11 मिशन विद माउटवेटन', राबट हाले लि०, लदन, 1952, पृ० 46
  - 12 हिंदुस्तान टाइम्स, 29 3 88, पृ० 11
  - 13 प्राचीन भारत मे साहित्यिक और राजभाषा होने के आधार पर ससृजत को सविधान म राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दन की दलील इसलिए सरासर पक्षातपूण लगती है क्योंकि फारसी और अपभ्रंश को यह दर्जा नही दिया गया । व भी क्रमश मध्यकालीन भारत और अशोक के युग म साहित्यिक और राजभाषाएं रही है ।
  - 14 'फ्रंटियर पोस्ट', पेशावर जिसे 'हिंदू' ने 29 11 87 के अक मे प० 1 पर उद्धृत किया ।
  - 15 'द लास्ट यियस आफ ब्रिटिश इंडिया', लदन, कसल, 1963
  - 16 '1947 म बंगाल के बटवारे से करीब 40 लाख हिंदुआ को पूर्वी बंगाल छोडकर भारत आना पडा और करीब 10 लाख मुसलमाना को, जिनमे ज्यादातर बिहारी थे, भारत छोडकर पूर्वी बंगाल जाना पडा । इस भावाजाही म लगभग आठ लाख लोग कत्ल कर दिए गए ।' ( डिसेम्बरमट आफ पाकिस्तान', जगदेव सिंह ब्रिग, लासर इंटरनेशनल, नई दिल्ली 1988, प० 23)
- उधर पंजाब क्षत्र मे "मारे गए या घायल हुए लोगो की सख्या अनगिनत थी । अत्यधिक अनुमान के अनुसार एक या दो लाख लोग मारे गए यायाघीश जी० डी० खोसला ने यह आकडा पाँच लाख आका है । ब्रिटेन के दो प्रमुख इतिहासकार मौतो की तादाद दो स ड़ाई लाख के बीच आकत है शरणाधियों की सख्या 105 लाख थी । ('फ्रीडम एट मिडनाइट', नई दिल्ली, 1976, पृ० 342)

## अध्याय-द्वितीय

### भारत की सामाजिक व्यवस्था

#### 1 व्यवस्था, राज्य, राष्ट्र और जनता के बीच संबंध

भारतीय सामाजिक व्यवस्था स अभिप्राय है भारत का राष्ट्र राज्य । राष्ट्र का मतलब है आधुनिक राज्य के रूप में संगठित जनता (उसी तरह जैसे कबीला शब्द किसी प्राचीन राज्य के रूप में संगठित जनता के अर्थों में इस्तमाल किया जाता था) । हर कोई राज्य सबसे बड़ी संगठित सामाजिक इकाई होती है जिसे उस जमाने की जनता (जो छोटी छोटी सामाजिक इकाइयों में भी बटी होती है, जैसे कि मौजूदा वक्त में पार्टियाँ, ट्रेड यूनियन, बग, धार्मिक संप्रदाय, जातिवाद, परिवार और व्यक्ति) अपनी सामाजिक पूँजी (मानवीय और टेक्नोनाजिकल दोनों) को क्रियाशील बनाने और विकसित करने के लिए स्थापित करती है । राज्य अमूमन (अपवादों को छोड़कर) अपने सविधान और 'यायशास्त्र के जरिए अपने इलाके के भीतर सभी सामाजिक इकाइयों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है । अमूमन अपनी जनता या उसकी बहुसंख्या के हितों का प्रतिनिधित्व न करने वाला कोई राज्य ज्यादा देर टिका नहीं रह सकता । मौजूदा दौर में राष्ट्र राज्य मौजूदा सामाजिक व्यवस्था का भी प्रतीक है (उसी तरह जैसे कबीलाई राज्य कबीलाई सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक हुआ करता था) ।

#### 2 राज्य और सरकार के बीच अंतर

भारतीय राष्ट्र राज्य को भारतीय सविधान और 'यायशास्त्र के आधार पर एक निश्चित काल तक चुनी गई प्रतिनिधि सरकार (यानी केंद्रीय कार्यपालिका) चलाती है । कोई सरकार अपनी नीतियों को लागू करने और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए शांतिपूर्ण और गैर शांतिपूर्ण दोनों तरीकों का इस्तेमाल करती है । सरकार हालांकि राज्य का ही एक अंग है पर मूल रूप से वह उसकी अगुआ सामाजिक इकाई (हमारे दौर में राजनैतिक पार्टियों) के हितों का और फिर उसके समर्थक गुटों का प्रतिनिधित्व करती है । जाहिर है, राज्य और सरकार के बीच अंतर है । राज्य मुख्य रूप से धारणात्मक अभिव्यक्ति है जबकि सरकार मुख्य रूप से क्रियात्मक होती है । इस अंतर की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए ।

#### 3 पार्टियों तथा पर आधारित सरकार व्यवस्था

भारत की सरकार व्यवस्था राजनैतिक पार्टियों के जरिए चलती है । ये पार्टियाँ माल के श्रम विभाजन और उससे जुड़ी औद्योगिक टेक्नोलॉजी के अनुरूप पैदा हुई हैं । इनमें से हरेक अपने सैद्धांतिक व व्यावहारिक ज्ञान के अनुसार भारत राष्ट्र को आधुनिक बनाने या उसका पूँजीकरण करने की धारणा का पक्षपोषण करती है ।

#### 4 भारतीय राष्ट्र राज्य—एक पंचमूली प्रक्रिया

(क) भारतीय राष्ट्र राज्य अमूमन अदरुती और बाहरी दो स्तरों पर प्रिया शील है जा अंतरसंबंधित और अंतरनिभर है। अदरुती स्तर पर इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तितरफा प्रक्रिया की घासियत है जबकि बाहरी स्तर पर यह कूटनीति सह प्रतिरक्षा की दोतरफा प्रक्रिया से संपन्न है।

(ख) राजनीति एक आधुनिक राज्यतंत्र में प्रियाशील संबंधानिक, सरचनात्मक और प्रशासकीय विचारों, गतिविधियों, सबधा व सस्याओं को व्यक्त करती है। अथव्यवस्था मानवीय और भौतिक ससाधनों के उत्पादन व वितरण में प्रिया शील विचारों, गतिविधियों, सबधा व सस्याओं के संचालन और प्रबंधन को अभिव्यक्त करती है। सस्कृति लोगों की जीवन शैली में प्रियाशील नैतिक, आचार-व्यवहार सबधी और सौंदर्यपरक विचारों, गतिविधियों, सबधा व सस्याओं को परिभाषित करती है। कूटनीति सह प्रतिरक्षा एक तरफ विदेश नीति और दूसरी तरफ रक्षा नीति की द्योतक है।

(ग) राजनीति, अथव्यवस्था, सस्कृति और कूटनीति सह प्रतिरक्षा अंतर संबंधित, अंतरनिभर और अटूट प्रक्रियाएँ हैं क्योंकि ये सभी एक विशिष्ट सामाजिक श्रम विभाजन और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के अनुरूप जन्म लेती हैं। वे समान महत्त्व की हैं और उनमें सहरव किसी समय विषाप में मूल भूमिका अदा करती हैं जबकि बाकी गौण स्थिति में होती हैं। इस तरह, सभी राजनीति, सभी अथव्यवस्था, सभी सस्कृति और सभी कूटनीति सह प्रतिरक्षा अगुआ स्थिति में आकर बाकियों को दिशा देती हैं। दुनिया में कोई ऐसा राज्य नहीं जो स्थायी तौर पर राजनीति या अथव्यवस्था या सस्कृति या कूटनीति-सह प्रतिरक्षा नीति से दिशा हासिल करता हो।

#### 5 भारत की सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता

भारतीय सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता यह है कि इसका राज्यतंत्र पश्चिमी उदारवादी मॉडल पर आधारित है (यह बात बहुदलीय तंत्र के चलने से स्पष्ट है), इसकी अथव्यवस्था कुछ-कुछ रूसी मॉडल से मिलती जुलती अति नियंत्रित अथवा अफसरशाही नियोजन पर डली है (यह बात अथव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र की प्रभावशाली स्थिति से स्पष्ट है), इसकी सस्कृति धर्मों-मुख्य धमनिरपेक्षता पर आधारित है (यह बात उस सरकारी अवधारणा से स्पष्ट है जिसका दावा सभी धर्मों को समान स्तर पर रखने का है), तथा इसको कूटनीति सह प्रतिरक्षा नीति की दिशा दक्षिण एशिया में प्रभुत्वकारी स्थिति हासिल करने की है (यह बात पड़ोसी देशों से इसके तनावपूर्ण सबधों और श्रीलंका के प्रति इसकी मौजूदा नीति से स्पष्ट है)।

#### 6 इस व्यवस्था के बारे में प्रमुख सवाल

(क) भारत की सामाजिक व्यवस्था के बारे में गौरतलब प्रमुख सवाल यह

है कि 41 साल के दौरान इस व्यवस्था और इसकी उत्तरोत्तर सरकारों ने क्या ठोस नतीजे हासिल किए हैं। इस सवाल को भारत की सामाजिक व्यवस्था के चार मुख्य क्षेत्रों (यानी राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कूटनैतिक सह प्रतिरक्षात्मक) के संदर्भ में तैयार करने के आधार पर ही ठीक तरीके से हल किया जा सकता है। इसके मुताबिक (i) क्या वादे किए गए थे (यानी सिद्धांत) और उन पर कितना अमल हुआ (यानी व्यवहार), (ii) इसी प्रकार के दूसरे देशों के मुकाबले इसकी उपलब्धियाँ कितनी रही, तथा (iii) भारतीय जनता ने इसके लिए कितना मूल्य चुकाया ?

(ख) अगले चार अध्यायों में इस अवलोकन प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही हम भारत की सामाजिक व्यवस्था और इसकी उत्तरोत्तर सरकारों की उपलब्धियों और खामियों को जानने की स्थिति में होंगे।

### संदर्भ

- 1 राष्ट्रीयता उस कहते हैं जो अपना राज्य स्थापित करने की प्रक्रिया में हो या जिसने किसी राष्ट्र राज्य के भीतर उप राष्ट्रीय दर्जा स्वीकार कर लिया हो, उसे कि बहुत सी राष्ट्रीयताओं ने भारत में कर लिया है।

## अध्याय तीन भारतीय राज्यतंत्र

इससे अभिप्राय 1947 उपरांत भारत के संवैधानिक, संरचनात्मक और प्रशासकीय विकास की प्रक्रिया से है।

### 1 सविधान

(क) संवैधानिक तौर पर, भारतीय सविधान वह मूल संहिता है जिसके आधार पर भारत का शासन चलता है अथवा यह भारतीय राज्य के मूल सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है।

(ख) सविधान की प्रस्तावना का आगाज इन शब्दों से होता है 'हम भारतीय लोग भारत का वनान का सर्वरूप सेते हैं।' इसका मतलब है कि भारतीय सविधान यहाँ की जनता की सहमति अथवा मौन सम्मति के आधार पर बना है। लेकिन हकीकत यह है कि इस सविधान के लिए न तो जनमत संग्रह और न ही पूण मताधिकार वाले सीधे चुनाव के जरिए भारतीय जनता की राय ली गई है। इस सविधान सभा न बनाया था जो पूरी तरह प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। उसमें राजवाड़ा रियासतों के नामजद प्रतिनिधियों के अलावा बाकी सदस्य गुल वालिग मताधिकार के करीब एक तिहाई पर आधारित प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से चुन गए थे। सविधान की रूपरेखा मुख्यतः भारत सरकार के 1935 के अधिनियम पर आधारित है। दरअसल इस कांग्रेस पार्टी का एक दस्तावेज कहा जा सकता है।

(ग) सुप्रीम कोर्ट की राय में सविधान की प्रस्तावना ही उसकी प्राणात्मा है। लेकिन यह प्राणात्मा कतई स्पष्ट नहीं है। सविधान अपनी प्रस्तावना में दज नौ मूल सिद्धांतों—प्रभुसत्तासंपन्न, समाजवादी, धमनिरपक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र, याय, आजादी, समानता और भ्रातृत्व में से किसी की भी कही व्याख्या नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनमें किसी मूल सिद्धांत को स्पष्ट नहीं किया है।

(घ) संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय सविधान की पांच मूल अभिधारणाएँ हैं। ये हैं—संघीय व्यवस्था, धमनिरपक्षता, समाजवाद, ससदीय लोकतंत्र और यायिक समीक्षा लेकिन समूचे सविधान में संघीय व्यवस्था का कही जिक्र नहीं है, पहले अनुच्छेद में भारत को 'राज्या का एक संघ' घोषित करके इसे संघीय सविधान जरूर बनाया गया है। पहले 25 साल तक तो इसमें 'समाजवाद' और धमनिरपेक्ष शब्द भी दज नहीं थे और अब उन्हें शामिल किए जाने के 13 साल बाद भी इसमें अस्पष्टता ज्यों की त्यों बरकरार है।

(ङ) सविधान के चौथे भाग में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की श्रेणी में

अनेक सभतावादी सिद्धांत दज हैं जो जनता को 'याय प्रदान करने के लिए तो लागू नहीं होते पर 'देश का शासन चलाने के लिए बहुत जरूरी है।' फिलहाल वे महज दिवावटी चीजें ह।

(घ) सविधान का पांचवा भाग (अध्याय 1) सारी सत्ता का केंद्र प्रधान मंत्री का बनाता है। इसके जलावा यह ससद की अनदेखी करवे राष्ट्रपति के नाम पर अध्यादेश जारी करन का अधिकार भी (अध्याय 3) मन्त्रिमंडल को देता है। प्रधानमंत्री और मन्त्रिमंडल का सत्रशक्तिमान बनाकर यह ससद और यायपालिका को कायपालिका के व्यापक अधिकारों पर अकुश लगा पाने म असमथ बना देता है। यह राष्ट्रपति के कामकाज की कोई स्पष्ट व्याख्या न करके उस ससदीय परंपराओं के सहार छाड देता है।

(छ) सविधान का छठा भाग (अनुच्छेद 163) राज्य विधायिका या राज्य सरकार के मामल म स्वनिणय का जतिम अधिकार राज्यपाल को देता है। यह अलोक-तांत्रिक मानदंड है जो एक नामजद व्यक्ति को निर्वाचित प्रतिनिधियों से भी ऊपर स्थान देता है।

(ज) नौवां भाग (अनुच्छेद 245 63), जो ससद को राज्य सूची वाले मामला मे कानून बनाने का अधिकार देता है और पहली व तीसरी सूची म अनुल्लिखित बाकी अधिकारों का भी ससद को ही सौंपता है, सत्ता का केंद्रीयकरण करके भारत की सधीय व्यवस्था को नाममात्र की बना देता है।

(झ) सतरहवा भाग (अनुच्छेद 343 44), जा हिंदी को भारत की सरकारी भाषा घोषित करता है, वास्तविकता के प्रतिकूल है। हकीकत मे अंग्रेजी और हिंदी दानो सरकारी भाषाओं के तौर पर इस्तेमाल हो रही है और यही इस समस्या का एकमात्र उचित समाधान है।

(ञ) अठारहवा भाग (अनुच्छेद 352 60) तीन किस्म की इमरजेंसी की कल्पना करते हुए केंद्र को असीम अधिकार प्रदान करता है तथा इस तरह लोगों को सभी मूल अधिकारों और राज्यों को सभी वैधानिक अधिकारों से वंचित करता है।

(ट) बहुसंख्यक समुदाय के कुछ रीति रिवाजों (देखें पृ० 18) को सर्वैधानिक दर्जा दना सविधान द्वारा उस समुदाय की तरफदारी और सविधान की धमनिरपक्षता की धर्मों मुख प्रकृति का ही दर्शाता है।

(ठ) सविधान की मूल त्रुटि यह है कि सत्ता को शासनाध्यक्ष के हाथों मे अति केंद्रित करके यह सभी प्रकार की सरकारी गतिविधियों म जनता की भागीदारी और सरकार की जनता के प्रति (चुनाव प्रक्रिया का छोड) जवाबदेही की पूरी तरह अनदेखी करता है।

## 2 सरचना

सरचनात्मक तौर पर, 1947 उपरांत भारतीय राज्यतंत्र कायपालिका, विधायिका और यायपालिका के तीन सरकारी अंगों के साथ साथ प्रेस और दलीय



प्रणाली के दो गैर सरकारी अंगों से गठित है। कायपालिका राज्य का वह अंग है जिस पर सविधान और दूसरे कानून लागू करा जायेगी जिम्मेदारी होती है। विधायिका का काम राज्य के लिए कानून बनाना है जबकि कायपालिका का उत्तरदायित्व काय प्रदान करना है। प्रेस सभी अद्यतन और पत्रिकाओं को दिया गया सामूहिक नाम है। दलीय प्रणाली में राजनैतिक दल आते हैं जिन्हें से हरेक दल विशिष्ट कायक्रम और नीतियों पर आधारित लोगों के एक समूह से गठित होता है। लोकसभा में बहुमत वाला दल कायपालिका का काम अंजाम देता है। कायदे के मुताबिक राज्य के तीनो अंग समान महत्व के होना चाहिए पर हकीकत में कायपालिका प्रमुख हैसियत अर्हियार करती है और प्रधानमंत्री सत्ता का केंद्र होता है जिससे राज्य के सभी अंगों के लिए उसका अनुकरण करने की स्थिति बन जाती है।

### 3 प्रशासकीय प्रक्रिया

प्रशासकीय तौर पर, 1947-उपरांत भारतीय राज्यतंत्र की प्रक्रिया शुरू हुए अब 41 वर्ष हो गए हैं। इस दौरान आठ राष्ट्रपति और छह प्रधानमंत्री विभिन्न मौकों पर दो सर्वोच्च कार्यकारी पदों पर विराजमान रहे हैं। भारतीय जनता ने अलग-अलग समय पर आठ लोकसभाएं चुनीं। ससदीय क्षेत्र में अमूमन कांग्रेस ही छापी रही। सिर्फ 1977 और 1980 के बीच के छोड़े अर्थात् में जनता पार्टी करीब ढाई साल तक कुर्सी पर रही। भारत में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू (कांग्रेस) लगातार 16 वर्ष (1947-1964) तक इस सर्वोच्च कार्यकारी पद पर बने रहे। उनकी मृत्यु के बाद लालबहादुर शास्त्री (कांग्रेस) उनका उत्तराधिकारी बने। 1966 शुरू होते ही वे भी चल बसे। तब नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी (कांग्रेस) प्रधानमंत्री बनीं और 1966 से 1977 तक इस पद पर रही। 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार के बाद पहले जनता पार्टी के मोरारजी देसाई (1977-79) और फिर जनता पार्टी से ही अलग हुए एक गुट के चरणसिंह (1979-80) इस पद पर विराजमान हुए। 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस की जीत से इंदिरा गांधी फिर सत्ता में आईं और 1984 में उनकी हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने आठवीं लोकसभा के चुनाव में इस पद की बागडोर संभाली।

### 4 पूर्व 1947 के राज्यतंत्र से तुलना

(क) पीछे की ओर झाँकें तो पूर्व 1947 भारतीय राज्यतंत्र ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत सिर्फ 30 फीसदी भारतीय जनता को मताधिकार दे रखा था (1919 के अधिनियम के तहत ऐसे 7 फीसदी ही लोग थे)। केंद्रीय विधानसभा के अधिकार सीमित थे। ब्रिटिश राज के कार्यकारी प्रतिनिधि वाइसरॉय के पास बीटो अधिकार हुआ करते थे। भारत का प्रशासनिक बटवारा किसी युक्ति

संगत सिद्धांत पर आधारित नहीं था। प्रात बहुभाषायी थे और 565 देशी रियासतों में रजवाड़ों का राज था। न्यायपालिका अद्ध स्वतंत्र थी क्योंकि 'यायाधीश वाइसराय के रहमोकरम पर ही पद पर टिके रहते थे। राजनैतिक दलों में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, फारवर्ड ब्लाक, अकाली दल आदि प्रमुख थे। कुछ पावदियों सहित प्रेस अमूमन आजाद था।

(ख) पूर्व-1947 पृष्ठभूमि में परखें तो 1947 उपरांत भारतीय राज्यतंत्र का कामकाज—यानी सबके लिए मताधिकार, ससद की वैधानिक प्रभुसत्ता, न्यायपालिका की ससद के प्रति जवाबदेही, न्यायपालिका की आजादी, बहुदलीय व्यवस्था और जागरूक प्रेस की भूमिका, रजवाड़ा रियासतों का भारत सघ में विलय, पश्चिम पाकिस्तान से आए लाखों शरणार्थियों का पुनर्वास, राज्यों का भाषायी आधार पर पुनर्गठन आदि निश्चय ही राजनैतिक उपलब्धिया हैं।

### 5 भारतीय राज्यतंत्र के मूल्यांकन की कसौटी

भारतीय राज्यतंत्र के कामकाज का मूल्यांकन करते वकत एक ही इकाई के भूत और वतमान की तुलना कोई ज्यादा कारगर कसौटी नहीं है। इस आधार पर भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का यह दावा बिलकुल उचित था कि उसने अपने पूर्ववर्ती मुगल राज्यतंत्र के मुकाबले उच्च स्तर का राज्यतंत्र विकसित किया है पर भारतीय जनता ने इस ब्रिटिश दावे को भारत की सामाजिक उन्नति का मूल्यांकन करने की उचित कसौटी नहीं माना। भारत की आजादी की मांग इस मूल्यांकन पर आधारित थी कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय जनता के नहीं बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी है, यह तानाशाही, उपनिवेशी शासन भारत के मानवीय एवं भौतिक स्रोतों को भारत के नहीं बल्कि ब्रिटेन के हितों में इस्तेमाल करता है, तथा इस प्रकार वह भारत को (राजनैतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक तौर पर) विकसित करने और उसकी अतर्निहित शक्ति को वास्तविक रूप देने में अक्षम है। जाहिर है उपनिवेशी शासन पर लागू की जाने वाली कसौटी राष्ट्रीय राज्यतंत्र पर लागू नहीं की जा सकती और राष्ट्रीय राज्यतंत्र का मूल्यांकन उससे उपनिवेशी शासन की तुलना करके नहीं किया जा सकता। तबसंगत रूप से, 1947-उपरांत भारतीय राज्यतंत्र को परखने का उचित मापदंड एक तितरफा कसौटी ही हो सकती है (जसे कि अध्याय 2, उपशीर्षक 6 में बताया गया है)। यानी (i) क्या वादे किए गए थे और उन पर कितना अमल हुआ, (ii) इसी प्रकार के दूसरे राज्यतंत्रों की तुलना में इसकी उपलब्धिया कितनी रही, और (iii) भारतीय जनता ने इसके लिए कितना मूल्य चुकाया।

### 6 संविधान के मूल उद्देश्यों की पूर्ति— भारतीय राज्यतंत्र की असल परीक्षा

इस तरह भारतीय राज्यतंत्र और इसके विभिन्न अंगों को उपरोक्त षट

पर परखने के लिए हम इसका मूल उद्देश्य में शुरुआत करते हैं। ये मूल उद्देश्य गद्यों में भारतीय संविधान में मिलते हैं। इसका कहा गया है कि 'हम भारतीय समाज भारत को एक प्रभुसत्तासंपन्न, सामताप्रिय, समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाए और अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचारों, अभिप्रायों, आस्था, धर्म व श्रद्धा की आजादी, एवं व अयोग्यता की समाप्ति प्राप्त तथा उच्च धरातल को बढ़ावा देकर व्यक्ति व गौरव और राष्ट्र की एकात्मता सुनिश्चित बनाए का स्वल्प सेते हैं।' संवैधानिक तौर पर हालांकि इन मूल उद्देश्यों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, फिर भी ये हम यह परखने में सहायता करते हैं कि भारतीय राज्य तंत्र के विभिन्न संरक्षकों और गैर-संरक्षकों अंगों के किस हद तक भारतीय संविधान की मूल भावना को अमल में उतारा है।

## 7 कायपालिका

(क) उक्त संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पहली पूरक शक्त यह है कि लोकतांत्रिक ढांचे और व्यवहार वाला एक सुगठित शासन दल है। जाहिर है अगर शासक दल सगठन, साच और अमल में साचमुच लोकतांत्रिक संस्था की तरह नहीं चलता तो उक्त विचार भी उद्देश्य की ईमानदारी से पूर्ति नहीं हो सकती। और इस संबंध में हम पाते हैं कि 1950 में पटेल की मौत के बाद नहरू ने कांग्रेस के अंदर बहस और वाद विवाद खत्म करने की शुरुआत की। उन्होंने 1951 में पुरुषोत्तम दास टंडन (पटेल समर्थक नेता) को कांग्रेस अध्यक्ष पद में इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया और खुद प्रधानमंत्री के साथ-साथ पार्टी अध्यक्ष भी बन गए। इसका बाद उनके जीवन काल में बनने वाले सभी कांग्रेस अध्यक्ष, उनकी बड़ी इंदिरा गांधी समेत, नेहरू के ही करीबी सहायक थे। कांग्रेस में आंतरिक पार्टी लोकतंत्र की धीरे-धीरे खाली के साथ ही नतीजा था कि 1950 के दशक के अंत में राजगोपालाचारी नेहरू की साया सेती की नीति का विरोध करने के लिए कांग्रेस के भीतर असंतुष्टों को इकट्ठा करने के बजाय स्वतंत्र पार्टी बनाने का वाध्य हुए। फिर 1963 में कामराज योजना के तहत मोरारजी देसाई समेत कई मंत्रियों को हटाना असंतुष्टों का कमजोर करने के लिए नेहरू की ही एक चाल थी। लालबहादुर शास्त्री ने भी अपने सीमित तरीके से मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी से सरीसे असंतुष्ट गुटों को कमजोर करने के लिए कमोबेश यही रुख अपेक्षित किया। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के भीतर मत भेद रखने के अधिकार को विलकुल ही खत्म कर दिया, अपनी सत्ता का चुनौती दे रहे सभी लोगों (कामराज देसाई, अतुल्य घोष, पाटिल निजलिंगप्पा आदि) को निकाल बाहर किया कांग्रेस को दो बार (1969 और 1978 में) तोड़ा पार्टी में चुनाव कराने (1973 से 1984) बंद कर दिए और कांग्रेस पदाधिकारियों को नामजद करने का तरीका अपनाया। इस तरह इंदिरा गांधी की बनाई गई कांग्रेस व्यक्ति का तमाशा बन गई। राजीव ने कांग्रेस की व्यक्ति पूजा की संस्कृति को

और आगे बढ़ाया। वे निजी प्रभुत्व की ज्यादा लालसा रखने लगे और मतभेदा के प्रति ज्यादा असहनशील हो गए।

(घ) सर्वैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दूसरी पूव शत यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के लिए दो दलों का विकल्प हो। यानी शासक दल का व्यवहार राष्ट्रीय विकल्प हो। जाने माने ब्रिटिश सर्वैधानिक वकील आइवर जेनिंग्स के मुताबिक, 'विपक्ष का होना भी लगभग सरकार जितना ही महत्वपूर्ण है। विपक्ष क बिना लोकतंत्र नहीं होता। वह लोकतांत्रिक राजनैतिक प्रक्रिया का निश्चित और आवश्यक अंग है।' इस सबध में भी हम पाते हैं कि नहरू ने ही विपक्षी पार्टियों पर भारत की तरफकी के रास्त में रखावट डालने में मिथ्यारोपी की बरसात करके (जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी एस की दलाल, जनसघ प्रतिक्रियावादी और स्वतंत्र पार्टी अमेरिका समर्थक गुट है) और फिर 1959 में बेरल की बहुमत वाली कम्युनिस्ट सरकार अस्थिर बनाने (वहाँ एक आंदोलन को गुप्त शह देकर) के बाद बर्खास्त करके विपक्ष को असहनीय मानने की शुरुआत की। इससे पहले 1954 में उन्होंने तत्कालीन पेंसू राज्य की अकाली सरकार को बर्खास्त कर दिया था। इंदिरा गांधी ने हमेशा विपक्ष पर राष्ट्रविरोधी, जनविरोधी और महज 'इंदिरा हटाओ' में दिलचस्पी रखने का आरोप लगाया। वे हमेशा एक या दूसरे विपक्षी दल को फुसलाकर या दबाकर खत्म करने की ताक में रहती थीं। उनके शासनकाल में विभिन्न राज्यों की विपक्षी सरकारों का बर्खास्त किया जाना (मसलन 1969 में बंगाल, 1983 में जम्मू कश्मीर और आंध्र आदि) आम बात थी। मुठभेद की उनकी नीति में विभिन्न लोकतांत्रिक सस्थाओं खास कर दलीय प्रणाली का गंभीर नुकसान पहुँचाया है। राजीव ने मुठभेद की इस नीति को जोर शोर से आगे बढ़ाया है। उन्होंने 1984 का अपना चुनाव अभियान इस आरोप से शुरू किया कि विपक्ष की सिख उग्रवादियों से साठगाठ है। तबसे वे अनगिनत बार विपक्ष को नम और गम छीने से पीटते आए हैं (कई बार उन्होंने अवज्ञाकारी विपक्षी सरकारों गिराने की धमकी दी और कई बार उन्हें बातचीत के लिए बुलाया)। उनका मकसद भारत में एक दल के प्रभुत्व वाली व्यवस्था और शासक दल के भीतर एक व्यक्ति का प्रभुत्व बनाए रखना है।

(ग) सर्वैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक और पूव शत यह है कि निचले स्तर पर नीति बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी हो। इस सबध में हम पाते हैं कि पहले नहरू और फिर जनता पार्टी के मोरारजी देसाई और लोकदल के चरणसिंह समेत उनके सभी उत्तराधिकारियों ने इस लोकतांत्रिक पूव शत की अनदेखी की। इस सिलसिले में तीन बातें काविलेगीर हैं। पहली, संविधान में चुनाव के समय को छोड़ कर ही राजनैतिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी की गारंटी नहीं दी गई है। दूसरी 1947 के बाद की हर सरकार ने लोगों को राजनैतिक प्रक्रिया से बाहर रखा है। तीसरी, निश्चित तिथि गुजर जाने के बाद भी वर्षों तक पंचायतों और स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं कराए जाते।

(घ) सर्वधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक ओर पूव शत यह है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और निष्पट वनें। इस संबंध में हम पाते हैं कि नेहरू की अगुआई में कांग्रेस ने ही चुनाव प्रक्रिया में सबसे पहले सांप्रदायिकता, जात-पात और धन गुंडो प्रशासन के त्रिकोण के तत्त्व दायित्व लिए। उम्मीदवारों के चयन में कांग्रेस ने उनकी जीतने की क्षमता का ही एतमात्र कसौटी माना और अभी भी यही सिल सिला चला आ रहा है। किसी उम्मीदवार की जाति और धर्म को उसके चरित्र में भी महत्वपूर्ण समझा गया और अभी भी समझा जाता है। चुनावी जीत मुख्य तौर पर जाति धर्म और धन एवं गुंडा शक्ति के आधार पर ही तय हो गयी। इस चुनाव प्रक्रिया को इंदिरा कांग्रेस से और प्रोत्साहन मिला तथा राजीव के शासन में यह अपने पूरे शवाब पर है। इस प्रक्रिया को जारी रखने में विपक्ष का भी कुछ योगदान है क्योंकि वह भी कई बार कांग्रेस के इन तरीकों की नकल करता है। इस तरह भारत में हर स्तर पर चुनाव प्रक्रिया बहुत दृढ़ तक सांप्रदायिकता, जात पात, पक्ष और अपराधी तत्वों से प्रभावित है। ऐसी चुनाव प्रक्रिया को वायू में रखने और इसकी अगुआई के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस इ कट्टरवाद के प्रति आम तौर पर और बहुसंख्यक समुदाय के कट्टरवाद के प्रति खास तौर पर तुष्टिकरण की नीति अपनाती है। आमतौर पर कट्टरवाद को खुश करने के प्रयास में वह भिड़रावाले या दमाम बुखारी जैसे धार्मिक अल्प संख्यकों के नेताओं से साठ गाठ करती है अथवा अकाली दल या मुस्लिम लीग से गठ जोड़ करती है। पर बहुसंख्यक समुदाय के कट्टरवाद को खुश करने के लिए वह अक्सर अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति भेदभाव की नीति अख्तियार करती है। इसका नतीजा यह होता है कि अल्पसंख्यक समुदाय अलग थलग पड़ जाते हैं पंजाब जसी अलगाववादी समस्या या राम जममूमि वावरी मस्जिद जस विवाद उठ उठे हाते हैं और इस तरह राष्ट्रीय एकता कमजोर पड़ती है।

(ङ) सर्वधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक ओर पूव शत यह है कि उच्च पदों पर भ्रष्टाचार बंद हो। इस संबंध में भी हम देखते हैं कि नेहरू ने ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पदा को किसी भ्रष्टाचार विरोधी पंचाट के दायरे में नहीं आने दिया। उन्होंने चोरवाजारिया को चोराहे पर फासी लटकाने की लच्छेदार बातें बघा रने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कारगर कदम नहीं उठाया। इतना ही नहीं, नेहरू ने उन सभी लोगों (प्रताप सिंह कैरो बड्डी गुलाम मुहम्मद और बीजू पटनायक) को सरक्षण दिया जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के प्रति शास्त्री ने बतौर गृह मंत्री उनका ध्यान खींचा था। उन्ही के शासनकाल में लदन में तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त वृष्ण मनन से संबंधित 1950 के जीप घोटाले का मामला 1955 में बिना किसी को दोषी ठहराए बंद कर दिया गया। उन्होंने वृष्ण मनन को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के बारे में मौलाना आजाद की आपत्तियों को रद्द कर दिया। वे० ही० मालवीय ने जिन्हें भ्रष्टाचार के एक आराप में मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा, बाद में कहा कि 'उत्तर प्रदेश में मेरे राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी शास्त्री का नेहरू पर इतना

देवाय था कि उन्होंने मुझसे इस्तीफा माँग लिया।" और फिर, 1960 के आसपास जब आईबी द्वारा नेताआ और यडे व्यावसायिक घरानों के सबधों के बारे में जाँच से यह पता चला कि 36 कांग्रेस सांसद एव ही व्यावसायिक घरानों से पसा पाते हैं तो नेहरू ने कोई कारवाई नहीं की। इंदिरा गांधी के शासन में भ्रष्टाचार तो जिन्दगी का तौर-तरीका ही बन गया। उन्होंने यह कहकर भ्रष्टाचार का अप्रत्यक्ष समर्थन किया कि यह तो ऐतिहासिक होने के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है। यह रख उच्च पदों में भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनकी उपधापूण प्रतिश्रिया से झलकता है। ऐसे कई मामले हैं। मसलन विपक्षी दल द्वारा बसीलाल के खिलाफ दिया गया आरोपपत्र जिसमें यह आरोप भी था कि उन्होंने सजय गाँधी की मारुति परियाजना के लिए सस्ते दाम पर जमीन दी थी, ललितनारायण मिश्र और वाद में भजनलाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप, तुल मोहनराम वाला मामला, नागरवाला का मामला जिसमें उसने स्टेट बैंक के पचाची से इंदिरा के नाम पर 60 लाख रु० हासिल कर लिए थे और बाद में जिसकी मृत्यु रहस्यमय हालत में जेल में हो गई थी, सजय की मारुति कारकपनों के लिए भारी रकम जमा किए जाने के आरोप, कपनिया द्वारा कांग्रेस को दिया गया चंदा जिसके मुताबिक 1962 और 1968 के बीच कपनियों की ओर से 47 दलों को दिए गए 260 लाख में से 205 लाख रु० सत्तारूढ़ दल को ही मिले थे।<sup>1</sup> राजीव प्रशासन ने तो भ्रष्टाचार के सार रिक्काड मात कर दिए हैं। आए दिन वोफोस, एचडब्ल्यूडी पनडुब्बी सौदा, वेस्टलड हेलिकाप्टर आदि जैसे नए घोटाले सुनने को मिलते हैं। सबसे ताजा सबूत तो हाल ही का मानहानि विधेयक था जो असल में भ्रष्टाचार छिपाओ विधेयक बनता। इसका मकसद प्रेस का गला घोटना था ताकि वह शासक दल के कारनामों का भंडाफंड न कर पाए।

(च) सर्वधानिक उद्देश्या की पूर्ति के लिए एक और पूव शत यह है कि संविधान की जीवात्मा और राज्य कानूनों का कडाई से पालन हो। इस सबध में हम पाते हैं कि शासनाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे लगभग सभी लोगों और उनके अपने शासक दलों ने इस सिद्धांत के उलट मानदंड अपनाए हैं। पहली बात तो यह है कि जात पात, सांप्रदायिकता और धन गुंडा शक्ति की राजनीति अपनाकर हर शासक दल ने जनता में सांप्रदायिक चेतना जगाए रखी, राष्ट्र निर्माण की प्रश्रिया में बाधा डाली और इस तरह भारतीय संविधान व राज्य कानूनों का उल्लंघन किया। दूसरे, राज्याध्यक्ष सबधों स्वस्थ परंपराओं की अवहेलना करते हुए केंद्र में हर सरकार ने इस पद की गरिमा को धीरे धीरे कम करने में हिस्सा डाला है। नतीजतन, 1975 की इमरजेंसी की घोषणा पर तत्कालीन राष्ट्रपति ने किसी आज्ञाकारी की तरह आधी रात को दस्त-खत कर दिए इसके बाद 1979 में सजीव रड्डी और मारारजी के बीच तनाव और फिर 1987 में ज्ञानी और राजीव के झगडे ने स्थिति अधिक बिगाड दी, हाल ही में मास्को की एक सांस्कृतिक सभा में राष्ट्रपति वैक्टरामन ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन संदेश पढकर तो हास्यास्पद हालात पैदा कर दिए। इस तरह राष्ट्रपति पद को रख

स्टाफ बना दिया गया है। तीसरे, शासनाध्यक्ष के हाथों में पायकारी अधिकार का अधिवर्द्धन करके हरेक शासक दल ने प्रधानमंत्री को भारत का सर्वोच्च शासक बनाया है। नतीजतन, सभी मंत्री पिछलग्गू बनकर रह गए हैं। यह स्थिति उस धारणा से कतई मेल नहीं खाती जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री समान हैसियत वाले म प्रथम होता है। 1955-56 में वित्तमंत्री रहे सी० डी० देशमुख ने 1956 के अपने इस्तीफा म<sup>२</sup> नेहरू पर मन्त्रिमंडल से अव्यक्त और असंवैधानिक तरीके से पेश आने का आरोप लगाया था। इंदिरा गांधी ने मन्त्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत ही लगभग त्याग दिया (मसलन 1975 में मन्त्रिमंडल की मजूरी के बिना इमरजेंसी लगाने का फसला)। चौथे शासक दल के वफादार नेताओं को राज्यपाल मुखर करके और गए गुजरे नेताओं (मसलन ए०पी० जैन, रामलाल, वुमुदनेन जोशी, वसंतदादा पाटिल आदि) का दस पद पर बिठाकर हरकेंद्र सरकार ने अपनी नापसंदीदा राज्य सरकारों का पायकाल घटाने में राज्यपालों का दस्तेमाल किया है। सरकारिया आयोग द्वारा हाल ही में किए सर्वेक्षण से पता चलता है कि 1947 और 1984 के बीच मुखरर हुए राज्यपालों में 60 फीसदी अपनी नियुक्ति से पहले राजनीति में सक्रिय थे। पाचवें विभिन्न कांग्रेस सरकारों ने दिल्ली से मुख्यमंत्री नामजद करके भारतीय राज्य तंत्र की सघीय प्रणाली को कमजोर किया है। छठे, संगठित उद्योग पर धीरे धीरे अपना नियंत्रण बढ़ाकर जनता और लोकदल सहित सभी केंद्र सरकारों ने राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण किया है (इस समय 93 फीसदी संगठित उद्योग केंद्र के अधीन है जबकि राज्यों के पास महज 7 फीसदी रह गया है,<sup>3</sup> हालांकि गृह में रक्षा और उससे जुड़े उद्योगों को छोड़ उद्योग, वाणिज्य और व्यापार के सभी क्षेत्र राज्य सरकारों के दायरे में आते थे)। इस तरह उन्होंने भारत के सघीय राज्यतंत्र को कमजोर बनाया है। खासकर इंदिरा गांधी ने गैर कांग्रेस के राज्य सरकारों का तत्पता पलटकर और कांग्रेस के अपने नापसंदीदा मुख्यमंत्रियों को हटाकर भारत के सस्थागत सघीय ढांचे पर प्रहार किए हैं। सातवें सघ लोक सेवा आयोग की 1986-87 की सालाना रिपोर्ट और उससे पहले भी कई रिपोर्टों में दज उसकी 50 फीसदी सिफारिशें रद्द करके विभिन्न सरकारों ने इस वैधानिक सस्था का अवमूल्यन किया है। आठवें, प्रशासन के रोजमर्रा काम में दखल देकर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इस सस्था की निष्पक्षता को खत्म कर दिया है। नौवें, कांग्रेस के हरेक प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में अत्यधिक सत्ता सकेंद्रित करके अपने निजी सचिवालयों को केंद्रीय मन्त्रिमंडल और मुख्यमंत्रियों से ऊपर सविधानेतर सस्थाओं में बदल दिया। इंदिरा गांधी ने तो अपने बेटे सजय गांधी को भी यह स्तबा दे रखा था।

(छ) संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक और पूव शत यह है कि लोक नैतिकता के यथोचित मानदंडों का पालन हो। इस संबध में हम पाते हैं कि पुरानी शाही परंपराएं जारी हैं। पहली बात तो यह कि इन परंपराओं की अभिव्यक्ति सत्तारूढ़ कांग्रेस के द्वारा केंद्र में खानदानों को शासन स्थापित करने से होती है और अब तो

दूसरे दलों (मसलम लीगदल, नेशनल काँग्रेस, अनाद्रमुक, तेलुगुदेशम आदि) में भी यह रोग लग गया है। नेहरू ने ही 1959 में इंदिरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनवाकर इस प्रक्रिया की शुरुआत की। इसमें तब सेवानिवृत्त हो रहे अध्यक्ष यू० एन० डेवर ने इंदिरा को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करके उनकी सहायता की। इंदिरा को अध्यक्ष पद पर रहते हुए नेहरू ने 'अपनी नेता' बताने के लिए उन्हें बढावा दिया। इसके बाद नेहरू ने उन्हें अखिल भारतीय नागरिक परिषद की अध्यक्ष मनोनीत किया। यह सर्वोच्च राष्ट्रीय अखिल सरकारी सभा सरकारी नीतियों के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए 1962 में चीन-भारत सीमा युद्ध के बाद बनाई गई थी। युद्ध के बाद अपनी प्रतिष्ठा कम हो जाने के कारण वे इंदिरा को अपना उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा का स्पष्ट संकेत नहीं दे पाए। लालबहादुर शास्त्री ने जयप्रकाश नारायण को बताया था कि नेहरू अपनी बटी का उत्तराधिकारी बनाने की प्रयत्न इच्छा रखते हैं। मोरारजी देसाई ने भी इस बात की पुष्टि की है कि नेहरू ने अपने अंतिम दिनों में उन्हें यू० एन० डेवर के माध्यम से एक सदेश भेजा था जिसके मुताबिक अगर वे इंदिरा को उत्तराधिकारी मान लें तो मंत्रिमंडल में उन्हें दूसरा स्थान दिया जा सकता है।<sup>5</sup> बाद में इंदिरा गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री अपने छोटे बेटे राजीव को उत्तराधिकार के लिए तैयार किया और उनकी मृत्यु के बाद बड़े बेटे राजीव को इस काम के लिए प्रशिक्षित किया। दूसरे, पुरानी शाही परंपराओं की अभिव्यक्ति चापलूसी की नई संस्कृति के उदय से होती है जिससे कांग्रेस के भीतर और जनता में व्यक्तिपूजा का बल मिला। 'इंदिरा भारत है और भारत इंदिरा' का नारा संस्कृति की इसी भावना का सटीक प्रतीक है। तीसरे, पड़यंत्र और तिकड़म की राजनीति में भी इसकी अभिव्यक्ति मिलती है। इसी प्रकार की राजनीति के चलते इंदिरा गांधी ने 1969 में पहले राष्ट्रपति पद के लिए सजीव रेडडी के नाम का प्रस्ताव किया लेकिन बाद में अंतरात्मा की आवाज पर वोट देना का बहाना बनाकर उनका विरोध करते हुए वी० वी० गिरि का समर्थन किया। इसी प्रकार की राजनीति की झलक पहले इंदिरा और अब राजीव द्वारा अस्थिरता के खतरे की हाथ-तीखा मचाने से मिलती है। इसका मकसद विभिन्न मोर्चों पर अपनी विफलताओं से जनता का ध्यान हटाना रहा है। चौथे, इसकी अभिव्यक्ति कांग्रेस की काले धन पर निर्भरता में मिलती है जिससे भारत में चहुं ओर भ्रष्टाचार फला फूला है। पाचवें, इसकी अभिव्यक्ति सत्ता की बढ़ती भूख और उसे हासिल करने के लिए बेहद घृणित तरीकों के इस्तेमाल में मिलती है। इस सिलसिले में नेहरू ने ही यह परंपरा कायम की कि 'चाहे सतुलन खो बटों पर सत्ता से चिपके रहो'। 1963-64 के दौरान खुद उनकी यह स्थिति थी। इस शैली के मर्दनजर अब यह साफ दीखता है कि 1958 में प्रधानमंत्री पद छोड़कर पार्टी के लिए काम करने की नेहरू की घोषणा महज एक झुलावा थी। इंदिरा गांधी ने भी इसी परंपरा का पालन किया। छठे, इसकी अभिव्यक्ति सत्ताखंड दल के नेताओं के व्यवहार में मिलती है। राजीव गांधी का अपने आलोचकों को 'भोक्ते कुत्ते', सासदों को 'जोकर', विरोधियों को 'नानी याद करा



देंगे' कहना तथा विपक्षी मुद्दयमत्रिया को बर्खास्त करने की धमकी देना, मजदूर वर्ग का निकम्मा करार देना आदि व्यवहार के पतित मानदण्डों की स्पष्ट मिसालें हैं। सातवें इसकी अभिव्यक्ति निजी फायदे की ऐसी राजनीति में हुई है जिसका किसी आस्था या कायधर्म से कोई लेना देना नहीं है। विजयी पक्ष में शामिल रहना और 'आया राम गया राम' की राजनीति इसके ठास उदाहरण हैं।

(ज) सर्वधार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक और पूर्व शत यह है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो। इस संबंध में हम पाते हैं कि भारतीय संविधान सरकार का पांच साल बाद ही जनता के प्रति जवाबदेह मानता है। मामूली कायधर्मों के रूप में शुरुआत करने वाले कुछ नेताओं के ता दिना में धार-न्यारे हो जाते हैं। साइकिल जुटा पाने के बाविल न होना पर भी वे माफ़तियों और बगलों के प्रातिक्रम बन जाते हैं। लेकिन काइ भी उनकी संपन्नता के स्रोत की तहकीकात नहीं करता। कुछ अपवादों को छोटकर कोई भी नेता राजनीतिको की जनता के प्रति जवाबदेही के सिद्धांत में यकीन नहीं रखता। तदनुसार, यह प्रधानमंत्रिया में स किसी न भी पार्टी कापो का अनिवाय रूप से आडिट कराने का कानून नहीं बनवाया। न ही उन्होंने कोई ऐसा कानून बनवाया जिसके तहत सबंधापो भ्रष्टाचार के स्रोत काल धन पर जोरदार हतला घोला जा सके। जवाबदेही लोकतंत्र का वह आधार है जिसके तहत नागरिकों को समय समय पर विभिन्न राजनैतिक दलों के आचरण के बारे में फंसला करने का अधिकार होता है। वे सही फंसला तभी ले सकते हैं जब उन्हें नेताओं खासकर सरकार चलाने वाला की कायप्रणाली के बारे में पूरी जानकारी हो। पर वे उस सरकार से पूरी जानकारी कैसे पा सकते हैं जिसमें नेहरू से लेकर राजीव तक ने हर एक राष्ट्रपति को जानकारी पाने के अधिकार से वंचित रखा हो। सरकार ने जनता से सारी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने के लिए हमशा सरकारी गोपनीयता कानून और विधायिका (संसद और राज्य विधानमंडल) के विशेषाधिकारों की आड ली है। ये दोनों ही कानून राजनैतिक प्रक्रिया के लोकतंत्रीकरण में बाधा हैं।

(झ) सर्वधार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक और पूर्व शत यह है कि दमनकारी कानूनों से मुक्त माहोल बन जिसमें हमारे प्राकृतिक एवं मानवीय ससाधनों का भरपूर इस्तेमाल हो सके। इस संबंध में हम पाते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों और आजादी पर अक्रुश लगाने वाले काले कानूनों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। निवारक नजरबंदी कानून (1950) से लेकर आंतरिक सुरक्षा कानून (1971), विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधि निरोधक कानून (1974) कालाबाजारी निरोधक एवं आवश्यक वस्तु आपूर्ति कानून (1980) राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (1980), गुजरात समाज विरोधी गतिविधि निरोधक कानून (1985) आतंकवाद विरोधी कानून (1986), अस्पताल एवं अन्य संस्थान संबंधी कानून (1987), 59वां संविधान संशोधन कानून (1988) आदि इसकी जीती जागती मिसालें हैं। इसके विपरीत उपनिवेशी शासन साम्राज्य दंड संहिता के अलावा कभी कुमार एक सा दो

नजरबंदी कानूनों से ही काम चलाता था। काले कानूनों की प्रक्रिया की शुरुआत नेहरू ने निवारक नजरबंदी कानून बनवाकर की। इंदिरा गांधी ने कई काले कानून बनाकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और अब राजीव इसे नया आयाम दे रहे हैं। नजरबंदी कानूनों की ऐसी भरमार क्या हो गई है? इसलिए कि 1947-उपरात भारत में अपराध बढ़ गए हैं। सांप्रदायिक, जातिवादी और धन गुंडा शक्ति के तीर-तरीको व प्रचलन से राजनैतिक प्रक्रिया का अपराधीकरण हो गया है।<sup>6</sup> समांतर अर्थव्यवस्था (यानी काले धन की अर्थव्यवस्था) व जन्म लेने से आर्थिक प्रक्रिया का अपराधीकरण हुआ है। यह समांतर अर्थव्यवस्था तस्कारी धाखाघड़ी, चोरवाजारी, कम या अधिक बीजक बनाने विदशी मुद्रा नियमन कानून के उल्लंघन, कर चोरी आदि जैसी आपराधिक गतिविधियों पर टिकी हुई है। यहां तक कि आचरण और व्यवहार व पतित एव भ्रष्ट मानदंड के फलने फूलने से सांस्कृतिक प्रक्रिया का भी अपराधीकरण हो गया है। अपराधीकरण की इस समूची प्रक्रिया की खास जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की है जबकि बाकी दल भी अमूमन इसमें भागीदार हैं।

(ज) सर्वैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंतिम मार जगदा महत्वपूर्ण पूर्व शत यह कि जनता में लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष विचारों का प्रचार हो। इस संबंध में हम पाते हैं कि विभिन्न राजनैतिक दलों मुख्यतया शासक दल ने अपन प्रचार और गतिविधि के जरिए खासकर चुनाव प्रक्रिया में (जो तब व्यापक पैमाने पर विचार फैलाने का मुख्य वायुमंडल है) भारतीय जनता में सामंजस्य जातिवादी और स्वायत्त चेतना बढ़ाई है।

## 8 विधायिका

में लाए गए दो तिहाई विधेयक जरूरी फोरम के बिना ही पारित हुए। और मुख्य बजह यह है कि ससद में कोई वैकल्पिक विपक्षी दल नहीं। सभी कायपालिका पर ससद का बमजोर अकुश है।

(ख) फिर भी, अगर ससद में चुली और निस्सकोच बहस पर अनुचित प्रति बध न हो तो उसकी भूमिका को थोड़ा अधिक कारगर बनाया जा सकता है। ससदीय रिवाज बताता है कि नेटव की पहल पर ही लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को असामान्य अधिकारों से लैस किया गया। लोकसभा की कायविधि के नियम 380 के तहत अध्यक्ष अगर किसी बात को अससदीय या असोभनीय समझ तो उसे उन अशो की सदन की कायवाही से पारित करने का अधिकार है। दिलचस्प बात है कि 1947 से पहले केंद्रीय विधानसभा में ऐसा कोई नियम नहीं था। तब कांग्रेसी और दूसरे भारतीय सदस्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ कुछ भी कह सकते थे। नियम 380 अलोकतांत्रिक है क्योंकि यह आम लोगो को ससद में अपने नुमायदा के कामकाज के बारे में जानने के अधिकार से वंचित रखता है। इसके अलावा ससद के दोनो सभापतिया के पास इतने अधिकार है कि वे अपने अपने सदन में किसी भी मुद्दे पर बहस रोक सकते हैं। 1987 में जब ससद के बाहर आम लोगो में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री विवाद पर चर्चा छिड़ी हुई थी तो दोनो सभापतिया न अपने-अपने सदन में इस मुद्दे पर इसलिए बहस नहीं होन दी कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को छोड़कर उसकी भूमिका के बारे में कोई बहस नहीं हो सकती।

(ग) ससदीय परंपराओं के अनुसार सभापतियों को दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए। मगर भारत में लोकसभा या किसी राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अथवा राज्यसभा या किसी राज्य विधान परिषद का सभापति दलीय उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ता है और सक्रियता से अपने दल का काम करता रहता है, तकनीकी तौर पर भले ही उसने किसी दल की सदस्यता ग्रहण न की हो। बीटो अधिकारों से लैस और दलों के प्रति निष्ठा रखने वाले ऐसे लोगो के सभापतित्व में भारतीय ससद में खुली और निस्सकोच बहस कस हो सकती है ?

(घ) ससद की भूमिका (सशक्त विपक्ष के न होने पर) थोड़ी अधिक कारगर बनाने का दूसरा तरीका यह है कि मौजूदा कायविधि के अनुसार काम किया जाए जिसके तहत सभी महत्वपूर्ण ससदीय कार्यों को संयुक्त समितियों और प्रवर समितियों को सौंपा जाता है। लेकिन कायपालिका इसे फालतू की बसरत मानती है। इंदिरा गांधी इस कायविधि की अधिकाधिक अनदखी करती गईं और राजीव ने करीब करीब इस खत्म ही कर दिया है। अब शायद ही कोई काम इन समितियों के हवाले किया जाता है। लोक लेखा समिति, सांख्यिक उपक्रम समिति, आकलन समिति आदि सरीखी संवैधानिक ससदीय समितियों को भी कायपालिका से सहयोग नहीं मिलता और उनकी सिफारिशों को खासी अहमियत नहीं दी जाती।

(ङ) अध्यादेशों, प्रशासकीय आदेशों प्रेस बक्तियों आदि जैसे विभिन्न

उपाया कि जरिए विधायिका की अनदेखी करना भारतीय कायपालिका का सामान्य कायदा बन गया है। कई बार तो ससद को गलत जानकारी तक दे दी जाती है (मसलन अप्रैल 1987 में राजीव का ससद में यह बयान कि वे राष्ट्रपति को हमेशा जानकारी देते आए हैं, बाद में झूठा निकला)। मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री की ओर से भी महत्वपूर्ण फैसले अमूमन ससद से बाहर लिए जाते हैं। फिर उन्हें सर्वैधानिक जामा पहनाने के लिए ससद में रखा जाता है। इन सबसे ससद की प्रतिष्ठा घटी है। लगता है जैसे वह बहस मुबाहिसे की ही सस्था बन गई है।

## 9 'यायपालिका

(क) सर्वैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक और महत्वपूर्ण बात स्वतंत्र और निष्पक्ष 'यायपालिका का होना भी है। ऐसा इसलिए है कि ससदीय प्रणाली में 'यायपालिका को सविधान की रक्षक माना जाता है। राज्यतंत्र के दूसरे दो अंग जब अपनी सीमाएं लाघ जात हैं तो पीडित पक्ष 'याय के लिए हमेशा अदालत का रुख करता है। 'यायपालिका के पास न तो पजाने की ताकत है, न सैन्य बल की। इसका एकमात्र गुण बिना किसी डर या पक्षपात के स्वतंत्रता और निष्पक्षता से 'याय का पक्ष लेना है।

(ख) कुल मिलाकर भारतीय 'यायपालिका (जिसके शीप पर सुप्रीम कोर्ट है और सबसे नीचे मुंसिफ की अदालत) की भूमिका नकारात्मक व मुकाबले ज्यादा सकारात्मक है। सामाजिक 'याय, मौलिक अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रताओं तथा महिलाओं, जनहित, सरकारी ज्यादातियों और अफसरशाही की अति के मुद्दों पर कमजोर वर्ग के अधिकारों जैसे अनेक महत्वपूर्ण मामलों में इसमें नहीं दिशाएं खोली हैं। पर यह अभी भी कई गंभीर मामलों में ग्रस्त है। मसलन कायपालिका और 'यायपालिका के बीच टकराव में कायपालिका उस पर हावी है, 'यायपालिका में भ्रष्टाचार की समस्या मुद्दों में खड़ी है, 'याय की प्रक्रिया लंबी और दुष्कर चली आ रही है, पुराने मुकदमों का भारी बोझ बना हुआ है, 'याय पान के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है, आदि आदि।

(ग) 'यायपालिका पर कायपालिका के हावी होने की वजह भारत के शासक दल की तानाशाही प्रकृति है जो एकदलीय शासन जारी रखने के लिए 'यायपालिका पर हमला और दबाव बनाए रखे हुए हैं। कायपालिका इस दबाव का इस्तेमाल न्यायधीशों की निष्पक्षता के तबादले और पदोन्नति (कई बार प्रतिस्थापन) के अपने सर्वैधानिक अधिकार के जरिए करती है। नहरू के शासनकाल में कायपालिका और 'यायपालिका के बीच टकराव की नौबत नहीं आई। वजह यह कि इधर उधर की मामूली बातों को छोड़कर 'यायपालिका कायपालिका के लिए गंभीर चुनौती नहीं बनी थी। ऐसी पहली गंभीर चुनौती 1967 में मिली जब गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 'जाज के बाद सविधान के भाग 3 की धाराओं में संशोधन करने

का अधिकार ससद को नहीं होगा ताकि वह उसमें दखल मोलिक अधिकारों को वापस न ले पाए या उनमें कटौती न कर पाए।" जब राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पस के मामला में यह चुनौती ज्यादा मजबूत हुई। इंदिरा गांधी ने 'यायपालिका के घाव को रोकने के लिए ससद का इस्तेमाल किया। उनका एक मंत्री ने तो सविधान के प्रति नहीं बल्कि शासक दल के दशन के प्रति निष्ठावाज 'यायपालिका का सिद्धांत तक पेश कर दिया। छुद प्रधानमंत्री न 1950 से चले आ रहे उस नियम का ताढा जिसके तहत सुप्रीम काट के मुख्य 'यायाधीश की नियुक्ति वरीयता के आधार पर की जाती रही है। उन्होंने 1973 में तीन यायाधीशों की वरीयता लापर ए० एन० राय की मुख्य यायाधीश मुकरर किया। विराध में तीनों यायाधीशों ने इस्तीफा द दिया। इंदिरा गांधी के लिए गभीर 'यायिक चुनौती 1975 में पदा हुई जब इलाहाबाद हाई-काट के एक यायाधीश न एक चुनाव याचिका पर फैसला सुनात हुए उनका ससदीय चुनाव को भ्रष्ट आचरण के आधार पर अवैध घोषित कर दिया। जबाब में उन्होंने देश भर में इमरजेंसी लगा दी। तब से हाईकोट के 'यायाधीशों का तबादल नित्यक्रम बन गए हैं। इससे पहले केंद्र सरकार सुप्रीम काट और हाईकोर्टों के 'यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले के मामलों में भारत का मुख्य 'यायाधीश की सिफारिशें वस्तुतः मान लिया करती थी। पर अब ये सिफारिशें औपचारिकता मात्र रह गई। यही नहीं, इंदिरा गांधी ने 'यायपालिका को अपने राजनतिक स्वार्थों की छातिर भी इस्तेमाल किया। कृष्णानिधि जब इंदिरा गांधी के विरोध में थे तो उन्होंने द्रमुक नेता के खिलाफ जाच आयोग मुकरर किया। पर जब द्रमुक न कांग्रेस के साथ सयुक्त मोर्चा बना लिया ता वह आयोग हटा लिया गया। फिर, जब अनाद्रमुक कांग्रेस के विरोध में आई तो प्रधानमंत्री ने उसके नेता एम० जी० रामचंद्रन के खिलाफ जाच आयोग बिठाया लेकिन बाद में वह आयोग भी रद्द कर दिया गया। राजीव के शासन में 'यायपालिका पर कायपालिका का दबाव और बढ़ गया है। इसका बहुत स उदाहरण हैं—कलकत्ता हाईकाट के मुख्य 'यायाधीश डी० एस० तबतिया का हाल ही में अपने अनुचित तबादले पर इस्तीफा, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य 'यायाधीश पद पर 'यायाधीश चावला की पदोन्नति वकीलों द्वारा उनके पक्ष में हड़ताल करने पर ही सभव हो पाई, केंद्र सरकार द्वारा हाईकाट के कुछ 'यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में गुजरात के मुख्य 'यायाधीश, राज्य सरकार और भारत के मुख्य 'यायाधीश की सबसम्मत सिफारिश को रद्द किए जान पर 1986 में वकीलों की राज्यव्यापी हड़ताल आदि आदि। राजनतिक हिंसा के लिए इस्तेमाल हो रहे 'यायाधीशों (जो छोटी मोटी रियायतों के जाल में फस जाते हैं) की सट्या में भी वृद्धि हुई है। 1987 में ठक्कर नटराजन आयोग (जो सुप्रीम काट के इन दो 'यायाधीशों से गठित था) के इस कथन से, कि प्रधानमंत्री को अस्थिर करना देश को अस्थिर करना है, भी 'यायपालिका की ईमानदारी के प्रति लोगों का विश्वास को गभीर ठस पड़ची है। बुदाल आयोग, रगनाथ मिश्र आयोग आदि 'यायाधीशों के राजनतिक उपयोग के कुछ और

चुनिदा उदाहरण है। जब 'यायाधीश कायपालिका' के जीवार बन जाते हैं तो जनता का विश्वास 'यायपालिका' में कम होने ही लगता है।

(घ) 'यायपालिका' को खा रहे दूसरे रोग में भ्रष्टाचार की समस्या अभी भी हल नहीं हुई है। सविधान में भ्रष्ट 'यायिक' अधिकारी पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। पर इस धारा का कभी प्रयोग नहीं हुआ। इसकी प्रतिया इतनी जटिल है कि आम आदमी के बस की नहीं। जहाँ तक 'यायिक' प्रतिया में 'देरी' का तात्लुक है, रोज ऐसे मामले देखने में आते हैं जहाँ 'यादी' की पूरी जिदगी ही मुकदमों की पेशी में गुजर जाती है। मामला न निरटन पर वह इस आगे विरासत में द जाता है। जाहिर है 'याय' में 'देरी' 'याय' से बचित रखने के समान है। अदालतों में सटके मामलों की सट्या—हाईकोर्टों में 15 लाख और सुप्रीम कोर्ट में 1,86,000—भी चौकान वाली है।<sup>8</sup> मौजूदा रफतार से उन्हें निबटान में 30 साल लग सकते हैं। 'याय' पाने के लिए ज्यादा खर्च भी आम आदमी की बर्दाश्त से बाहर है। मुकदमेबाजी में फसने का मतलब है कज में घसना। अदालतों की पूरी फीस अग्रिम देनी पड़ती है पर यह भरोसा नहीं कि मामला जिदगी में ही निबट पाएगा या नहीं। जाहिर है भारतीय 'यायिक' व्यवस्था आम आदमी की पहुँच से बाहर है। इतिहास में 'यायिक' व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा है कि 'याय' सुगमता से उपलब्ध हुआ करता था। पुराने जमाने में बादशाह अपने महल के बाहर एक घटा लगा दिया करते थे और 'याय' चाहने वाला कोई भी शरस उसे बजा सकता था।

(ङ) ये सभी रोग 'यायपालिका' की देन हैं और वह ही कानूनी कायप्रणाली में तब्दीलिया करके और 'यायाधीश' की सट्या बढाकर इन्हें खत्म कर सकती है। 'यायिक' विश्वसनीयता अभी बनी रह सकती है जब 'यायपालिका' सविधान और कानून का पालन करने के अलावा भारतीय जनता के प्रति गभीर रूप से जवाबदह हो तथा अदालत की अवमानना (जो 'यायपालिका' के लोकतन्त्रीकरण में बाधा है) के अपने विशेषाधिकार का त्याग करे।

## 10 प्रेस

(क) संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक और पूर्व शत आजाद और जिम्मेदार प्रेस का होना है। ऐसा इसलिए है कि आधुनिक राज्यतंत्र में प्रेस जनमत को पालन का एक शक्तिशाली माध्यम है। यही वजह है कि कुछ राजनीति शास्त्रियों ने इसे चौथे स्तंभ का नाम दिया है। कुल मिलाकर भारतीय प्रेस ने 1947-उपरात दौर में सवारात्मक भूमिका निभाई है और मौजूदा वक्त में भी उसकी यही स्थिति है।

(ख) भारतीय सविधान में प्रेस की आजादी का बही जिक्र नहीं मिलता। पर सुप्रीम कोर्ट का मत है कि सविधान का अनुच्छेद 19 (1 क) अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी देता है जिसमें प्रेस की आजादी भी शामिल है।

(ग) भारतीय प्रेस घासकर बड़े व्यापारिक घरानों की मिलवियत वाले प्रेस ने अमूमन 1947-उपरात भारत में वनी सभी सरकारों की मूल नीतियाँ का समर्थन किया है। कुछ ही मौकों पर जब इसके अपने हितों को चोट पहुँची (मसलन 1951 में अनुच्छेद 19 में संशोधन जिससे सरकार को मानहानि पर कानून बनाने का अधिकार मिला तथा 1988 में मानहानि विधेयक के वक्त) अथवा जब सरकार को भारी जन विरोध का सामना रहा (मसलन 1975 की आंतरिक इमरजेंसी तथा फेयरफैक्स, योफोस आदि सरीखे घोटालों के वक्त) इसने सरकारी नीतियों की आलोचना की है। कभी कभी भार कोई निष्पक्ष या शायद भावुक सवात्पाता ने इस पर कुछ कटाक्ष अथवा कोई दुष्पी पत्रकार अपने मन की भद्दास जखूर निवालाता रहता है। पर भारतीय प्रेस की आम दिशा हमेशा सरकारी लाइन का समर्थन करना रही है। इस समय 'इंडियन एक्सप्रेस' और इसके सहयोगी पत्र पत्रिकाओं मौजूदा सरकार के खिलाफ बड़ा जेहाद छेड़ रहा है लेकिन वे भी बहुत सी मूल समस्याएँ (जैसे कि पंजाब, श्रीलंका पाकिस्तान, आर्थिक नीति, राष्ट्रीय नीति, सांस्कृतिक नीति आदि) पर सरकार के साथ पडे हैं। निस्संदेह भारतीय प्रेस ने घासकर खोजी पत्रकारिता के जरिए अपनी शैली और रचना में बहुत सुधार किए हैं पर इसने अक्सर सनसनीखेज और व्यक्तिवादी राजनीति को प्रमुखता देकर मुद्दा पर आधारित राजनीति को गौण हैसियत दी है। नतीजतन, जनता में ऐसी व्यक्तिवादी चेतना पैदा हुई है जिसमें राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारी का अभाव है।

(घ) बहरहाल, प्रेस द्वारा सरकारी नीतियों को आम समर्थन देने के बावजूद भारत में हावी एकदलीय प्रशासन ने हमेशा उसे दबू बनाने का प्रयास किया है। नेहरू के शासनकाल में अनुच्छेद 19 में संशोधन करने सरकार ने मानहानि के बारे में कानून बनाने का अधिकार हासिल कर लिया। उत्तेजना में आकर प्रेस ने इस संशोधन का जोरदार विरोध किया। इंदिरा गांधी ने पहले अखबारों को विभिन्न श्रेणियों के लिए मुहरर कीमत पष्ठ परिगणना के जरिए और फिर प्रसार सख्या के आधार पर कागज का कोटा बांटने की चाल के जरिए बाधने की कोशिश की। इमरजेंसी के दौरान पहले मुहरर अखबारों का मुह बढ़ करने के लिए सेंसरशिप का प्रयोग हुआ और बाद में विभिन्न समाचार एजेंसियों का विलय करके 'समाचार' नाम की सरकारी एजेंसी बज्जद में लाई गई। जनता सरकार ने रेडियो और टीवी की स्वायत्तता के लिए वर्गज समिति की सिफारिशों की अनदेखी की। फिर, इंदिरा गांधी राज में अखबारों पर पाबंदियाँ लगाने वाले बिहार प्रेस विधेयक को सबत्र विराध के कारण वापस लेना पडा। राजीव सरकार ने पहल कुछ जिम्मेदार पत्रकारों (इ० पी० वीकली और कौमी आवाज के सपादकों तथा पीयूसीएल व पीयूडीआर के नेताओं आदि) को आपराधिक मामलों में फसाकर और फिर मानहानि विधेयक लाकर प्रेस को आतंकित करने की कोशिश की। दोनों मौकों पर उसे अपने कदम तुरत पीछे खींचने पडे।

(ङ) भारतीय प्रेस अब परिपक्व हो गया है। उसने जिदगी में पर्याप्त

सकारात्मक और नकारात्मक अनुभव हासिल किए हैं। इन अनुभवों के निचोड़ स उसे जनता के हितों की पूर्ति के लिए एक उचित मंडातिक व व्यावहारिक रण्य अपनाना चाहिए। ऐसा करते समय उस सरकारी नियंत्रण स मुक्त रहने और लोगों के प्रति जवाबदेह होन व जुड़वा सिद्धांत का पालन करना चाहिए।

## 11 राजनेतिक दल

(क) सर्वधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक और पूव शत यह है कि एक सुगठित पार्टी तत्र मौजूद हो। ऐसा इसलिए है कि ससलीय राज्यतत्र इस तरह के पार्टी तत्र के बिना चल नहीं सकता। बहरहाल, भारत के पार्टी तत्र की अपनी निम्नलिखित घासियतें हैं।

पहली बात यह है कि भारत म न तो रूस की तरह का एकदलीय तत्र है, न ग्रीन जैमा दो दलीय तत्र और न ही इटली और फ्रांस सरीखा बहुदलीय तत्र। यहा बहुदलीय तत्र वाली व्यवस्था पर हावी एक पार्टी का तत्र मौजूद है।

दूसरे भारत के अधिकांश दलों मे वैचारिक आधार का अभाव है। वैचारिक अमूलों के बजाय उन पर 'यक्ति हावी' हैं। कामपधी (यानी भाकपा, माकपा और कुछ अन्य गुट) तथा कट्टरपधी दलों (यानी शिवसेना भाजपा, अकाली दल, मुस्लिम लीग आदि) को छोड़कर बाकी सभी दल वैचारिक रूप से तटस्थ सगठन हैं। वे व्यक्तियों से अधिक मराकार रखत हैं। उनकी मुख्य रुचि सत्ता के फल बटोरन म है और वे किसी खास कायक्रम या नीति के प्रति निष्ठा नहीं रखते। इस तरह राजनीति पर अनतिकता हावी हो गई है। कांग्रेस नेतृत्व ने ही शासक दल के भीतर और जनता के बीच सिद्धांतो-मुख के बजाय व्यक्ति उ-मुख रण्य की शुरुआत करके इसे बढावा दिया और इस तरह मृत्यो पर आधारित राजनीति की जड़ें छोदी।

तीसर, एक ही पार्टी व प्रभुत्व वाला तत्र भारतीय राज्यतत्र का स्थायी पहलू नहीं ह। प्रभुत्वकारी दल यानी कांग्रेस दल किसी भी आम चुनाव मे कुल वोटो का बहुमत (यानी 50 फीसदी से कुछ ऊपर) कभी हासिल नहीं कर पाया। 1977 मे भारतीय जनता ने तब की जनता पार्टी का साथ देकर इसे सत्ता से बाहर कर दिया। 1967 व चुनाव म कांग्रेस मामूली बहुमत पाकर ससदीय चुनाव तो जीत गई थी पर उसे नौ राज्यों मे मुह की खानी पडी। इस समय 10 राज्यों मे गैर कांग्रेसी दलों की सरकारें हैं।

चौथे, भारत के राजनेतिक दलों को तीन मोटी श्रेणियों मे बाटा जा सकता है—राष्ट्रीय दल (यानी कांग्रेस इ, भाकपा, माकपा जनता, लोकदल आदि), क्षेत्रीय दल (यानी नेशनल काँग्रेस, अनाद्रमुक, तलुगु देशम आदि) और सांप्रदायिक दल (यानी शिवसना, भाजपा, मुस्लिम लीग अकाली दल आदि)।

पाचवें, अत्यधिक गुटपदी से राजनेतिक दलों की पातें बार बार ि हुई हैं। इस तरह अब कांग्रेस के दो, कम्युनिस्ट पार्टी के तीन या चार, जनता



के दो, लोकदल के दो, अनाली दल के तीन, नेशनल वॉर्कर्स व द, द्रमुक के दो गुट वजूद में हैं।

(घ) उक्त घासियतें बताती हैं कि भारत में अभी स्वयं पार्टी तंत्र नहीं उभर पाया है। 1947 के बाद यहाँ शासक दल का राष्ट्रीय विवलय न उभर पान का मुख्य कारण यह है कि कोई भी परंपरागत विपक्षी दल लोगों के सामान वकल्पिक कायन्म और नीतियाँ रखने में समर्थ नहीं हुआ है। इसके बजाय उन्होंने एक तरफ कांग्रेस को प्रतिश्रियावादी ताकत बताकर और दूसरी तरफ अधिकांश मूल सवाल (जैसे एटमी हथियारों की नीति, रक्षा, पाकिस्तान विराधी, चीन विरोधी, रूस समर्थक विदेश नीति, योजना, सावजनिक क्षेत्र आदि) के बारे में शासक दल की नीतियाँ का समर्थन करके प्रायः लोग का उलथन में डाले रखा है।

## 12 भारत की विविधता में एकता का आधार

पाकिस्तान के मुकाबले भारत का राज्यतंत्र 40 साल से अधिक तक अपना ससदीय स्वरूप बनाए रखने में कामयाब रहा है। जा लोग मानते हैं कि काइ निरकुश शासन और सनिक तानाशाही ही किसी बहुभाषायी और विभिन्न संस्कृतियाँ वाले देश को एकजुट रख सकती हैं उनके लिए भारत में ससदीय स्वरूप वाली सरकार का कायम रहना चमत्कार संकम नहीं। उनके लिए यह भी भारी आश्चर्य की बात है कि इस देश में—जहाँ सविधान से मायता प्राप्त 16 भाषाएँ हैं, करीब 4000 भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं, 70 फीसदी लोग अभी अनपढ़ हैं—जाठ बार नियमित अवधि पर ससद और राज्य विधानसभाओं का चुनाव हा चुके हैं। यह आश्चर्य उस परंपरागत धारणा पर आधारित है जा 1945 से पहले के दौर में भाकूल थी। तब सामाजिक सोच मुन्यतया उपनिवेशी दृष्टिकोण और प्रभुत्वकारी अधीनस्थ संबंधों के आधार पर बनती थी तथा विविधता में एकता, घासकर अल्पविकसित दशों में किसी निरकुश राज्यतंत्र के जरिए ही बनाए रखे जा सकती थी। भारत का अनुभव इस तथ्य का (जा कई यूरोपीय देशों में पहले ही स्थापित हा चुका है) सिद्ध करता है कि 1945 के बाद की दुनिया में सांप्रदायिक और उग्रवादी खतरे व दवावों के आगे लोकतांत्रिक राज्यतंत्र निरकुश राज्यतंत्र से ज्यादा लाचदार है। अगर भारतीय राज्यतंत्र जति केद्रीयकरण से मुक्त होता और इसकी विभिन्न कांग्रेसी सरकारों पर तानाशाही का नशा सवार न हाता तो 1947 उपरांत सांप्रदायिक और उग्रवादी खतरे पैदा ही न हाते अथवा इस हद तक भयानक रूप अख्तियार न कर पाते। निस्संदेह भारत का ससदीय लाकतन उपमहाद्वीप में बड़ी उपलब्धि है पर पिछले 40 साल से श्रीलंका जैसे छोटे लोकतंत्र भी ससदीय अभियान में जमे रहे हैं।

## 13 भारतीय जनता द्वारा चुकाई गई भारी कीमत

उपरोक्त लेखे-जाखे से पता चलता है कि भारतीय सविधान ने प्रधानमंत्री के

हाथों में अति केंद्रित सत्ता सौंपकर भारतीय राज्यतंत्र को अति केंद्रीयकृत राज्यतंत्र बना दिया है। अति केंद्रीयकरण का अभिशाप यह है कि इससे सोच व अमल के तानाशाही तौर-तरीके जन्म लेते हैं। असतोष को लोकतान्त्रिक तरीके से शांत करने के बजाय तानाशाही शैली हमेशा उससे सहार या दमन के जरिए निवटती है। इससे स्वाभाविकतया सरकार और जनता के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है। देश के सभी भागों में लोगों के बड़े और छोटे सघप, आंदोलन, हड़तालें, प्रदर्शन, विरोध सभाएँ आदि इन्हीं तथ्यों की पुष्टि करती हैं। इन सघपों में सरकार की गोलियों, लाठियों और आसू गैस से बहुत सारे लोग मरे और घायल हुए हैं। 1947 के बाद असम, पंजाब और गुजरात में सैनिक कारवाइयाँ हुई हैं। इन कारवाइयों में पहले भी भारत में विभिन्न नागरिक विवादों में 369 बार सेना ने हस्तक्षेप किया।<sup>9</sup> पिछले 40 साल में सेना और पुलिस बलों के हाथों कितने लोगों की जानें गई हैं, इसके बारे में कोई सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 1952 के दौरान संसद में दिए गए पुराने आंकड़ों के अनुसार 15 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1950 के बीच 1,982 मौकों पर सेना और पुलिस की गोली से करीब 3,784 लोग मारे गए और लगभग 10,000 घायल हुए। इस आधार से कम आंकड़ों पर भी हम अगर एक साल में मत्कों की 1,000 और घायलों की 3,000 सख्या मानें तो पिछले 40 साल में पुलिस और सेना की गोली से मरे लोगों की संख्या 40,000 और घायलों की 1,20,000 बैठती है। इसके अलावा तेलंगाना नक्सलबाड़ी, नगालड, मणिपुर, मिजोरम, निपुरा, असम के सशस्त्र सघपों तथा जूनागढ़, हैदराबाद, गोआ और पंजाब की सैनिक कारवाइयों में भी भारी तादाद में लोग मरे या घायल हुए थे। पर इनके बारे में भी कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन अकेले पंजाब में ही, बाबा आमटे के अनुसार, सभी पक्षा (यानी आम सिखों और हिंदुओं, खालिस्तानियों तथा सरकारी बलों) के हताहतों की संख्या 1978 और 1987 के दौरान 25,000 से अधिक पहुंच गई थी। ऊपर बताए गए हरेक सशस्त्र सघप में अगर पंजाब के मुकाबले एक चौथाई लोग भी मारे गए हों तो मोटे तौर पर इस श्रेणी में कुल मरे लोगों की संख्या 50,000 और घायलों की 1,00,000 बैठती है। इसके अलावा पिछले 40 साल के दौरान हुए 12,000 सांप्रदायिक दंगों में 20,000 से कम लोग नहीं मरे<sup>10</sup> और इससे दुगुने घायल हुए हैं। कुल मिलाकर अति केंद्रीयकृत भारतीय राज्यतंत्र और तानाशाह कांग्रेस सरकार के एवज भारतीय जनता को लगभग 1,10,000 मौतों और करीब 2,60,000 घायलों से कीमत चुकानी पड़ी है। जन हानि के मायने में यह कीमत सैनिक शासन वाले पाकिस्तान और राजशाही नेपाल से कहीं ज्यादा है। हमने अति केंद्रीयकृत राज्यतंत्र और तानाशाही शासन के लिए सचमुच भारी कीमत चुकाई है।

- 1 कुलदीप नायर, 'इडिया आपटर नेहरू', वीपी हाउस, दिल्ली, 1975, पृ० 138
- 2 माइकल ब्रोखर, 'नेहरू—ए पालिटिकल बायोग्राफी', ओयूपी सदन, 1959, पृ० 458
- 3 इडियन एक्सप्रेस, 24 3 88, पृ० 2
- 4 से 5 'इडिया आपटर नेहरू', पृ० 6 और 8
- 6 बताया जाता है (हिंदुस्तान टाइम्स, 13 10 88, पृ० 10) कि 1984 में उत्तर प्रदेश के 50 000 ग्राम सभा चुनावों में 50 फीसदी से ज्यादा उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास रहा है। 1984 में सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के एक विधायक को 20 किलो हेरोइन और अन्य प्रतिबंधित माल सहित रंग हाथा गिरफ्तार किया। गुजरात में 'यायाधीश भियाभाई आयोग' ने इस बात का पर्याप्त सबूत पाया कि नाजायज शराब के व्यापारी राजनैतिक जीवन में घासकर चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जे० एफ० रिबरो जब गुजरात में थे तो उन्होंने 1985 के दंगों पर टिप्पणी करते हुए कहा था गुजरात नताओ और नाजायज शराब के व्यापारियों के बीच साठ गांठ का उत्कृष्ट उदाहरण है। बिहार के कुछ माफिया नेताओं को मध्य प्रदेश की यात्रा में सरकार ने सुरक्षा गांठ उपलब्ध कराए। आजीवन कैदियों को पेरॉल पर रिहा करना आम राजनैतिक चलन हो गया है और वे इस मौके का फायदा उठाकर अपने विरोधियों को खत्म करते हैं। दिल्ली में नवंबर 1984 के सिख विरोधी दंगों पर मिश्र आयोग की रिपोर्ट सच्चाई का पता लगाने में भले ही नाकाम रही पर उसे भी वे टिप्पणियाँ करने पर बाध्य होना पड़ा कि पुलिस दबाव के तहत ड्यूटी पर नहीं रही, सरकार का एहसास होना चाहिए कि पुलिस जनता की सेवा के लिए है, सत्ताधारी दल के राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं, तथाकथित जनहित के आधार पर मुकदमे वापस लेना अब अपवाद नहीं रहा आम दस्तूर हो गया है। यदि इडियन एक्सप्रेस के एक विमान के अपहरण की घटना यह कहकर माफ कर दी जाती है कि अपहृताओं का इरादा अपनी पार्टी नेता के प्रति निष्ठा व्यक्त करना था और 1980 में उनका खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया जाता है, यहाँ तक कि एक अभियुक्त को तो कांग्रेस विधानसभा के लिए टिकट भी दे दी है यही चलन सभी सत्ताधारी दलों में भी अपना लिया है जैसे 1985 में असम में अगप ने 1977 में केंद्र में जनता सरकार ने और 1980 में कांग्रेस सरकार ने। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने फायपालिका द्वारा किसी भी फौजदारी मुकदमे को वापस लेने के बेलगाम अधिकार को कबूल करके राजनीति और अपराध के बीच गठजोड़ सुगम बनाया है। मुठभेड़ में भीतें राजनीति के संरक्षण में पुलिस की गैर कानूनियत का ही एक उदाहरण है। कानून स्थापित करने

वाली सस्या में अत्यधिक भ्रष्टाचार है।

- 7 'फ़ेश पॅसपेक्टिव्ह आन इंडिया ऐंड पाकिस्तान', बुक ट्रेड्स लाहौर, प० 8 के मुताबिक 1950 और 1984 के बीच केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों ने राष्ट्रपति के नाम पर कुल 348 अध्यादेश जारी किए। इनमें से कुछ अध्यादेश तो ऐसे वक्त में भी जारी किए गए जब संवैधानिक विधायिका के किसी एक सदन का सत्र चल रहा था।
  - 8 ट्रिब्यून, 17 11 84, प० 4 और टाइम्स ऑफ इंडिया, 10 12 88, पृ० 4
  - 9 मासिक सेमिनार, दिल्ली, अप्रैल 1985
  - 10 भारत में 1960-70 के दौरान सांप्रदायिक वारदातों की तादाद 700 से बढ़कर 3 000 हो गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान 3,508 लोग मारे गए जबकि 1950 से 1963 के बीच इस तरह से मरने वालों की संख्या 389 थी (डिस्टेंट नेवरलैंड, कूलदीप गायर, पृ० 178)
- 1977 से 1983 तक के सात साल के दौरान भारत में हुए सांप्रदायिक दंगों में करीब 2,359 लोग मारे गए। यानी हर साल औसतन 300 लोगों की जानें गईं। इसके अलावा 1984 जैसे असामान्य वर्ष में करीब 4,000 लोग सिख विरोधी दंगा में मारे गए और 1983 में 3,000 से अधिक जानें असम में भेरी की सांप्रदायिक हिंसा में ली लीं।

## अध्याय चार भारतीय अथव्यवस्था

इसका संवध 1947 उपरांत भारतीय अथव्यवस्था के कामकाज जीर इसके प्रबध की प्रनिया से है ।

### 1 सरचना

सरचनात्मक रूप से, 1947 उपरांत भारतीय अथव्यवस्था मोट तौर पर दो भागा—आधुनिक जीर पारंपरिक से गठित है । आधुनिक भाग मे आधुनिक टेक्नोलॉजी और पारंपरिक भाग मे पारंपरिक टेक्नोलॉजी की विशेषता है । आधुनिक भाग आगे फिर दो उप भागो—संगठित और छोटे व मध्यम आकार वाले खडो मे बटा है । संगठित भाग सावजनिक क्षेत्र जीर निजी क्षेत्र से गठित है । सावजनिक संगठित क्षेत्र की भूमिका प्रमुख है । निजी संगठित क्षेत्र भी राजकीय वित्तीय सस्थाआ द्वारा नियमित है क्यकि बहुत मे बडे कारखानो मे इ ही सन्थाना के ज्यादातर शेयर है । इस प्रकार समूची भारतीय अथव्यवस्था मे निजी संगठित क्षेत्र सावजनिक संगठित क्षेत्र का कनिष्ठ भागीदार ही है । छोटे जीर मध्यम आकार के क्षेत्र पर मूलत निजी क्षेत्र का ही नियंत्रण है । पारंपरिक भाग मे कृषि और उससे संबधित उद्योगो का प्रमुख स्थान होने के कारण उम पर भी निजी क्षेत्र का कन्त्रा है । यही निजी क्षेत्र भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन मे करीब 80 फीसदी योगदान देता है ।

### 2 समस्याएं

समस्याआ के लिहाज से भारतीय अथव्यवस्था एक अध विकसित अथव्यवस्था है जिसकी सात विशेषताएं हैं । ये हैं—पति व्यक्ति कम आय या व्यापक गरीबी, भ्रष्ट पैमाने पर बेरोजगारी और अध-बेराजगारी, कृषि की प्रमुखता, प्राथमिक माल के निर्यात की प्रधानता, अपर्याप्त पूजी, यून उत्पादकता निरक्षरता होने के साथ ही निपुणता का अभाव और बढ़ती जनसंख्या । इनमे से अपर्याप्त पूजी और यून उत्पादकता की दो विशेषताएं ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं । इसलिए भारतीय अथव्यवस्था के विकास का मतलब है इन सात विशेषताओं को आम तौर पर जीर अल्प विकास की दो विशेषताओं को खास तौर पर दूर करना ।

### 3 आर्थिक विकास के मूल सिद्धांत के रूप मे राज्य नियोजन

प्रशासकीय रूप से, भारतीय राज्य न नियोजन (यानी पूर्व निर्धारित सध्या और साधनो की हासिल करने के लिए सभेत् रूप से किया जाने वाला काम) को

आर्थिक विकास के अपने मूल सिद्धांत के रूप में अपनाया है। भारतीय संविधान में नियोजन का कोई सांविधिक महत्व नहीं है। इसमें सामाजिक और आर्थिक नियोजन की व्यवस्था समवर्ती सूची में की गई है। इसके अनुसार देश में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों या विकास चौथे भाग में व्यवस्था राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को लागू करने हासिल किया जाए। संविधान में किसी नियोजन संस्था को बनाए जाने की व्यवस्था भी कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए योजना आयोग की स्थापना 1950 में सरकारी प्रस्ताव द्वारा एक संविधानेतर संस्था के रूप में की गई। योजना आयोग संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है। 1952 में कुछ केंद्रीय मंत्रियों, योजना आयोग के सदस्यों और मुख्यमंत्रियों को मिलाकर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। इसका काम समय समय पर योजना के कामकाज की समीक्षा करना है। अब तक छह पंचवर्षीय योजनाएँ और तीन एक वर्षीय योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। इस समय सातवीं पंचवर्षीय योजना चौथे वर्ष में चल रही है।

#### 4 पीछे की स्थिति और मौजूदा कामकाज की कसौटी

(क) पीछे की तरफ झाँककर देखें तो बहुत सारे अनुमानों से पता चलता है कि वर्तमान शासन के आधारी दशका में आर्थिक ठहराव आ गया था। 1947 के आसपास लोगों की औसत जिंदगी महज 33 साल हुआ करता थी। 1943 में बंगाल के अकाल के दौरान करीब 30 लाख लोग मर गए थे। इस पृष्ठभूमि में देखा जाए तो भारत का आर्थिक विकास असाधारण दीपता है। 1950 के बाद राष्ट्रीय उत्पादन में 28 गुना वृद्धि हुई है।<sup>1</sup> औद्योगिक उत्पादन चार गुना<sup>2</sup> और कृषि उत्पादन तीन गुना<sup>3</sup> बढ़ा है। औसत जीवन अवधि 33 से बढ़कर 52 वर्ष हो गई है।<sup>4</sup> बहर-हाल, किसी नियोजित अर्थव्यवस्था के मूल्यांकन के लिए (i) उसकी आर्थिक वृद्धि और वृद्धि (ii) इसी तरह की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उसकी उपलब्धियाँ तथा (iii) तरक्की के लिए अंदा की गई कीमत ही उचित मापदंड हैं।

(ख) हम इनके घोषित उद्देश्यों और उनकी अपनी अपनी उपलब्धियों से शुरू करते हैं।

#### 5 कुल आर्थिक विकास

(क) भारतीय नियोजन का सबसे प्रथम उद्देश्य आर्थिक विकास रहा है। छह योजनाओं में विकास दर का औसत वार्षिक लक्ष्य पाँच फीसदी रखा गया।<sup>5</sup> मगर इसकी उपलब्धि कहीं पीछे यानी 3.5 फीसदी रही।<sup>6</sup> इस दौरान कृषि की विकास दर का लक्ष्य 3.5 फीसदी रखा गया जबकि उसकी उपलब्धि 2.2 फीसदी रही।<sup>7</sup> इसी प्रकार उद्योग की विकास दर का लक्ष्य 7 फीसदी रहा लेकिन यहाँ उपलब्धि 5.5 फीसदी रही।<sup>8</sup> सातवीं योजना के आसार तो और निराशाजनक दीखते हैं। अब तक की सर्वाधिक 3.5 फीसदी विकास दर भी शायद ही पूरी हो पाए।

पंचवर्षीय योजना (1951-56) में 27 वर्षों में (यानी 1977 तक) प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करने का दूरगामी लक्ष्य रखा गया था पर इस आय की सालाना 1.33 फीसदी वृद्धि (यानी 3.57 फीसदी वार्षिक आर्थिक विकास दर में से 2.24 फीसदी वार्षिक जनसंख्या विकास दर को घटाकर) का दृष्टि दृष्टि इस लक्ष्य का पूरा करने में 52 साल (यानी सन 2003 तक) लगेंगे। दा ही मामलों में भारत की विकास दर ऊँची रही है। एक है पूँजी/उत्पादन का अनुपात का उदाहरण जिसका अनुमानित लक्ष्य ता 4 फीसदी का पर 1970-79 के दौरान यहाँ उपलब्धि 8.9 फीसदी रही।<sup>9</sup> दूसरा उदाहरण जनसंख्या की विकास दर का है जहाँ लक्ष्य तो 1.5 से 2 फीसदी का पर उपलब्धि करीब 2.5 फीसदी रही।<sup>10</sup>

(घ) और फिर, इस अपर्याप्त आर्थिक विकास का फायदा भी लोगों की विभिन्न श्रेणियों को समान रूप से नहीं मिला है। कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद 1950-51 से 1984-85 तक के 34 वर्षों में जहाँ व्यावहारिक तौर पर बिलकुल नहीं बढ़ा वहीं गैर कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद सालाना 2.48 फीसदी की विकास दर से बढ़ा।<sup>12</sup> गैर कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद और कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद का अनुपात 1950-51 में 1.46 था। 1960-61 में यह बढ़कर 1.94, 1970-71 में 2.53, 1980-81 में 2.93 और 1984-85 में 3.23 हो गया।<sup>13</sup> कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच बढ़ते अंतर की दो वजह हैं। एक तो यह कि कृषि की विकास दर 2.12 फीसदी पर स्थिर जबकि गैर कृषि क्षेत्र में इसकी दर 4.97 फीसदी है।<sup>14</sup> दूसरी यह कि दोनों क्षेत्रों में भारी अंतर होने के बावजूद कृषि क्षेत्र की जनसंख्या 1950-51 से ही कुल जनसंख्या का करीब दो तिहाई चली आ रही है।<sup>15</sup> जबकि गैर कृषि क्षेत्र आर्थिक तौर पर सगठित होने से फलतः लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं देता।

(ग) 1950 और 1980 के बीच भारत की 3.5 फीसदी सालाना विकास दर की तुलना इस अर्थ में उसके राष्ट्रीय उत्पादन की 2.8 गुना वृद्धि से की जाए (1950-51 में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 16,731 करोड़ ₹० और 466 करोड़ ₹० से बढ़कर 1984-85 में 1970-71 की कीमतों पर क्रमशः 57,014 करोड़ और 772 ₹० हो गई) तो हमें पता चलता है कि कुल मिलाकर विश्व अर्थव्यवस्था औसतन सालाना 4.1 फीसदी की दर से विस्तृत होती गई।<sup>16</sup> और इन्हीं 30 वर्षों में उसका सकल उत्पाद 3.3 गुना बढ़ा। तीसरी दुनिया में तरक्की की यह रफ्तार इससे भी तेज यानी सालाना 4.9 फीसदी की दर से अथवा भारत की तुलना में 40 फीसदी अधिक सालाना दर से हुई है।<sup>17</sup> नतीजतन 1950-80 के दौरान तीसरी दुनिया में सकल उत्पाद भारत के 2.8 गुना के मुकाबले 4.2 गुना बढ़ा।<sup>18</sup> प्रति व्यक्ति आय के आँकड़े बताते हैं कि 1950-80 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति आय 4.3 फीसदी से अधिक नहीं बढ़ी (छठी योजना के अंतर्गत 7.1 फीसदी), वहीं तीसरी दुनिया ने इसी अवधि में अपनी प्रति व्यक्ति आय में दुगुनी से भी ज्यादा वृद्धि

कर ली।<sup>19</sup> आज भारत प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पाद के क्रम में 126 देशों की सूची में 116वें स्थान पर है।<sup>20</sup>

### (1) कृषि

भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार कामकाज को देखें तो कृषि की उपलब्धियाँ तीसरी दुनिया के स्तर के मुताबिक भी घटिया हैं। 1973-83 की अवधि के बारे में खाद्य एवं कृषि संगठन के एक अध्ययन<sup>21</sup> से पता चलता है कि भारत का खाद्यान्न उत्पादन सालाना 2.9 फीसदी की दर से बढ़ा जो कि एशिया की 3.5 फीसदी औसत से बहुत नीचे है। चीन (3 फीसदी), बर्मा (6.6 फीसदी), श्रीलंका (6.2 फीसदी) और पाकिस्तान (4.6 फीसदी) जैसे भारत के पड़ोसी देशों में कृषि का विकास ज्यादा तेजी से हुआ। 1965-80 के दौरान 21 अफ्रीकी देशों से भारत के कृषि विकास की तुलना करते हुए एक और अध्ययन<sup>22</sup> में कहा गया है कि 10 अफ्रीकी देशों में तो भारत से भी ज्यादा विकास दर थी। कृषि उत्पादकता के मामले में भी भारत सबसे कम उत्पादकता वाले देशों की श्रेणी में है।<sup>23</sup> भारत में खाद्यान्न का औसत उत्पादन महज 1.6 टन प्रति हेक्टेयर है जो कि चीन के आधे से भी कम है।<sup>24</sup> 1981-82 में चीन ने 9.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जहाँ 34.40 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन किया, वहीं भारत 10.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर महज 13.9 करोड़ टन ही उपजा पाया।<sup>25</sup>

खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार<sup>26</sup> भारत में खाद्यान्न की प्रति हेक्टेयर पैदावार 1286 किलो दाला की 485 किलो, तिलहन की 497 किलो और विनोले की 502 किलो है। इससे विपरीत दुनिया में खाद्यान्न की यह औसत पैदावार 1975 किलो, दाला की 683 किलो, तिलहन की 822 किलो और विनोले की 1259 किलो है। बर्दाश्त स्थित भारतीय अर्थव्यवस्था प्रबोधक केंद्र का अनुमान है कि 1971 और 1984 के बीच कृषि उत्पादन की प्रति इकाई पर लागत में 32 फीसदी की वृद्धि हुई।<sup>27</sup> पिछले सात साल की अवधि में कृषि क्षेत्र अस्थिर चाल से बढ़ा। वास्तविक वाली जमीन, सिंचाई सुविधाओं, अधिक पैदावार देने वाले बीजों और रासायनिक खाद के इस्तेमाल के बावजूद 1978-79 और 1982-83 के बीच खाद्यान्न उत्पादन करीब 13 करोड़ टन पर अटक रहा।<sup>28</sup> पर 1983-84 में यह 15 करोड़ टन हो गया और तब से वहीं पर स्थिर है।<sup>29</sup> सातवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा<sup>30</sup> से पता चलता है कि 1987-88 के सूखा वर्ष को छोड़कर योजना के पहले वर्ष (यानी 1985-86) में कृषि की विकास दर महज 0.3 फीसदी और दूसरे वर्ष (यानी 1986-87) में शून्य से भी 2.6 फीसदी नीचे थी। 1986-87 और 1987-88 के वर्षों में कुल खाद्यान्न उत्पादन क्रमशः 14.41 करोड़ और 13.7 करोड़ टन था।<sup>31</sup>



## (ii) उद्योग

जौद्योगिक क्षेत्र मे पहली तीन पचवर्षीय योजनाओ (1951 से 1965) के दौरान सालाना करीब 7.7 फीसदी की<sup>32</sup> और उसके बाद चौथी, पाचवी और छठी पचवर्षीय योजनाओ (1971 स 1985) के दौरान सालाना 4.3 फीसदी की वृद्धि हुई।<sup>33</sup> एक और अध्ययन<sup>34</sup> भारत और समूची तीसरी दुनिया के औद्योगिक विकास की तुलना करते हुए 1950 और 1980 के बीच भारत की सालाना विकास दर 4.1 फीसदी अथवा कुल मिलाकर 3.3 गुना वृद्धि बताता है जबकि समूची तीसरी दुनिया के लिए यह आंकड़ा 6.3 फीसदी अथवा 6.3 गुना है। प्रति व्यक्ति आधार पर भारत में औद्योगिक उत्पादन महज 7.6 फीसदी बढ़ा जबकि समूची तीसरी दुनिया में इसमें 23.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। भारत की विकास दर भी विश्व की दर से कम है।

विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार<sup>35</sup> भारत आज अल्पविकसित देशों में चौथे और विश्व स्तर पर 12वें नंबर पर है। भारत के महज 30 अरब डालर मूल्य के औद्योगिक उत्पादन के मुकाबले 1984 में (1980 की कीमतों पर) चीन का 144 अरब डालर का उत्पादन उससे कहीं ज्यादा था। ब्राजील (57 अरब डालर) और मेक्सिको (43 अरब डालर) का नाम भी भारत से ऊपर है। दक्षिण कोरिया ने 1970 से अपना औद्योगिक उत्पादन में छह गुना वृद्धि की है और इस समय 27 अरब डालर का उत्पादन करके वह भारत के समकक्ष होना जा रहा है। चीन के औद्योगिक उत्पादन का मूल्य 1970-84 के दौरान 209 फीसदी बढ़ा, इसके बाद 90 और 101 फीसदी के साथ त्रयश ब्राजील और मेक्सिको का नंबर रहा जबकि इनके मुकाबले इसी दौर में भारत की वृद्धि 8.4 फीसदी थी। 1980-85 के दौरान चीन का औद्योगिक उत्पादन सालाना 13.4 फीसदी और पाकिस्तान का 10 फीसदी बढ़ता रहा। इसके मुकाबले इसी अवधि में भारत की औद्योगिक विकास दर महज 5.6 फीसदी थी, भारत में प्रति कर्मचारी औद्योगिक उत्पादन (औद्योगिक उत्पादकता का एक पैमाना) 1980=100 के आधार पर 1985 तक 128 पर ही पहुँच पाया जबकि पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया का यह सूचकांक त्रयश 158 और 149 था।

## सावजनिक क्षेत्र

भारतीय उद्योग का समूचा ममस्थल—इस्पात विजली तेल, गैस, खाद, कोयला भारी इंजीनियरिंग विजली की भारी मशीनें आदि सावजनिक क्षेत्र के अधीन है। 1951 में 29 करोड़ रु० के निवेश के साथ पांच उपक्रमों से स्थापित हुआ यह क्षेत्र 1986 तक बढ़कर 53,000 करोड़ रु० की लागत वाले 225 उपक्रमों में विकसित हो गया।<sup>36</sup> इसलिए आर्थिक विकास के लिए सावजनिक क्षेत्र का कामकाज भारी महत्व का है। पहले 30 वर्षों (1950 से 1980) में सावजनिक क्षेत्र ने कोई

शुद्ध लाभ रही बरमाया। 1981-82 में इसने 485 करोड़ ₹ का शुद्ध लाभ  
 किया।<sup>37</sup> अगर उस साल के 21 965 करोड़ ₹ का निवल पर यह मात्र 2.2  
 फीसदी लाभ ही बताता है। 1987-88 में गांवनिव धन में 1748 83 करोड़  
 ₹ का शुद्ध लाभ बरमाया जबकि इसमें पहले साल 1831 89 करोड़ ₹ का<sup>38</sup>  
 जाहिर है मात्र 2.5 फीसदी का यह लाभ कुल निवल पर दस ब्याज से भी कम था।  
 उद्योगों के आधार पर रिक्तपण करें ता पता चलता है कि 1987-88 में 2074 57  
 करोड़ ₹ का लाभ के माप पट्टालियम उद्योग नाम बरमान वाल उद्योगों में अग्रणी  
 था।<sup>39</sup> मर बाद दूर गंधार संग उद्योग (291 87 करोड़ ₹) और विजली उद्योग  
 (241 84 करोड़ ₹) का स्थान है।<sup>40</sup> अगर इन तीनों उद्योगों और रलय को छोड़  
 दें तो गांवनिव क्षेत्र में हाजि ही हाजि है। 1987-88 के दौरान घाट वाले उद्योगों  
 में बायना उद्योग (307 04 करोड़ ₹) अग्रणी था। इसके बाद कपडा उद्योग  
 (177 38 करोड़ ₹) स्थापन उतरक और दवा उद्योग (166 95 करोड़ ₹)  
 तथा उपभोगा वस्तु उद्योग (129 87 करोड़ ₹) का स्थान था।<sup>40</sup> बेंद्र न जिन  
 191 बीमार व्ययमा का हाथ में ल रया है, उनमें 37 में 1987-88 के दौरान  
 401 10 करोड़ का घाटा हुआ जबकि हमे पहले साल उभा घाटा 271 50 करोड़  
 ₹ का।<sup>41</sup> यह 'उपलब्धि' भी सरकार द्वारा हर साल अपने घाट की भारी मात्रा को  
 कम करने के लिए गांवनिव क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ात जाने  
 के कारण ही संभव हुई है। सावजनिक क्षेत्र और बड़े निजी क्षेत्र में निवल पर लाभ  
 की तुलना करने से पता चलता है कि जहां सावजनिक क्षेत्र का शुद्ध हाजि अथवा 2  
 से 3 फीसदी शुद्ध लाभ हुआ वहीं बड़े निजी क्षेत्र में 8.2 और 14.1 फीसदी के बीच  
 शुद्ध लाभ बरमाया है।<sup>42</sup> इन दोनों क्षेत्रों के बीच एक और अंतर यह है कि जहां  
 निजी क्षेत्र में स्थायी परिमपत्ति के लिए धन मुख्य रूप से अदरुनी साधना (यानी  
 घर उपरान नाम में से साभाशा मनीना की घिसाइ और बड़ा घाता घटाने के बाद)  
 जुटाया जाता है वहीं गांवनिव क्षेत्र में यह मूलत भारी साधनों (यानी नकदी  
 वाले जेयरा उधार, विविध ऋणताताओं और दूसरी तत्कालिक दनदारिया) पर निर्भर  
 होता है।

### निजी क्षेत्र

इस क्षेत्र का कामकाज भी समान रूप से खेदजनक है। पहली बात तो यह  
 है कि सरकार की आर से दी गई विभिन्न सुविधाओं (जैसे जल्दी और ज्यादा मुनाफे  
 वाले उपभाक्ता उद्योगों का काम, विदेशी प्रतियोगिता से पर्याप्त सुरक्षा तथा टेक्ना-  
 लॉजी, सस्थागत ढांचों, सस्ते श्रम और सरकारी षेसे की उपलब्धता) का फायदा  
 उठाकर और सरकारी टैक्सों व उचित मजदूरी की अदायगी से बचकर यह  
 बहिस्साव वामदनी जुटा लेता है। इस प्रकार वह सरकार, मजदूर वग और  
 की ठगी करता है। दूसरे, इन सुविधाओं का उपभोग करने के बावजूद

रखता का शिकार है। निजी क्षेत्र के दस लाख से अधिक उद्यमों में से इस समय 1,47,740 औद्योगिक इकाइयाँ बंद हैं<sup>43</sup> और इन पर 4,874 करोड़ रु० का बकाया बकाया है।<sup>44</sup> राजीव सरकार के पिछले तीन साल के दौरान ही करीब 40,000 फ़ैक्टरियाँ बंद हुई हैं, जिनसे लगभग दो लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं<sup>45</sup> तीसरे, पिछले पांच साल से गठजोड़ की बेहद गुंजाइश के बावजूद विदेशी सयुक्त उद्यमों में खासकर तीसरी दुनिया के देशों में भारतीय निजी निवेश वस्तुतः स्थिर रहा है। यह बात फंडेशन आफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 1987 के एक अध्ययन में कही गई है। जुलाई 1986 तक विदेशों के सयुक्त उद्यमों में कुल भारतीय निजी निवेश 114.13 करोड़ रु० था जबकि दिसंबर 1985 में यह 114.20 करोड़ रु० था।<sup>46</sup> चौथे, शेर बाजार (जिसके अर्थ करीब 20 लाख सदस्य हैं) काफी हद तक पुराने तरीकों व सस्थाओं द्वारा चलाए जाने के कारण सफट में चला आ रहा है, हालांकि निजी क्षेत्र को उसके स्वस्थ कामकाज की जरूरत है। पाचवें, सुरक्षित क्षेत्र होने की वजह से यह देश और विदेश में उच्च लागत वाला गैर प्रतियोगी क्षेत्र है।

निजी क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि यह है कि पहले ही अमीर बड़ी तर्जी से और ज्यादा अमीर हुए हैं। एकाधिकार जांच आयोग का अनुमान था कि निजी कंपनी क्षेत्र (बक कंपनी को छोड़कर) की 1964 में कुल संपत्ति 5,500 करोड़ रु० थी। इसमें से 46 फीसदी 75 बड़े औद्योगिक घरानों और 33 फीसदी 20 बड़े औद्योगिक घरानों की थी। इन बड़े औद्योगिक घरानों की संपत्ति 1963-64 में 1,780 करोड़ रु० से बढ़कर 1986-87 में 23,154 करोड़ रु०<sup>47</sup> हो गई यानी इसमें 13 गुना वृद्धि हुई। एक ही साल (1985-86) में अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी संपत्ति में करीब 1,000 करोड़ रु० का इजाफा किया (1,056 करोड़ रु० से बढ़कर यह 2,021 करोड़ रु० हो गई) जबकि बिडला घराने की संपत्ति 4,111 करोड़ रु० से बढ़कर 4,606 करोड़ रु० और टाटा घराने की 3,698 करोड़ रु० से 4,348 करोड़ रु० हो गई।<sup>48</sup> एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बड़े औद्योगिक घरानों की यह आवश्यकता वृद्धि औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली और दूसरे नियंत्रण के कारण हुई है। बड़े भारतीय औद्योगिक घराने निजी कंपनी क्षेत्र से कस अनुचित मुनाफा बटोर रहे हैं इसकी झलक आप्रवासी भारतीय उद्योगपति स्वराज पाल द्वारा 19 अगस्त 1983 को प्रेस क्लब आफ इंडिया में की गई टिप्पणी से मिलती है।<sup>49</sup> उन्होंने कहा था, "सुभाष्यपूर्ण बात है कि देश के मात्र 11 कारोबारी घराने उस उद्योग पर नियंत्रण जमाए हुए हैं जिसमें सांख्यिक सस्थानों में करीब 27,000 करोड़ रु० का निवेश कर रखा है जबकि इन घरानों का अपना निवेश महज 148 करोड़ रु० है", और कि ये "11 औद्योगिक घराने वित्तीय लाभों का एक बड़ा हिस्सा अपने स्वार्थों में लगा रहे हैं तथा कुछ अनुमानों के अनुसार उन्होंने 25,000 करोड़ रु० विदेशी बैंकों में जमा करा रखे हैं।" अभी तक इन घरानों ने इस टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की है।

## (iii) सरचनात्मक उद्योग

सरचनात्मक उद्योग के सभी प्रमुख क्षेत्र—विजली, रेल, इस्पात, सीमेंट आदि में वृद्धि हुई है। लेकिन उनके अपन अपन नियोजित लक्ष्य पूरे न हो पाने से आर्थिक प्रक्रिया में निरंतर बाधाएँ छाड़ी हुई हैं। विजली के क्षेत्र में छठी योजना का लक्ष्य 5 12 करोड़ किलोवाट का था जबकि असल पूर्ति 4 71 करोड़ किलोवाट ही हो पाई।<sup>50</sup> रेल टुलाई के मामले में छठी योजना का लक्ष्य 30 9 करोड़ टन था जबकि असल पूर्ति 26 5 करोड़ टन रही।<sup>51</sup> परिष्कृत इस्पात के क्षेत्र में छठी योजना का लक्ष्य 11 5 करोड़ टन था पर असल पूर्ति 8 8 करोड़ टन हुई।<sup>52</sup> सीमेंट के मामले में छठी योजना का 3 45 करोड़ टन का मगर असल पूर्ति 2 95 करोड़ टन रही।<sup>53</sup> आपूर्ति में इस कमी की झलक समूचे भारत में विजली के सपट (इस कमी का अनुमान 10,000 मेगावाट है),<sup>54</sup> रेलगाड़ियों में भारी भीड़ तथा इस्पात में सीमेंट की ऊँची कीमती से मिलती है।

## (iv) शिक्षा और स्वास्थ्य

सावजनिक शिक्षा के मामले में संविधान में प्रावधान है कि लागू होने के 15 वर्ष के भीतर (यानी 1965 तक) सबको शिक्षित किया जाना है। लेकिन इस लक्ष्य के 22 वर्ष बाद भी भारत की 64 फीसदी जनता अनपढ़ चली आ रही है। भारत की 36 फीसदी साक्षरता दर के मुकाबल वर्मा में यह 70 फीसदी और श्रीलंका में 85 फीसदी है।<sup>55</sup> समय के साथ साथ गिपट अनपढ़ों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में अनपढ़ों की संख्या 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का मिलाकर 33 4 करोड़ थी। 1971 में यह संख्या करीब 38 7 करोड़ और 1981 में करीब 43 7 करोड़ हो गई। अनपढ़ों की बढ़ती संख्या न सिर्फ जीवन स्तर सुधारने बल्कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के आधुनिकीकरण में भी रुकावट है। आज भारत शिक्षा पर 1950 की तुलना में प्रति व्यक्ति जाघी रकम ही खर्च कर रहा है<sup>56</sup> और अनुमान है कि शिक्षा खर्च का 90 फीसदी अब शिक्षकों की तनख्वाह पर ही खर्च हो रहा है।<sup>57</sup> पहली योजना राशि का 7 8 फीसदी शिक्षा के लिए रखा गया था पर सातवीं योजना में यह घटकर 3 5 फीसदी रह गया है।<sup>58</sup> शिक्षा सबघी बंदोबस्त को देखें तो भारत में करीब 94,000 प्राइमरी स्कूल बिना किसी इमारत के चल रहे हैं<sup>59</sup> और 1,92,000 से ज्यादा स्कूलों में बोर्ड चटाई या फर्निचर तक नहीं,<sup>60</sup> 40 फीसदी में ब्लैक बोर्ड नहीं,<sup>61</sup> 70 फीसदी में बच्चों के लिए पुस्तकें नहीं,<sup>62</sup> और 80 फीसदी में शौचालय की व्यवस्था नहीं।<sup>63</sup>

सावजनिक स्वास्थ्य के मामले में देश में सफाई और स्वास्थ्य सुधार के लिए अनेक योजनाएँ शुरू की गई हैं लेकिन आकड़े अपनी कहानी खुद बहते हैं। हीनता (विटामिन ए की कमी से), कोढ़ और तपेदिक के मामले में भारत दुनिया

अग्रणी है।<sup>64</sup> यहाँ 3,690 लोगों के पीछे एक डॉक्टर और 5,460 लोगों के पीछे एक नर्स है।<sup>65</sup> दो तिहाई भारतीयों का पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं और लगभग आधे गावों में न कोई सड़क है, न बिजली।<sup>66</sup> कहा जाता है कि राष्ट्र के स्वास्थ्य की नब्ज अक्सर शिशुओं की मृत्यु दर से पहचानी जाती है। दिलचस्प बात है कि चीन में शिशु मृत्यु दर भारत की तुलना में करीब एक तिहाई है।<sup>67</sup> यदि चीन आधुनिक तकनीक के बिना शिशु मृत्यु दर कम कर सकता है तो भारत क्या नहीं? अब उस सरकारी योजना का भारी प्रचार किया जा रहा है जिसका लक्ष्य 'सन् 2000 ई० तक सबके लिए स्वास्थ्य रखा गया है। लेकिन पुराना अनुभव (जो अक्सर भविष्य का सूचक होता है) बताता है कि कांग्रेस की 40 साल की स्वास्थ्य सबधी रणनीति कचलते रहने के बाद भी भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में एशियाई देशों में नीचे से तीसरे स्थान पर ही है।<sup>68</sup>

## 6 आधुनिकीकरण

भारतीय नियोजन का दूसरा उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाना रहा है। 1947 उपरांत भारत में आधुनिकीकरण का मतलब जाधिक गतिविधियों में ऐस सरचनात्मक और सस्थागत परिवर्तन लाना रहा है जिनसे पुरानी औपनिवेशिक जोर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बदला जा सके। यह परिवर्तन सक्षेप में तीन सघटकों में परिवर्तन से गठित रहा। एक तो राष्ट्रीय आय व रोजगार के ढांचे में बदलाव पर जोर दिया गया। दूसर, अर्थ व्यवस्था के ऐस विविधीकरण पर ध्यान दिया गया जिसमें अनेक किस्म की वस्तुओं का उत्पादन हो सके। तीसरे, टेक्नोलॉजी की तरक्की की तरफ रुझान रहा।

### (1) राष्ट्रीय आय का ढांचा

राष्ट्रीय आय के ढांचे में बदलाव पर नजर डालने से पता चलता है कि 1950-51 में विभिन्न क्षेत्रों का राष्ट्रीय आय में निम्न योगदान था<sup>69</sup>—प्राथमिक क्षेत्र (अर्थात् कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियाँ) 59 फीसदी, द्वितीय क्षेत्र (अर्थात् उद्योग, बिजली और इनसे जुड़ी गतिविधियाँ) 14.40 फीसदी, और तृतीय क्षेत्र (अर्थात् व्यापार, परिवहन, संचार, बैंक, बीमा, प्रशासन और इस जुड़ी सेवाएँ) 26.60 फीसदी। इसका मुकाबले 1985-86 में राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान इस प्रकार था<sup>70</sup>—प्राथमिक क्षेत्र 37 फीसदी, द्वितीय क्षेत्र 21.9 फीसदी और तृतीय क्षेत्र 41.1 फीसदी। विभिन्न क्षेत्रों के इस विश्लेषण से पता चलता है कि राष्ट्रीय आय में कृषि के योगदान में कमी हुई है और इसकी पूर्ति सेवा क्षेत्र ने की है जबकि औद्योगिक क्षेत्र का योगदान में हुई बढ़ातरी अभी भी कम है। लेकिन यह परिवर्तन निम्न कारणों से किसी बड़े सरचनात्मक परिवर्तन का संकेत नहीं देता।

पहली बात तो यह कि सेवा क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि मुटपतया प्रशासन, प्रतिरक्षा और होटलो व रस्तराजो व योगदान के कारण हुई है जबकि सरचनात्मक ढांचे के लिए महत्वपूर्ण परिवहन और संचार ने बहुत कम योगदान दिया है। दूसरे औद्योगिक क्षेत्र के हिस्से में हुई थोड़ी सी वृद्धि 1951-65 के दौरान ही हुई थी और 60 वाले दशक के मध्य से इसमें ठहराव-सा चला आ रहा है। तीसरे सबसे महत्वपूर्ण यह है कि श्रम के क्षेत्रवार ढांचे में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ। कृषि क्षेत्र में अब भी 70 फीसदी श्रम शक्ति तगी हुई है। काश्तवारा व मुकादले कृषि मजदूरो का अनुपात 1961 में श्रम शक्ति के 17.2 फीसदी से बढ़कर 1971 में 26.9 फीसदी हो गया और 1981 की जनगणना के अनुसार लगभग 25 फीसदी है। सारी श्रम शक्ति में उद्योगो के हिस्से में 1960 से कोई बदलाव नहीं आया और यह करीब 11 फीसदी कायम है। इस तरह कृषि में तगी और 1950-51 में 59 फीसदी राष्ट्रीय आय पर वसर कर रही 70 फीसदी श्रमिक शक्ति को अब 37 फीसदी राष्ट्रीय आय पर गुजारा करना पड़ रहा है। यह उलटा रज्जान औद्योगिक क्षेत्र के तीव्र विकास से ही बदल सकता है।

### (11) अध्धयवरथा में विविधता किस हद तक

जहां तक अयव्यवस्था के विविध क्षेत्रों का विकास का ताल्लुक है भारतीय अयव्यवस्था का ढांचा इस हद तक बदल गया है कि इसमें पारपरिक उद्योगो (जैसे चीनी, वपडा पटसन आदि) का महत्ता कम हा गई है जबकि नए उद्योगो (जैसे इजीनियरिंग, रसायन आदि) को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। लेकिन विविधीकरण की इस प्रक्रिया में कई खामिया हैं। पहली तो यह कि प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाओ (1951 से 65) के दौरान यह प्रक्रिया औसत गति से आगे बढ़ी है जबकि '60 वाले दशक के मध्य से इसकी रफ्तार बहुत धीमी रही। दूसरे, पिछले चार दशका के दौरान इसकी औसत विकास दर नियोजित लक्ष्य से पीछे रही है। तीसरे, इसमें अशुशलता की खासियत रही है। यह अशुशलता उत्पादन की ऊँची लागत (मसलन भारतीय स्टील अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर उपलब्ध स्टील से सवा दो गुना महंगा है, भारत में बिजली औसत अंतरराष्ट्रीय कीमत से 4 गुना और तावा 3 गुना महंगा है जबकि गेहूँ उत्पादन की लागत ऑस्ट्रेलिया और जर्जेटोना आदि से चार गुना ज्यादा है), उत्पादता के निम्न स्तर (मसलन भारत में गेहूँ का औसत उत्पादन 1,236 किलो प्रति हेक्टर है जबकि यूरोपीय संघ बाजार में देगा में यह 6,000 से 8,000 किलो और चीन में 4,000 किलो प्रति हेक्टर है) पूँजी, उत्पाद के दृष्टि अनुपात, सावजनिक क्षेत्र में घाट, क्षमता का कम उपयोग (यह क्षमता उद्योग से उद्योग और साल दर साल बदलती रहती है तथा स्टील ढलाई, साइकिल ट्यूब, घनन, बोयला घुलाई मशीनरी, सीमेंट मिल मशीनरी, भवन व सड़क निर्माण मशीनरी आदि जस कई इसके शिकार हैं), तथा उद्योग की रगता (जिसकी लपट में वपडा, स्टील की

इवाइया आदि हैं) से चलती है। चीये, इसमें धोत्रीय अमृतुला पैदा हो गया है, जिसके चलते कई राज्यों को बड़ा हिस्सा मिलता है। फँवट्टी क्षेत्र के लिए उद्योगों के वापिक सर्वेक्षण (1979-80) के अनुसार नौ राज्यों—आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भारतीय उद्योग भारी मात्रा में (करीब 80 फीसदी) है।

### (iii) टेक्नोलॉजी

टेक्नोलॉजी सुधार के मामले में भारत का रिकार्ड निराशाजनक है। यह बहुत हद तक आयातित टेक्नोलॉजी पर आश्रित रहा है। 1951 और 1986 के बीच भारत ने विदेशों से तकनीक आयात करने के लिए 2,219 समझौता पर हस्ताक्षर किए। टेक्नीकल फीस और रायल्टी के रूप में आयातित टेक्नोलॉजी के कुल भुगतान में भी भारी वृद्धि हुई है। 1964-65 में यह राशि चार करोड़ ₹० से बढ़कर 1972-73 में 186 करोड़ ₹० हो गई।<sup>71</sup>

टेक्नीकी अनुसंधान विकास पर भारत का वापिक खर्च कम है। विद्वान वैज्ञानिक शास्त्र संस्थान द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक<sup>72</sup> 1950-51 से 1980-81 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में तकनीकी विकास दर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 0.7 फीसदी और 1.1 फीसदी के बीच रही जबकि पूंजी संचय में वृद्धि की दर इसी दौरान करीब 4.7 फीसदी रही। नेहरू शासन के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर कुल खर्च 1958 के आसपास सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मात्र 0.23 फीसदी था।<sup>73</sup> अधिकांश विकसित देशों में तकनीकी विकास की दर 2.5 से 3 फीसदी के बीच हासिल कर ली है।<sup>74</sup>

### 7 आत्मनिर्भरता

भारतीय नियोजन का तीसरा उद्देश्य विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करने, आयतों के अनुकूल ढूँढकर तथा निर्यातों को बहुमुखी विस्तार देकर अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना (यानी अपने संसाधनों और निधि पर निर्भर करते हुए अधिकतम अधिक लाभ कमाना) था।

#### (1) विदेशी ऋण

भारतीय नियोजन की विदेशी सहायता पर निर्भरता गंभीर स्थिति में पहुँच चुकी है। विदेशी सहायता की राशि (जिसमें अनुदान व ऋण दोनों शामिल हैं और जिसमें अनुदान मुक्त सहायता के रूप में है जबकि ऋण भय व्याज चुकाना होता है) इतनी ज्यादा हो चुकी है कि भुगतान की समस्या ज्यादा कठिन हो गई है। वर्षों तक सरकार यह बहाना करती रही कि विदेशी ऋण नगण्य है। लेकिन अब सरकारी बयानों

मे भी चिंता जताई जाने लगी है। फरवरी 1988 के बजट सत्र में सरकार ने बताया कि भारत पर 22,517 करोड़ रु० विदेशी बज है मगर 24 नवंबर 1988 को सरकार ने फिर लोकसभा में बताया कि मार्च 1988 तक अत तक विदेशी ऋण 54,817 करोड़ रु० यानी अदरुनी बज का करीब दा तिहाई था। अब हम विदेशों से सालाना लगभग 6000 करोड़ रु० उधार लेते हैं। यह रकम 1980-81 की तुलना में तीन गुना ज्यादा है। शुरू में योजनाकारों का अनुमान था कि चौथी योजना के अंत (1976) तक विदेशी सहायता पर भारत की निर्भरता खत्म हो जाएगी जबकि पांचवी योजना का लक्ष्य था कि भारत 1985-86 तक आत्मनिर्भर हो जाएगा। लेकिन विदेशी बज के मामले में स्थिति गंभीर है। इस साल खतर के तीन संकेत मिले हैं। एक तो नीवें वित्त आयाग ने दूसरे भारत के महालखाकर ने ससद के समक्ष रखी अपनी रिपोर्ट में और तीसरे रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ये संकेत दिए। ये रिपोर्टें भारत के विदेशी बज के बारे में बहुत सारी चिंताजनक बातों की तरफ इशारा करती हैं। 1984-85 में विदेशी कज का भुगतान कुल निर्यातों से होना वाली आय का महज 13.6 फीसदी था और यह स्तर काफी सुरक्षित था। तब से लेकर यह गुब्बारे की तरह ऊपर ही ऊपर उठता जा रहा है 1985-86 में यह 21.2 फीसदी, 1987-88 में 24.1 फीसदी और चालू वर्ष में 27.2 फीसदी तक पहुंच गया है। इसमें निजी बजों का भुगतान शामिल नहीं है। यदि सरकारी और निजी विदेशी बज भुगतानों को जोड़ा जाए तो यह 33 फीसदी से भी ज्यादा बैठेगा। लेकिन वार्षिक गणना स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान के अनुसार 1986-87 में भारत के विदेशी बज का भुगतान 47 अरब डॉलर के कुल विदेशी बज का 33.5 फीसदी हो चुका था। भारत निश्चित रूप से विदेशी बज के जाल में फंस गया है क्योंकि विदेशी कज भुगतान के रूप में आयात 25 फीसदी से ज्यादा बढ़ते ही खतरनाक माना जाता है। ऐसी स्थिति में बाहर जाने वाले ससाधन दश में आने वाले ससाधनों से कहीं ज्यादा होते हैं। ज्यादा भयावह स्थिति तो सावजनिक बज की है जो मार्च 1987 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 64 फीसदी था<sup>6</sup> (1987 में 99,520 करोड़ रु० और 1988 में 1,10,000 करोड़ रु०)। पिछले पांच वर्षों में सरकार द्वारा सावजनिक बज पर ब्याज भुगतान में 250 फीसदी की वृद्धि हुई है यानी 1987-88 में यह कुल बज प्राप्तियों का 21.9 फीसदी हो गया है।<sup>7</sup>

विदेशी और अदरुनी बजों में नाटकीय वृद्धि का मुख्य कारण बजट और विदेशी व्यापार का बढ़ता घाटा है। विदेशी व्यापार का घाटा 1970-71 के 99 करोड़ रु० से बढ़कर 1985-86 में 8,735 करोड़ रु० हो गया।<sup>8</sup> चालू वर्ष में केंद्र सरकार के बजट में 7,484 करोड़ रु० के घाट को बिना पूरा किए छोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त राज्यों का घाटा 842 करोड़ रु० का था। लेकिन पांच वर्ष पहले इनका संयुक्त घाटा लगभग 1,600 करोड़ रु० ही था।<sup>9</sup> मौजूदा रूझानों अनुसार केंद्रीय घाटा खतर की सीमा पार कर गया है और चालू वर्ष के



12,000 करोड़ रु० तक जा सकता है।<sup>80</sup> यह एन रिवाइड वट्टि है जा सबल राष्ट्रीय उत्पाद का करीब 35 फीसदी है। राज्यों व लिए घाटे की सीमा जहा बजट का मात्र एक फीसदी मुक्करर है वही केंद्र व लिए यह सीमा 10 फीसदी है। बजट म भारी घाटे से कीमतों म वट्टि होती है जिससे रहत सहा और विकास कार्यों का खच बढ जाता है। भारी मात्रा मे विदेशी व अदरुनी वज और बजट म घाटा सरकार को दिवालिपन की तरफ ले जा रहे है। 1988 मे इसकी कुल दादारी 2,24,180 करोड़ रु० मूल्य की और कुल परिसपति मात्र 184,100 कराट रु० की थी यानी देनदारी 40080 करोड ज्यादा है।<sup>81</sup>

भारतीय अथ वचस्या को ससाधना की कमी का सामना है। पिछल दशक के दौरान उसकी वचत दर म लगातार कमी हाती रही है। वचत दर 4 वष पहल 24 फीसदी थी जबकि दो वष पहल घटकर 18 फीसदी रह गई है।<sup>82</sup> दूसरी तरफ निवेश मे लगातार वट्टि हो रही है। निवेश जोर वचत के अतर को प्रतिदिन 20 करोड रु० उधार लेकर और घाटे की अथव्यवस्या के जरिए (यह भी प्रतिदिन 20 करोड रु० है) पूरा किया जा रहा है।<sup>83</sup>

रुपए व बाहरी मूल्य मे तेजी से कमी हुई है। चार साल पहले पौंड स्टर्लिंग 15.15 रु० मूल्य का था। नवंबर 1988 म इसका मूल्य 27.40 रु० व बराबर पहुच गया है। यह खतरे का संकेत है। क्याकि भारत को साने की तस्वीरी और इससे रुपए के अवमूर्यन के कारण अरबा रुपए का (एक अनुमान व अनुसार 10000 करोड रु० का—टाइम्स आफ इंडिया, 7.12.1988, पृ० 4) विदेशी मुद्रा का नुकसान हा रहा है।

## (ii) आयात प्रतिस्थापन

जहा तक आयात प्रतिस्थापन (अर्थात बाहर स भगाई जान वाली वस्तुओ का देश म ही निर्माण करने और इस प्रकार देश के औद्योगीकरण और विदेशी मुद्रा को बचाने) का सबध है, भारत इस उद्देश्य म अभी तक सफल नहीं हुआ है। 1947 के बाद स भारत ने 13,000 विदेशी सहयोग के अनुबध किए है।<sup>84</sup> लेकिन सहयोग वाली कोई भी इकाई आयात व मामले म स्वायत्त नहीं बन पाई और बिना किसी आयात तत्व वाली कोई भी बडी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं की जा सकी है।<sup>85</sup> आयात प्रतिस्थापन की रणनीति आम तौर पर दा रूप लेती है—स्वायत्त आयातित प्रतिस्थापन' और जायातित आयात प्रतिस्थापन'। पहला माडल जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान आदि ने अपनाया जबकि भारत ने दूसरे माडल को चुना जिसस औद्योगीकरण की प्रक्रिया तकनीक, वित्त और सेवाओ व आयात पर अधिक निर्भर हो गई।

### (iii) निर्यात प्रोत्साहन

जहाँ तक निर्यात की विविधता (अर्थात् विकास पर आधारित निर्यात की रणनीति जिससे आयात के भूगतान के लिए विदेशी मुद्रा की कमाई होती है और जिसके मुताबिक निर्यात विकास का इंजिन होता है) का सवाल है, भारत की उपलब्ध विलकुल असतोपजनक है। यह निम्न रथानों से जाहिर है। पहली बात तो यह है कि 35 वर्षों में निर्यात लगभग 18 गुना बढ़ा है<sup>86</sup> (1950-51 में 600 करोड़ रु० से घटकर 1985-86 में यह 11,012 करोड़ रु० हो गया)। यह वृद्धि कीमतों में बढ़ोतरी की ही प्रकट करती है, आयात की मात्रा में वृद्धि का नहीं। दूसरे, निर्यात की विविधता उन कुछ उत्पादों तक ही सीमित रही है जिनकी मात्रा भी सीमित रही है। तीसरे, भारतीय निर्यात अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ावों के अनुरूप ढलने में असफल रहा है। चौथे, एक अहितकर प्रवृत्ति यह रही है कि विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा लगातार कम होता रहा है (जो 1950-51 में 2.4 फीसदी से घटकर पिछले कुछ वर्षों में मात्र 0.5 फीसदी रह गया है)।<sup>87</sup> इस घटिया उपलब्धि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं—पारंपरिक निर्यात पर बहुत ज्यादा निर्भरता, प्रतियोगी स्थिति में न पहुँचना, पर्याप्त घरेलू बाजार की उपलब्धता निम्नकाटि के संस्थागत प्रबंध (जैसे कि जानकारी, ऋण सुविधाएँ आदि) तथा बाहरी दबाव (जैसे मंदी की हालत, संरक्षणवाद आदि)।

### 8 सामाजिक "याय

भारतीय नियोजन का चौथा उद्देश्य कमजोर तबकों के जीवन स्तर को सुधारकर, बेरोजगारी को दूर करके तथा आय और परिसंपत्तियों के वितरण में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भारी असमानताओं का दूर करके गरीबों को सामाजिक "याय प्रदान करना रहा है।

#### (1) गरीबी

कमजोर तबकों के जीवन स्तर को सुधारने के मामले में स्थिति बहुत निराशाजनक रही है। गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने में सारी योजनाएँ असफल हो गई हैं। उनकी गरीबी की तस्वीर भयावह है। यह तस्वीर सरकारी सोच के आधार पर खींची गई है जिसके अनुसार भारत में गरीब वे हैं जो पहले ही से तब "यूनतम उपभोग स्तर—गरीबी रेखा—से कम खर्च करते हैं। "यूनतम उपभोग खर्च पहले ही से तब "यूनतम पोषण मापदंड पर आधारित है। यह मापदंड मानव अस्तित्व के लिए जरूरी बेलॉरी संख्या पर आधारित है जिसे भोजन की निश्चित मात्रा से प्राप्त किया जा सकता है। निश्चित कीमतों पर उस भोजन सामग्री को खरीदने के लिए जितने

रूपयो की जरूरत होती है, उसे 'यूनतम उपभोग' खच माना जाता है। कोई भी व्यक्ति जो इस राशि से कम खच में गुजर बसर करता है उसे गरीब माना जाता है। इस प्रकार के सारे लोग ही मिलकर भारतीय जनसंख्या का वह हिस्सा बनते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे ज़िंदगी बसर करता है। स्पष्टतया, यह सोच पूणतया एकपक्षीय है क्योंकि मान खाद्यसामग्री को ही इसमें शामिल किया जाता है और बाकी ज़रूरी चीज़ें जैसे पीने का साफ पानी, कपड़ा, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएँ आदि इसमें शामिल नहीं हैं। लेकिन इस सामान्य नुटिपूण रवैए के बावजूद विभिन्न गरीबी जाच विशेषज्ञों (बढ़न—1970 और 1973, दाडकर और रथ—1971, मिहास—1974, अहलूवालिया—1978, सुखात्मे—1978 तथा विभिन्न राष्ट्रीय सपस सर्वेक्षणों आदि) न गरीबी के विभिन्न अनुमान प्रस्तुत किए हैं क्योंकि पोषण के बारे में उनके मापदंडों और खच का 'यूनतम स्तर' निर्धारित करने में उनके द्वारा चुने गये मूल्य सूचकांकों में भिन्नता थी। लेकिन ये सब जाचें साफ सकेत देती हैं कि यह समस्या कितनी विकराल और 'यापक' है। विकास के बारे में संयुक्त राष्ट्र की हाल ही की रिपोर्ट<sup>88</sup> बताती है कि 1965 में निपट गरीबों की संख्या 35 करोड़ थी जो 1977 में 80 करोड़ और 1986 में तीन गुना बढ़कर 100 करोड़ से ज्यादा हो गई। इनमें 30 फीसदी गरीब भारत में रहते हैं। यही दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब बसते हैं। इस लिहाज़ से भारत के गरीबों की आबादी अफ्रीकी महाद्वीप या लेटिन अमेरिका या दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मुक्त सोवियत संघ की आबादी से भी ज्यादा है। केंद्रीय उर्जामंत्री बसंत साठे के अनुसार 1981-82 में भारत की 70 करोड़ आबादी में से 60 करोड़ (जो उस समय करीब 85 फीसदी बनती थी) गरीबी की रेखा पर या उसके नीचे बसर कर रही थी।<sup>89</sup> इसमें वह सौभाग्यशाली वर्ग (करीब 8.52 करोड़ लोग) शामिल नहीं जिसमें प्रति व्यक्ति 1200 रु० या उससे ज्यादा प्रतिवर्ष खच करता है और जिसके इदगिद सारी आर्थिक गतिविधियाँ केंद्रित हैं।<sup>90</sup> भारतीय लोगों के एक हिस्से की समृद्धि का दूसरा आर्थिक सूचक आयकर रहा है। 1979-80 में कुल आयकर दाताओं की संख्या 18 लाख से ऊपर थी। करीब 75 फीसदी कर उन लोगों ने भरा जिनकी अनुमानित आय एक लाख रु० या इससे ज्यादा थी। ऐसे लोगों की संख्या महज 34,607 थी। ध्यान देन योग्य बात है कि सालाना 5 लाख या उससे ज्यादा कर योग्य आय वाले और कुल आयकर का 65 फीसदी भुगतान करन वाले लोगों की संख्या कुल आबादी में मात्र 3,245 थी।<sup>9</sup>

कीमती में लगातार बढि गरीबी को निचोडती जा रही है। जुलाई 1984 में मूल्य सूचकांक 1960 के आधार पर 598 था, 1947 के आधार पर 761 और अगस्त 1939 के आधार पर 2,623 था।<sup>93</sup> 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान यह मूल्य सूचकांक क्रमशः 4, 5.5<sup>94</sup> और 9 फीसदी की बृद्धि हुई जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हर बार इससे एक से दो फीसदी ज्यादा रहा। आवास में भी गरीबों को परेशान किए रखा है। लगभग तीन करोड़ लोग गंदी बस्तियों

मे रह रहे हैं। भारत में लगभग 24 करोड़ मकानों की कमी आती गई है।<sup>95</sup>

गरीबी की मार सबसे ज्यादा देहाती इलाकों में है जहाँ 70 फीसदी लोग रहते हैं और समूची देहाती आबादी में से करीब 40-50 फीसदी निपट गरीब है। अर्थात् वे पोषण के लिहाज से 'यूनितम प्रस्तावित खाद्य सामग्री का उपभोग करने में असमर्थ हैं।<sup>96</sup> ग्रामीण अथवा कृषि मजदूरों की स्थिति भयावह है। श्रमिक मंत्रालय से जुड़ी ससदीय सलाहकार समिति ने निष्कर्ष निकाला है<sup>97</sup> कि करीब सात करोड़ (यानी कुल आबादी का 10 फीसदी) आके गए कृषि मजदूरों का अर्थात् क्षेत्रों में साल में 60-70 दिन और मिचित क्षेत्रों में 120 दिन से अधिक रोजगार नहीं मिलता। निजी ठेकेदार 'यूनितम मजदूरी नहीं देते। यहाँ तक कि कुछ सरकारी विभाग भी पूरा भुगतान नहीं करते और स्थानीय प्रशासन आम तौर पर इन असहाय गरीबों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अख्तियार नहीं करता। समिति ने यह भी कहा है कि सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का ठोस असर नहीं हुआ है। औरतों को समान काम के लिए मर्दों से कम मजदूरी देने की अपसोसपूर्ण प्रथा बेरोकटोक जारी है। कई राज्यों में बहुआ मजदूरी का दस्तूर है और 'सलगन' मजदूरी वास्तव में बहुआ मजदूरी का ही दूसरा रूप है।

प्रति व्यक्ति आय भी किसी देश के हालात जिंदगी का एक मोटा सूचक हो सकती है। पिछले तीन दशकों के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत धीमी गति से बढ़ी है। यह विश्व में अल्पविकसित देशों की विकास दर के मुकाबले आधी से भी कम है।<sup>98</sup> प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से भारत अल्पविकसित देशों के समूह में 66वें स्थान पर है।<sup>99</sup> मूलभूत उपभोग वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में भी कमी का रुझान दिखता है। चर्च समेत खाद्य सामग्री की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी 1960-61 में 4687 ग्राम<sup>100</sup> से 1984-85 में 4633 ग्राम<sup>101</sup> पर ठहराव की स्थिति ही दर्शाती है। दालों का प्रति व्यक्ति उपभोग, जो गरीबों के लिए प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है भी इसी दौरान कम होकर आधा रह गया है। यह मात्रा 1961 में 69 ग्राम से घटकर 1985 में 39 ग्राम ही रह गई है। सूती कपड़े का प्रति व्यक्ति उपभोग 1960-61 में 138 मीटर से कम होकर 1984-85 में 106 मीटर ही रह गया है।<sup>102</sup> 1947 में भारत विश्व के सबसे गरीब देशों में एक था। आज यह विश्व में गरीबी की संख्या में वृद्धि करने वाला अकेला सबसे बड़ा देश है। 1947 से लेकर प्रत्येक योजना दस्तावेज बयान और शासक दल के घोषणापत्र में भारत से गरीबी हटाने की बात दुहराई गई। लेकिन गरीबों के लिए निर्धारित नीतियाँ और कार्यक्रम वास्तव में परिणाम नहीं दे सके। प्रधानमंत्री ने खुद माना है कि गरीबों को आवंटित प्रत्येक छह रु० में से मात्र एक रुपया ही उन तक पहुँचता है।<sup>103</sup> यही वजह है कि व्यापक गरीबी का सवाल आज भी भारत में सबसे ज्यादा अहम है।

## (ii) बेरोजगारी

बेरोजगारी की स्थिति भी वह निर्वाशाजग है। प्रत्येक योजना में बेरोजगारी कम करने का लक्ष्य रखा गया लेकिन हर योजना के बाद बेरोजगारी लगभग दुगुनी होती गई। पहली योजना की समाप्ति पर बेरोजगारी 29 फीसदी थी। तीसरी योजना की समाप्ति पर यह बढ़कर 45 फीसदी हो गई और मार्च 1969 के आखिर तक यह आवश्यकजनक रूप से बढ़कर 96 फीसदी हो गई। बेरोजगारी के बारे में सरकारी विशेषज्ञ समिति ने अपनी 1973 की रिपोर्ट में टिप्पणी की है "आकड़ा के आधार पर माना जा सकता है कि 1971 में बेरोजगारी की समाप्ति लगभग 1.87 करोड़ थी। इसमें 90 लाख लोग ऐसे भी हैं जिनके पास किसी प्रकार का रोजगार नहीं है और 97 लाख व हैं जिन्हें सप्ताह में 14 घंटे से भी कम काम मिलता है। इन्हें भी बेरोजगारों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इनमें 1.61 करोड़ (यानी कुल बेरोजगारों का 86 फीसदी) ग्रामीण क्षेत्रों में और 26 लाख शहरों में हैं।" समूचे देश में बेरोजगार कुल थम शक्ति का 10.4 फीसदी है। इनमें 10.9 फीसदी ग्रामीण क्षेत्रों में और 8.1 फीसदी शहरी क्षेत्रों में है। इसके अतिरिक्त उपरान्त समिति के अनुसार 2.352 करोड़ लोग (यानी भारत की थम शक्ति का 15.9 फीसदी) सप्ताह में 28 घंटे से कम काम मिलने के कारण अर्द्ध बेरोजगार थे। 1979-80 में 5वीं योजना की समाप्ति पर भारत में 1.2 करोड़ लोग बेरोजगार थे। छठी योजना की समाप्ति पर बेरोजगारों की संख्या 1.39 करोड़ थी। 7वीं योजना में घोषणा की गई कि 3.99 फीसदी सालाना विकास दर के हिसाब से योजना के दौरान 4.036 करोड़ मानव व्यक्ति वर्ष अतिरिक्त रोजगार जुटाया जाएगा। मगर सरकार की इस क्षमता में उपलब्धि पर एक प्रसिद्ध साप्ताहिक की टिप्पणी देते हुए 'जोधागिक विकास के दावे का एक और भयावह पहलू यह है कि 1983 के बाद औद्योगिक क्षेत्र में कोई रोजगार पैदा नहीं हुआ। कुल मिलाकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कारखानों में मार्च 1983 के अंत तक 62.6 लाख और मार्च 1985 के अंत तक आखिरी मूचन जो आर्थिक सर्वेक्षण में दी गई है, 61.8 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। इस पर भी आर्थिक सर्वेक्षण में यह टिप्पणी करने में कोई हिचक महसूस नहीं की गई कि औद्योगिक नीति का प्रमुख जार उत्पादन को बढ़ावा देना और रोजगार पैदा करना है। विस्तार में यह नाकामी दूसरे क्षेत्रों में भी चलवती है। कुल मिलाकर संगठित क्षेत्र में (जिसमें सरकारी प्रशासन और प्रतिरक्षा भी शामिल है) जून 1985 और जून 1986 के बीच रोजगार में मात्र 1.6 फीसदी की ही वृद्धि हुई। दूसरे शब्दों में, थम शक्ति में 2.6 फीसदी की दर से वृद्धि होने के कारण संगठित क्षेत्र में रोजगार का अनुपात वास्तव में घटता जा रहा है। 1987 के अंत तक भारत में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 3 करोड़ हो गई।<sup>101</sup> अर्थात् 1957 से 1987 के बीच बेरोजगारों की संख्या में 10 गुना वृद्धि हुई (1951 में बेरोजगारों की संख्या मात्र 30 लाख ही थी) जबकि जनसंख्या में इसी दौरान मात्र 2.5 गुना वृद्धि ही हुई है। इन

3 करोड़ पजीवित बेरोजगारों में लगभग 30 लाख (हिंदुस्तान टाइम्स, 29 2 88, पृष्ठ 16 के अनुसार) डॉक्टर, इंजीनियर और विज्ञान के स्नातक हैं। लेकिन सबसे चिंताजनक बात तो प्राथमिक व माध्यमिक क्षेत्रों में बेरोजगारी के रज्जान में कमी होना है। जनगणना के आकड़े बताते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रों की सभी नौकरियां में निरंतर कमी आई है। 1961 में 74 26 फीसदी से घटकर 1981 में ये 69 33 फीसदी रह गई हैं।<sup>100</sup> यदि फालतू लागू माध्यमिक या तृतीय क्षेत्रों में रोजगार पा लेते तो यह कमी स्वागतयोग्य होती। लेकिन जहां तृतीय (अथवा सेवा) क्षेत्र में रोजगार में कुछ वृद्धि हुई है, वहीं माध्यमिक क्षेत्र इस मामले में वस्तुतः स्थिर रहा है। हकीकत में सगठित माध्यमिक क्षेत्र की सभी नौकरियां 1961 की 37 3 फीसदी से घटकर 1987 में 32 9 फीसदी रह गई हैं।<sup>106</sup> इसकी प्रमुख वजह यह है कि निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हो गए हैं। जहां सगठित निजी क्षेत्र में 1961 और 1987 के बीच रोजगार में 1 2 फीसदी कमी हुई है वहीं इसी दौरान सगठित सरकारी क्षेत्र में 3 फीसदी की वृद्धि हुई।<sup>107</sup> पिछले कुछ वर्षों में निजी क्षेत्र ने कोई ऐसी परियोजना नहीं दी है जिसमें 500 से ज्यादा लोगों का सीधा रोजगार दिया गया हो। सावजनिक क्षेत्र भी नए रोजगार पैदा करने में अक्षम है। इसमें पहले ही जहरत से ज्यादा कमचारी भरे हैं। इसलिए प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर न होने की स्थिति में बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने का बीड़ा तृतीय (सेवा) क्षेत्र के कंधे पर है। लेकिन सगठित तृतीय क्षेत्र (सरकारी सेवाएं, व्यापार, परिवहन व संचार आदि) में भी बहुत सारी अनुत्पादक नौकरियां ही हैं। प्रशासनिक सेवा क्षेत्र पहले ही जहरत से ज्यादा लोगों से भरा है। इस समय नई सरकारी नौकरियों पर पाबंदी लगी है। ऐसी हालत में नए रोजगार या तो असगठित क्षेत्र में स्वयं रोजगार के जरिए या बड़े उद्योगों को लगाकर (जिससे नए उद्योग धंधे पनपें) पैदा किए जा सकते हैं। यह काम किसी भी सूरत में साल दो साल में पूरा नहीं किया जा सकता। योजना आयोग के एक सदस्य ने कहा था कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति की बात तो अगले 20 वर्षों तक सोची भी नहीं जा सकती।<sup>108</sup>

आम भाषा में बेरोजगारी का मतलब है ऐसे लोगों के लिए काम का पूर्ण अभाव जो कोई नौकरी नहीं करते पर सरगर्मी से काम की तलाश में हैं या फिर उन लोगों के लिए काम की कमी जो छिटपुट काम कर रहे पर पूर्णकालिक रोजगार चाहते हैं। सामाजिक तौर पर बेरोजगारी का मतलब वह अप्रयुक्त मानव श्रम अथवा मानव ससाधनों का वह क्षय है जिस किसी श्रम विभाजन में इस्तेमाल नहीं किया जा सका। बेरोजगारी की कई किस्में हैं—जैसे कि उच्च मजदूरी दर, चक्रीय, घघणात्मक, सरचनात्मक, टेक्नोलाजिकल आदि। और हर प्रकार की बेरोजगारी का अपना कारण और समाधान होता है। वहरहाल बेरोजगारी का आम कारण श्रम की मांग और पूर्ति के बीच असंतुलन होना है। इसका आम समाधान यह है कि इस असंतुलन दूर किया जाए।

## (111) परिसंपत्ति और आय वितरण में असमानताएँ

परिसंपत्ति और आय वितरण में असमानताओं की स्थिति बहुत ही दुःखदायी है। हर योजना के बावजूद इन असमानताओं का कम करने की बात दुहराई गई मगर स्थिति और खराब होती गई।

भारतीय अर्थव्यवस्था में परिसंपत्ति का वितरण बेहद असमान है। मसलन 1961 और 1971 के अखिल भारतीय ऋण एव निवेश सर्वेक्षणों के अनुसार इन दोनों वर्षों में सबसे गरीब 10 फीसदी लोगों के पास परिसंपत्ति का महज 0.1 फीसदी हिस्सा था। यहाँ तक कि 1961 में सबसे गरीब 30 फीसदी लोगों के पास परिसंपत्ति का 2.5 फीसदी हिस्सा था जो 1971 में मात्र 2 फीसदी ही रह गया। इसके विपरीत सबसे अमीर 10 फीसदी लोगों के पास 1961 और 1971 में क्रमशः 51.4 फीसदी और 51 फीसदी हिस्सा था। 1961 में सबसे अमीर 30 फीसदी के पास 79 फीसदी और 1971 में 81.9 फीसदी हिस्सा था। गरीब लोगों की अधिकांश परिसंपत्ति ज़ापड़ियाँ, घरेलू सामान और कुछ पशु थे जिनसे होन वाली आय नहीं के बराबर थी।

जहाँ तक जमीन का प्रश्न है, मिलकियती अथवा बटाई पर ली गईं जोतों के आँकड़े बताते हैं कि 1976-77 में 2 हेक्टेयर से भी कम की जोत वाले छोटे व सीमांत किसान 70 फीसदी से भी ज्यादा थे। पर व कुल जमीन के मात्र 24 फीसदी हिस्से पर ही काम करते थे। इसके विपरीत 2 से 10 हेक्टेयर की जोत वाले किसान कुल जमीन के 50 फीसदी हिस्से पर काम करते थे। 10 हेक्टेयर से ज्यादा की जोत वाले सबसे अमीर 3 फीसदी लोग 26 फीसदी जमीन के मालिक थे।

राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने अनुमान लगाया है कि गहरी धंधों में 57 फीसदी निर्मित संपत्ति सर्वोच्च 10 फीसदी संपत्ति मालिकों के कब्जे में है जबकि नीचे के 10 फीसदी परिवारों के पास इस संपत्ति का मात्र एक फीसदी भाग है। कंपनी शेयरों की मिलकियत के मामले में महालनायकिस समिति ने अनुमान लगाया कि 1964 के आसपास शेयरों के रूप में परिसंपत्ति का आधे से ज्यादा भाग लाभार्थी बनाने वाले सर्वोच्च एक फीसदी परिवारों के पास था। उसके बाद स्थिति में और बिगाड़ ही हुआ होगा जसा कि बड़े पैमाने पर होने वाली करो की चोरी और भारी मात्रा में काले धन के देश के बाहर जान से स्पष्ट होता है।

समय समय पर किए जाने वाले जाँच सर्वेक्षणों से स्पष्ट होता है कि आय का वितरण भी बेहद असमान है। लिडाल ने अनुमान के अनुसार 1955-56 में ऊपर के 10 फीसदी लोग राष्ट्रीय आय का 34 फीसदी हूबप जाते थे जबकि नीचे के 25 फीसदी लोगों के पल्ले 9.6 फीसदी हिस्सा ही आता था। आयकर और मुछर्जियों के अनुमान के अनुसार 1956-57 में ऊपर के 10 फीसदी लोग राष्ट्रीय आय का 25 फीसदी हिस्सा ले जाते थे जबकि नीचे के 24 फीसदी लोगों को मात्र 8.5 फीसदी

ही मिल रहा था। 1950 वाले दशक के लिए रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में (1953-54 में) ऊपर के 5 फीसदी लोगों को राष्ट्रीय आय का 17 फीसदी और निम्न 20 फीसदी को 9 फीसदी हिस्सा मिल रहा था। इन अनुमानों से यह भी पता चलता है कि 1956-57 में शहरी क्षेत्रों में ऊपर के 5 फीसदी लोगों को राष्ट्रीय आय का 25 फीसदी हिस्सा मिला जबकि नीचे के 20 फीसदी मात्र 7 फीसदी पर गुजारा करते थे। वरीय 20 वष बाद राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिपद का 1970-71 के लिए अनुमान था कि ऊपर के 30 फीसदी लोगों को राष्ट्रीय आय का 53.4 फीसदी हिस्सा मिला जबकि नीचे के 30 फीसदी लोग मात्र 11.3 फीसदी पर ही गुजर कर रहे थे।

बढ़ती हुई असमानता से गरीबी दूर होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सापेक्ष गरीबी को दूर किए बिना निरपेक्ष गरीबी कैसे दूर की जा सकती है।

### 9 काला धन

भारत का नियोजित आर्थिक विकास जहाँ घोषित लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच अंतर से सदा पीड़ित रहा, वही सरकार द्वारा काले धन की अथव्यवस्था को हर तरीके से खत्म करने की बार-बार घोषणाओं के बावजूद उसमें तेजी से वृद्धि हुई है।

काली अथव्यवस्था से अभिप्राय बिना लेखे-जोखे वाले ऐसे धन से है जो गैर-कानूनी गतिविधियों से जुटाया जाता है। इसे समांतर अथव्यवस्था भी कहते हैं। इसे 'दो नम्बर वाले खातों' के व्यवसाय में इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि साने, हीरे-जवाहरात की वस्तुओं की तस्करी, विदेशी मुद्रा का गैरकानूनी लेन देन, जमाखोरी, सट्टेबाजी, अनुचित लाभ और काला बाजारी के लिए वंशकीमती वस्तुओं की खरीदारी गुप्त दलाली, रिश्वतखोरी, मुकदमेबाजी आदि में पैसा लगाना, कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ, आभूषण आदि जँभी चल व अचल संपत्ति की खरीदारी, बनामी और झूठे नामों से देशी विदेशी वकों में जमा गुप्त व झूठे नामों से दान देना वगैरह-वगैरह। सबसे बड़ी बात यह कि यह धन चुनाव में खर्च होता है और राजनैतिक पार्टियों को चढ़े के तौर पर भी दिया जाता है।

काले धन का अदाजा लगाने के लिए पहले पहल प्रत्यक्ष कर जाँच समिति ने जिसे वाचू समिति के नाम से जाना जाता है 1971 में प्रयत्न किया था। उसका अनुमान था कि 1968-69 में काले धन की मात्रा 7,000 करोड़ ₹० या सकल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 6.5 फीसदी थी। 1980 वाले दशक के शुरू में किए गए एक अध्ययन<sup>109</sup> के अनुसार 1978-79 में देश में 46,866 करोड़ ₹० का काला धन था जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सरकारी आकड़ों का 48.8 फीसदी था। हाल ही में राष्ट्रीय सावजनिक वित्त नीति संस्थान ने अनुमान लगाया है कि 1984-85 में 36,786 करोड़ ₹० है। यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 21 फीसदी है। अद्य घट में 4 करोड़ ₹० के बराबर काला धन पनपता है। केंद्रीय उर्जा मंत्रो



के अनुसार यह रकम बढ़कर 70 000 करोड़ रु० हो गई है।

सफल राष्ट्रीय उत्पाद आर्थिक गतिविधि के सिद्धान्त से तमाम जनसंख्या में बढ़ता है, तो काला धन ऐसा धधा कराने वाले कुछ हजार लोगों तक ही सीमित रहता है। सफल राष्ट्रीय उत्पाद का वरीय 21 फीसदी कुछ ही हाथों में सीमित है। इस तथ्य से पता चलता है कि दश में शीलत आय का जिस हद तक अनुचित वितरण है। सभी प्रमुख राजनैतिक दल प्रत्यक्ष या पराध रूप से इससे जुड़े हैं।<sup>110</sup> आज विधायिका की एक भी सीट काले धन के बिना नहीं जीती जा सकती। जरा भर ईमानदारी रखने वाला कोई सांसद या विधायक यह नहीं कह सकता कि उसका सारे चुनाव पक्ष कानून के अनुसार थे। स्पष्टतया यह अत्यधिक चुनाव खर्च काले धन से पूरे होते हैं। काले धन के प्रश्न पर सत्ताधारी कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दलों में झगडा इस बात पर है कि इसका बड़ा हिस्सा सत्ताधारी दल मार ले जाता है जबकि दूसरे के हिस्से कम ही ही रकम आती है।

काले धन का प्रचलन न भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई तरीकों से बुरा असर डाला है। पहली बात तो यह कि राष्ट्रीय ससाधना का गलत इस्तेमाल हुआ है। उन्हें या तो अनुत्पादक गतिविधियों में लगाया जाता है या दिग्बाध के नामों पर फिजूलखर्चों की जाती है या भारत से बाहर ले जाकर विदेशी बैंकों में जमा करवा दिया जाता है। पैसे का यह वार्षिक पलायन लगभग 13 अरब डॉलर है।<sup>111</sup> दूसरा असर यह हुआ कि आय के असमान वितरण में बढ़ोत्तरी हुई है। तीसरे, सांस्कृतिक मूल्यों में ह्रास हुआ है जिससे ईमानदारी और बड़ी महनत का कोई मूल्य नहीं रहा तथा राजनैतिक प्रक्रिया समेत हर जगह धन शक्ति और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है।

काले धन का जम देने वाले मुख्य कारण यह हैं आवश्यक वस्तुओं की कमी और चार बाजारी में उनकी बिस्की, सीमित ससाधना को चलाने के लिए बढ़ोली, परमिट्टा लाइसेंसों कोटा प्रणाली आदि का लागू किया जाना, चोरी छिपे लेन-देन में इन परमिट्टों, कोटा और लाइसेंसों की ऊँची कीमतें तथा इन्हें पाने के लिए रिश्वत और भ्रष्टाचार कर चोरी निम्न सांस्कृतिक स्तर, तथा निरकुश राजनैतिक प्रणाली।

सरकार काले धन को दबाने की जितनी घोषणाएँ करती है उतनी ही इसमें वृद्धि होती जाती है। क्योंकि जब तक इसके प्रमुख कारण बने रहेंगे इसका अंत नहीं हो सकता। काली अर्थव्यवस्था की समस्या सरचनात्मक है। इसलिए इसके ख़ात्मे के लिए एकीकृत राजनैतिक आर्थिक व सांस्कृतिक प्रयासों की जरूरत है। काला धन खत्म करने का एकमात्र रास्ता आर्थिक प्रक्रिया पर लोगों का नियंत्रण कायम करना है।

## 10 भारतीय जनता पर लादी गई भारी हानि

इस सर्वेक्षण में विश्लेषित विभिन्न आर्थिक तत्वों को जोड़ने पर भारतीय अर्थव्यवस्था की निराशाजनक तस्वीर उभरती है। इसके कामकाज को आय वृद्धि दर के

पश्चिमो उदारवादी पैमाने से नापा जाए या गरीबी उन्मूलन अथवा आय असमानता घटाने के समाजवादी मापमंड से, किसी भी हालत में इसे दुरुस्त नहीं ठहराया जा सकता। क्या भारत किसी दूसरे ढंग से बहतर परिणाम प्राप्त कर सकता था? दुनिया में तुलना करने पर पता चलता है कि चीन, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, ताइवान आदि जैसे तीसरी दुनिया के अलग-अलग व्यवस्था वाले अनेक देशों ने न सिर्फ ज्यादा विकास दर वल्व गरीबी उन्मूलन और वरोजगारी मिटान में भी अच्छे परिणाम पाए हैं।

भारतीय अथव्यवस्था का प्रमुख दोष यह है कि पिछले 40 वर्षों में यह अपना एक भी घोषित उद्देश्य और एक भी नियोजित लक्ष्य पाने में नाकाम रही है। इससे भारतीय लोगों को भारी नुकसान उठाना पडा है। यह इन तीन कारणों से स्पष्ट है (i) नियोजित लक्ष्यों का अधूरा रहना से भारतीय अथव्यवस्था को हुई हानि, (ii) पूँजी/उत्पाद के अनुपात में हुई वृद्धि से भारतीय अथव्यवस्था को हुई हानि, तथा (iii) गैर-उत्पादक खर्च में वृद्धि से भारतीय अथव्यवस्था को हुई हानि।

### (i) नियोजित लक्ष्यों के अधूरा रहने से हुई हानि

इसके बारे में कोई सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं है। लेकिन कुछ सरकारी और गैर सरकारी स्रोतों के आधार पर हम इस प्रश्न को मोटे ढंग से सुलझा सकते हैं। पहला सरकारी स्रोत जो हाल ही में प्रधानमंत्री ने दिया, उसके मुताबिक गरीबों के लिए आवंटित प्रत्येक छह रुपए में से उन तक मात्र एक रुपया ही पहुँचा है। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी एजेंसी अथवा विशेषज्ञ ने चूँकि भारतीय योजनाकारी के कामकाज पर इस महत्वपूर्ण टिप्पणी का प्रतिवाद नहीं किया है इसलिए हम इसे 1947 उपरांत भारतीय योजना की फिजूलखर्चा (जो भ्रष्टाचार प्रथम, अव्यवस्था आदि के जरिए होती है) को नापने की बसौटी बनाते हैं। इस आधार पर हमारा मोटा अनुमान है कि 1951 से 1988 के बीच जो 4,00,000 करोड़ रु० भारतीय नियोजन पर खर्च किए गए,<sup>112</sup> उनमें से 66,666 करोड़ रु० (यानी भारतीय नियोजन पर खर्च कुल राशि का 1/6 भाग) ही उत्पादक अथवा सामाजिक तौर पर फायदे-मद कार्यों पर खर्च हुए जबकि 3,33,334 करोड़ रु० (यानी भारतीय नियोजन की कुल राशि का 5/6 भाग) सामाजिक तौर पर व्यर्थ गए।

नियोजित लक्ष्यों के अधूरा रहने से 1947 उपरांत भारतीय अथव्यवस्था को हुई हानि के बारे में दूसरा गैर सरकारी स्रोत करीब पांच साल पहले प्रकाशित एक अध्ययन<sup>113</sup> से मिलता है। इससे पता चलता है कि भारत की एक पंचवर्षीय योजना को पूरा होने में सात वर्ष लगते हैं। योजना लक्ष्यों के समय पर पूरा न होने से उत्पादन में भारी हानि तो हुई ही, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि पर भी अकुशलता। इसके अनुसार अगर नियोजित लक्ष्य समय रहते पूरे होते तो राष्ट्रीय आय में 1,20,082 करोड़ रु० की वृद्धि होती जिससे 1980-81 में प्रति व्यक्ति आय 1,537 रु० के बजाय दुगुनी यानी 3,398 रु० होती।

### (ii) पूँजी/उत्पाद के अनुपात में वृद्धि से हुई हानि

भारतीय अर्थव्यवस्था में पूँजी/उत्पाद के अनुपात के धारे में अनेक अनुमान उपलब्ध हैं। लगभग सभी सहमत हैं कि निवेश की उत्पादकता लगातार घटी है। वी० के० आर० वी० राव के अनुमान के अनुसार<sup>114</sup> 1960-61 की कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अनुरूप शुद्ध निवेश में परिवर्तन से पूँजी/उत्पाद के अनुपात की दीर्घकालिक प्रवृत्ति बताती है कि वह 1950 के दशक में 2.39 से बढ़कर '70 के दशक में 4.63 पर पहुँच गया। उनके अनुमान आगे बताते हैं कि औसत पूँजी/उत्पाद का अनुपात भी '50 के दशक के 2.7 से बढ़कर '60 के दशक में 2.9 और '70 के दशक में 3.33 हो गया। आर० एम० सुदरम के अनुमान<sup>115</sup> भी शुद्ध पूँजी/उत्पाद के अनुपात, शुद्ध अचल पूँजी/उत्पाद के अनुपात और औसत पूँजी/उत्पाद के अनुपात में वृद्धि की तरफ इशारा करते हैं। इससे पता चलता है कि तकनीकी तरक्की अपेक्षितता कम हुई है। सुखमय चन्वर्ती ने भारतीय अर्थव्यवस्था में पूँजी/उत्पाद के मौजूदा अनुपात को 5.96 माना है।<sup>116</sup> एस० आर० हाशमी का अनुमान है कि 1950-51 से 1973-74 के बीच पूँजी/उत्पाद का अनुपात 5.36 और 1974-75 से 1983-84 के बीच 5.44 था।<sup>117</sup> 1950-51 से 1983-84 तक के काल के लिए उहोंने इस 5.61 माना। यह सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर प्राप्त की गई औसत थी। अकेले सरकारी क्षेत्र के लिए उहोंने यह आँकड़ा 1960-61 और 1983-84 के बीच 7.00 तथा 1974-75 और 1983-84 के बीच 5.92 बताया।

ये सार अनुमान बताते हैं कि पिछले 40 वर्षों में पूँजी/उत्पाद का अनुपात 3 से बढ़कर 6 हो गया है यानी इसमें दुगुनी वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि 1951 में तीन रु० लगाकर एक रु० का उत्पादन हुआ करता था जबकि 1980 के दशक में 6 रु० लगाकर एक रु० का उत्पादन हो रहा है। जाहिर है अगर पूँजी/उत्पाद का अनुपात दुगुना नहीं होता तो भारत में आर्थिक विवास का मौजूदा स्तर पिछले 40 वर्षों के दौरान देश में किए गए कुल निवेश से भी आधी रकम में पूरा हो सकता था। इस तरह भारतीय लोगो द्वारा उठाई गई कुल हानि अर्थात् रु० में बँठती है। चूँकि पिछले तीन दशकों (1951-81) में भारतीय अर्थ व्यवस्था का उत्पादन 2.8 गुना बढ़ा है हमारा मोटा अनुमान है कि इस दौरान पूँजी/उत्पाद का अनुपात दुगुना हो जाने के मद्देनजर बढ़े हुए उत्पादन पर खर्च हुई अतिरिक्त पूँजी भारत की मौजूदा राष्ट्रीय आय (1986-87 में 2,71,500 करोड़ रु०) के दुगुने से हरमिज कम नहीं हो सकती। यानी इस दौरान 5,43,000 करोड़ रु० का फायदा खर्च हुआ है।

### (iii) गैर-उत्पादक खर्च में वृद्धि से हुई हानि

यह मामला पहले ही गंभीर स्थिति धारण कर चुका है। वैंद सरकार का खर्च 1950-51 में 500 करोड़ से 100 गुना बढ़कर 1988-89 में 52,640 करोड़ रु० हो गया है जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सिर्फ 2.8 गुना ही बढ़ाव हुआ है।

इस षच में वृद्धि का प्रमुख कारण गैर विास खच या गैर योजना खच में वृद्धि होना है। यह अथ कुल षच का करीब 90 फीसदी है। गैर विकास खच का 72 फीसदी हिस्सा प्रतिरक्षा, व्याज भुगतान और अनुदानों की मदों में जाता है।<sup>118</sup> 1948 और 1988 के बीच प्रतिरक्षा खच ही 84 गुना बढ़ गया है। अनुचित सैन्य खच का मतलब है या तो दूसरों को दबाकर रखना या जनता में बढ़ती बैचनी को दबाना। सेना पर ज्यादा खच का मतलब है विकास कार्यों पर खच में कमी। व्याज भुगतान 1950-51 में शून्य के मुकाबले 1988-89 में बढ़कर 14,000 करोड़ रु० हो गया है जबकि केंद्र और राज्यों द्वारा अनुदान पर किया जाने वाला खच 1950-51 में 0.4 अरब रु० से बढ़कर 1960-61 में 0.9 अरब, 70-71 में 3.4 अरब और 82-83 में 38.6 अरब रु० हो गया है।<sup>119</sup>

केंद्रीय बजट का आम ढर्रा यह है कि जहां केंद्र सरकार के राजस्व में सालाना औसतन 10 फीसदी की वृद्धि होती है, वहीं इसका खच हर साल 15 फीसदी बढ़ जाता है। घाटे की अथव्यवस्था पहले ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद की 2 फीसदी सुरक्षित सीमा का पार कर चुकी है। 1987-88 में केंद्र और राज्यों का कुल मिलाकर बजट घाटा 10,132 करोड़ रु० आया जाता है जो कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 3.1 फीसदी हो सकता है।<sup>120</sup> नौवें वित्त आयोग के मुताबिक<sup>121</sup> केंद्र और राज्यों का कुल मिलाकर सावजनिक ऋण 1974-75 के अंत में 29,933 करोड़ रु० से बढ़कर 1986-87 के अंत में 1,60,834 करोड़ रु० यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 61.8 फीसदी हो गया है। अनुमान है कि 31 मार्च 1988 तक यह 2,10,377 करोड़ रु० तक पहुंच गया है।

गैर विकास खच के अतिरिक्त बर्बादी, अकुशलता और पस का दुरुपयोग भी भारतीय अथव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। भारतीय अथव्यवस्था में बर्बादी का इजहार इस बात से होता है कि मार्च 1987 के अंत तक सारे राज्य विजली बोर्डों का कुल घाटा<sup>122</sup> 2748.40 करोड़ रु० था जबकि मार्च 1986 के अंत तक यह 2161.50 करोड़ रु० और मार्च 1985 के अंत तक 1647.8 करोड़ रु० था। यह भारी घाटा बड़े पैमाने पर होने वाली विजली की चोरी के कारण है। ऊर्जामंत्री के अनुसार भारत में विजली की 50 फीसदी चोरी होती है।<sup>123</sup> यहां तक अकुशलता का तात्लुक है, इस बारे में लोक लखा समिति द्वारा ससद को प्रस्तुत रिपोर्ट<sup>124</sup> में अनुमान लगाया गया कि 1951 के बाद के तीन दशकों में सिंचाई परियोजनाओं पर लगभग 150 अरब रु० खच करके 3.9 करोड़ हेक्टेयर जमीन के लिए सिंचाई सुविधाएं जुट पाईं जबकि लक्ष्य छह करोड़ हेक्टेयर के लिए था। इस 2.1 करोड़ हेक्टेयर की कमी को पूरा करने के लिए अनुमान लगाया जाता है कि वर्तमान कीमतों पर 140 अरब रु० की और जरूरत होगी। यहां तक बाढ़ नियंत्रण का सबंध है, सिंचाई अधिकारियों का अनुमान है कि बाढ़ की सहायना वाले कुल 4 करोड़ हेक्टेयर इलाके में से 80 फीसदी में सुरक्षा प्रबंध किए जा सकते हैं

लेकिन अब तक मात्र 1.2 करोड़ हेक्टेयर इलाका ही गुरागित किया जा सका है। दिवगत राजकृष्ण के अनुसार<sup>105</sup> 1951 से 1980 तक के 30 वर्षों के दौरान जा 192 बड़ी सिंचाई परियोजनाएँ शुरू की गईं उनमें से सिर्फ 42 ही अब तक पूरी की जा सकी हैं। इतने लंबे काल से अधूरी पट्टी योजनाओं पर ध्यान जाना वाली राशि दुगुनी हो गई है। 66 परियोजनाओं में अतिरिक्त लागत पहले ही 50 अरब रु० बढ़ गई है। 150 बड़ी और 3 000 छोटी परियोजनाओं को पूरा होने में 2 से 25 वर्षों तक की देरी हो चुकी है। दो बड़ी स्टील कारखाना विस्तार परियोजनाओं (बोकारो और भिलाई) की लक्ष्य से 4-5 साल बाद पूरा होने की उम्मीद है। इस पर अतिरिक्त लागत 12 अरब रु० से ज्यादा होगी। अति महत्व के एटमी ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं को पूरा हान में 2 से 7 वर्षों की देरी हो रही है और इस पर अतिरिक्त लागत करीब 3 अरब रु० बँठ रही है जो मूल अनुमानित लागत की दुगुनी है। प्रमुख कोयला परियोजनाएँ एक से चार साल पीछे और उत्तरी क्षेत्र में 5 प्रमुख ताप बिजली परियोजनाएँ 7 से 45 महीने पीछे चल रही हैं।

इसी प्रकार कई क्षेत्रों (जैसे सीमेंट, नागज, अलौह धातुएँ, रासायनिक खाद, इंजीनियरिंग उद्योग और तेल शोधन आदि) में प्रमुख परियोजनाएँ देरी और लागत वृद्धि से ग्रस्त हैं। लागतों में वृद्धि और इससे जुड़े दूसरे नुकसान 1970 के दशक में 10 अरब रु० के बराबर आने गए। यहाँ तक कि वे दुर्घटनाओं का प्रश्न है, कज मले इसका जीता जागता उदाहरण है। वैश्वीय सतकता आयोग की 1987 की रिपोर्ट में संबंधित बका को अधाधुध उधार के लिए आड़े हाथा लिया गया है। इनमें सिर्फ सत्ताधारी दल का प्रभाव बढ़ाने की खातिर 2,800 करोड़ रु० बाट दिए गए। एक गैरसरकारी अनुमान के मुताबिक प्रत्येक वर्ष जनता के लगभग 20 000 करोड़ रु० दुरुपयोग में फुव जात है।<sup>106</sup>

## 11 आर्थिक परिणाम

मानवीय और तकनीकी ससाधनों के उत्पादक इस्तेमाल में असफलता का पहला परिणाम तो भारतीय अर्थव्यवस्था के दिवालियापन में निबला है। इसके कारण सरकार की देनदारियाँ इसकी परिसंपत्ति से 40 000 करोड़ रु० ज्यादा हैं।<sup>127</sup> दूसरे, इससे विश्व में भारत का आर्थिक स्तर गिरा है। 1951 में विश्व उत्पादन में भारत का योगदान दो फीसदी था। वह 1985 में घटकर 1.42 फीसदी रह गया है।<sup>128</sup> 1951 में विश्व के औद्योगिक उत्पादन में भारत का हिस्सा 1.2 फीसदी था। वह 1985 में घटकर 0.5 फीसदी रह गया।<sup>129</sup> 1951 में विश्व के कृषि उत्पादन में भारत का हिस्सा 11 फीसदी था। वह 1985 में घटकर 9 फीसदी रह गया।<sup>130</sup> इसी प्रकार इस दौरान विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 2.4 फीसदी से घटकर 0.5 फीसदी रह गया।<sup>131</sup> विश्व के औद्योगिक देशों में तब भारत का 10वाँ स्थान था। अब वह बिससकर 12वाँ हो गया है।<sup>132</sup> शिक्षा के क्षेत्र में भारत की 36

फीसदी साक्षरता दर तजानिया जैम अफ्रीकी देशो से भी वही पीछे है।<sup>133</sup> तीसरे, इससे गेसा वातावरण बना है जिमम छ्र्टाचार रोजमर्रा की जिदगी या हिस्सा बन गया है मानदंड जोर मूल्य गही छूट गए है, कानून कायदो का उल्लघन आम हो गया है और अपराध की जडें गहरी होती जा रही है। चौथ, इसका परिणाम भारत की लगभग 40 फीसदी आबादी का कुपोषण मे निक्ला है। प्रत्येक नागरिक को मुश्किल से जिदा रहने लायक 1800 केलारी प्रतिदिन ऊर्जा के बराबर खाद्य सामग्री मिलती है। इसी वजह से प्रतिबष लगभग 20 लाख लोग विभिन्न बीमारियों के शिकार होकर दम ताड दत हैं।

सदभ

- 1 और 2 इकानामिक ऐंड पालिटिकल वीक्ली, 28 9 85, पृ० 1651
- 3 'स्टेटिस्टिकल आउटलाइस', टाटा सर्विसज बवई
- 4 फ्रीश पेंस्पेक्टिव आउट इडिया ऐंड पाकिस्तान', बुक ट्रेडस लाहौर, 1987, पृ० 87
- 5 से 10 एम० एस० आन्थ्रोपिया, फाइनाशियल एक्सप्रेस, 25 1 88, पृ० 5
- 11 से 15 बी० एम० दाडेकर इ० पा० वीक्ली, 9 1 88, पृ० 49
- 16 से 19 एम० जे० पटल, इ० पो० वीक्ली 28 9 85, पृ० 1652
- 20 हिंदुस्तान टाइम्स सडे मंगजीन, 31 1 88 पृ० 2
- 21 से 22 इडियन एक्सप्रेस 12 10 88, पृ० 8
- 23 ट्रिव्यून, 14 11 84, पृ० 4
- 24 से 25 हिंदुस्तान टाइम्स, 16 11 84 पृ० 9
- 26 हिंदुस्तान टाइम्स, 8 4 87
- 27 टाइम्स ऑफ इडिया, 24 10 84, पृ० 9
- 28 से 29 इकानामिक टाइम्स, 4 5 87, पृ० 5
- 30 इकॉनॉमिक टाइम्स, 1 4 88, पृ० 5
- 31 टाइम्स आफ इडिया, 9 1 88, पृ० 1
- 32 इकानामिक टाइम्स, 4 5 87, पृ० 5
- 33 टाइम्स आफ इडिया (जयपुर), 8 6 87, पृ० 5
- 34 इ० पो० वीक्ली 28 9 85, पृ० 1652
- 35 टाइम्स आफ इडिया, 22 7 87, पृ० 6
- 36 फाइनाशियल एक्सप्रेस, 28 1 88, पृ० 5
- 37 इकॉनॉमिक सर्वे 1982 83, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
- 38 से 41 इकानामिक टाइम्स, 10 9 88, पृ० 1
- 42 सेंटर फार मानिट्रिंग इडियन इकानामी, अगस्त 1981
- 43 से 44 पट्रियट, 27 2 28, पृ० 9

- 45 पेट्रियट 3 2 88, पृ० 2  
 46 पेट्रियट, 5 1 87, पृ० 9  
 47 स 48 मेनस्ट्रीम, 23 4 88, पृ० 13  
 49 टाइम्स ऑफ इंडिया, 20 8 83  
 50 से 53 'स्टेटिस्टिकल आउटलाइस, 1986 87', टाटा सविस्त्र बर्द  
 54 हिंदुस्तान टाइम्स, 28 11 88, पृ० 11  
 55 'फोश पॅसेपविटव्ज', युव ट्रेड्स साहीर, पृ० 92  
 56 स 58 सडे ट्रिव्यून, 6 9 87, प० VIII  
 59 से 60 पेट्रियट, 10 3 88, प० 5  
 61 से 64 इंडिया टुडे, 15 1 85  
 65 वल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 1984  
 66 'द पोलिटिक्स इकॉनॉमी ऑफ डेवलपमेंट', ओयूपी, इलड 1984, पृ० 3  
 67 से 68 ट्रिव्यून 21 12 88, पृ० 4  
 69 राष्ट्रीय आय के अनुमान, वेंद्रीय साधिका सगटन, फरवरी 1964  
 70 टाइम्स आफ इंडिया (जयपुर), 8 6 87, प० 5  
 71 'द इकॉनॉमी आफ इंडिया', यो० एन० बालमुद्रमण्यम, यीदनफील्ड एंड  
 निकोलसन, लदन 1981, पृ० 162  
 72 पेट्रियट 31 1 85, पृ० 2  
 73 मेनस्ट्रीम, 25 6 88, प० 15  
 74 पेट्रियट, 31 1 85, पृ० 2  
 75 इकानामिक टाइम्स 4 5 88 पृ० 5  
 76 टाइम्स ऑफ इंडिया, 20 10 88 पृ० 6  
 77 ट्रिव्यून, 10 9 88, प० 4  
 78 मुद्रा एव वित्त सवधी रिजव बैंक की रिपोर्टें तथा इकानामिक सर्वे 1986 87  
 79 ट्रिव्यून, 10 9 88, पृ० 4  
 80 टाइम्स की 'सैटडे टाइम्स', 10 12 88, पृ० 2  
 81 इंडियन एक्सप्रेस, 9 3 88, पृ० 8  
 82 सैटडे टाइम्स, 10 12 88, पृ० 2  
 83 इंडियन एक्सप्रेस, 9 3 88, पृ० 8  
 84 से 85 हिंदुस्तान टाइम्स 5 11 88 प० 13  
 86 रिजव बैंक की रिपोर्टें तथा इकानामिक सर्वे 1986 87  
 87 स्टेटसमैन, 1 8 87, प० 10  
 88 हिंदुस्तान टाइम्स, 26 4 88, पृ० 11  
 89 से 90 'टुवड स सोशल रेवोल्यूशन', बीपीएच दिल्ली 1984 प० 79  
 91 से 92 अबिल भारतीय कर आकडे 1979 80, आयकर विभाग

- 93 इकॉनॉमिक टाइम्स, 29 9 84, प० 1
- 94 फाइनांशियल एक्सप्रेस, 10 6 87, प० 5
- 95 पेट्रियट, 10 10 87, पृ० 2
- 96 'द इकॉनॉमी ऑफ इंडिया', बालमुन्नमण्यम, प० 3
- 97 इंडियन एक्सप्रेस, 23 4 88, प० 8
- 98 से 99 वही, प० 10 और 3
- 100 से 102 'स्टटिस्टिकल आउटलाइस', टाटा सर्विसेज, पृ० 12
- 103 हिंदुस्तान टाइम्स, 17 11 88, प० 11
- 104 टाइम्स ऑफ इंडिया, 22 3 88, प० 5
- 105 से 108 वही, 16 12 88, पृ० 5, खड एक
- 109 इ० पो० बीकली 16 1 82
- 110 एक अनुमान के अनुसार 1980 के लोकसभा चुनावो म 170 करोड रु० का बाला धन खच हुआ—ट्रिव्यून, 17 11 88, पृ० 4
- 111 फाइनांशियल एक्सप्रेस, 31 12 87, पृ० 5
- 112 विभिन्न सरकारी दस्तावेजो के आधार पर सकलित
- 113 एस०के० तुलसी, 'प्लान्स ऐंड पर्फार्मस', आर्थिक एव वैज्ञानिक शोध संस्थान नई दिल्ली
- 114 इ० पा० बीकली, 31 5 80, पृ० 965-77
- 115 'सेविंग्स इनरस्ट्रुमेंट ऐंड इकॉनामिक ग्रोथ', लेख न० 165, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, त्रिवेंद्रम, मार्च 1983
- 116 प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने भारतीय नियोजन पर 1987 म प्रकाशित अपनी पुस्तक म आकडे दिए हैं
- 117 योजना आयोग की नियोजन समिति द्वारा लिखा लेख जो 8वें विश्व आर्थिक सम्मेलन (दिसंबर 1986) म रखा गया
- 118 टाइम्स आफ इंडिया, 7 12 88, पृ० 5
- 119 प्रणव बदन 'द पालिटिकल इकॉनॉमी आफ डेवलपमेंट इन इंडिया', थोयूपी लदन, 1984, पृ० 62
- 120 से 121 टाइम्स ऑफ इंडिया, 4 9 88, प० 7
- 122 पेट्रियट, 15 3 88, पृ० 5
- 123 पेट्रियट, 28 2 88, प० 5
- 124 प्रणव बदन, वही, पृ० 12-13
- 125 'स्टगनेट परामीटस', सभिनार, जनवरी 84, पृ० 65
- 126 इंडिया टुडे, 15 3 1987
- 127 बजट 1988 89, परिसंपत्ति एव देनदारियां
- 128 से 131 इकॉनामिक टाइम्स, 23 3 87, पृ० 5
- 132 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट', टाइम्स आफ इंडिया, 22 7 87, पृ० 5
- 133 पेट्रियट, 5 12 86, पृ० 9



## अध्याय पाच भारतीय सस्कृति

### 1 प्रचलित जीवन पद्धति

भारतीय सस्कृति से यहाँ अभिप्राय 1947 उपरात भारतीय राष्ट्रीय जीवन मे प्रचलित आध्यात्मिक, नैतिक और सौंदर्यपरक मूल्यों की प्रक्रिया से है। यानी यह सस्कृति 1947 उपरात भारतीय लोगो की प्रचलित जीवन पद्धति को अभिव्यक्त करती है। हरेक जीवन पद्धति मानव आचरण व व्यवहार के सभी सामाजिक मान दंडो—यानी विचारो, आस्थाओ, मूल्यों, भावनाओ, ढंगो, रुचियो, आदतो, रीति रिवाजो, परंपराओ भाषा, वर्ण, साहित्य, कला, विज्ञान आदि का योगफल होती है। इनसे प्रत्येक व्यक्ति का दूसर व्यक्तिओ, नारी, परिवार, विवाह, धर्म, विभिन्न विचारधाराओ, राज्य और दूसरी प्राकृतिक वस्तुओ के प्रति रुच का इजहार होता है। यह बहुत ही विस्तृत अवधारणा है। विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियो की सटीक अभिव्यक्ति जितनी इस एक शब्द स होती है उतनी किसी और से नहीं। इसलिए सस्कृति सामाजिक विकास मे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भूमिका सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी। सकारात्मक भूमिका वचारिक और भौतिक विकास को आग वढाती है जबकि नकारात्मक भूमिका उसमे बाधा डालती है। यह भूमिका अथ ववस्था और राजनीति से अभिन्न तौर पर जुडी होती है, इसलिए इनके साथ करीबी तौर पर जोडकर ही इसका उचित अध्ययन किया जा सकता है।

### 2 भारतीय राज्य के सास्कृतिक सिद्धांत और इसकी सरकार की सास्कृतिक शाली की अभिव्यक्ति

(क) 1947 उपरात प्रचलित भारतीय सस्कृति भारत के राष्ट्र राज्य के सास्कृतिक सिद्धांत की अभिव्यक्ति है (ठीक उसी प्रकार जैसे कबीलाई सस्कृति को कबीलाई राज्य और शाही सस्कृति को धार्मिक सह सैनिक राज्य की अभिव्यक्ति माना जाता है)। खास तौर पर यह शासक दल या उसकी सरकार की सास्कृतिक शाली की प्रतीक है (ठीक उसी तरह जैसे कबीलाई सस्कृति को विशेषकर कबीलाई शासक परिषद और शाही सस्कृति को शासक धार्मिक सह सैनिक गुट की सास्कृतिक शाली का प्रतीक माना जाता है इसी तरह आदिम कुल सस्कृति कुल के सास्कृतिक सिद्धांत को अभिव्यक्त करते हुए कुल के मुखिया की सास्कृतिक शाली की प्रतीक थी)।

(ख) भारतीय राज्य कही भी सस्कृति की अपनी निश्चित अवधारणा प्रस्तुत

नहीं करता। यह अयधारणा यहाँ-तहाँ विघरे रूप में ही मिलती है। सविधान में शिवा, भाषा, धर्म, वैज्ञानिक व तार्किकी प्रगति और सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की तरफकी जैसे कुछ सांस्कृतिक विषया का ही जिन्न है। इसमें वही भी इस समस्या का प्रभवद वणन नहीं है। इसकी प्रस्तावना में लोकतांत्रिक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष संस्कृति की एक सामान्य दिशा तो मौजूद है पर इसका कुछ दूसरे प्रावधानों में हिंदुओं के रीति रिवाजों का इजहार मिलता है (दर्रें पृष्ठ 18)। सरकार भी संस्कृति का सवाल वही समग्र रूप से नहीं उठाती। वह इसे सभी धर्मों के लिए समान श्रद्धा की परिभाषा देकर निबटा देती है। इस प्रकार यह भारतीय राज्य और सरकार की विचारधारा में अस्पष्ट रह जाँ वाला सर्वाधिक जटिल सवालो में से एक है।

(ग) बहरहाल, सरकारी या शासक दलीय संस्कृति लगातार अपने विशिष्ट सांस्कृतिक सिद्धांत और शैली का लोगो में प्रचार करती आ रही है। सैद्धांतिक तौर पर, इसका मानना है कि भारतीय संस्कृति एक प्राचीन संस्कृति है और इसका सबसे उत्कृष्ट रूप आर्यों की वैदिक संस्कृति थी जिसने राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, नैतिकता और अहिंसा व सर्वोच्च मानदंड मानव धर्म (सावभूमिक आचार संहिता) का पक्षपोषण किया। शासक दल की संस्कृति के अनुसार इस मानव धर्म का प्रतीक अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता है जो हर धर्म के अनुकूल है। शैली में शासक दलीय संस्कृति सभी प्रकार के और खासकर बहुसंख्यक समुदाय के कट्टरवाद को तुष्ट कराने की कोशिश करती है। ममलन, लगभग सभी सरकारी कार्यक्रमों का उदघाटन पूजा, मंत्रोच्चारण, गणनाद और माथे पर तिलक धारण करके किया जाता है। अंतिम ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड माउंटबैटन के अनुसार 15 अगस्त 1947 का स्वतंत्रता समारोह न सिर्फ हिंदू धार्मिक पद्धति के मुताबिक ही मनाया गया बल्कि सत्ता हस्तांतरण का ऐन समय भी हिंदू ज्योतिषियों द्वारा निर्धारित किया गया था। दूसरा उदाहरण सन 1947 से लेकर हिंदू मंदिरों के पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार में दिए गए सरकारी संरक्षण का है। अगस्त 1947 के तुरंत बाद गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर (जिसे 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने तबाह कर दिया था) को केंद्र सरकार की सहायता से पुनर्निर्मित किया गया और इसके बाद मई 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद ने वेदमंत्रोच्चारण और 101 तोपों की गड़गड़ाहट के बीच पुनर्निर्माण किए गए इस मंदिर में ज्योतिषलिंगम की स्थापना की थी। देश के विभिन्न भागों में ऐसे मंदिरों के जीर्णोद्धार और सरकारी उदघाटन समारोहों की लंबी सूची है। इसी प्रकार की सांस्कृतिक झलक शासक दल की राजनैतिक गतिविधियों से भी मिलती है। उम्मीदवारों का चयन हो या चुनाव प्रचार, मंत्रिमंडल का गठन हो अथवा राज्यपालों, उच्चाधिकारियों और अधीनस्थ अफसरों की नियुक्ति, आयोगों और समितियों का गठन हो या परमिट्टा और लाइसेंसों का जारी किया जाना या फिर कहीं सांस्कृतिक शिष्टमंडलों को भेजना—ये सभी काम सांप्रदायिक और जातिवादी आधार पर किए जाते हैं।

### 3 दैनिक जीवन में शासक संस्कृति

रोजमर्रा की जीवन शैली में शासकदलीय संस्कृति कुर्सी, धन, लालच और लाभ की लालसा को जन्म देती है। इसके पनपन का आधार शासक दल के नेताओं की अभिप्रेरणा और गतिविधि में निहित है। इन नेताओं के लिए कुर्सी से चिपक रहना और दौलत जमा करना ही जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य है। इसकी प्राप्ति के लिए वे हर तरीके को जायज मानते हैं। जाहिर है, ऐसी सामाजिक दिशा कतहत्त पड्यन्न, छल और कपट सामान्य मानदंड हो गई है। यह बात शासक दल के नेताओं के रोजमर्रा व्यवहार से साफ झलकती है। वे हर वही जनक सदेहास्पद कामों में सलग्न रहते हैं। उनके लिए भ्रष्टाचार भारत की 'उदार' प्रणाली का तकसगत नतीजा है। प्रधानमंत्री समेत उनमें से अधिकांश पर भ्रष्टाचार के गभीर आरोप लगते आए हैं। पर वे बेशर्मी से अपनी कुर्सियों पर जमे हुए हैं। अगर ऐसा वही यूरोप में हुआ होता तो आरोपी व्यक्ति अपने सम्मान की रक्षा के लिए या तो अदालतों की शरण लेते या सावजनिक पदों से चुपचाप इस्तीफा दे देते। बाला धन अधाधुध रफ्तार से बढ़ रहा है। लाइसेंसों पर मिट्टी, कोटों, सिविल ठेकों, रक्षा सौदों आदि नई-यापक पैमाने पर फैला दिया है। जिसना बड़ा सौदा होता है, उतनी ही ऊंची भ्रष्टाचार का दर और उतना ही ज्यादा काले धन का सचय हाता है। जब शासक दल को अपना सागठनिक ढांचा चलाने के लिए टनों के हिसाब से काले धन की जरूरत हो तो ऐसा हो भी क्यों नहीं। तस्करी, दवाओं के अवैध व्यापार, विदेश व्यापार में हेराफेरी, विदेशी मुद्रा की धोखाधड़ी और विदेशी वक्ता में काले धन की जमा स सालाना अरबों रुपए भारतीय जनता से लूट लिए जाते हैं। कर चोरी से सरकारी खजाने की सहज ही ठगा जाता है। नकली करसी नोट चिट फंड कंपनियां फर्जी रोजगार दफतर, पासपोर्ट और बीसा एजेंसियां हजारों लोगों से पसा ऐंठती जा रही हैं। सिनमा टिकटा की बालाबाजारी दश भर में चरम पर है। खाद्य सामग्रियों में मिलावट, नशीली दवाओं का उपभोग, नकली दवाइया, कम ताल, अवध शराब जुआखारी, घटिया दर्जे का सामान आदि राष्ट्रीय शगल बन गए हैं। हर वही अनतिक्रम माहौल हावी हो गया है।

### 4 आचरण के शासकीय मानदंड

(क) इस अनतिक्रम माहौल में स्वाथ, दम अहंकार अधिकारियों के प्रति सम्मान पर अति बल, उत्तराधिकार और पितृसत्ता पर जोर, दौलत और हैसियत के भेद प्रदर्शन, तावदारी, चापलूसी, झूठ पड्यन्न, चालाकी, चुगलखोरी आदि आचरण के सभी पतित मानदंडों को जन्म दिया है। ये पतित मानदंड एक ऐसे दोतरफा सांस्कृतिक मॉडल का अनुरूप त्रियाशील हैं जिसके तहत आम लोगों के प्रति दम और बड़े लागा के प्रति चापलूसी सही ठहराई जाती है। राजीव की दुष्यधहार वाली और आत्मानक मुद्राएँ—मसलन अपने आलाचकों को 'भोषते पुत्र'

कहना, अपने विरोधियों के लिए 'नानी याद करा देंगे' जैसी घुड़कीभरी घोषणाएं करना, विपक्षी मुख्यमंत्रियों को यह चेतावनी देकर घमकाना कि 'मैं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की दोषी किसी भी राज्य सरकार को खुद बर्खास्त कर दूंगा', मजदूरों को दुनिया में बहद अकुशल' वर्ग की सज्ञा देकर उन्हें हतोत्साहित करना, विपक्षी सांसदों की आवाज दवाने के लिए सदन में मजें पीटना आदि—संस्कृति की दभी शैली के उदाहरण हैं। चापलूसी की संस्कृति 1970 के दशक में कांग्रेस के इंदिरा भारत है और भारत इंदिरा' के जाने माने नारे अथवा 1988 में कांग्रेस के कामराज नगर सम्मेलन में 'राजीव ही भारत के एकमात्र नेता' वाले नारे अथवा कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा जो काई सत्ता प्रमुख हो उसके प्रति तावेदारी वाले रवैए से जाहिर है।

(ख) शासक दल के नेता अपने दोहरे मानदंडों के ऐन मुताबिक आम लोगों को तो ज्यादा से ज्यादा कुरवानिया देना का उपदेश देते हैं पर प्राचीन युग के शाही रिवाज को मात करके हुए खुद आलीशान जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने अथाह धन-दौलत जमा कर ली है और बढ़ती गरीबी के सागर में ऐश्वर्य के छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण कर लिया है। उनकी भ्रष्ट, आडवरपूण और विलासितापूण जीवन शैली का भारत से कोई सरोकार नहीं है, जहां करीब 40 करोड़ लोग बड़ी मेहनत की जिंदगी जी रहे हैं। यह जीवन शैली सामाजिक पतन के हर पहलू को बढ़ावा देती है।

(ग) मानव धर्म की अपनी संस्कृति को दुनिया में सर्वोत्कृष्ट गुणों की पक्षधर होने की डींग हाकते हुए शासक दल के नेता अमूमन शकुनों और ज्योतिष, तारों और ग्रहों के प्रभाव, सपनों की महत्ता, शुभ और अशुभ लग्नों, जादू टोना के अधविश्वास तंत्र मंत्र और वशीकरण, कुत्तों, बिल्लियों सियारों, छिपकलियां, उल्लुआ और कौओं के आचरण के साथ साथ भाग्य और कम की सब यापकता का मानते हैं। मुलदीप नायर<sup>2</sup> द्वारा दिए गए तथ्यों के अनुसार नेहरू भी अपने आखिरी दिनों में धार्मिक बन गए थे, 'उनकी मौत के समय गीता और उपनिषद उनके सिरहाने पड़े थे', और इससे पहले भी नेहरू के (जब वे जिंदा थे) निवासस्थान पर सवा चार लाख मृत्युञ्जय मंत्रों का जाप किया गया और वे अक्सर इस अनुष्ठान में शरीक होते थे'। इंदिरा गांधी सभी प्रकार के अधविश्वासों और ज्योतिषीय भविष्यवाणियों की पक्की भगत बनी रहीं। राजीव इस पारिवारिक परंपरा का पालन कर रहे हैं। बहुत-से मंत्री, सांसद, विधायक और यहां तक कि कुछ विपक्षी नेता भी तंत्रिकों, सिद्धों और ज्योतिषियों का आशीर्वाद लेते हैं।

## 5 दमघोटू माहौल

(क) आचरण के इन भ्रष्ट मानदंडों के बढ़ते प्रभाव से भारत में सीमित आजादी और स्वाधीनता के वास्तविक अंश में कई घूत तरीकों के माध्यम से ओपटोती हुई है (जसा कि पीयूडीआर, पीयूसीएल और एमनस्टी इंटरनेशनल<sup>3</sup> ने

रिपोर्टों में कहा है)।

पहली बात तो यह कि बल्लू और विघटन की ताकतों (यानी सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रीयता आदि) को लागू मफूट डालन के लिए पूरी तरह प्रास्तावित किया जाता है। विभिन्न धार्मिक समुदायों में सांप्रदायिक दंग कराने वाले सांप्रदायिकतावादी, अनुसूचित जातियां व जनजातियों पर हमल करने वाले जातिवादी, और क्षेत्रीय तनावों का लाभ उठाने वाले क्षेत्रीयतावादी—लगभग सभी ताकतें (कुछ अपवादों को छोड़कर) शासक दल की उपज हैं और प्रायः उसकी वृत्तपात्र हैं।

दूसरे, लोगों को हतोत्साहित करने के लिए सामाजिक जिदगी में माफिया, गुंडागर्दी और आतंकवाद का खुलेआम बढावा दिया जाता है। नतीजतन अपराध बढ़ते जाते हैं। 1982-83 और 84 के दौरान सालाना करीब 24,000 हत्याएँ हुईं।<sup>4</sup> अगर हत्याओं की सालाना औसत 10,000 भी मान ली जाए तो पिछले 40 साल में लगभग चार लाख हत्याएँ हो चुकी हैं।

तीसरे, लोगों को आतंकित करने के लिए बिना मुकदमा चलाए नजरबंद रखना सामान्य ढर्रों बन गया है। अक्टूबर 1975 की इमरजेंसी के दौरान ही करीब एक लाख लोगों को नजरबंद किया गया।<sup>5</sup> अख्तवारी रिपोर्टों के मुताबिक पंजाब में आज लगभग 10,000 बंदी हैं। अपुष्ट आकलन है कि पिछले 40 साल के दौरान नजरबंदी के करीब पांच लाख मामले पाए गए हैं।

चौथे, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे लोगों को बरहमी और नश्वता से दबाया जाता है। बड़्यों को आतंकवादी गतिविधियों के आरोपों में दिनदहाड़े घर बानूनी ढंग से गोलियों से उड़ा दिया जाता है (जैसे नक्सलवादी आंदोलन के दौरान हुआ और इस समय आंध्र प्रदेश और बिहार में किसान आंदोलन तथा पंजाब में उग्रवाद आदि के खिलाफ हो रहा है)। गाली, लाठी आसूंस बगरह आज आम बात है। पिछले 40 साल में ब्रिटिश शासन के 190 वर्ष के दौरान मार गए कुल भारतीयों से भी शायद ज्यादा लोग मार गए हैं।

शासकों के इस प्रतिशोधी रवैए के कारण हर वही दमघोटू माहौल व्याप्त है। लेकिन वे खेद प्रकट करने के बजाय गवपूण दावे करते हैं कि भारत का सांप्रदायिक रिकार्ड कम से कम पाकिस्तान से बुरा नहीं है।

(ख) इस माहौल में कमजोर वर्गों कासकर अनुसूचित जातियों व जनजातियां, अल्पसंख्यकों (ज्यादातर मुसलमानों और सिखों) और महिलाओं के उत्पीड़न की रफ्तार तेज कर दी है। अनुसूचित जातियां व जनजातियां (जो कुल आबादी का 21 फीसदी हैं और जिनमें ज्यादातर भूमिहीन गरीब किसान और कुछ हद तक औद्योगिक मजदूर आते हैं) अभी भी सामाजिक तौर पर घटिया और अछूतों वाली जिदगी जी रहे हैं। छआछूत निरोधक कानून से उन्हें कोई फायदा नहीं पडा है। इस तथ्य की पुष्टि अनुसूचित जातियों व जनजातियों हतु आयुक्त की निरंतर सालाना रिपोर्टों से होती है। हर रोज अनुसूचित जातियों व जनजातियों की किसी श्रेणी पर एक या

दूसरा अत्याचार ढाए जाने की खबरें मिलती हैं। देश के हर भाग में उह जुल्म का और कई बार तो क्रूर हमलो का शिकार बनाया जाता है जिसका नतीजा हत्याओ, अंग काट लेने और पूरे परिवारा, बस्तियो और गावो को जिंदा जला देने में निकलता है। नेहरू के जमाने से शुरू हुआ यह सिलसिला आज भी बरोकटोक जारी है। शासक दल ने कुछ विशेष रियायतें (राजनैतिक और आर्थिक दोनों) दकर जैसे कि विधायिका, प्रशासन और शक्षिक संस्थाओ में आरक्षण मुहैया करके अनुसूचित जातियो व जनजातियो में एक ऊँची श्रेणी पैदा कर ली है। यह श्रेणी शासक दल और उसकी सरकार के लिए प्रायः सुरक्षा कवच का काम देती है।

अल्पसंख्यक (जो कुल आबादी का 17 फीसदी हैं), खासकर मुसलमान और सिख भी भेदभाव और राजनैतिक उत्पीडन का शिकार हैं। सांप्रदायिक वारदाता की संख्या लगातार बढ़ी है। मसलन गोर करें कि अति असामान्य वष 1946 में भी उत्तर प्रदेश में 347 सांप्रदायिक दंगे हुए थे जिसमें कुल 148 व्यक्तिगत और सामूहिक हत्याएं हुई लेकिन 38 साल बाद 1984 में तीन दिन के सिख विराधी दंगे के दौरान अकेले दिल्ली में ही करीब 2,700 लोग मारे गए।

महिलाओ की दशा भी बुरी है। तथाकथित उदारक कानूना (हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, दहेज अधिनियम आदि) ने महिलाओ की जिंदगी में मामूली अंतर ही डाला है और इनका लाभ ज्यादातर उच्च वर्ग की महिलाओ को ही मिला है। बहु जलाना<sup>१</sup>, विधवा जलाना और पैदा होते ही बच्चाओं की हत्याएं आज भी जारी हैं, वही कम तो कही ज्यादा। तकनीकी तौर पर कानून तो मौजूद हैं मगर व्यावहारिक तौर पर वे पुनरुत्थानवादी संस्कृति के नीचे दब गए हैं। इसलिए महिलाओ के साथ बड़ी हद तक अभी भी निंदयतापूर्वक व्यवहार किया जाता है, उनसे भेदभाव होता है और उह सामान्य जीवन नहीं जीने दिया जाता। बालिका के मुकाबले अभी भी बालक की इच्छा की जाती है। शादी से पहले हर महिला की जिंदगी पिता पर, शादी के बाद पति पर और पति की मृत्यु के बाद पुत्र पर निर्भर होती है। वह हमेशा पुरुषों पर निर्भर और उही के अधीन रहती है।

शासक दल अनुसूचित जातियो व जनजातियो, अल्पसंख्यकों और महिलाओ के उत्पीडन पर घडियाली आंखों से बहाता है मगर इन श्रेणियों की दयनीय दशा उसकी सामाजिक व्यवस्था और नीतियो के ही कारण हुई है।

## 6 शासन संस्कृति के लिए प्रचार माध्यम का इस्तेमान

अपनी संस्कृति का विस्तार करने और इसकी जड़ें गहरी करने के लिए शासक दल समूचे सरकारी प्रचार माध्यम (जो इसकी संस्कृति का एक आधार स्तंभ है) — रेडियो, टीवी, सरकारी प्रकाशन, कला एक संस्कृति संबंधी समितियो आदि का पूरा-पूरा इस्तेमाल करता है। ये सरकारी प्रचार माध्यम एक तरफ तो अमूमन सभी बिस्म के और धासकर हिंदू बट्टरवादी विचारों का प्रचार करते हैं तथा दूसरी

ऐसी भद्दी और अश्लील जीवन शैली को प्रोत्साहन देते हैं जो अद्यविश्वास पर आधारित रहस्यवाद-सह हिप्पीवाद का प्रतिरूप है।

इस सस्कृति का दूसरा आधार स्तम्भ इसकी शिक्षा प्रणाली है जो न तो भारतीय लोगो के हितो और न देश की जरूरता के अनुरूप है। यह एक तरफ तो अमूमन सांप्रदायिक जातिवादी या क्षत्रीय दृष्टिकोण के साचे में ढली हुई है और दूसरी तरफ धन, स्वायत्त, आदि की आकांक्षाएं जगाती है। पाठ्य पुस्तकें भगवान, भाग्य, नक, स्वयं आदि की ध्रातियो से भरी पडी हैं। वे खास तौर पर सरकार और शासक दल के नेताओ का गुणगान करते हुए उ हे सामाजिक विकास के रचयिता और लोगो के हित रक्षक बताती ह। समाज में विचारधारा का मुख्य अक्षर इतिहास, शासक दल के दृष्टिकोण से पढाया जाता है। एक तरफ बताया जाता है कि भारतीय इतिहास मूल रूप से हिंदुओ उनके धर्म तथा जाति, परिवार और विवाह के उनके सामाजिक संस्थानो की गाथा है—जो दुनिया में कही न पाई जाने वाली सांस्कृतिक निरंतरता प्रदान करते हैं। दूसरी तरफ कहा जाता है कि मौजूदा भारत के निर्माता काग्रस और उसके नेता ही है।

### 7 सस्कृति की दूसरी किस्में

शासक दल की प्रचलित सस्कृति हालांकि भारत की राष्ट्रीय सस्कृति में प्रमुखता रखती है पर सस्कृति की कुछ दूसरी किस्में भी यहाँ क्रियाशील हैं। इनमें कुछ किस्में परंपरागत हैं (जैसे विभिन्न जातिवादी सस्कृतियाँ, धार्मिक सस्कृतियाँ और क्षेत्रीय सस्कृतियाँ), कुछ अर्द्ध आधुनिक हैं (जैसे विभिन्न उपराष्ट्रीयताओं अथवा राष्ट्रीयताओं की सस्कृतियाँ, भाषायी सस्कृतियाँ और वर्गों अथवा समूहों की सस्कृतियाँ) तथा एक नई पैदा हो रही अंतरराष्ट्रीयवादी सस्कृति है जो हमारे दौर की आधुनिक सस्कृति है। शासक दल की सस्कृति इसलिए प्रभुत्व रखती है क्योंकि यह पुनरुत्थानवाद और अर्द्ध आधुनिकवाद का सम्मिश्रण है। इसका चरित्र प्रतिक्रियावादी इसलिए है कि यह पुनरुत्थानवाद को प्रमुख हैसियत देती है। इस युग में परंपरागत सस्कृतियाँ रचनात्मक दिशा देने के बाविल नहीं हैं। अर्द्ध आधुनिक सस्कृतियों की कुछ समय तक सीमित दिशा देने की उपयोगिता है। अंतरराष्ट्रीयवादी सस्कृति ही नव परिवर्तित दुनिया के अनुकूल एक उचित दिशा है। इसका मतलब है देशों की अंतरनिभरता से पैदा हुई मौजूदा सांस्कृतिक समस्याओं पर अंतरराष्ट्रीयवादी दिशा के आधार पर सोच विचार करना।

### 8 सस्कृति का रचयिता कौन

यह विवादास्पद सवाल रहा है। मार्क्सवाद का मत है कि सामाजिक वर्ग अपनी उत्पादन क्रिया के दौरान सस्कृति का विकास करते हैं जिसमें विशिष्ट-युक्त गौण

भूमिका निभाते हैं। पश्चिमी उदारवादियों का मत है कि विशिष्ट अथवा प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों में सस्कृति को जन्म देते हैं और इसमें जनसामान्य की कोई भूमिका नहीं होती। धर्म का दावा है कि इसकी रचयिता मातृ आलौकिक शक्ति ही है। मगर सस्कृति की बहुपक्षीय और बहुआयामी प्रक्रिया बताती है कि कोई एक सामाजिक इकाई (पश्चिमी उदारवादियों का प्रतिभाशाली व्यक्ति हो या भावसवादियों का वर्ग) वास्तुकला संगीत, भाषा, खान पान, घुमपान, रहस्यवाद, मध्यकालीन साहित्य, नए वैज्ञानिक विचारों आदि जैसे मानवीय आचरण की विधाओं की स्रोत न तो होती है और न ही हो सकती है। जाहिर है अलग-अलग सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न सामाजिक इकाइयाँ सस्कृति की विभिन्न विधाओं को जन्म देती हैं, जैसे वास्तुकला इकाई वास्तुकला विधा को, भाषायी इकाई भाषायी विधा का आदि आदि जन्म देती हैं। किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्ति और समूह के बीच व्यावहारिक संबंध में विशिष्ट व्यक्ति (आकड़ों और तथ्यों को सैद्धांतिक रूप देकर) परिष्करण सत्र जैसी भूमिका निभाता है जबकि समूह इस प्रक्रिया में कच्चा माल (यानी आकड़ों और तथ्यों) मुहैया कराता है। सामूहिक सामाजिक इकाई (साहित्यिक हो, कलात्मक या कोई अन्य) सबद्ध आकड़ों और तथ्यों जुटाते वक्त मूल भूमिका निभाती है जबकि विशिष्ट व्यक्ति आकड़ों और तथ्यों का विश्लेषण करके उन्हें सिद्धांत में सूत्रबद्ध करते समय मूल भूमिका निभाता है। आकड़ों और तथ्यों का स्रोत सामाजिक धर्म विभाजन और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी में निहित होता है जबकि उन्हें जुटाने का काम सामूहिक सामाजिक इकाई (यानी किसी विशेष क्षेत्र में काम कर रहे समूचे लोगों) के जिम्मे होता है। अब उनकी व्याख्या और सैद्धांतिक सूत्रीकरण का काम विशिष्ट शाखा से जुड़ा कोई विशिष्ट व्यक्ति करता है। सस्कृति को महज मनुष्य के स्वभाव का प्रतिबिम्ब मानने वाले लोग उसके सामाजिक आधार की अनदेखी करते हैं (सामाजिक आधार में परिवर्तनों के कारण ही मनु के पशु चराई वाले युग के जातिवादी मानवीय स्वभाव की जगह आधुनिक युग के धर्मनिरपेक्ष मानवीय स्वभाव ने ली)। दूसरी ओर सस्कृति को महज सामाजिक प्रतिबिम्ब मानने वाले लोग उसकी मानवीय विशेषताओं की उपेक्षा करते हैं (मानवीय विशेषताओं का प्रतीक रूप मानवीय साच है जो हमें विभिन्न चीजों की संरचना और आचरण के बारे में वास्तविक ज्ञान मुहैया कराती है, उक्त तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों को सूत्रबद्ध करती है तथा विभिन्न हालात से निवटने के लिए हमें समाधान सुझाती है)। कुल मिलाकर, सस्कृति एक जैव-सामाजिक प्रक्रिया है। विभिन्न विशिष्ट व्यक्ति अपनी सामूहिक मानवीय इकाइयों के सहयोग से अपने समय के सामाजिक आधार पर इसके विभिन्न तत्वों को आकार देते हैं।

## 9 भारतीय सस्कृति का योगदान

(क) इतिहास बताता है कि भारत में प्रचलित रही विभिन्न



संस्कृतियों—कुलीय, कबीलार्ई, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, धर्म आधारित, भाषायी, उपराष्ट्रीय, उपनिवेशी, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय आदि—में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों मूल्य हैं। सकारात्मक रूप से भारतीय संस्कृति मानवीय आचरण के उन मानदंडों की प्रतीक है जो मानवतावाद, आत्मत्याग, समय, परोपकार, निष्ठा, सदभाव, सतोष, धैर्य आदि जैसे नैतिक गुणों और उच्च आचरण को भारी महत्व देते हैं। नकारात्मक रूप से इसमें जाति प्रथा (जिसके तहत शूद्रों को मानव अधिकार नहीं हैं), सांप्रदायिक रुढ़िवाद (जिसमें मनुष्य और मनुष्य के बीच धार्मिक आधार पर घृणा पनपती है) तथा उपनिवेशी सिद्धांत (जिसमें सत्ता का केंद्र किसी बाहरी एजेंसी को बनाया जाता है) का समावेश है। भारतीय संस्कृति के इस दोतरफा चरित्र का तकाजा है कि एक तरफ हमें इसके उत्कृष्ट मानदंडों को ऊँचा उठाकर उनका विकास करना चाहिए और दूसरी तरफ इससे अप्रतिष्ठित मानदंडों को एकदम जड़ से उखाड़ देना चाहिए।

(ख) लेकिन कुछ लोग भारतीय संस्कृति के मूल्यों को काल्पनिक रूप में पेश करके इसे रहस्यमय बना देते हैं। ऐसा ही एक मिथक यह है कि भारतीय संस्कृति सहनशीलता की भावना से ओत प्रोत है, जो दुनिया की किसी दूसरी संस्कृति में नहीं मिलती। लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसका खंडन न सिर्फ सदियों से शूद्रों से (और बाहर से आए मुसलमानों और ईसाइयों से भी) की जा रही छुआछूत व प्राचीन सांस्कृतिक मानदंडों के 1947 उपरांत भारतीय जन जीवन में सांप्रदायिक और जातिवादी हिंसा की बढ़ती लहर से भी हाता है।

(ग) एक अन्य मिथक यह है कि भारतीय संस्कृति की आस्था विवाद के मुकामले मेलमिलाप में है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसका भी खंडन न सिर्फ दो सबसे बड़े पारंपरिक पौराणिक ग्रंथों (रामायण और महाभारत, जो हिंसात्मक विवादों से भरे पड़े हैं) बल्कि अति प्राचीन समय से इस देश के शासकों के पाशाविक युद्धों से भी होता है (भारतीय इतिहास की आधी अवधि तो इन युद्धों में ही बीती)।

(घ) फिर, एक और मिथक यह है कि भारतीय संस्कृति इस भौतिक सत्ता अथवा ऐतिहासिक बोध के मुकामले आध्यात्मिक सासारिकता को ज्यादा महत्व देती है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसका भी खंडन न सिर्फ वैदिक और पौराणिक साहित्य बल्कि 1947 उपरांत सत्ता धन दौलत स्वार्थ और लाभ की लालसा से भी होता है। वैदिक और पौराणिक साहित्य में छल, फरेब चारी डकैती बेईमानी, प्रलोभन, व्यभिचार, शराबखोरी, जुएबाजी आदि के वर्णन से हमें उस जमाने के मानदंडों का पता चलता है। ऋग्वेद के नौवें अध्याय में सोमरस (शराब) की खूबियों का वर्णन है। सत्ययज्ञोपवीत में मांस को सर्वोत्तम भोजन बताया गया है जबकि ऋग्वेद और यजुर्वेद गोमांस खाने की निस्संकोच वकालत करते हैं। महाभारत के पांच नायकों, पांडवों द्वारा जुए के दाव में अपनी समस्त संपत्ति और यहाँ तक कि अपनी सामूहिक प्रिय पत्नी को भी हार बैठना, एक दिलचस्प उदाहरण है। -

(ड) प्राचीन भारत में इतिहास को ज्यादा महत्व न दिए जाने का कारण दरअसल कम सिद्धांत में व्यापक आस्था का होना है। इस सिद्धांत पर चलने वाला व्यक्ति अन्वेषण व अनुसंधान से दूर और निष्प्रियता की भावना से ओत प्रोत होता है तथा इस तरह उसकी चेतना बंद रहती है। दूसरे घर्मों की तरह आध्यात्मिक सांसारिकता की बात महज आदश रही है। पर यह प्रमुख जीवन शैली कभी नहीं रही। रघुकुल के राम रहे हो या इस समय राजीव, सत्ता और धन की लालसा हमेशा चली आई है।

### संदर्भ

- 1 टाइम्स लंदन, परिशिष्ट, जनवरी 1973
- 2 'इंडिया आफ्टर नेहरू', बीपी हाउस दिल्ली, 1975, प० 2
- 3 जिसकी जुलाई 1988 की रिपोर्ट में भारत सरकार पर नक्ली मुठभेड़ों में अनेक 'उग्रवादियों की हत्याओं और पुलिस हिरासत में प्रायः मीठा समेत व्यापक पुलिस अत्याचार और मानव अधिकारों के दूसरे उल्लंघनों के आरोप हैं।
- 4 'स्टैटिस्टिकल आउटलाइस आफ इंडिया 1986-77', टाटा सर्विसज लि०, बंबई।
- 5 मासिक 'सेमिनार', मार्च 1977, प० 17
- 6 'फ्रेश पेंस्पेक्टिव्ज आन इंडिया ऐंड पाकिस्तान', बुक ट्रेडस लाहौर, 1987, प० 9

## अध्याय छह भारतीय कूटनीति-मह-रक्षा नीति

इससे अग्रिमप्रायः भारत द्वारा एक तरफ़ अपनी विदेशी सम्बन्ध (यानी विदेश नीति) की व्यवस्था करने और दूसरी तरफ़ अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों (यानी रक्षा नीति और सशस्त्र सेनाओं) का संचालन करा स है।

### 1 विदेश नीति बनाने वाले तत्व

किसी देश की विदेश नीति अनेक तत्वों जैसे कि यहाँ की सरकार अथवा शासक दल के राजनैतिक प्रयोजन या उद्देश्य, भौगोलिक स्थिति, मानवीय एवं प्राकृतिक स्रोत, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि पर आधारित होती है। इनमें से पहला तत्व खास तौर पर प्रमुख भूमिका निभाता है।

### 2 भारतीय विदेश नीति का सिद्धांत

सिद्धांतिक तौर पर, भारत की विदेश नीति नेहरू न इन्ही तत्वों और खास तौर पर भारत की दक्षिण एशिया में प्रभुत्वकारी क्षेत्रीय ताकत बनाने के अपनी पार्टी के राजनैतिक उद्देश्य के मद्देनजर तयार की। लेकिन इसमें क्षेत्रीय प्रभुत्व का पुट होने के बावजूद नेहरू ने अपनी विदेश नीति का शांति और गुटनिरपेक्षता की नीति करार दिया। यानी ऐसी नीति जिसका लक्ष्य शांति स्थापित करना और जिसकी कायशैली दोनों महाशक्तियों (जिनके इद गिद तब दुनिया बटी हुई थी) से गुटनिरपेक्ष रहना थी। उपनिवेशी जकड़ से तब छुटकारा पा रहे अल्पविकसित देशों के सद्म में गुटनिरपेक्षता की व्याख्या पांच सिद्धांतों के रूप में की गई (पंचशील वहे जान वाले इन सिद्धांतों को 1954 में भारत और चीन के बीच हुई एक व्यापार संधि की प्रस्तावना में पहली बार शामिल किया गया)। ये हैं एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता एवं प्रभुसत्ता का सम्मान, अनाश्रमण, एक-दूसरे के अदखली मामलों में अहस्तक्षेप, समानता एवं पारस्परिक लाभ तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व।

### 3 भारतीय विदेश नीति का व्यवहार

व्यावहारिक तौर पर, भारतीय विदेश नीति ने शांति और गुटनिरपेक्षता की अपनी घोषणाओं के बदले भारत की प्रभुत्वकारी क्षेत्रीय ताकत बनाने के शासक दल के राजनैतिक उद्देश्य की ही पूर्ति की है। यह बात पहले दो महाशक्तियों और उनके अपने-अपने यूरोपीय सहयोगियों के प्रति तथा फिर नव स्वतंत्र देशों के प्रति इसके व्यवहार में देखी जा सकती है।

### (1) भारत और दो महाशक्तियाँ व उनके पश्चिमी सहयोगी

(क) दो महाशक्तियों और उनके अपने अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ भारत के संबंधों के मामले में नेहरू की विदेश नीति ने शुरू में ब्रिटेन से पारंपरिक रिश्ते बनाए रखे। 1947-49 के दौर में भारतीय सेना ने ब्रिटिश कमान के तहत ब्रिटिश सेना के साथ संयुक्त सैनिक अभ्यासों में शिरकत जारी रखी। भारत ने 1947-49 के दौरान बर्मा और मलाया के राष्ट्रवादी आंदोलनों के खिलाफ हथियार, विमान और भारत की धरती पर गोरखाओं को भर्ती करने की सुविधाएँ देकर ब्रिटिश सरकार को समर्थन देना भी जारी रखा। 1949 में भारत ने ब्रिटिश पौंड के अवमूल्यन के बाद रुपए का अवमूल्यन किया।

(ख) 1950 से भारतीय विदेश नीति का झुकाव अमेरिका की ओर होने लगा। उसी साल भारत ने संयुक्त राष्ट्र सभ में अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन किया जिसके तहत अमेरिका और उसके 16 सहयोगी देशों की सेनाओं को कोरिया पर आक्रमण का अधिकार मिला। फिर भारत ने 1951 में कोरिया में अमेरिका समर्थक सेनाओं की सहायता के लिए एक चिकित्सा दल भेजा। उस समय कुछ अमेरिकी अखबारों द्वारा भारत की विदेश नीति को तटस्थ बताया जाने का खंडन करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की तत्कालीन स्थायी प्रतिनिधि और नेहरू की बहन विजय-लक्ष्मी पंडित ने कहा था, "खेद है कि हम पर तटस्थता का विल्ला चिपकाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की हाल की बैठक में हमने आपके (अमेरिका के) समर्थन में 38 वार मत दिया, 11 वार हमने मतदान में भाग नहीं लिया और सिर्फ दो वार आपसे भिन्न मत प्रकट किया।" 1950 में भारत ने अमेरिका द्वारा अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवाद को रोकने की खातिर संयुक्त कार्यक्रम बनाने के लिए बुलाए गए वागुइयो सम्मेलन (फिलीपींस) में भी भाग लिया। 1950 में ही भारत ने अमेरिका के साथ पॉइंट फोर सैनिक संधि की। इस प्रकार की संधि अमेरिका पहले फिलीपींस और थाइलैंड से भी कर चुका था। 1950-53 के दौरान भारत ने वियतनाम के विरुद्ध युद्ध सामग्री पहुँचाने के लिए फ्रांस को भी वायु परिवहन सुविधाएँ प्रदान कीं।

(ग) 1954 में जब पाकिस्तान अमेरिका की प्रायोजित सीएटो सैनिक संधि में शामिल हुआ तो भारत की विदेश नीति एक या दूसरी महाशक्ति के साथ चुनिन्दा गठजोड़ के आधार पर चलने लगी। 1955 में सावियत कम्युनिस्ट पार्टी व महासचिव और सोवियत प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते हुए। रूस ने भारत को हथियार बचता भी शुरू किए। 1956 में रूस ने जब पोलैंड और हंगरी में अदरुनी विरोध दबाने के लिए सेना भजी तो भारत ने इसकी आलोचना नहीं की जबकि उसी वर्ष इंग्लैंड-फ्रांस इजरायल द्वारा मिश्र पर संयुक्त आक्रमण की निंदा करने में भारत ने अमेरिका और रूस का साथ दिया। यही नहीं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पारित उस प्रस्ताव का भी विरोध किया जिसमें,

हमारी मे रूसी हस्तक्षेप की निंदा करते हुए उसे वहाँ से अपनी सेनाएँ हटाने का बहा गया था। 1958 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की। 1960 में भारत ने समुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में अपने सैनिक दस्ते कागो भेजे। यह बंदम अमेरिका का अनुकूल था। भारत ने जहाँ सीएटो और मँटो सैनिक सधियों का विरोध किया, वही राष्ट्रमंडल के एक सम्मेलन में नाटो सैनिक सधि का समर्थन भी किया। 1956 से 62 के दौरान भारत ने अल्जोरिया की अस्थायी सरकार को मान्यता देने से इनकार किया। देश में तीसरे आम चुनाव के कुछ पहले (1961 में) भारतीय सेना ने गोआ में दाखिल होकर पुतगाल के उपनिवेशी प्रशासन को खदेड़ दिया तथा गोआ, दमन और दीव को भारत सध में शामिल कर लिया।

(घ) 1962 में चीन के साथ हुए सीमा युद्ध के बाद भारतीय विदेश नीति दोहरे गठजोड़ की रही। तब भारत ने दोनों महाशक्तियों से सैनिक सहायता लेना शुरू की। 1963 के दौरान भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन को अपने सैनिक सधों और चौकियों का निरोक्षण करने देने की शर्तों पर उनसे हथियार लिए, उनकी अगुआई में भारत में वायुसेना के समुक्त अभ्यास आयोजित किए तथा अमेरिका के साथ वायस ऑफ अमेरिका समझौता सपन किया। भारत ने अमेरिका को वियतनाम और एशिया में उसके दूसरे ठिकानों तक सैनिक सामग्री पहुँचाने के लिए कई साल तक सप्ताह में दो बार हवाई पट्टियों को इस्तेमाल करने की सुविधा प्रदान की। इस समय तक गुटा में शामिल और गुटनिरपक्ष दशा के बीच अंतर बहुत हद तक मिट चुका था। गुटों से जुड़े देशों, जैसे थाइलैंड और फिलीपींस के साथ सवध सुधारे।

(ङ) लालबहादुर शास्त्री के जमाने में विदेश नीति का रूस के प्रति स्रुवाव कम होने के साथ साथ वियतनाम और कंबोडिया सवधी अमेरिकी नीतियों की आलोचना नरम हो गई। यह बात ससद के प्रश्नोत्तरों से जाहिर होती है।

(च) इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल के शुरू में अमेरिका से दोस्ताना सवध मजबूत करने की कोशिश की (1966 में इंदिरा और जानसन ने एक समुक्त बयान में चीन को शांति के लिए खतरा बताते हुए वियतनाम में अमेरिकी स्रु का समर्थन किया, उसी साल भारतीय रुपए का अचमूत्यन किया गया आदि)। लकिन बाद में घरेलू विवशता (वामपथी नारों और कम्युनिस्टों की मदद से प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस गुट को मार देने की खातिर) तथा पाकिस्तान को अमेरिका के निरंतर समर्थन के कारण वे अपनी विदेश नीति को रूस की ओर मोड़ने को प्रवृत्त हुए। 1968 में जब रूस ने अपनी सेना चेकोस्लोवाकिया के लोगों को दबाने के लिए भेजी तो वे चुप रही। विरोधस्वरूप केंद्रीय मंत्री अशोक महता ने इस्तीफा दे दिया। 1971 में उन्होंने रूस साथ 'शांति, मित्रता और सहयोग की सधि पर हस्ताक्षर किए। इस सन्निक सधि का फायदा भारत को पाकिस्तान से बांग्लादेश की 'मुक्ति' कराने में मिला।

(छ) जनता शासन में भारत सावियत सधि के रहते भी अमेरिका से सवध सुधारे गए। पडोसियों के साथ सवध बेहतर बनाने और चीन से सामाय रिश्ते

बनाने की कोशिशें की गईं ।

(ज) इंदिरा शासन के दूसरे दौर (1980-84) में भारतीय विदेश नीति का झुकाव फिर रूस की तरफ हुआ । भारत ने अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप की आलोचना नहीं की । उसने वियतनाम समर्थित कम्बोडिया सरकार को भी मायता दे दी । भारत न हिंद महासागर में दिग्गो गांधिया में अमेरिकी सैनिक अड्डा बनाने की तो आलाचना की पर उसने रूसी नौसेना को अपनी बंदरगाह में सुविधाएं देना भी जारी रखा ।

(झ) राजीव के शासन में अमेरिका के साथ इस बात पर सबंध सुधारने की कोशिश की गई कि वह पाकिस्तान को सैनिक सहायता बन्द कर देगा । लेकिन अमेरिका को यह मजूर नहीं है । इसलिए रूस की तरफ पुराना झुकाव बंदस्तूर जारी है । बहुरहाल तनाव कम करने के लिए दो महाशक्तियों के बीच वार्तालाप के नए सबंध और दुनिया की दूसरी घटनाओं का असर भारत की विदेश नीति पर निश्चय ही पड़ेगा ।

(11) भारत और नवस्वतंत्र देश 10807  
20 3-91

(क) जहां तक नवस्वतंत्र देशों के प्रति पंचशील की उपयोगिता का सबंध है, भारतीय विदेश नीति का चरित्र दोतरफा रहा है । एक तरफ दक्षिण एशिया से बाहर के देशों के प्रति इसे लागू करने में थोड़ी भिन्नता रही है जबकि दूसरी तरफ दक्षिण एशियाई देशों के प्रति इसका उपयोग बिलकुल ही उलटा रहा है ।

(ख) उत्तरी सीमाओं के प्रति 1947 उपरांत भारतीय विदेश नीति ब्रिटिश उपनिवेशवाद से रूसी भर भिन्न नहीं रही । सिक्किम में भारत ने 1949 में भी वहां के शासकों के खिलाफ स्थानीय विद्रोह का दवाने के लिए अपनी सेना भेजी थी । तब भारत न वहां के शासकों को सरक्षित राज्य की हैसियत से अपने साथ निकट सबंध बनाने को बाध्य किया था । उसी साल भारत ने भूटान के साथ एक संधि की । इसके तहत भारत ने विदेशी मामलों में भूटान को सलाह देने का ब्रिटेन का अधिकार खुद हासिल कर लिया । नेपाल में भारत का दबदबा कायम रहा । 1950 में जब भारत सरकार ने राणाओं की सदियों पुरानी जकड तोड़ने में नेपाल के राजा को समर्थन दिया तो उसका प्रभाव और बढ़ गया । इस तरह नेहरू सरकार शुरू से ही सरक्षित राज्यों की कठिनाई जोड़ने में लगी रही । लेकिन इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने 1974 में सिक्किम को जबरन भारत में शामिल कर लिया । भूटान पर भारतीय शकंजा और कस दिया गया । नेपाल के साथ भारत ने 1950 में मित्रता की एक संधि पर दस्तखत किए जो एक दशक तक ठीकठाक चली । पर 1960 में जबसे नेपाल ने दलविहीन पंचायत व्यवस्था शुरू की है वह भारत पर राजा की सरकार को पलटने और प्रभुत्ववादी तैवर दिखाने के आरोप लगाता आया है । भारत नेपाल सबंधों में मुख्य बाधा भारत का 'बड़े भाई वाला' रवैया रहा है जिसके विरोध में नेपाल ने

चीन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाने की कोशिश की है। दूसरी बड़ी बाधाएँ भी हैं—मसलन, भारत के साथ व्यापार और आवाजाही की संधि की शर्तों को लेकर नेपाल का असंतोष खुद की शांति क्षेत्र घोषित करने के नेपाल के प्रस्ताव पर भारत का विरोध क्योंकि भारत समझता है कि इससे नेपाल उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर हो जाएगा, नेपाल की मौजूदा दलविहीन पचासत व्यवस्था के कुछ विरोधियाँ या भारत में बन रहना आदि।

(ग) भारत की पूर्वी सीमा पर, पाकिस्तान के टूटने और स्वतंत्र बांग्लादेश बनने के बाद भारत-बांग्लादेश संबंध बहुत मधुर बन गए थे क्योंकि इसमें भारतीय सेना ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। लेकिन 1975 में मुजीबुर्रहमान की हत्या के बाद से ये संबंध खराब घले आ रहे हैं। भारत बांग्लादेश संबंधों में मुख्य बाधाएँ भारत में रह रहे चक्का शरणार्थियों द्वारा ढाका प्रशासन के खिलाफ सशस्त्र सघप छेड़ना, गंगा जल का बंटवारा, सीमा पर अतिक्रमण आदि हैं। मौजूदा इरशाद सरकार असें स आरोप लगाती आ रही है कि चक्का विद्रोह भारत की ही करतूत है और वह बांग्लादेश के प्रति प्रभुत्ववादी आकांक्षाएँ रखता है।

(घ) भारत-बर्मा संबंध चाहे ऊँ नू की नागरिक सरकार रही या नेविन का सैनिक शासन, 1947 के बाद कभी ज्यादा घनिष्ठ नहीं रहे। मतभेद का प्रमुख मुद्दा नागरिकता विहीन भारतीयों का था जिनके खिलाफ 1948 के बाद बर्मा में लगातार सांप्रदायिक दंगे होते जाएँ हैं। इसकी वजह से उनकी आबादी 1931 के 10,17,825 से कम होकर करीब दो लाख रह गई है। उन्हें बर्मा नागरिकता देने की समस्या अभी भी नहीं सुलझ पाई है।

(ङ) 1947 के बाद भारत श्रीलंका संबंध मधुर तो नहीं पर अमूमन सामान्य रहे हैं। श्रीलंका की विदेश नीति में लगातार ऐस मित्रों की तलाश का तत्व टावी रहा जिससे वह भारत की प्रभावक्षमता को निष्प्रिय कर सके। आजादी के शुरुआती वर्षों में यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) की अगुआई में श्रीलंका ने ब्रिटेन से करीबी संबंध बनाए रखे। पर 1956 में सत्ता सभालने के बाद मडारनायके और उनकी पत्नी दोनों की अगुआई में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी ने चीन और तीसरी दुनिया के दूसरे देशों के साथ संबंध विकसित किए। हाँ, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में वे भारत को महत्वपूर्ण तत्व जरूर मानते रहे। यही परंपरा यूएनपी के डडले सेनानायके और जयवर्द्धने के शासनकाल में रही। भारत श्रीलंका संबंधों में मुख्य बाधाएँ श्रीलंका में नागरिकता विहीन तमिलों का मसला, कच्चातिवू द्वीप पर विवाद, श्रीलंका के तमिलों की जातीयता आदि को लेकर रही है। पहला और दूसरा मसला शास्त्रों और इदिरा के शासनकाल में हल कर लिया गया। पर तीसरी समस्या '80 वाले दशक के शुरू में विस्फोटक बन गई। इस पर भारत ने पहल तो वहा के तमिलों को पसा हथियार, प्रशिक्षण और पनाह देकर उनका साथ दिया लेकिन बाद में उनके खिलाफ श्रीलंका की ओर से सडाई छेड़कर वह क्षेत्रीय आरक्षक की भूमिका पर उतर आया।

(च) दक्षिण पूर्व एशिया भारतीय विदेश नीति में कोई इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं रहा है। 1949 में इंडोनेशिया पर हालैंड के हमले से पैदा हुए मामले पर एक सम्मेलन आयोजित करने में सिवा इस क्षेत्र में इसकी कोई खास उपलब्धि नहीं रही। हाल ही में वपों में भारत और इस क्षेत्र के कुछ देशों में आर्थिक संबंध बढ़े हैं।

(छ) जापान पिछले चार दशकों के दौरान ज्यादातर अर्द्ध में भारतीय विदेश नीति में पश्चिमी देशों और निकट पड़ोसियों की तुलना में उतने महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं रहा। मगर कुछ साल पहले जापान के आर्थिक महाशक्ति के तौर पर उभरने के बाद वह भारतीय विदेश नीति में प्राथमिकता वाला क्षेत्र बन गया है।

(ज) पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका को भारतीय विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान मिलता आ रहा है। इसकी बड़ी वजह यह रही है कि वहाँ धार्मिक पहचान के आधार पर बन पाकिस्तानी प्रभाव से मुकाबला करने की जरूरत समझी जाती है। इस क्षेत्र में भारतीय विदेश नीति पाकिस्तान के सब इस्लामी भाईचारे के बजाय अरबों के उपनिवेशवाद विरोधी सघर्षों और सब अरब भाईचारे तथा फिलीस्तीनी सघर्ष को समर्थन देने की रही है।

(झ) सहारा के दक्षिणी पार अफ्रीकी देशों के उपनिवेशवाद विरोधी सघर्षों में भारत ने शुरू में कोई भौतिक या नैतिक समर्थन नहीं दिया। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान रूस की ओर झुकाव होने से भारत पश्चिम विरोधी सरकारों और जन आंदोलनों को समर्थन देने लगा।

(ञ) लेटिन अमेरिका 1947 उपरांत भारतीय विदेश नीति में ज्यादातर दूरदर्ती क्षेत्र ही बनाना रहा। हा इसके भारत के साथ कूटनीतिक और व्यापारिक संपर्क जरूर रहे। इसकी खास वजह यह है कि भारत इसे मुख्यतया अमेरिका का ही प्रभावक्षेत्र मानता रहा है। भारत इस संबंध में अमेरिकी भावनाओं का कितना महत्व देता आया है, यह कान्फ्रों द्वारा क्यूबा की यात्रा के निमंत्रण के प्रति नेहरू के जवाब से जाहिर होता है (नेहरू का जवाब भेजा था कि 'मेरे पास तो अपने देश में ही करने को बहुत काम पड़ा है')<sup>9</sup>।

### (iii) पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंध

(क) इन दोनों देशों के साथ संबंध भारतीय विदेश नीति की कायसूची में निरंतर पहले और दूसरे स्थान पर रहे हैं।

(ख) भारत पाक संघर्ष भारतीय विदेश नीति की धुरी है। 1947 के बटवारे में दोनों देशों में बीच गहरी कटुता छोड़ी थी। कश्मीर विवाद और उससे उपजे अनक युद्धों ने पुरानी कटुता को पूरी तरह बरकरार रखा है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने के 1948 में किए अपने वादे से मुकर गया है। उधर, भारत का आरोप है कि पाकिस्तान संग्रह की तैयारियों के लिए संयुक्त राष्ट्र को दिए बचन का पूरा करन में



है। हालांकि बटवारे से पैदा हुई कई पुरानी समस्याएँ—संयुक्त भारत की नक्दी का बटवारा, शरणागियों की संपत्ति, सिंधु जल आदि—हल हो गई थी पर कुछ नई समस्याओं (यानी दोनों पक्षों द्वारा हथियार खरीदी, एटमी हथियार, दूसरे देशों के साथ संबंध, व्यापार आदि) के साथ-साथ रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण बश्मीर विवाद उनके आपसी संबंधों को लगातार ग्रहण लगाए हुए है। भारतीय विदेश नीति में पाकिस्तान को भारत के लिए एकमात्र तो नहीं, प्रमुख चतरा हमेशा माना गया है। उधर पाकिस्तान हमेशा यह समझता आया है कि भारत विभाजन की शर्तों का उल्लंघन करके उसके टुकड़े-टुकड़े करने पर आमादा है। आपस की इही शकाओं के चलते पाकिस्तान पश्चिमी देशों के साथ सैनिक गठजोड़ करने को प्रेरित हुआ जबकि भारत ने सैनिक लिहाज से रूसी खेमे से गठजोड़ कर लिया। इससे भारतीय उपमहाद्वीप में भी शीतयुद्ध की शुरुआत हुई। क्रिया-प्रतिक्रिया के इस सिलसिले का नतीजा यह हुआ कि दोनों देशों का रक्षा खर्च बढ़ता गया और उनके आर्थिक विकास में बाधा बन गया है। अभी तक दोनों देश तीन बार युद्ध कर चुके हैं जिनमें हरेक को भारी जानी और माली नुकसान हुआ है। मगर पाकिस्तान का नुकसान कहीं ज्यादा है। 1971 के युद्ध में उस अपनी आधी भूमि और आबादी से हाथ धोना पड़ा जिसका नतीजा उपमहाद्वीप में एक नया देश—बांग्लादेश बनने में निकला। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस) की स्थापना उह एक साझे आर्थिक मंच पर लाने में सहायक भले ही हुई पर सुरक्षा संबंधी उनकी धारणाओं में रत्ता भर फक नहीं आया है। दोनों देश एक दूसरे से इस बदर आजात है कि वे किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं पाते।

(ग) भारत चीन संबंध 1959 से लेकर भारत पाक संबंधों के बाद दूसरे महत्वपूर्ण स्थान पर रहें हैं। दलाई लामा के भारत चले आने और दोनों देशों की सेनाओं के बीच गभीर सशस्त्र मुठभेडा के बाद से यही स्थिति चली आ रही है। ब्रिटिश शासन ने भारत को चीन के साथ लगी 2,500 मील लंबी विवादास्पद सीमा विरासत में दी थी। निब्वत में अपने विशेष दावों को छोड़ते हुए भारत ने सीमा संबंधी दावों को बनाए रखा, हालांकि चीन ब्रिटिश शासकों द्वारा मानी जाने वाली भारतीय सीमा को मायता नहीं देता था। भारत और चीन के बीच 1954 की तिब्बत संधि के मौके पर किसी भी ने अपनी साझी सीमा के बारे में कोई विवाद का पक्ष मुद्दा नहीं उठाया। लेकिन '56 से दोनों के बीच सीमा विवाद शुरू हो गए और कई बार दाना पक्षों के सीमा रक्षकों के बीच झड़पें भी हुईं। जब भारत ने दलाई लामा की अगुआई वाली बगावत को राष्ट्रीय विद्रोह मानते हुए 59 में उनके गुट को भारत में शरण दी तो स्थिति और बिगड़ गई। 1959 में चीन भारत संबंधों के बारे में एक श्वेतपत्र जारी किए जाने के बाद 1960 में चीन और श्वेत पुस्तकों के अलावा 1961 में एक लंबी रिपोर्ट प्रकाशित होने पर भारत में राष्ट्रीय चेतना का ज्वालामुखी फूट पड़ा। 1961 की रिपोर्ट में चीन भारत सीमा विवाद और सीमा झड़पों के बारे में तफसील दज थी। सतद में चीन के प्रति भावणों का लहजा तल्ख होने लगा। भारत सरकार सीमा संबंधों अपने दावों पर जमी रही

और उसने यह कहकर बातचीत करने से इनकार कर दिया कि इसका फैसला तो अब युद्धभूमि में ही होगा। इस अडिगल दृष्टिकोण से स्थिति बिगड़ने का ही अदेशा था। 1960 में चाउ-एन-लाई भारत आए। बताया जाता है कि उन्होंने नेफा में भारत के दावे को मान लेना का प्रस्ताव रखा बघाते कि बदले में भारत अक्साई चिन में चीन के दावे को मान ले। यहाँ चीनियों ने तिब्बत और सिक्किम को जोड़ने वाली एयर रणनीतिक सड़क का निर्माण कर लिया था। भारत सरकार ने यह प्रस्ताव नहीं माना। दोना पक्षों का रवैया सख्त हो गया। नतीजतन 1962 में भारत चीन सीमा युद्ध हुआ। भारत हार गया। खासकर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँची। चीनी सेनाएँ निश्चित समय के भीतर एक चौकी को छोड़कर बच्चे में लिए सार क्षेत्र से पीछे हट गईं। चीन सरकार ने बंदी बनाए गए सभी भारतीय सैनिकों को भारत सरकार के रजामद होते ही लौटा दिया। अफ्रीका और एशिया के छह देशों की सरकारों ने बोलबोलों में गँठब करके दोनो पक्षों के बीच मुलह वार्ता के लिए कुछ प्रस्ताव तैयार किए। लेकिन दोनो के अडिगल रुख के कारण बातचीत शुरू नहीं हो सकी। भारत चीन संवध कायदूत के स्तर तक ही रह गए। 1976 में आकर ही दोना देश एक दूसरे के यहाँ राजदूत भेजने को सहमत हुए। 1979 में जनता सरकार के विदेश मंत्री ने पीकिंग की यात्रा की और संवधों में आया ठहराव कुछ हद तक टूटा। 1980 का दशक के शुरू से भारत और चीन के बीच विवादास्पद सीमा के सवाल पर सरकारी स्तर की बातचीत के दौर चल पडे। अभी तक बातचीत के आठ दौर हो चुके हैं। आने वाले महीनों में भारतीय प्रधानमंत्री पीकिंग की यात्रा पर जा रहे हैं।

#### 4 हथियारों, विदेशी सहायता और देशों के बीच विवादों के प्रति भारत का रुख

(क) हथियारों के मामले में भारतीय विदेश नीति ने हमेशा निरस्त्रीकरण का रुख अपनाया लेकिन खुद भारत हर साल सेनाबा पर खच बढ़ाता आ रहा है।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संध के प्रति भारतीय विदेश नीति उरो शांति स्थापना करने वाली संस्था के रूप में मान्यता देती है। पर दूसरे देशों के साथ अपने विवादों में खुद भारत संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के खिलाफ रहा है।

(ग) विदेशी सहायता के मामले में भारतीय विदेश नीति आर्थिक आराम निर्भरता पर जोर देती है। मगर हर योजना के साथ भारत की विदेशी बज्रों पर निर्भरता बढ़ती गई है।

(घ) मुलह बातचीत के अरिए विभिन्न देशों के बीच विवाद मुलहाने का जहाँ तक संवध है भारतीय विदेश नीति हर क्षेत्रीय विवाद में दृगी सिद्धांत पर जोर देती है। लेकिन भारत चीन सीमा, कश्मीर आदि विवादों के प्रति यह रुख अपनाते को तैयार नहीं।

## 5 भारतीय विदेश नीति की उपलब्धि

पिछले चार दशकों में भारतीय विदेश नीति का मूल उद्देश्य दक्षिण एशिया में भारत के लिए प्रभुत्वकारी शक्ति वाला दर्जा हासिल करना रहा है। लेकिन यह मूल उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि वह दक्षिण एशिया में किसी एक देश तक की मित्र बनाने में नाकाम रही है। गुटनिरपेक्ष दशा से भारत का अलगवृत्तता 1962 के भारत-चीन युद्ध के समय ही स्पष्ट हो गया था।

## 6 रक्षा नीति

(क) किसी देश की रक्षा नीति मूलतः वहाँ की सरकार अथवा शासक दल की विदेश नीति के अनुरूप ही होती है।

(ख) भारतीय विदेश नीति का अनुरूप ही भारतीय रक्षा नीति का उद्देश्य भी देश को दक्षिण एशिया में प्रभुत्वकारी शक्ति बनाना और इस क्षेत्र के सभी देशों को भारत के प्रभावाधीन लाना रहा है।

(ग) (i) पहली बात तो यह कि भारतीय रक्षा नीति विदेश नीति के इस विश्व रणनीतिक मूल्यांकन पर आधारित है कि 1960 और 1970 वाले दशक के दौरान दो महाशक्तियाँ अमेरिका और रूस के बीच तनाव शक्तिय विश्व शांति या बहतर माहौल के रक्षान का संकेत नहीं देती। इसके मुताबिक सामरिक शस्त्र परिसीमन संधि-1 (साट 1) चूँकि प्रक्षपका के आकार और गुणवत्ता वृद्धि पर रोक लगाए बिना उनकी संख्या को ही सीमित करती है, इसलिए उसे निरस्त्रीकरण की दिशा में कदम नहीं माना जा सकता, साट 2 क्यादातर कुछ चुनिंदा और अत्यधुनिक हथियारों पर असहनीय आर्थिक घच के कारण पदा होने वाली आपसी हाड को सीमित करने के लिए दो महाशक्तियों का प्रयास मान है, अणु परिसीमन संधि दुनिया की संय शक्तियों का सामरिक हथियारों पर एकाधिकार बनाए रखने का साधन है, 1987 की मध्यम अणु शस्त्र संधि हालांकि निरस्त्रीकरण की दिशा में एक कदम है पर इसके तहत दुनिया के महज 3 से 4 फीसदी अणु हथियार ही जाते हैं और फिर इससे उन देशों के भारी भरण रक्षा बजटों में कमी आने के कोई आसार नहीं है। बहरहाल, थोड़ी नरमी के बावजूद तनाव शक्तिय का यह रक्षान अभी अणु शस्त्रों का एकाधिकार और दो महाशक्तियों की प्रभुत्ववादी जाकाक्षाओं को खत्म करने की कोई पर्याप्त गारंटी नहीं माना जा सकता।

(ii) दूसरे, भारतीय रक्षा नीति विदेश नीति के इस क्षेत्रीय मूल्यांकन पर आधारित है कि 1959 तक तो पाकिस्तान भारतीय सुरक्षा के लिए एकमात्र खतरा था और उसके बाद चीन प्रमुख खतरा बन गया है।

(घ) इस विश्व और क्षेत्रीय मूल्यांकन के आधार पर भारतीय रक्षा नीति जोर इस कदर मजबूत रक्षा शक्ति बनाना रहा है जो किसी भी समय अणु हथियार

बनाने और इस्तेमाल करने के सक्षम हो। यह बात भारतीय रक्षा बजट में निरंतर वृद्धि से स्पष्ट है। 1948-49 में 167.5 करोड़ रु०<sup>4</sup> से बढ़कर यह खर्च 1988-89 में 14,000 करोड़ रु० जा पहुँचा यानी पिछले 40 साल में इसमें 84 गुना वृद्धि हुई है। 1987-88 के लिए अनुमानित रक्षा खर्च ऊर्जा के सीनो क्षेत्रों (कायला बिजली और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों) में कुल मिलाकर अनुमानित खर्च से करीब 5 गुना, ग्रामीण विकास से 6 गुना, शिक्षा से 11 गुना, परिवार कल्याण से 23 गुना, शहरी विकास से 39 गुना, जल ससाधनों से 59 गुना वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान से 73 गुना और विज्ञान एवं टेक्नालॉजी से 85 गुना ज्यादा था। यहाँ जिनकी की गई सभी मदों के तहत कुल मिलाकर आवंटन रक्षा की मद के आधे से भी कम है।<sup>5</sup>

(ड) रक्षा पर अपने साधनों से भी ज्यादा खर्च करते हुए भारत सरकार ने सभी अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मंचों से दुनिया में पूर्ण निरस्त्रीकरण, सभी अणु शस्त्रों को तबाह करने, सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों के रक्षा बजटों में कटौती किए जाने तथा निरस्त्रीकरण से बचे पैसे को दुनिया के आर्थिक विकास में लगाने की माँगें उठाई हैं।

(च) इस रक्षा नीति के साथ साथ कश्मीर और भारत-चीन सीमा विवादों के बने रहने से इस क्षेत्र में हथियारों की होड़ निरंतर बढ़ी है तथा भारत-सावियत संघ के नजदीक पहुँचा है।

(छ) 1971 के भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान के टूटने से उसकी तरफ का खतरा अपक्षतया कम हुआ गया है। उधर भारत-चीन संबंधों में धीरे-धीरे मगर निरंतर सुधार से दोनों देशों के बीच तनाव घटा है। लेकिन विश्व और क्षेत्रीय तनावों में कमी होने के बावजूद अभी इस बात का कोई संकेत नहीं है कि भारत की विश्व अथवा क्षेत्रीय रणनीति का चीन या पाकिस्तान की रणनीति से तालमेल बढेगा। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय प्रभुत्व हासिल करने के लिए भारत की महत्वाकांक्षा पहले से तेज हो गई है (इसका सबूत श्रीलंका और मालदीव में भारतीय सेना की हाल ही की दखलदाजी से मिलता है)। मगर न तो पाकिस्तान और न बांग्लादेश, नेपाल आदि भारतीय प्रभुत्व मानने को तैयार हैं जबकि अणु शक्ति होने के कारण चीन भी महाशक्ति बनने की आकांक्षा रखता है।

## 7 भारतीय कूटनीति सह-रक्षा नीति द्वारा बढोरी गई भारी कीमत

ऊपर दिए विवरण से पता चलता है कि भारतीय कूटनीति सह-रक्षा नीति नीति कोई फलदायक प्रक्रिया साबित नहीं हुई है। सबसे पहली बात यह कि इससे भारत की दुष्ट छवि बनी है यानी वह कहता कुछ है और करता कुछ। दूसरे इससे भारत अपने पड़ोसियों से अलग-थलग पड़ा है। तीसरा, यह उपमहाद्वीप हथियारों की होड़ रोकने और 1947 के बाद भारत के अपने दो पड़ोसियों युद्ध टालने में नाकाम रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य तौर

सवाल पर लड़े गए तीन युद्ध (1948, 1965 और 1971) दोनों देशों के लिए बहुत महंगे पड़े हैं। कश्मीर सवाल पर दोनों देशों के बीच अगर कोई समझौता हुआ होता या दोनों में महासंध बनाने पर सहमति हुई होती अथवा उन्होंने युद्ध न करने की संधि पर हस्ताक्षर किए होते तो कोई भारत-पाक युद्ध न होता। ये पुराने तर्क कि 1947 के बंटवारे से सांप्रदायिकता पर प्रहार होगा अथवा भारत में कश्मीर के विलय से धमनिरपेक्षता मजबूत होगी, पूरी तरह निराधार साबित हुए हैं। भारत में सांप्रदायिकता पर प्रहार पाकिस्तान के साथ मूठभेद नहीं बल्कि उसके प्रति दोस्ती और देश में धर्म और राजनीति को अलग करने की नीति अपनाने से होगा। 1962 का चीन-भारत युद्ध भी पूरी तरह गैर जरूरी था और उस शायद टाला जा सकता था। अगर भारतीय कूटनीति सह रक्षा नीति का रूख अधिक लचीला होता तो भारत और चीन शायद यह युद्ध न करते। कुल मिलाकर इस नीति की वजह से भारत को जानी घ माली दाना तरह से भारी बीमता चुकानी पड़ी है। इसका कोई सरकारी विवरण उपलब्ध नहीं। पर मोटे अनुमान के अनुसार इन चार युद्धों में भारतीय सेना के 13,000 जवान खेत रहे और 30,000 घायल हुए।<sup>6</sup> दूसरी तरफ का जानी नुकसान भी कमोबेश इतना ही रहा होगा। माली लिहाज से भी दृष्टिकारों की होड़ और युद्धों में भारत को अरबों रूपए फूकन पड़।

### संदर्भ

- 1 इस सिलसिले में नेहरू ने एक बार कहा था, 'भारत पश्चिमी, दक्षिणी और दक्षिण-पूर्व एशिया की घुरी है।' (नेहरू के चुनिंदा भाषण, सितंबर 1946 अप्रैल 1961 नई दिल्ली 1961 पृ० 2-5)। उन्होंने आगे भी कहा था, भारत एशिया में जति असाधारण स्थिति में है और इसका इतिहास बहुत हद तक भौगोलिक तत्वों और दूसरे तत्वों से प्रभावित रहा है। एशिया में चाहे जिस समस्या को भी लें भारत किसी न किसी रूप में सामने आता ही है। उसकी अपनी वास्तविक या सम्भावित क्षमता और संसाधनों के कारण भी उपेक्षा नहीं की जा सकती।' (जवाहरलाल नेहरू के भाषण, 1949-53, प्रकाशन विभाग, दिल्ली 1953, खंड 1 पृ० 316)।
- 2 मनसंध, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के दस्तावेजों का संवैधान, 1952-62, पृ० 459
- 3 हिंदू, 29-9-1960
- 4 हिंदुस्तान टाइम्स, 11-2-88, पृ० 11
- 5 वही, 14-2-88, पृ० 13

6 कश्मीर में 1948 के भारत-पाक युद्ध में जम्मू कश्मीर राज्य सेना के करीब 1,263 जवान मारे गए ('द इंडियन मिलिट्री रिवाइवल', जी० डी० बक्षी, लासर इंटरनेशनल, नई दिल्ली 1987, प० 66)। इसके अलावा भारतीय सेना के भी करीब 2,000 जवान खेत रहे।

1962 के चीन भारत सीमा युद्ध में करीब 3,200 भारतीय सैनिक मारे गए और 6,000 से अधिक घायल हुए ('इंडियाज चाइना वार', मेक्सवेल)।

1965 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना के 2,226 जवान मारे गए और 7,870 घायल हुए ('इंडिया पाकिस्तान वार 1965' हरिराम, हरियाणा प्रकाशन, दिल्ली 1968, प० 20)। लंदन के सामरिक अध्ययन संस्थान का अनुमान है कि भारत के मृत और घायल सैनिकों की संख्या 4,000 से 6,000 के बीच रही।

1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना के करीब 3 000 जवान मारे गए और लगभग 8000 घायल हुए ('डिससेम्बरफ्रेट आफ पाकिस्तान', पृ० 239)।

## अध्याय सात 1945 के बाद की दुनिया

### 1 देशों के बीच बढ़ती अंतरनिभरता

1945 के बाद की दुनिया की खासियत यह है कि देश सांगठनिक, वचारिक, भौतिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक अंतरनिभर होत जा रहे हैं। अंतरनिभरता का मतलब आपसी निभरता है जबकि निभरता किसी बाहरी ताकत द्वारा निर्धारित स्थिति का भान कराती है। देशों की अंतरनिभरता विकास की वह प्रथिमा है जिसे कदाचित कोई व्यक्ति या राष्ट्र राज्य नियोजित नहीं करता। इसकी शुरुआत अनेक व्यक्तियों और राष्ट्रों के संबन्धों आकारों से विकसित हुए नए टेक्नोलॉजिकल रचना तंत्र के उदय से हुई है। 1945 के बाद देशों की अंतरनिभरता की प्रक्रिया निम्न तथ्यों से स्पष्ट है।

#### (क) नए विश्व संगठनों का उदय

सबसे पहले तो यह विभिन्न श्रेणियों के विश्व संगठनों के उदय से स्पष्ट है। ये संगठन हैं—(i) संयुक्त राष्ट्र संघ जो विश्व मंच के मुख्य पात्रों यानी राष्ट्र राज्यों की राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के आधार पर गठित है और जिसकी स्थिति आने वाले कुछ वक्त तक ऐसी ही रहेगी, 1945 में विद्यमान 51 राज्यों द्वारा स्थापित इस संस्था की सदस्य संख्या अब 159 तक पहुँच गई है, (ii) संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियाँ जैसे यूनेस्को एफएओ, यूनिडा, अकटाड आदि, (iii) आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान जैसे विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि, (iv) आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन गैट, (v) सरकारी और गैर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय बैंकों सहित निजी बहुराष्ट्रीय और पार राष्ट्रीय निगम (शेल, एक्सान, आईबीएम आदि) तथा राजकीय स्वामित्व वाली कंपनियाँ, (vi) विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय मजदूर महासंघ अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ अंतरराष्ट्रीय डाक संघ आदि, (vii) अधिराष्ट्रीय (अथवा क्षेत्रीय) समूह जैसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद लेटिन अमेरिकी देशों का संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन, एसियान, दक्षिण आदि (viii) 'अंतरराष्ट्रीय संगठन' (ग्रुसेल्स 1977) नामक वार्षिकी के 16वें संस्करण में करीब 300 सरकारी और 4,600 से अधिक गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सूची दर्ज है। इनमें 250 संगठन विज्ञान, 370 स्वास्थ्य, सफाई और चिकित्सा और 240 टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से संबंधित हैं।

## (ए) राष्ट्रीय समस्याओं का सावभौमिकरण

दूसरे, यह विभिन्न भौतिक समस्याओं के सावभौमिकरण से स्पष्ट है। ये समस्याएँ हैं पर्यावरण प्रदूषण, अणु युद्ध और हथियार, समुद्र और अंतरिक्ष की खोज, दुनिया की बढ़ती आबादी और उसकी छाछान जरूरतें, कच्चे माल और ऊर्जा के घटते स्रोत, बढ़ती गरीबी, अमीर और गरीब लोगों के दशों में बढ़ती खाई, दुनिया भर में मुद्रा-स्फीति, बेरोजगारी, मंदी, मुद्रा व्यवस्था आदि। ये समस्याएँ राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर गई हैं। सोवियत संघ में चेरनोबिल अणु दुर्घटना ने स्कैंडेनेवियाई देशों को भी प्रभावित किया। अगर ओजोन की परत को नुकसान पहुँचा तो इसका प्रभाव समाजवादी और गैर समाजवादी देशों पर समान रूप से पड़ेगा। अगर प्राकृतिक स्रोत घटने लगे हैं या दुनिया की आबादी पर बाँव नहीं पाया जाता तो इसका असर विकसित और अल्पविकसित दोनों किस्म के देशों पर पड़े बिना नहीं रहेगा। विश्व-यापी प्रश्रियाएँ हालाँकि पिछले युगों में भी रही हैं (मसलन निकट पूर्व में कभी उपजाऊ रही भूमि का रेगिस्तान बनना, भूमध्य सागर के इंद गिद जगलो का विनाश होना, संस्कृति का अनियोजित प्रसार होना आदि) पर उनकी सख्या बहुत कम रही है और उन्हें परिपक्व होने में कई सदियाँ लग गईं। चालू सदी में विश्व समस्याएँ बहुत तेजी से बढ़ी हैं और उनकी परिपक्वता अवधि कुछ दशकों तक सीमित रह गई है। अंतरनिभरता से पहले के दौर में विश्व समस्याएँ चूँकि कभी कभी ही उठा करती थी इसलिए उनके बारे में कम ही सामाजिक ज्ञान उपलब्ध है। जितनी जल्दी हम उनका ज्ञान हासिल कर लें, उतना ही इस दुनिया के लिए बेहतर है।

## (ग) राष्ट्रीय आर्थिक मॉडलों की बढ़ती अप्रासंगिकता

तीसरे, यह राष्ट्रीय आर्थिक मॉडलों—राज्य नियोजित तंत्र (सोवियत मावस-वादी मॉडल), निजी बाजार तंत्र (पश्चिमी उदारवादी मॉडल) और मिश्रित तंत्र—की बढ़ती अप्रासंगिकता से स्पष्ट है। इन सभी मॉडलों को अधिकाधिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना है। सोवियत संघ में पूँजी/उत्पादन के बढ़ते अनुपात के साथ साथ घटती विकास दर और आवश्यक वस्तुओं की कमी पश्चिमी जगत में (जिसका अगुआ अमेरिका अब सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय बजटाता बन गया है) मुद्रा एवं वित्तीय संकट के साथ साथ कम आर्थिक विकास दर तथा अल्पविकसित देशों में बज के बढ़ते बोझ के साथ साथ मामूली आर्थिक विकास-दर और छाछान की कमी इन्हीं कठिनाइयों की अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय आर्थिक मॉडलों अथवा एक ही राष्ट्र के कल्याण का युग अथ बीत गया है। मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के मुकाबले राष्ट्रीय आर्थिक मॉडलों की अप्रासंगिकता इस उदाहरण से समझी जा सकती है कि पारिवारिक उद्यम से ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में विस्तार पाने के बाद हमेशा एक नए किस्म के प्रयुधन की जरूरत होती है।



### (घ) सत्ता के नए मापदंड का उदय

चीये, यह मौजूदा दुनिया में सत्ता के नए मापदंड के उदय से स्पष्ट है। पुरानी दुनिया में (मानव समाज की शुरुआत से लेकर राष्ट्र-राज्य तक) सभी परंपरागत धारणाएँ (यानी युटुवीय, कबीलाई, जातिवादी, धार्मिक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय) जहाँ प्रभुत्व/अधीनता के संबंधों से प्रलंबित थी, वहीं मौजूदा दुनिया में यह संबंध तेजी से बदल रहे हैं। अब सबसे ताकतवर इकाई भी कमजोर पर अपनी इच्छा लागू करने में कम कारगर होती जा रही है। सर्वोच्च सैन्य और आर्थिक ताकत वाला अमेरिका भी उत्तर कारिया, दक्षिण वियतनाम, निकारागुआ आदि से निपटन का कोई रास्ता नहीं निकाल पाया। यहाँ तक कि ईरान में अपने दूतावास पर बमों और बहा कमचारिया का बंदी बना लिए जाने पर भी वह बचकन दिसा। उधर, महाशक्ति होने के बावजूद सोवियत संघ अफगानिस्तान में आठ साल बमबाँझा जमाएँ रखने के दौरान विरोधी पक्ष का बंधन नहीं कर पाया। जाहिर है कोई भी महाशक्ति अब दूसरों पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकती। दो महाशक्तियों में केंद्रित दुनिया की जगह सामूहिक केंद्रित दुनिया ले रही है। दुनिया ज्यों ज्यों अंतरनिभर होती जाएगी, प्रभुत्वकारी देश ताकत खोते चले जाएंगे और अधीनस्थ देशों को सौदेबाजी की अधिकाधिक ताकत हासिल होती जाएगी।

### (ङ) राष्ट्र राज्य का घटता प्राधिकार

पाचवें, यह अंतरराष्ट्रीय संगठना को काबू रखने में राष्ट्र-राज्यों के घटते प्राधिकार से स्पष्ट है। सयुक्त राष्ट्र कोष में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला अमेरिका सयुक्त राष्ट्र या उसकी किसी एजेंसी को बमों में नहीं कर पाया है। अल्पविकसित देश भी पार राष्ट्रीय निगमों और बहुराष्ट्रीय निगमों पर काबू पाना अधिकाधिक दुश्वार पा रहे हैं। कुछ मामलों में तो ये निगम आर्थिक तौर पर बहुत से अल्पविकसित राज्यों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हैं।

### 2 घटनाक्रम को समझने में मुश्किल

अनुभव बताता है कि ज्ञात घटनाक्रम का नए घटनाक्रम के मुकाबले आसानी से पहचाना जा सकता है। इस तरह राष्ट्रों क्षेत्रों, धार्मिक समुदायों, जातियों, जन जातियों कुलों आदि की समस्याओं को कम परिचित विश्व समस्याओं के मुकाबले आसानी से समझा जा सकता है। अनुभव यह भी बताता है कि जब नई प्रक्रिया सामने आती है तो मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति उसे पारंपरिक तरीके से निबटाने की होती है। व्यक्ति और राष्ट्र राज्य आज विश्व समस्याओं के बारे में राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाते हैं जबकि उनका तकसगत हल दुनिया की सामूहिक कोशिशों से ही हो

सकता है। मसलन, सामूहिक साधनों के इस्तेमाल के लिए अगर किसी साक्षी अंतर-राष्ट्रीय योजना पर सहमति होती है तो इससे दुनिया भर में मूल्य की समस्या हल हो सकती है। इसी तरह, सामूहिक अंतरराष्ट्रीय अतिरिक्त शोध कार्यक्रम से हमें अकेले अकेले राष्ट्रीय प्रयासों के मुकाबले ज्यादा पान मिल सकता है। अनुभव आगे बताता है कि अगर किसी समस्या की ओर उचित समय पर ध्यान न दिया जाए तो उसमें तब्दीलियां आ जाती हैं जिससे अक्सर उसे निवटाना मुश्किल हो जाता है और कई बार तो वह बेकाबू हो जाती है। खतरे के स्तर तक पहुंच रही बहुत सी विश्व समस्याओं (जैसे प्रदूषण) का हल करना अभी उतना मुश्किल नहीं पर वक्त गुजरने के साथ-साथ यह टेढ़ी घीर होती जाएगी।

### 3 सावभौमिकता के प्रति मनुष्य की पिछड़ी अनुश्रिया

यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जहां राष्ट्रों की राजनतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अंतरनिभरता अधिक स्पष्ट रूप से सामने आई है, वहीं विभिन्न देशों के बीच नीतियों का तदनुसंध विवास नहीं हुआ है। मसलन, दोनों महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ ने 1987 में ही देशों की अंतरनिभरता का एहसास किया, हालांकि अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों में वे अपने मित्र देशों को आर्थिक और सैनिक गुटों में संगठित करके इस पर पहले सज्मल करते आ रहे हैं। ब्रेटन वुड्स संधि और माशाल योजना एक तरह से सावभौमिकता के प्रति अमेरिका की अनुश्रियाए ही थी। इसी प्रकार, कोमिनफाम और कोमिक्ॉन भी अंतरराष्ट्रीयवाद के प्रति सोवियत संघ की अनुश्रियाए थी। लेकिन अपनी-अपनी राष्ट्रीय दिशाओं (एक देश में समाजवाद की सोवियत भावसवादी दिशा तथा राष्ट्रीय बाजार और राष्ट्रीय ससदीय लोकतंत्र की अमेरिकी उदारपथी दिशा) के कारण उनमें हर कोई अपने प्रभाव क्षेत्र के अंदर और बाहर अपने ही प्रभुत्व के तहत सावभौमिकता स्थापित करने के प्रयास करता आ रहा है। दोनों महाशक्तियों के आपसी संबंध दूसरे विश्वयुद्ध के बाद ही तनावपूर्ण हुए हैं। शीतयुद्ध की यह अवस्था, जिसमें कभी तनाव घट भी जाता था (जैसे 1958 में ख़ुश्चोव की अमेरिका यात्रा), 1962 में क्यूबा पर उठे संकट तक बनी रही। इसके बाद भुरभुरे तनाव शैलित्य का दौर चला जिसमें कभी शीतयुद्ध के मुद्दे उभरते रहे (जैसे अमेरिका द्वारा 1962-75 के दौरान वियतनाम पर और 1970-75 के दौरान कंबोडिया पर सशस्त्र आक्रमण, 1983 में ग्रेनाडा पर हमला और 1986 में लीबिया पर बमबारी तथा सोवियत संघ द्वारा 1986 में चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप, 1976 में अगोला में क्यूबाई सेना की झाकना, 1978 में कंबोडिया पर वियतनामी सशस्त्र आक्रमण का समयन तथा 1979 में अफगानिस्तान में सशस्त्र हस्तक्षेप) और कभी तनाव में शिथिलता सामने आई (जिसका इजहार (i) 1963 में आर्थिक अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, (ii) 1968 में अणु भंडार न करने की संधि, (iii) 1971 में साल्ट-1 संधि, (iv) 1975 में हेलिसेंकी संधि तथा (v) 1978 में साल्ट-2 संधि

से होता है)। 1987 में पहली बार दोनों महाशक्तियों को एहसास हुआ कि न सिर्फ राष्ट्र राज्य बल्कि वे खुद भी एक दूसरे पर अंतरनिभर हो गए हैं। अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा अंतरनिभरता की बात मान लिए जाने का मतलब है कि उनमें किसी का भी दूसरे के बिना बजूद नहीं रह सकता। चीन तो अमती तौर पर 1978 से ही इसी आधार पर अमेरिका के साथ संबंध बनाए हुए है। सद्घातिक तौर पर इसका मतलब है कि रूस और चीन इन भावसवादी दृष्टिकोणों को छोड़ चुके हैं जिनके मुताबिक सवहारा शक्ति द्वारा अतंत कम्युनिज्म की विजय होगी, वगैरे संघ द्वारा पूंजीवाद का तहता पलट दिया जाएगा, साम्राज्यवाद (यानी अमेरिका और पश्चिमी जगत) मृत्युशैया पर पड़ा क्षयग्रस्त पूंजीवाद है, पूंजीवाद समाजवाद को और समाजवाद पूंजीवाद को घटम करके ही जिंदा रह सकता है, शक्ति पूण प्रतियोगिता और सहअस्तित्व का जमाना आ गया है आदि आदि। यह बात दीगर है कि रूस और चीन फिलहाल कथनी में इस तथ्य को न मानें। सद्घातिक तौर पर इसका यह मतलब भी है कि अमेरिका अथवा पश्चिमी जगत न कम्युनिस्ट राज्यों को तानाशाही राज्य मानने का दृष्टिकोण (रूस को दुष्ट साम्राज्य मानने वाला रणन का दृष्टिकोण) छोड़ दिया है तथा उह उदारवादी राज्या के रूप में स्वीकार कर लिया है। जाहिर है यह मूल अवधारणात्मक परिवर्तन है जिससे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संबंध बढ़ने से दुनिया में संबंधों का आधार बदल गया है। इससे दुनिया में बाकी सभी संबंधों यानी विभिन्न सैनिक गुटों (मसलन नाटा, वार्सा आदि) के बीच और हरेक गुट के भीतर, एक तरफ दो महाशक्तियों और दूसरी तरफ गुट निरपेक्ष देशों के बीच, खुद गुटनिरपेक्ष देशों के अपने बीच, एक या दूसरी महाशक्ति से जुड़े विभिन्न शत्रु देशों (मसलन भारत और चीन) के बीच संबंधों पर भी असर पड़ने की संभावना है।

#### 4 सावभौमिकता के देर बोध से मानवीय उद्देश्य को पहुंचती हानि

(क) सामाजिक यथाथ को समझने में देरी के कारण मनुष्यजाति विश्व मुद्रा-स्फीति, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार आदि के रूप में पहले ही भारी कीमत चुका चुकी है। पहले विश्वयुद्ध के बाद अजर हमन उचित अनुश्रिया दिखाई होती तो दूसरा विश्वयुद्ध टल सकता था। यदि 1920 के दशक में तनाव शथित्य की प्रतीक श्लोकानों की भावना वाली सधियों पर अमल किया जाता, जिनमें तब मौजूद विश्व समस्याओं के प्रति सामूहिक रक्ष अत्तियार करने पर जोर दिया गया था, तो 1930 के दशक की आर्थिक मदी का परिणाम इतना भयंकर न होता। इसी का नतीजा था कि जर्मनी में नाजीवाद और जापान में मंयवाद जोर पकड़ गया जबकि बाकी पश्चिमी राज्यों में अकमण्यता हावी हो गई। अगर वैसे ही मदी आज आ गई तो इसकी कीमत चुकाना असह्य हो जाएगा क्योंकि विश्व जयव्यवस्था अब ज्यादा ध्यापक हो गई है। जितनी जल्दी हम अंतरनिभरता की वास्तविकता को समझ लेंगे, मानवजाति के

लिए चतना ही बेहतर होगा।

(ख) सावभौमिकता के प्रति उचित अनुश्रिया आज मानवजाति की पहली जरूरत है। दो महाशक्तियों की अनुश्रिया अगर दूसरे देशों के तालमेल से और सबसे बड़ी बात यह कि सचेत विश्व जनमत की निगरानी में सपन्न नहीं होती तो वह गलत दिशा में जा सकती है। ऐसी सूरत में वह दुनिया पर प्रभुत्व जमाने के लिए महाशक्तियों के साथे उदम में बदल सकती है या फिर नई उभरती आर्थिक महाशक्ति जापान के खिलाफ दोनों महाशक्तियों का संयुक्त मार्चा भी खड़ा हो सकता है।

### 5 विश्व लोकतांत्रिक राज्य ही उचित अनुश्रिया

(क) हमारी राय में सावभौमिकता के प्रति उचित अनुश्रिया यही हो सकती है कि विश्व समुदाय अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र का गठन कर जिसमें विश्व लोकतांत्रिक राज्य के तहत राष्ट्र राज्य गौण इकाइया हो। विश्व लोकतांत्रिक राज्य दुनिया के लोगों और छोटे राष्ट्रों के हितों की रक्षा की धातिर दो सदस्यीय सदन से गठित होगा जिनके अधिकार बराबर होंगे। एक निचला सदन जो सीधे लोगों द्वारा (जनसंख्या के आधार पर) चुना गए प्रतिनिधियों से गठित होगा और दूसरा ऊपरी सदन जो राष्ट्र-राज्यों की संसदा द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से गठित होगा जिसमें छोटे या बड़े हर राष्ट्र राज्य के बराबर प्रतिनिधि होंगे। हर क्षेत्र के मतदाताओं का किसी भी समय अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार होगा। विश्व लोकतांत्रिक राज्य और उसकी विभिन्न एजेंसियों का मुख्य काम निचली प्रशासनिक इकाइयों से लेकर राज्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक राजनैतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर जनसमुदाय का लोकतांत्रिक नियंत्रण कायम करना होगा।

(ख) विश्व लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना से अधिक प्रायश्चित सामाजिक व्यवस्था वजूद में आएगी। मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में तो विश्व की 6 फीसदी जनसंख्या वाले अमेरिका में दुनिया की सालाना ऊर्जा और चुनिंदा खनिजों की 30 फीसदी खपत के साथ साथ दुनिया का 30 फीसदी उत्पादन भी होता है। उधर, विश्व की 7 फीसदी जनसंख्या वाले सोवियत संघ में दुनिया का करीब 20 फीसदी उत्पादन होता है और लगभग इतनी ही खपत होती है। इस व्यवस्था के तहत अमेरिका उत्तरोत्तर भारी घाटे के बजट लाकर विश्व अर्थव्यवस्था को तहस नहस करता है जबकि सोवियत संघ अपने विशाल माहीगिरी बेड़ों के जरिए दुनिया के मछली ससाधनों को नुक्सान पहुंचाता है। इसी व्यवस्था में पूजा लगान के अधिार बहु-राष्ट्रीय अथवा राज्य निगमों के हाथों में सुरक्षित है जबकि राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में लोगों की राय कोई मानने नहीं रखती।

(ग) इस अंतरनिर्भर संसार में भारत दक्षिण एशिया में अपनी क्षेत्रीय प्रभुत्ववादी नीति पर चलकर अच्छे पलासियों जैसे सबघों में बाधा डाल रहा है और इस तरह सावभौमिकरण की प्रक्रिया में रोड़े अटका रहा है।

संदर्भ

- 1 एड्यू एम० स्काॅट, 'द टाइमिंग्स ऑफ इंटरेडिपेंडेंस', नॉथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी प्रेस, अमेरिका 1982, पृ० 40

## अध्याय आठ

# भारत के आधुनिकीकरण की व्यापक योजना और राष्ट्रीय विकल्प बनाने की नीति

अभी तक हमने इस सवाल पर गौर किया है कि पिछले 40 वर्षों में क्या हुआ और क्यों हुआ। हमारे अध्ययन का निचोड़ यह है कि पिछले चार दशकों से भारतीय राष्ट्र राज्य और उसकी एक पार्टी के प्रभुत्व वाली सरकार जो घटिया राजनैतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कारणों से अजाम होती आ रही है, उसके लिए भारतीय जनता को भारी जानी व माली कीमत चुकानी पड़ी है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता इन दो सामाजिक तत्वों का सही समाधान ढूँढे। इसमें 1947 उपरांत भारतीय राष्ट्र राज्य दीर्घकालिक सामाजिक तत्व और उसकी एक पार्टी के प्रभुत्व वाली सरकार अल्पकालिक सामाजिक तत्व है। दीर्घकालिक तत्व के समाधान के लिए यह जरूरी है कि भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और कूटनीति सह रक्षा नीति के आधुनिकीकरण की व्यापक योजना तैयार की जाए जबकि अल्पकालिक तत्व के समाधान के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस इ का राष्ट्रीय विकल्प बनाने की नीति तैयार करना जरूरी है। व्यापक योजना और राष्ट्रीय विकल्प की नीति को लोगों में लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए।

## भारत के आधुनिकीकरण की व्यापक योजना

### 1 इसका मूल लक्ष्य, निदेशक सिद्धांत और वायशली

(क) इस व्यापक योजना का मूल लक्ष्य खास तौर पर भारतीय जनता (सामूहिक और व्यक्तिगत दानों रूप से) और अमूमन दुनिया के लोगों की वंचित और भौतिक लिहाज से सामाजिक उन्नति करना है। मतलब यह कि हमारा सामाजिक पूंजी (यानी टेक्नोलॉजी और मनुष्यजाति की रचना अथवा प्रकृति और मनुष्य) का विकास करना तथा हर कहीं और हर समय इसके दो पक्षों के बीच अनुकूलता बरकरार रखना, उस भंग न होना।

(ख) इस व्यापक योजना का निदेशक सिद्धांत (जा देशों की अंतरनिभरता के हमारे युग की खासियत से निकलता है) अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र की अभिधारणा है। यह अभिधारणा एक ऐसा विश्व लोकतांत्रिक राज्य स्थापित करने की पगथर है जिसमें राष्ट्र-राज्य उसकी गौण इकाइया हों तथा जो छोटे या बड़े राज्यों की समानता और सभी सामाजिक प्रक्रियाओं पर जनता के लोकतांत्रिक नियंत्रण व जुड़वा असूती पर

आधारित हो—यानी निचली प्रशासनिक इकाइयों से लेकर राष्ट्र-राज्य और अंतरराष्ट्रीय लोकतांत्रिक राज्य के स्तर तक राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर जनता का नियंत्रण हो। उपरोक्त मूल लक्ष्य की पूर्ति के लिए आज मनुष्यजाति की सबसे उचित व्यवस्था यही हो सकती है। इसका मतलब है कि हमेशा अंतरराष्ट्रीय लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अद्वितीय करना अथवा सामाजिक समस्याओं के प्रति अंतरराष्ट्रीयवादी लोकतांत्रिक दिशा अपनाना यानी प्रत्येक सामाजिक गतिविधि में समूची जनता को शामिल करना। यद्यपि यह है कि मौजूदा दौर में सामाजिक समस्याएँ राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से न तो सही तौर पर समधी जा सकती हैं और न ही कारगर ढंग से हल की जा सकती हैं। क्योंकि यह दृष्टिकोण दुनिया की समूची जनता को नहीं जोड़ सकता।

(ग) इस व्यापक योजना की गायशैली हमेशा उक्त मूल लक्ष्य और निदेशक सिद्धांत को ध्यान में रखकर उच्च ठोस हालात में लागू करना और इस तरह कथनी व करनी की रूपरेखा तैयार करना है।

## 2 अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में

निदेशक सिद्धांत के अनुरूप इस योजना के तहत भारत समेत विश्व जनमत को मोलबंद करने के लिए जहाँ कहीं और जय कभी संभव हो समान विचारों वाली दूसरी ताकतों के साथ मिलकर नीचे बताए विश्व-यापी पग उठाना वांछित है।

(i) जंगल उगाकर तथा वायु, जल, भूमि आदि के प्रदूषण की रोकथाम करके पृथ्वी के पर्यावरण की रक्षा की जाए।

(ii) विश्व शांति बनाए रखी जाए और सामूहिक सुरक्षा की एक ऐसी व्यवस्था कायम हो जिसके तहत सभी दश शांतिपूर्ण वातावरण में रह सकें।

(iii) विश्व लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना की जाए (विवरण के लिए देखें ऊपर पैरा ख)।

(iv) सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों को मिले वीटो अधिकार खत्म हो और इस तरह संयुक्त राष्ट्र और दूसरी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में छोटे-बड़े सभी राष्ट्र राज्यों को बराबरी का दर्जा मिले।

(v) सभी प्रकार के प्रभुत्व और खासकर दो महाशक्तियों के प्रभुत्व का विरोध तथा प्रभुत्ववाद विरोधी सभी आंदोलनों का समर्थन किया जाए।

(vi) संयुक्त राष्ट्र सभ की गिरानी में सभी प्रकार के घातक हथियारों खासकर एटमी और रासायनिक हथियारों के पूर्ण निरस्त्रीकरण की मुहिम चलाई जाए तथा सभी प्रकार की सैनिक संधियों खासकर नाटो व वार्सा संधियों को रद्द करने और दूसरे देशों से सभी सैनिक अड्डे खत्म करने और वहाँ से विदेशी सनाए वापस बुलाने के साथ साथ दुनिया में जहाँ कहीं मुमकिन हो शांति क्षेत्र और अणु मुक्त क्षेत्र स्थापित करने की मांग उठाई जाए।

(vii) अतरिक्ष में सभी प्रकार की सैनिक गतिविधियों का निषेध हो और सयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में एक विश्व अतरिक्ष सस्था कायम हो।

(viii) सभी राज्य युद्ध प्रचार पर पाबंदी लगाए तथा सयुक्त राष्ट्र की निगरानी में एक साथ अपने अपने सैन्य बजटों और सशस्त्र सेनाओं को भंग करें।

(ix) विभिन्न राष्ट्र-राज्यों के बीच मौजूद सभी विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा हो तथा राज्यों की प्रभुसत्ता व क्षेत्रीय अखंडता, अनाश्रमण, राज्यां क अदरूनी मामलों में हस्तक्षेप, समानता व पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर उनके बीच दोस्ताना संबंध स्थापित हो।

(x) विवादास्पद इलाकों के लिए सयुक्त राष्ट्र की स्थायी शांति सेना और खतरनाक सामुद्रिक क्षेत्रों के लिए सयुक्त राष्ट्र की नौसेना स्थापित हो।

(xi) विश्व न्यायालय के फंसले (जिनकी इस समय महज परामर्शों हैसियत है) सयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के लिए बाध्यकारी हो।

(xii) दुनिया भर में मानवाधिकारों का परचम बलव हो।

(xiii) हरेक देश के लिए समान दर्जों के आधार पर दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग परिषद के सदस्य राज्यों का महासभ बने।

(xiv) नायसगत आधार पर जितना जल्द मुमकिन हो चीन भारत सीमा विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान हो।

(xv) कश्मीर समेत सभी भारत पाक विवाद शांतिपूर्ण तरीके से हल हो तथा सयुक्त रक्षा और समान दर्जों के आधार पर दोनों देशों का एक महासभ बने, सीमा पर जम्भू कश्मीर पंजाब राजस्थान और गुजरात में सभी रास्ते खोले जाए, इसके बाद पारस्परिक सहमति के दूसरे मुद्दे निबटाए जा सकते हैं। अगर फिलहाल पाकिस्तान को महासभ का सुझाव मंजूर न हो तो तुरंत अनाश्रमण संधि और एटमी हथियारों का भंडार न करने की संधि की जाए।

### 3 भारतीय राज्यतंत्र के क्षेत्र में

निदेशक सिद्धांत के अनुरूप इस योजना के तहत राजनतिक प्रक्रिया में समूची भारतीय जनता को शामिल करने के लिए जहां कहीं और जब कभी संभव हो समान विचारों वाली दूसरी ताकतों के साथ मिलकर नीचे बताए सर्वधानिक, कानूनी और राजनतिक पग उठाना वांछित है।

(क) मूल लक्ष्य निदेशक सिद्धांत, कायशैली और अंतरराष्ट्रीय राज्य की स्थापना (जसा कि ऊपर दिए पैरों में बताया गया है) के मुद्दे भारतीय संविधान में दज हो ताकि उसका उद्देश्य और दिशा निर्धारित हो सके।

(ख) संविधान में दज सभी मूल अभिधारणाओं की परिभाषा की जाए।

(ग) सरकार की ऐसी व्यवस्था कायम हो जिसमें केंद्रीय और राज्य विधायिकाओं के जरिए केंद्र और राज्य की कायपालिकाओं पर जनता का नियंत्रण





के ससद और केंद्र सरकार से है ।

(घ) केंद्र राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच आर्थिक एवं विकास संबंधी कार्यों को छोड़कर सभी प्रमुख समस्याओं के निवटारे के लिए अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतरसरकारी परिपद स्थापित हो जिसमें प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल हों, परिपद की सहायता के लिए मंत्रियों की एक छोटी स्थायी समिति और विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति हो, अंतरराज्यीय समस्याएँ अंतरसरकारी परिपद में उठाए जाने से पहले उन पर क्षेत्रीय परिपदों में विचार विमर्श हो ।

(ङ) अनुच्छेद 263 के तहत बनी मौजूदा राष्ट्रीय विकास परिपद का आर्थिक एवं विकास परिपद के रूप में पुनर्गठन हो, सभी आर्थिक और विकास समस्याओं के निपटारे के लिए उसकी एक छोटी स्थायी समिति हो तथा जिला स्तर के नियोजन को उच्च प्राथमिकता दी जाए ।

(च) राज्यों को अधिक वित्तीय और औद्योगिक अधिकार दिए जाए ।

(छ) व्यापार, वाणिज्य और आपसी लेन देन का काम से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए अनुच्छेद 307 के तहत एक विशेषज्ञ प्राधिकरण गठित हो ।

(ज) अनुच्छेद 352, 356 और 357 के अलावा अनुच्छेद 359 और 360 के उपबंधों के तहत केंद्र को मिले आपातकालीन अधिकारों को खत्म किया जाए । पंजाब और जय ऐसे राज्यों को, जहाँ अल्पसंख्यक और जनजातीय समुदायों का प्रबल बहुमत है, विशेष अधिकार मिलें (जैसे जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत हासिल हैं) ।

(झ) भाषा, तारतम्यता और गांव एक इकाई के तितरफा असूली के आधार पर विभिन्न राज्यों के बीच क्षेत्रीय और सीमा विवाद हल किए जाए ।

(ञ) जिला परिषदों, निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों आदि स्थानीय निकायों को अपने अपने क्षेत्रों का कामकाज चलाने के लिए पूरे अधिकार सौंपकर, इन क्षेत्रों में प्रशासकीय सेवाओं को उक्त सावजनिक संस्थाओं के प्रति जवाबदेह बनाकर तथा इन संस्थाओं के चुनाव और कामकाज को एक अखिल भारतीय कानून की तर्ज पर सुनिश्चित बनाकर प्रशासन पर लोगों का नियंत्रण स्थापित किया जाए ।

(ट) केंद्र या राज्य विधायिका के दोनों सदनों के समान अधिकार हो तथा अध्यक्ष अथवा सभापति के निर्णयों को वाद योग्य बनाया जाए ।

(ठ) सरकार के अध्यादेश जारी करने के अधिकार संबंधी संवैधानिक प्रावधानों को खत्म किया जाए ।

(ड) राजकीय समारोहों को धार्मिक आयोजनों से अलग करके, धार्मिक संस्थानों को राज्य से मिलने वाली सारी सहायता बंद करके और राज्य के मामलों में धार्मिक संस्थानों के हस्तक्षेप पर रोक लगाकर राजनीति को धर्म से अलग किया जाए तथा राज्य के धर्मनिरपेक्ष आधार को मजबूत बनाया जाए ।

(ड) रक्षियों और दूरदर्शन का काम एक स्वायत्त संस्था को सौंपा जाए जो

सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो।

(ग) केंद्र और राज्या के बीच तथा विभिन्न राज्या के बीच पत्र व्यवहार के लिए अंग्रेजी और हिंदी का जुड़वा सरकारी भाषाया के रूप में माध्यम देकर सरकारी भाषा की समता हट कर जाए तथा राज्या में उनकी अपनी अपनी भाषा को शिक्षा और प्रशासन का माध्यम बनाया जाए।

(त) लागू द्वारा 10 साल के लिए जब चुनने की प्रणाली लागू करके तथा नौधा सन्ना और चन्द्र पाप प्रदान करके न्यायशास्त्रिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित बन, न्यायिक व्यवस्था का अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उच्चतरीय विधि आयोग द्वारा उनका सन्तुष्टे कामकाज की समीक्षा करवाई जाए।

(ध) रहन की आजादी, पत्र करण की आजादी धार्मिक आस्था और पराधना, दोनों नियम नभा करने साटा बनाने हडनास करने चलने फिरन और व्यवसाय रहन की आजादी सुनिश्चित हो नस्ल धर्म राष्ट्रीयता लिंग, जाति आदि का भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों को समान अधिकार की गारंटी हो, प्रत्येक नागरिक को किसी भी अधिकारी या निर्वाचित प्रतिनिधि (राष्ट्रपति पंचवा प्रधान-मंत्री सहित) के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करने का अधिकार हो।

(द) मृत्युदंड छत्म किया जाए सभी प्रकार के नजरबंदी कानून (भीता, एस्मा आनकवाद विरोधी कानून आदि) को मसूय किया जाए पञ्चान क्षेत्र कानून वापस लिया जाए भारतीय दंड संहिता के तहत लोगों की स्वतंत्रताओं पर रोक लगाने वाली सभी धाराया (जैसे धारा 144 107 151 आदि) को हटाया जाए गुप्तचर एजेंसिया द्वारा डाक रोकन और टेलीफोन की बातचीत सुनने का काम बंद हो, सभी प्रकार के राजनैतिक नजरबंदी को रिहा किया जाए तथा राजनैतिक बट्टेडूनियन कार्यकर्ताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमों और वारंट गिरपतारी वापस लिए जाए।

(ध) कैदियों को बेहतर नागरिक बनाने के उद्देश्य से जेल व्यवस्था में सुधार किए जाए।

(न) चुनाव की एक निष्पक्ष प्रणाली सुनिश्चित बने जिसके तहत हर प्रकार के चुनाव में (पचासत से लेकर समद तक) खड़े सभी उम्मीदवारों का खच चुनाव आयोग उठाए, केंद्रीय और राज्य विधायिकाओं के चुनाव दलीय सूचियों के अनुसार सानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर तथा बाकी सभी चुनाव क्षेत्रवार आयोजित हो, क्षेत्रवार चुनावों की स्थिति में हर चुनावक्षेत्र के मतदाताओं की बहुसंख्या को किसी भी समय अपना निर्वाचित प्रतिनिधि वापस बुलाने का अधिकार हो। उन्ही निदलीय उम्मीदवारों को विधायिकाओं के चुनाव लड़ने की अनमति हो जो अपनी-अपनी जिला परिषदों से घमनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और होन व प्रमाणपत्र पत्र करें 18 साल या उससे अधिक उम्र वाले हर पहचान पत्र मिले चुनाव लड़ने वाले सभी दलों की टीवी और

पहुँच हो, केंद्र या राज्य सरकारें चुनाव से एक महीना पहले इस्तीफा दे दें और इस अवधि में ससदीय चुनावों की सूरत में राष्ट्रपति शासन और विधानसभा चुनावों की सूरत में राज्यपाल शासन लागू हो, चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था हो जिसके सदस्य प्रधानमंत्री, ससद में विपक्षी पार्टियों के नेताओं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह मशविरे से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो, राज्यों के चुनाव आयुक्त पूर्णकालिक हो और उनका दर्जा हाईकोर्ट जज के बराबर हो, व चुनाव को प्रत्येक राज्य के तौर पर निभाने वाले कार्यकारी अफसर न हों, छात्रों की सालाना परीक्षाओं, कटाई के मौसम, जलवायु संबंधी परिस्थितियों आदि के महेंजर चुनाव की एक स्थायी तिथि मूकरर की जाए जबकि उपचुनाव हर साल आयोजित किए जाए तथा यथासमय लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ नियमित चुनाव कराए जाए।

(१) नीचे दी शर्तें पूरी करने के आधार पर चुनाव लड़ने वाली सभी पार्टियों का चुनाव आयोग में पंजीकरण हो

(i) ये पार्टियाँ धर्म को राजनीति से अलग करने का सिद्धांत मानें।

(ii) अपने पक्ष से किसी भी धर्म, जाति, नस्ल, भाषा आदि के खिलाफ प्रचार करने या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने की मनाही करें।

(iii) चुनाव आयोग की देखरेख में कम से-कम दो साल में एक बार हर स्तर पर पदाधिकारियों का चुनाव करवाए।

(iv) चुनाव आयोग द्वारा सुधारी गई लेखाकारों की सूची में से किसी लेखाकार से अपने हिसाब किताब की जांच करवाए।

(v) भारत की विविधता में एकता को मानें।

(फ) प्रशासकीय सेवाओं का वैज्ञानिक पुनगठन हो और फालतू नौकरियों का खतम किया जाए (जा प्रशासकीय काम में लोगों को पूरी तरह जोड़ने से जरूरी बन जाता है), इस तरह करोड़ा रुपए की बचत करके इस रकम को पूँजी के अभाव वाली भारतीय अर्थव्यवस्था में लगाया जाए।

(ब) जानकारी पाने की आजादी का कानून बने जिसके तहत कोई व्यक्ति किसी भी सरकारी एजेंसी से वांछित दस्तावेजों का उचित हवाला देकर उनके बारे में जानकारी पाने का अनुरोध कर सकता हो जिस पर उस सरकारी एजेंसी को 10 दिन के अंदर जवाब देना होगा। अटवारी पर उद्योग समूहों के नियंत्रण के बजाय ट्रस्टों की मिलकियत अपना प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाए तथा प्रेस कौंसिल की ओर से प्रेस के लिए आचार संहिता तैयार की जाए।

(भ) सरकारी गोपनीयता कानून की धारा 5 को हटाया जाए जैसा कि भारतीय प्रेस कौंसिल और भारतीय विधि संस्थान ने सिफारिश की है तथा उसके दूसरे दमनकारी प्रावधानों को खतम किया जाए, अदालत की अचमानना वाले कानून को रद्द किया जाए तथा विधायिका के सदस्यों को मिल विश्वासविचार खतम हो।

(म) विभिन्न राष्ट्रीयताओं के स्वच्छिन्न पक्ष में तौर पर भारत की एकता

का पक्षपोषण किया जाए।

#### 4 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में

निदेशक सिद्धांत के अनुरूप इस योजना के तहत आर्थिक प्रक्रिया (यानी उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग) में समूची भारतीय जनता को शामिल करने के लिए जहां वही और जब कभी संभव हो समान विचारों वाली दूसरी ताकतों के साथ मिलकर नीचे दिए आर्थिक पग उठाना वांछित है।

(क) ऐसा लोकतांत्रिक आर्थिक मॉडल बनाया जाए जिसका लक्ष्य सतुलित आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक 'याय और मानवीय एवं भौतिक ससाधनों का पूण उपयोग करना हो, जिसका प्रबंध भारतीय जनता के हाथ में हो, जिसमें परंपरागत मालिकों के साथ-साथ सवध खत्म कर दिए जाए तथा जिसके तहत प्रतियोगी बाजार व्यवस्था और सगठित राज्य नियोजन दोनों का उपयोग हो। इस तरह यह मॉडल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वाले मौजूदा सभी मॉडलों (यानी राज्य नियंत्रित भावसवादी मॉडल, बाजार पर आधारित पश्चिमी उदारवादी मॉडल, मिश्रित पश्चिमी के-सवादी मॉडल और मिश्रित पिछड़े देशों के मॉडल) से भिन्न होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का यह लोकतांत्रिक मॉडल सगठित और असगठित दो क्षेत्रों से गठित होगा।

(1) सगठित लोकतांत्रिक क्षेत्र (भारतीय अर्थव्यवस्था का करीब 15 फीसदी हिस्सा) सगठित सरकारी क्षेत्र और सगठित निजी क्षेत्र के विलय से बनेगा। इस क्षेत्र में बड़े पूंजीपति घरानों की मिलकियत वाले ब्लाक शेयरों (जो विभिन्न उद्योगों में एक से 10 फीसदी तक हैं) को कानूनन खत्म कर दिया जाएगा पर उन्हें नए कानून के तहत अनुज्ञेय शेयर रखने की अनुमति होगी। 50 फीसदी शेयर भारतीय राज्य के पास रहेंगे जबकि बाकी 50 फीसदी भारतीय लोगों में बांटे जाएंगे जिनमें एक-तिहाई तकनीशियनों व कमचारियों समेत मजदूरों में, एक तिहाई ग्रामीण लोगों और एक-तिहाई शहरी लोगों में वितरित होंगे। इस समूचे क्षेत्र और इसके हरेक उद्यम का नियंत्रण ऐसे प्रबंधकों बोर्डों के पास रहेगा जिनमें 30 फीसदी राज्य के प्रतिनिधि (अफसर-कर्मचारी, सांसद अथवा विधायक आदि समेत), 30 फीसदी मजदूरों के चुने गए प्रतिनिधि, 20 फीसदी तकनीशियनों और कमचारियों के चुने गए प्रतिनिधि, 10 फीसदी ग्रामीण शेयरधारकों के चुने हुए प्रतिनिधि और 10 फीसदी शहरी शेयरधारकों के चुने हुए प्रतिनिधि रहेंगे। इस क्षेत्र की सभी समस्याएँ (जैसे पूंजी, टेक्नोलॉजी, बाजार, आयात निर्यात, रीमार उद्योग पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण आदि) राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय प्रबंधक बोर्ड, राज्य स्तर पर राज्य प्रबंधक बोर्ड और उद्यम स्तर पर फ़ैक्ट्री प्रबंधक बोर्ड द्वारा निबटाई जाएगी।

(2) असगठित लोकतांत्रिक क्षेत्र (भारतीय अर्थव्यवस्था का लगभग 85 फीसदी हिस्सा) खुद मालिकाना और खुद रोजगार वाला क्षेत्र है जिसमें ज्यादातर कृषि क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में लगे लोग मुख्यतया दो श्रेणियों से गठित हैं। एक

वे जो शारीरिक श्रम बेचते हैं अथवा ग्रामीण खेतिहर मजदूर और गैर औद्योगिक शहरी मजदूर। इनमें निर्माण मजदूर, धोखा उठाने वाले मजूर, घरेलू नौकर, सपाईं मजदूर, ढावा मजदूर, ठेला खींचने वाले, रिक्शाचालक, लकड़ी चीरने वाले, इट भट्टा मजदूर आदि आते हैं। दूसरे वे जो अपनी खेती व्यापार छोटे उद्यमों आदि में काम करते हैं अथवा प्रशासन, संचार तंत्र आदि में नौकरी करते हैं दोनों श्रेणियों की समस्याएँ एक-दूसरे से अलग हैं। यहाँ तक कि एक ही श्रेणी की समस्याओं में भी अंतर है। पहली श्रेणी को अमूमन गरीबी या कम-त्रय शक्ति और बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी की समस्याओं का सामना है। दूसरी श्रेणी की जरूरतें मुख्यतया सस्ते ऋण और बाजार की सुविधाएँ प्राप्त करने और कभी-कभी अनुकूल तकनीक और कच्चा माल पाने की हैं। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दोनों श्रेणियों के विभिन्न आर्थिक समूहों को राष्ट्रीय संगठनों में पिरोया जाएगा। मसलन देहाती खेतिहर मजदूरों, शहरी गैर औद्योगिक मजदूरों, मध्यम और धनी जमींदारों, छोटे व्यापारियों, बड़े व्यापारियों, छोटे उद्योग पतियों सरकारी कर्मचारियों आदि के अलग-अलग संगठन बनाए जाएंगे। हर राष्ट्रीय संगठन में उसके पूरे समूह को सदस्यता दी जाएगी और वह राज्य, जिला, शहर, नगर, गाँव आदि सभी स्तरों पर निर्वाचित ऐसी समितियों के जरिए काम करेगा जिनमें एक तिहाई सरकारी प्रतिनिधि होंगे।

(iii) असंगठित लोकतांत्रिक क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए कृषि का उद्योग के समान विकास किया जाएगा। दोनों में एक-जैसे कानून लागू किए जाएंगे। कृषि का उद्योग में विकास करने के लिए एक अखिल भारतीय कृषि उद्योग परिषद बनाई जाएगी। इसमें सरकार, कृषि औद्योगिक विशेषज्ञ, संगठित लोकतांत्रिक क्षेत्र, मध्यम और बड़े जमींदारों के राष्ट्रीय संगठन तथा खेतिहर मजदूरों के राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। यह परिषद कृषि की दूसरी समस्याओं को भी निबटाएगी जैसे कि आवश्यकता पर आधारित कृषि जीविका उन्नत, वर्तमान हदबंदी कानूनों पर कारगर ढंग से अमल, फालतू और खाली पड़ी जमीन को भूमिहीनों में बाँटने और उन्हें खेती के लिए लंबी अवधि के कर्ज मुहैया कराने, किसानों पर पुराने कर्ज खत्म करने उन्हें आसान कर्ज, बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ मुहैया कराने, कृषि उपज के लाभकारी मूल्य, भूमि जोतों को इकट्ठा करने, भूमि बँटाव, बाढ़ नियंत्रण, भूमि सुरक्षण, पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार मौजूदा सबकों स्कूलों और चिकित्सालयों की मरम्मत परंपरागत और आधुनिक सिंचाई कार्यों के जरिए सभी उपलब्ध जल ससाधनों का पूरा उपयोग, दोहरी फसल, सूखी खेती, डेयरी फार्मिंग, मछली पालने, मुर्गी पालने, कोल्ड स्टोर, बागवानी, पारिवारिक इकाई के आधार पर फसल बोमा आदि आदि।

(घ) (1) योजना आयोग को सवधानिक दर्जा दिया जाएगा। उसे सभी राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों की शिखर सस्था माना जाएगा। वह सामाजिक-व्यापक सहित सतुलित आर्थिक विकास के लिए समस्त मानवीय, तकनीकी और कच्चे माल के साधनों

के उपयोग की योजना बनाएगा तथा राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों की विभिन्न आर्थिक नीतियों में सामंजस्य स्थापित करेगा।

(ii) योजना आयोग में 20 फीसदी सरकारी प्रतिनिधि, 20 फीसदी अगुआ अर्थशास्त्री, 20 फीसदी ससदीय प्रतिनिधि, 20 फीसदी संगठित लोकतांत्रिक क्षेत्र, 10 फीसदी कृषि उद्योग परिषद और 10 फीसदी असंगठित लोकतांत्रिक क्षेत्र के लोग होंगे।

(ग) विदेशी पूँजी को सुविधाएँ दी जाएगी बशर्ते कि यह अपनी निर्यात बमाई का महज 50 फीसदी और भारत में पैदा किए गए अतिरिक्त धन को बाहर न ले जाना स्वीकार कर ले।

(घ) विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी में मूल और प्रायोगिक दोनों विस्म के शोध पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का कम से कम दो फीसदी निवेश किया जाए। टेक्नोलॉजी को आधुनिक बनाया जाए और ठोस हातात के मुताबिक उसका प्रयोग हो।

(ङ) विजली उत्पादन पर अधिक जोर दिया जाए।

(च) मानव वस्तुओं, खासकर असंगठित लोकतांत्रिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के उत्पादन और विपणन में पूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित हो।

(छ) काम, आवश्यकता पर आधारित निर्वाह वेतन, आवास, वृद्धाप और बीमारी अथवा पूण या आंशिक विकलांगता की स्थिति में जीविषा, माध्यमिक स्तर तक मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा परामर्श, 35 घंटे के कार्य सप्ताह आदि को सर्वैधानिक अधिकार बनाया जाए।

(ज) मौजूदा कर प्रणाली का पुनर्गठन हो और उसमें करों का बोझ उठा सकने की क्षमता का अमूल लागू किया जाए।

(झ) आम लोगों के हितों में एक कारगर दाम नीति लागू हो और गरीबी रेखा से नीचे जिनकी बमर करने वालों को सस्ते दाम पर जरूरी वस्तुएँ मुरैया हो।

(ञ) रक्षा खच पर तत्काल 50 फीसदी कटौती हो और फिर धीरे धीरे इसका पूरी तरह उमूलन कर दिया जाए।

### भारतीय सस्कृति के क्षेत्र में

निदेशक सिद्धात के अनुरूप इस योजना के तहत सास्कृतिक प्रक्रिया में समूची भारतीय जनता को शामिल करने के लिए जहाँ कहीं और जब कभी सम्भव हो समान विचारा वाली दूसरी ताकतों के साथ मिलकर नीचे बताया सास्कृतिक पग उठाना बाछिन है।

### शिक्षा

(1) शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय, मानवतावादी, लोकतांत्रिक, धमनिरपेक्ष, वैज्ञानिक, व्यावसायिक आदि बनाकर उसमें मूल परिवर्तन लाए जाएँ और इस प्रकार

उसे भारत और दुनिया के तेजरपतार औद्योगीकरण के अनुरूप बनाना जाए।

(ii) विश्वविद्यालय स्तर तक योग्य छात्रों को और माध्यमिक स्तर तक सभी को मुफ्त शिक्षा दी जाए और उसे मौजूदा व्यवसायों से जोड़ा जाए।

(iii) प्रौढ़ शिक्षा का कारगर बंदोबस्त बरके निरक्षरता का खात्मा हो।

(iv) उच्च वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा के लिए सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ।

(v) विभिन्न उद्योग घटो में मजदूरों के लिए ट्रेनिंग कोर्सों का बंदोबस्त हो।

(vi) वैज्ञानिक टेक्नीकल संस्थानों में हुई खोजों और लोकतांत्रिक क्षेत्रों की जरूरतों के बीच नियोजित सतुलन कायम हो।

(vii) विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता और अकादमिक स्वतंत्रता मिले।

(viii) शिक्षकों को उचित वेतन मिले।

### भाषा

(i) भारत की सभी भाषाओं खासकर सर्वाधिक धन द्वारा माय भाषाओं को बराबर दर्जा मिले तथा लोगों की किसी भी श्रेणी पर उनकी मर्जी के खिलाफ कोई भाषा न थोपी जाए।

(ii) किसी भी निर्वाचित संस्थान (संसद हो या पंचायत) में हर सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार हो तथा केंद्र सरकार के प्रकाशना को सविधान द्वारा माय सभी भाषाओं में छापा जाए।

(iii) अखिल भारतीय सेवाओं की सभी प्रतियोगी परीक्षाएँ सविधान द्वारा माय सारी भाषाओं में आयोजित की जाएँ।

(iv) एक ही क्षेत्र में रहने वाले एक लाख लोगों द्वारा बोली जा रही हरेक भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया जाए।

(v) लागू द्वारा अपन मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को स्वीकार किया जाए।

(vi) उन राज्यों और क्षेत्रों में उर्दू और उसकी लिपि की रक्षा की जाए जहाँ वह परंपरागत रूप से इस्तेमाल होती आ रही है।

### साहित्य और कला

(i) भारत में जनजातीय समूहों समेत हरेक राष्ट्रियता के साहित्य, कला और संस्कृति (जिसमें लोक संस्कृति भी शामिल है) के विकास में सहायता दी जाए, उनके मानवीय और लोकतांत्रिक पक्षों को उजागर किया जाए और उन्हें अंतरराष्ट्रीय भाईचारे की दिशा दी जाए, जातिवादी व साम्प्रदायिक पूर्वाग्रहों के अन्तर्गत चापलूसी,

अधविश्वास, नस्ली व राष्ट्रीय घृणा और युद्ध प्रचार के विचारों को जड़ से उखाड़ दिया जाए।

(ii) साहित्य, कला और सस्कृति के प्रोत्साहन के लिए और इस क्षेत्र के कर्मियों की बेहतरी के लिए सबद्ध व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित केंद्रीय, राज्य और जिला कमेटियाँ कायम की जाएँ।

(iii) अश्लील सस्कृति को छोड़ सास्कृतिक गतिविधियों पर लगी सभी पाबंदियों को हटाया जाए।

### स्वास्थ्य

(i) लोग के स्वास्थ्य के लिए बेहतर बंदोबस्त हो और चिकित्सा व प्रसूति सेवाओं का जाल बिछाकर चिकित्सा सुविधाओं को आम आदमी की पहुँच तक लाया जाए, हैजा, मलेरिया आदि महामारियों के उन्मूलन की ओर विशेष ध्यान दिया जाए तथा पीने का साफ पानी मुहैया करके देहाती इलाकों में सफाई और सफ्रमण निरोधी टीके लगाकर और सस्ती दवाइयों का उत्पादन करके स्वास्थ्य पर पर्याप्त बल दिया जाए।

(ii) खेल और शारीरिक व्यायाम के दूसरे रूपों के लिए सहूलियतें मुहैया कराई जाएँ ताकि आम लोग उनमें भाग ले सकें।

### स्वच्छ जीवन के लिए

(i) धम को राजनीति से अलग किया जाए।

(ii) भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाए जाएँ, इनमें भ्रष्टाचार के मामलों की जाच के लिए केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी बोर्ड कायम करना भी शामिल है जिन्हें ससदीय और विधानसभा चुनावों के साथ ही 10 वर्ष की अवधि के लिए लोगों द्वारा चुना जाए।

### धार्मिक और सास्कृतिक अल्पसंख्यक

सभी अल्पसंख्यकों के धार्मिक व सास्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए तथा राजनैतिक, आर्थिक व सास्कृतिक क्षेत्रों में उनके खिलाफ सभी भेदभावपूर्ण कारवाइयों के खاتم के लिए जरूरी पग उठाए जाएँ।

### अनुसूचित जातियाँ

(i) उन सभी सामाजिक असमर्थताओं को हटाया जाए जिनका शिकार अनुसूचित जातियाँ हैं।

(ii) जातीय उत्पीड़न को कानून के क्षेत्र में लाकर दंडनीय करार किया जाए।



(iii) अनुसूचित जातियों के राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए जरूरी पग उठाए जाए।

(iv) दलितों पर जुल्म ढाए जाने के मामले निपटान के लिए विशेष अदालतें स्थापित हो।

### अनुसूचित जनजातियां

(i) जनजातीय इलाकों में सामाजिक विकास के स्तर के मद्देनजर उनकी अलग अलग प्रशासनिक इकाइया बनाई जाए अथवा ऐसे किसी भी क्षेत्र को भारत सभ के राज्य (नगालैंड, मिज़ोरम की तरह) का दर्जा प्रदान किया जाए।

(ii) जनजातीय इलाकों में उद्योगों और संचार व्यवस्था का विकास हो।

(iii) बदली खेती के स्थान पर टिकाऊ खेती शुरू करने के लिए जनजातियों को आर्थिक और तकनीकी सहायता मिले।

(iv) निहित स्वार्थों की ओर से जनजातियां की भूमि पर बच्चे और जंगल के ठेकेदारों की ओर से उनके शोषण पर पाबंदी लगे।

(v) जनजातियों को स्थानीय वन उपज का इस्तेमाल करने के अधिकार हो।

(vi) सस्ती दरों पर जरूरी चीजें (जैसे कपड़ा, चीनी, नमक, मिट्टी का तेल आदि) मुहैया कराने और उनकी चीजों की उचित कीमत दिलाने के लिए जनजातियों की सहकारी समितियां कायम हों।

(vii) भाषा कला और संस्कृति के विकास में उनकी मदद की जाए।

(viii) उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य की मुफ्त सेवाएं प्रदान की जाएं।

### अनुसूचित जातियां और जनजातियों को मिले मौजूदा विशेष अधिकार

इन समुदायों को उन समस्याओं को मौजूदा विशेष अधिकार जारी रखे जाए जिनकी आमदनी औसत प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय से कम है तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को कानूनी मजूरी प्रदान की जाए।

### महिलाएं

(i) एसी सामाजिक असमर्थताएं हटाई जाएं जिनका शिकार महिलाएं हैं।

(ii) उजरतों संपत्ति के उत्तराधिकार विवाह, तलाक, शिक्षा समस्याओं में प्रवेश व्यवसायों और नौकरियों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार हो।

(iii) बलात्कार दहज उत्पीड़न, पत्नी की मारपीट तथा महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की यौन हिंसा के मामलों के लिए हर ब्लॉक में महिलाओं की निर्वाचित सतर्कता समितियां कायम हों।

(iv) वैश्यावृत्ति और देवदासी प्रथा का उन्मूलन हो तथा इससे निजात पाई महिलाओं को रोजगार मिले ।

(v) सभी प्रकार की दहेज प्रथा पर रोक लगे ।

(vi) सेवाओं की कुछ श्रेणियों जैसे एअर होस्टेस आदि के काम में महिलाओं के प्रवेश पर लगी पावदिया हटें ।

(vii) शिशु गृह और बाल सदन जैसी विशेष सेवाएँ प्रदान करके देहाती और शहरी दोनों इलाकों में माँ और बच्चे की ओर विशेष ध्यान दिया जाए ।

(viii) ऐसी महिलाओं का आवश्यकता पर आधारित भत्ता प्रदान किया जाए जिनकी आय का कोई स्रोत न हो ।

(ix) सती और शिशु हत्या के कानून कारगर ढंग से लागू हो ।

## 6 विभिन्न वर्गों की जीवन स्थितियों के क्षेत्र में

निदेशक सिद्धांत के अनुरूप इस योजना के तहत लोगों की जीवन स्थितियों की प्रक्रिया में समूची भारतीय जनता को शामिल करने के लिए जहाँ कहीं और जब कभी संभव हो समान विचारों वाली दूसरी ताकतों के साथ मिलकर नीचे बताए पग उठाना वांछित है ।

### औद्योगिक मजदूर

(i) त्रिपक्षीय सम्मेलनों द्वारा निर्धारित आवश्यकता पर आधारित निर्वाह वेतन और महंगाई भत्ते की परिवर्तनशील स्केल, बोनस और ग्रेज्यूटी, सवेतन छुट्टियाँ तथा वेतन का हफ्तावार भुगतान हो ।

(ii) किसी नस्ल घम जाति या लिंग के भेदभाव के बिना समान काम के लिए समान वेतन हो ।

(iii) पूर्ण वतन सहित एक महीने की छुट्टी या अगर छुट्टी मजूर नहीं की जाती तो उसके बराबर रकम पाने का अधिकार हो ।

(iv) 35 घंटे का काय सप्ताह मुकर्रर हो ।

(v) सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़े जैसे कि बेरोजगारी, खराब सेहत, बुढ़ापे की सुरत में सहायता मिले और सस्ती दर पर आवास सुविधाएँ मुहैया हो ।

(vi) मजदूरों के गुप्त मतदान के आधार पर ट्रेड यूनियनों को अनिवार्य मान्यता मिले, सामूहिक सौदेबाजी और हड़ताल व हमदर्दी में होने वाली हड़ताल का अधिकार हो, मजदूरों को ट्रेड यूनियनों के जरिए भर्ती किया जाए तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उनकी प्रवृद्ध में भागीदारी हो ।

(vii) कानून में मजदूर विरोधी सभी प्रावधान खत्म हो तथा वेतनजाम, अनिवार्य जमा योजना, वेतन कटौती, छटनी और कारखाना बंदी, यूनियन के सदस्यों

की भेदभावपूर्ण वर्खास्तगी, तालाबदी, मजदूरी द्वारा यूनिजन से लुक छिपकर समझौता करने की प्रवृत्ति पर रोक हो।

(viii) ओवर टाइम और रात के काम पर पाबंदी हो, सिवा उन हालात के जहाँ तकनीकी कारणों से ऐसा करना बेहद जरूरी है।

(ix) सभी अनियमित, अस्थायी और बदली मजदूर स्थायी हो।

(x) सोलह वष से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाना वर्जित हो और किशोरो (16 से 20 वष की आयु) के लिए काम का दिन चार घंटे तक सीमित हो।

(xi) महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकार उद्योगों में महिला मजदूरों को नियुक्ति वर्जित हो, महिलाओं को रात की पाली से मुक्त रखा जाए, तथा उच्च वेतन व नुकसान के बिना प्रसव के आठ हफ्ते पहले और आठ हफ्ते बाद काम से छुट्टी हो।

(xii) ठेका मजदूरी पर पाबंदी लगाई जाए।

(xiii) ऐसी सभी फक्ट्रियों में जहाँ महिला मजदूर हैं शिशुओं के लिए नसरिया और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए कमरे उपलब्ध हो, ऐसी माताओं को हर तीन घंटे के अंतराल में कम से कम आध घंटे का अल्पअवकाश मिले तथा उनके काम के छह घंटे मुकरर हो।

(xiv) सभी श्रेणियों और सभी जगहों के मजदूरों को हर प्रकार की असमयता (खराब सेहत, बच्चावस्था, दुर्घटना आदि) और बेरोजगारी व विरुद्ध पूण सामाजिक बीमों की गारंटी हो।

(xv) भविष्यनिधि, इंसुअरि के अशदानों में जमा, सुरक्षा नियमों और दूसरे श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले मालिकों को सजा का प्रावधान हो।

(xvi) मायता रहित मजदूर वस्तियों में बिजली, पानी और दूसरी शहरी सुविधाएँ देकर गरीब वस्तियों का तत्काल सुधार हो और यथाचित समय के भीतर हर मजदूर परिवार को ठीकठाक मकान उपलब्ध हो।

(xvii) राज्य और जिला स्तरों पर श्रम निरीक्षणालय कायम हो और उन्हें अपनी सीमाओं में सभी श्रम कानून लागू करने का अधिकार हो।

(xviii) सभी प्रकार के औद्योगिक विवादों का एक निश्चित अवधि में निपटान के लिए उद्योगों की सभी शाखाओं में औद्योगिक न्यायालय स्थापित हो जिनमें मजदूरों और मालिकों व निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या बराबर हो।

(xix) श्रम उत्पादकता बढ़ाने के लिए मजदूरों की पहल और खोजी प्रवृत्ति प्रयोग में लाई जाए जबकि बकलोड की स्थिति में उनके हितों की रक्षा हो।

### गर-औद्योगिक शहरी मजदूर

(1) इन मजदूरों को कोई परिभाषा देना जिनमें निर्माण मजदूर, लकड़ी चीरने वाले, इट भट्टा मजदूर, बाक्षा उठाने वाले, ठेला खींचने वाले, रिक्शाचालक,

ढावा मजदूर, घरलू नौकर, सफाई मजदूर और दूसरे कई प्रकार के मजदूर हो सकते हैं ।

(ii) इन मजदूरों को ट्रेड यूनियन अधिकार, आवश्यकता पर आधारित निर्वाह वेतन, छुट्टियाँ और दूसरी सुविधाएँ सुनिश्चित हो ।

(iii) सफाई मजदूरों के काम की अमानवीय स्थितियों (मसलन सिर पर मँला ढोने, मँनहोलो और नालियों की सफाई) पर रोक लगे और उन्हें स्वास्थ्य रक्षा के आधुनिक यंत्र मुहैया कराए जाए ।

### कृषि मजदूर

(i) कृषि मजदूरों को ट्रेड यूनियन अधिकार, आवश्यकता पर आधारित निर्वाह वेतन वोनस, मुआवजा, पेंशन और दूसरी सुविधाएँ सुनिश्चित हो ।

(ii) सभी सूदखोरी कज मसूख ही ।

(iii) उन्हें कुटीर उद्योगों, डेयरी फार्म आदि के लिए व्याज मुक्त कज मिलें ।

(iv) सामुदायिक कार्यों के लिए जरूरी जमीन को छोड़कर सारी कृषि योग्य भूमि मजदूरों से उनकी अपनी निर्वाचित कमिटियों की देखरख में बटे तथा उन्हें कृषि काय के लिए नकद सहायता भी मिले ।

(v) काश्तकारी समेत सभी प्रकार के बहुआश्रम का उमूलन हो ।

(vi) कृषि मजदूरों को मकान के लिए मुफ्त जगह और उसे बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध हो ।

(vii) कृषि मजदूरों को सर्वेच्छिक कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटियाँ बनाने में सरकारी सहायता मिले ।

(viii) देहाती उद्योग शुरू करके और खाली दिना में वैकल्पिक रोजगार देकर कृषि मजदूरों के अल्प रोजगार की समस्या हल की जाए ।

### मध्यम किसान

उन्हे सस्ता कज तथा बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, मशीनरी आदि जैसे दूसरे कृषि उपकरण मुहैया कराए जाए ।

### छात्र एवम युवा

(i) माध्यमिक स्तर तक उन्हें मुफ्त शिक्षा खासकर रोजगारपरक शिक्षा और स्नातक हो जाने के बाद उचित रोजगार मिले ।

(ii) माध्यमिक स्कूल स्तर तक माता पिता और शिक्षका की निर्वाचित संयुक्त समितियाँ के जरिए तथा उससे उपर शिक्षको, कमचारियों और

निर्वाचित सयुक्त समितियों के जरिए सभी शिक्षा संस्थानों के प्रबंध को प्रणाली लागू हो।

(iii) विश्वविद्यालयों का बिना सरकारी हस्तक्षेप के पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जाए और शिक्षा संस्थानों में पुलिस हस्तक्षेप बंद हो।

(iv) स्कूल व कॉलेज शिक्षकों को आतंकित करने और छात्रों को दह देने का प्रावधान रखने वाले सभी नियमों को रद्द किया जाए।

(v) सभी शिक्षकों और 18 वर्ष से ऊपर छात्रों को संगठन बनाने और राजनैतिक सभ स्थापित करने का अधिकार मिले।

(vi) होस्टल, लेबोरेट्री, लाईब्रेरी, खेलो, परिवहन, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों की पर्याप्त सुविधाएं सभी छात्रों की पहुंच के भीतर हो तथा स्कूल कॉलेजों में गरीब व जहरतमद छात्रों को पर्याप्त वजीफे मिलें।

### प्रशासकीय सेवाएं (पुलिस सहित)

(i) उनके लिए आवश्यकता पर आधारित निर्वाह वेतन का सिद्धांत लागू हो तथा सामाजिक बीमा, भविष्यनिधि, पेंशन या ग्रेज्युटी, आवास, चिकित्सा भत्ता और दूसरी सुविधाओं का उचित प्रबंध हो।

(ii) नियुक्तियों, पदोन्नतियों और सेवा शर्तों के लिए (कर्मचारी सभों के साथ समझौते करके) उचित नियम बनें।

(iii) उन्हें राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने और सभी निर्वाचित संस्थाओं के चुनाव में छड़ा होने के अधिकार समेत सभी लोकतांत्रिक अधिकार मिलें।

### सशस्त्र सेनाएं (अर्द्ध सैनिक बला सहित)

7

(i) वेतन, आवास, बच्चा की पढाई आदि के मामले में सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों के रहने सहने का उचित स्तर सुनिश्चित हो तथा मारें गए या बिकलांग हो गए सैनिकों के परिवारों का ध्यान रखा जाए।

(ii) सशस्त्र सेनाओं को ट्रेड यूनियन अधिकार मिलें।

8

### बेघर लोग

बेघरों को आसकर गद्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए सहकारी आवास समितियां बनें।

119

### 7 राष्ट्रीय विवरण का सवाल

119 (ii) (1) यह सवाल 1947 से ही भारत की राजनैतिक कायस्थों में पहले सवाल (119) का आ रहा है। लेकिन इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया।

शासक दल ने इस निशा में 1947-उपरात हर कोशिश को राष्ट्रविरोधी करार देकर औद्योगिक युग के ससदीय लोचनत्र के बारे में अपनी तानाशाही समझ का ही सबूत दिया है। परंपरागत विपक्षी दल भी इस मामले का हर पाच साल बाद ससदीय चुनाव के मौने पर उठने वाला क्षणिक मुद्दा ही मानते आए हैं। सिफ एक बार यानी इमरजेंसी के बाद अथवा 1977 के ससदीय चुनाव की पूर्ववेला में यह सवाल गभीरता से उठाया गया था। उस समय भी इस बारे में पहल जयप्रकाश नारायण ने की थी। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर गैर कम्युनिस्ट विपक्षी दलों ने अपना अलग अस्तित्व बनाए रखा तो वे तत्कालीन विपक्षी संयुक्त मोर्चे (जो तब इंदिरा गांधी की तानाशाही नीतियों के खिलाफ समय कर रहा था) के नेतृत्व से अलग हो जाएंगे। इस तरह के दबाव डालकर इन दलों को एक दल में पिरोने में सफल हुए थे। नतीजा यह निकला कि कांग्रेस, जनसंघ, सीएफडी, भारतीय क्रांति दल और समाजवादियों के विलय से जनता पार्टी बजुद में आई।

लेकिन पीछे का मूल्यांकन करते हुए अब यह कहा जा सकता है कि जनता पार्टी (जिसने लागो में उम्मीदें जगाईं) के गठन के बजाय अगर पाच पार्टियों का संयुक्त मोर्चा बनता तो वह ज्यादा बेहतर होता (क्योंकि इसके टूटने के बाद लागो में वैसी निराशा नहीं पैदा होती)।

(ii) क्षेत्रीय अथवा राज्य स्तर पर शासक दल का विकल्प बर्नाली की पाणिश ज्यादा फायदेमंद रही हैं। इस तरह 1967 में संयुक्त विधायक दल की अगुआई में विपक्ष की मिली जुली सरकारें भी बनी थी। सीपीएम के प्रभुत्व वाले दो राज्यों केरल और पंजाब में तो संयुक्त मोर्चे का समृद्ध अनुभव रहा है।

(iii) हर परंपरागत विपक्षी दल ने खुद को शासक दल के विकल्प के तौर पर डालने की कोशिश की है। लेकिन इनमें कोई भी राष्ट्र-विरोधी के रूप में लागो में अपनी साख कायम नहीं कर पाया।

(ख) (i) परंपरागत विपक्षी दल अकेले या सामूहिक तौर पर एक विपक्षीय राष्ट्रीय विकल्प नहीं बना पाए तो इसकी वजह संवैधानिक तौर पर शासक दल है।

(ii) संवैधानिक तौर पर कोई भी परंपरागत विपक्षी दल शासक दल के साथ गठजोड़ बनाकर शासक कांग्रेस के मुकाबले एक संयुक्त मोर्चा के तौर पर लागो में विश्वास अर्जित करने में सफल नहीं हो पाया। उदाहरण के लिए विरोधाभासी रूप अपनाया है। एक तरफ यह संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधित्व करता है तो दूसरी तरफ उसकी एक या दूसरी दल की संयुक्त मोर्चा में मसलन, सभी परंपरागत विपक्षी दल भारतीय संसद के संयुक्त मोर्चा के हैं तथा कांग्रेस की विदेशी मामलों, रक्षा और न्याय के क्षेत्रों में प्रभुत्व का पूरा समय करते हैं। उन्होंने न्याय-विरोधी के तौर पर कुछ बने-बनाए प्रेस पर नकेल डालने वाली कामकाज के संयुक्त मोर्चा के तौर पर राष्ट्रविरोधी करार देने तथा सर्वथा विपक्षी के तौर पर, 1977 के चुनाव में

की कांग्रेसी नीतियों का बहुत कम भडाफोड किया है। उन्होंने अमूमन कट्टरवाद और खास तौर पर बहुसंख्यक समुदाय के कट्टरवाद को तुष्ट करने की कांग्रेसी नीति (मसलन शासक दल द्वारा लगभग हर सरकारी उद्घाटन समारोह में पूजा और आरती करने) के अलावा धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव रखने और अनुसूचित जातियाँ व जनजातियों का दमन करने की उसकी नीतियों का शायद ही कभी विरोध किया है। उन्होंने तो नगालैंड, मणिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम आदि जैसी उलझी जातीय समस्याओं को सशस्त्र दमन से हल करने की कांग्रेसी नीति की भी आलोचना नहीं की। पंजाब के नाजुक मसले को निबटाने में उन्होंने वस्तुतः गोली के बदले गोली की कांग्रेसी नीति का ही समर्थन किया है। अभी पिछले साल ही उन्होंने शासक कांग्रेस की पहल पर संयुक्त रैलियों में बरनाला को 'शेरदिल राष्ट्रवादी' घोषित किया लेकिन बरनाला की ओर से प्रथियों के आगे घुटने टेकने से यह बात गलत सिद्ध हुई। उन्होंने हमेशा अलोकतांत्रिक तरीकों के जरिए (चुनाव में हेराफेरी करके और नागरिक स्वतंत्रताओं को दबाकर) कश्मीर की क्षेत्रीय पहचान के मसले को निबटाने की कांग्रेसी नीति का समर्थन किया है। हर दल को अलग अलग भी परखें तो दानो कम्युनिस्ट पार्टियों का मामूली मतभेदों को छोड़कर अमूमन मानना है कि विदेशी मामलों आर्थिक नियोजन, सांख्यिक क्षेत्र, सांप्रदायिकता और जातिवाद के बारे में कांग्रेस की नीतियाँ प्रगतिशील हैं। जनता पार्टी और लोकदल पूरी तरह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। उन्हें मतभेद सिर्फ नहरूवादी रूप में समझकर विदेश नीति और सरकारी क्षेत्रों की अगुआई में आर्थिक नियोजन से है। जनमोर्चा का कांग्रेस से मतभेद महज उच्च पदों पर भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर है। भाजपा अधिक मजबूत केंद्र (संविधान के अनुच्छेद 370 जैसे प्रावधानों को खत्म करके जिनके तहत एक या दूसरे समुदाय की बहुलता वाले राज्यों को कुछ रियायतें हासिल हैं) तथा अल्पसंख्यकों के प्रति तुष्टिकरण की कांग्रेसी नीति का विरोध करने के सिवा कांग्रेस से कोई मूल मतभेद नहीं रखती (उसने तो 1980 में गांधीवादी समाजवाद को भी मान लिया था लेकिन 1984 में उसे छोड़ दिया)। ध्यान देने की बात है कि ये सभी विपक्षी दल राजीव शासन के पहले दो वर्षों के दौरान सत्ताह्व कांग्रेस के आगे एकदम भीगी बिल्ली बने रहे। प्रधानमंत्री समेत उच्चाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के घोटालों का पर्दाफाश होने पर ही उनमें फिर से प्राण लौटे थे। सत्ताह्व और सत्ता से बाहर क्षेत्रीय पार्टियाँ अपनी-अपनी क्षेत्रीय समस्याओं के सवाल पर कांग्रेस से मतभेद रखती हैं। उनका राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से कोई ज्यादा लेना-देना नहीं है। जाहिर है कांग्रेस और विपक्षी दलों (राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय) के बीच वैचारिक रूप से कोई स्पष्ट विभाजन रखा नहीं रही है जिसमें आधार पर लोग कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी सिद्धांत के बीच फक कर पाते।

(iii) व्यावहारिक तौर पर भी कांग्रेस और इन विपक्षी दलों के बीच कोई मूल अंतर नहीं रहा है। उन्होंने भी कांग्रेस जैसी चुनावी प्रक्रिया (जिस पर धन,





चुनाव के दौरान उन्होंने द्रमुक के साथ अपने-अपने ढंग से चुनाव गठबंधन किया। इसी तरह जनवरी से अप्रैल 1987 तक वे पंजाब में सिख मुख्यग्रथियों के खिलाफ तत्कालीन मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला के 'धमनिरपक्ष' रखे जाने के समर्थन देने के लिए एक ही मंच से भाषण देते रहे। जहाँ तक कि जुलाई 1988 में ज्योति बसु और अटल बिहारी वाजपेयी ने कलकत्ता में वी० पी० सिंह का इलाहाबाद संसदीय चुनाव की जीत के बाद एक ही मंच से स्वागत किया। इससे पहले भी दोनों पक्षों ने अक्सर निवृत्त सहयोगी के तौर पर काम किया है। सीपीआई और जनसंघ (अब भाजपा) 1967-68 के दौरान पंजाब और बिहार की संयुक्त सरकारों में सहभागी रहे हैं जबकि सीपीएम और जनसंघ (जो जनता पार्टी का घटक था) 1977-79 में जनता शासन के दौरान करीबी मित्र थे। जाहिर है एक दूसरे के खिलाफ उनके बयान और रखे उनके मौजूदा और पिछले कामकाज के चलते हैं। इस तरह के जनता को उलझाव में डालकर राजीव सरकार को हटाने के अपने मुख्य उद्देश्य का नुकसान पहुँचाते हैं। इसके अलावा, सीपीआई और सीपीएम कभी सांप्रदायिकता तो कभी विदेशी अस्थिरीकरण को भारत की एकता के लिए मूल खतरा बताते हैं जबकि भाजपा कभी अल्पसंख्यकों का तो कभी पाकिस्तान को भारत के लिए खतरा करार देती है। दोनों कम्युनिस्ट पार्टियाँ और भाजपा की यह सारी तूमतडक अव्यवस्थित सोच के सिवा कुछ नहीं, जिसके प्रभाव में कभी वे राजीव सरकार को हटाने की व्यापक प्राथमिकता पर जोर देते हैं तो कभी अपनी-अपनी पार्टियों का प्राथमिकता देने लगते हैं।

(च) दूसरे प्रमुख विपक्षी दल भी न तो अकेले-अकेले और न ही सामूहिक तौर पर मौके की पहचान कर पाए हैं। चार विपक्षी दलों—जनता, लोकदल, जनमोर्चा और कांग्रेस स की एकता प्रक्रिया भी क्षुद्र क्षणों का मनहूस नजारा पेश करती है। हर कोई गुट नई पार्टी के नाम, झंडे, चुनावचिह्न, कायक्रम, संविधान, राष्ट्रीय कायकारिणी, संचालन समिति और संसदीय बॉड के गठन आदि का लेकर दूसरे से भिड़ रहा है। कांग्रेस इ का राष्ट्रीय विकल्प बनाने के लिए चार घटकों में कांग्रेस-एस ने खुद का जनता दल से अलग कर लिया, लोकदल (व) और जनमोर्चा में फूट पड़ गई जबकि जनता पार्टी चंद्रशेखर और रामकृष्ण हेगड़े के गुटों द्वारा पदों की छीना छापटी से वस्तुतः दो प्रतिद्वंद्वी शिविरो में बंट गई। जनता दल के नेताओं की राजनीति का इस हद तक पतन हुआ है कि देवीलाल एक दिन चंद्रशेखर पर कांग्रेस इ का एजेंट हान का आरोप लगाते हैं और दूसरे दिन उन्हें जनता दल के एक दिग्गज नेता बताते हैं एक दिन वे अपने पार्टी अध्यक्ष बहुगुणा को ठग नटवरलाल की सजा देते हैं और उन पर विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए कांग्रेस इ से करोड़ों रूपए लेन का आरोप लगाते हैं जबकि अगले दिन पार्टी कायकारिणी की बैठक में उनके साथ बैठते हैं तथा राष्ट्रीय मोर्चे में अभी तक उनके सहयोगी बने हुए हैं। एक दिन चंद्रशेखर वी० पी० सिंह पर सजय गांधी का चेला, बड़ा ढागी, विभीषण और राजीव गांधी सरीखे के आरोप लगाते हैं और अगले ही दिन उन्हें अपना नेता स्वीकार कर लेते हैं।

श्री अजीत सिंह वी० पी० सिंह पर जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अपने 'डाइवरा-क्वोनरो' तब को भर्ती कर लेने का आरोप लगाते हैं और अगले ही दिन प्रमुख महासचिव का पद मिलने पर तत्काल वी० पी० सिंह के सहायक बन जाते हैं, एक दिन व चंद्रशेखर से गठजोड़ करत हैं तो दूसरे दिन देवीलाल से। वी० पी० सिंह की स्थिति भी ऐसी है। एक तरफ व कांग्रेस पर तानाशाही व्यवहार का आरोप लगाते हैं तो दूसरी तरफ खुद जनता दल के तानाशाह बनकर उसकी सर्वोच्च समिति और पदाधिकारियों को नामांकित करते हैं, एक दिन मुद्दे पर आधारित राजनीति की बात करते हैं तो अगले ही दिन बायथम या नीति के किसी मुद्दे पर कोई पूव सहमति हुए बिना अपन जनमोर्चे का व्यवितगत राजनीति के आधार पर जनता दल में विलय कर देते हैं, एक दिन एक व्यक्ति एक पद के फामूले का प्रचार करते हैं तो अगले दिन खुद जनता दल का अध्यक्ष होने के साथ ही राष्ट्रीय मोर्चे के संयोजक भी बन जाते हैं तथा हरियाणा व मुख्यमंत्री देवीलाल को दूसरा पद देकर जनता संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना देते हैं, एक दिन वे अजीत सिंह पर लोगो का विश्वासपात्र न होने का व्यग्य करते हैं तो दूसरे ही दिन उन्हें जनता दल का महासचिव पद दे देते हैं, एक दिन वामपथियों को अपना स्वाभाविक दोस्त बताते हैं तो दूसरे ही दिन राज्यसभा की सीट जीतने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा से गठजोड़ कर लेते हैं, एक दिन मूल्यों पर आधारित राजनीति की बातें बघारते हैं तो दूसरे ही दिन इलाहाबाद संसदीय चुनावक्षेत्र के अपने चुनाव प्रचारको को कांग्रेस की तरह धन एवं वाहुबल का इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं, आरिफ खा को चुनाव मुहिम से अलग रखते हैं तथा मुसलमान वोट पाने के लिए शहाबुद्दीन और हाजी मस्तान के बट्टरवादी प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं, एक दिन कोई सावजनिक पद स्वीकार न करने की प्रतिज्ञा करते हैं तो अगले ही दिन लोकसभा सदस्य बनना मान जाते हैं तथा अब भारत का सर्वोच्च कार्यकारी पद पाने के लिए सभी प्रकार के समझौते कर रहे हैं। जाहिर है, जनता दल के नेता अपने अहं के टकरावो को जारी रखने में ज्यादा सन्निय हैं और जन समस्याओ के मुकाबले अपने अपने गुटा के स्वाय आगे बढ़ाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। उनमें सत्ता हासिल करने के मुद्दे के सिवा किसी सिद्धांत पर आपसी सहमति नहीं है।

(छ) मौजूदा हालात के तथ्यों के मद्देनजर हमारा मत है कि पिछले चार दशकों के दौरान एकदलीय कांग्रेस शासन नाकारा सिद्ध हुआ है। दूसरे, इस समय चल रहे घ्रष्ट कांग्रेसी प्रशासन के मुकाबले सरकार में किसी भी प्रकार की तब्दीली बहुत ही होगी। इससे लोगो को कम से कम कुछ रियायतें तो मिलेंगी। तीसरे, वार्ड भी अकेला विपक्षी दल कांग्रेस इ का विकल्प नहीं हो सकता। चौथे, सभी परंपरागत विपक्षी दलो ने मूल्यों पर आधारित राजनीति के सिद्धांतों का जय-शय उत्सव न करके घज्जिया उड़ाई है। पाचवें अगर समूचा विपक्ष 'यूनियन बायथम और नीतियों के आधार पर एक ही झंडे तले एकजुट हो जाय और हर -

विपक्षी उम्मीदवार खड़ा करके शासक दल की सामना करे तो ऐसा विपक्षी गठजोड़ चाहे राष्ट्रीय मोर्चे के रूप में हो या सघीय पार्टी के, जनहिता के अनुरूप है और भारतीय लोगों के समयन का पात्र है। छठे अगर विपक्ष वामपंथी, दक्षिणपंथी और मध्यमार्गियों में बटा रहता है तथा हर चुनावक्षेत्र में शासक दल के मुकाबले विपक्ष के विभिन्न मोर्चों के दा या अधिक उम्मीदवार मैदान में है तो जन हितों की रक्षा के लिए सही रास्ता यह है कि पार्टी सवद्धता की अनदेखी करके ऐसे उम्मीदवारों का समयन किया जाए जो ज्यादा लोकतांत्रिक, ज्यादा धमनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय के प्रति ज्यादा समर्पित हैं। सातवें, यह तक कि किसी अखिल भारतीय पार्टी की चुनावी जीत पर ही भारत की स्थिरता का दारोमदार है, एक भ्रामक और ववुनियामक विचार है क्योंकि औद्योगिक युग में स्थिरता मुख्यतया लोकतांत्रिक संस्थाओं, मानदंडों और ताकतों पर निर्भर होती है। कांग्रेस इसी अतिकेंद्रीकृत अथवा तानाशाही पार्टी ज्यादा देर तक लोकतांत्रिक एकता बनाए नहीं रख सकती (1947 में दश विभाजन और उसके बाद बढ़ते साम्प्रदायिक और जातिवादी दंगे इसका स्पष्ट उदाहरण हैं)। राष्ट्रीय सेना जैसे सवशक्तिमान और देश-यापी संगठन की अगुआई में पाकिस्तान का मजबूत सैनिक शासन दश को दो भागों में बांटने में ही सहायक हुआ। वजह साफ है कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय सेना में तानाशाह कांग्रेस की तरह लोकतांत्रिक मानदंडों का अभाव है। भारत में स्थिरता निरंतर कांग्रेस शासन की वजह से नहीं (उल्टे उसने अधिक स्थिरता के रास्ते में बाधाएं डाली हैं) बल्कि देश में बहुदलीय तंत्र की मौजूदगी के कारण रही है जो भारत जैसे बहुसांस्कृतिक, बहुभाषायी, बहुधार्मिक और बहुक्षेत्रीय देश को एकजुट रखने का समुचित आधार है। अगर आगामी चुनाव में लोग कांग्रेस की तानाशाही को रद्द करके अधिक लोकतांत्रिक विकल्प को चुन लें तो भारत की स्थिरता ज्यादा मजबूत बनेगी। आठवें, इस समय भारत और यहाँ की जनता के लिए दो ही विकल्प फायदेमंद हो सकते हैं। पहला यह कि सभी प्रमुख विपक्षी दल यूनितम कायध्रम और महत्वपूर्ण नीतियों के आधार पर आपसी सहमति वाले किसी नाम के तहत एक हो जाए (चाहे वह नाम राष्ट्रीय मोर्चा ही हो)। अगर यह काम सरे नहीं बढ़ता तो दूसरा विकल्प यह है कि भारतीय जनता आगामी चुनाव में कांग्रेस को और सभी विपक्षी मोर्चों को रद्द कर दे तथा उम्मीदवारों की पार्टी सवद्धता की अनदेखी करते हुए अधिक लोकतांत्रिक, अधिक धमनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय के प्रति अधिक समर्पित लोगों को चुने। इस तरह के लोगों की व्यापक जीत से भारत में एक नया राजनैतिक माहौल बनेगा। इसमें नए राजनैतिक गठजोड़ बनाना जरूरी हो जाएगा। जीते हुए लोग (विभिन्न दलों के बेहतर तत्व) या तो साझे कायध्रम और नीतियों के आधार पर राष्ट्रीय संयुक्त सरकार बनाएंगे अथवा अधिक प्रगतिशील कायध्रमों और नीतियों के आधार पर एक तीसरी राजनैतिक ताकत के रूप में एकजुट होंगे। ये दोनों ही तरीके व्यवहार्य हैं और भारत के साथ साथ दुनिया के लोगों के हितों

मे हैं। नीचे, भारत की दीर्घकालिक प्रगति एक अंतरराष्ट्रीयवादी लोकतांत्रिक संगठन बनाने पर निर्भर करती है। यही संगठन भारतीय जनता को उस विश्व लोकतांत्रिक राज्य की ओर ले जाने का उचित साधन हो सकता है जो राष्ट्र-राज्य के विकास की अगली अवस्था है और जो 21 वीं सदी के पहले दशक में भारत समेत दुनिया के लोगों के सामने प्रमुख काम भी है।





